

# आर्थिक समीक्षा

## का सारांश 2024-25



अहमदाबाद



बेंगलूरु



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची

## आर्थिक समीक्षा का सारांश: 2024-25

### विषय-सूची

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को समझें                                                                    | 3   |
| अध्याय 1: अर्थव्यवस्था की स्थिति: पुनः तेज गति की ओर                                                 | 4   |
| अध्याय 2: मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र का विकास: अन्योन्याश्रित संबंध                                  | 14  |
| अध्याय 3: बाह्य क्षेत्र: FDI को व्यवस्थित रूप देना                                                   | 27  |
| अध्याय 4: कीमतें और मुद्रास्फीति: उतार-चढ़ाव को समझना                                                | 39  |
| अध्याय 5: मध्यम अवधि का परिदृश्य: गैर-विनियमन से विकास को बढ़ावा                                     | 45  |
| अध्याय 6: निवेश और अवसंरचना: अनवरत रहे                                                               | 53  |
| अध्याय 7: उद्योग: समग्र व्यवसायिक सुधार                                                              | 61  |
| अध्याय 8: सेवा: दिग्गजों के समक्ष नई चुनौतियाँ                                                       | 70  |
| अध्याय 9: कृषि और खाद्य प्रबंधन: भविष्य का क्षेत्र                                                   | 79  |
| अध्याय 10: जलवायु और पर्यावरण: अनुकूलन की अनिवार्यता                                                 | 88  |
| अध्याय 11: सामाजिक क्षेत्र: पहुंच का विस्तार करना और सशक्तिकरण को प्रोत्साहन                         | 98  |
| अध्याय 12: रोजगार और कौशल विकास: अस्तित्वगत प्राथमिकताएँ                                             | 111 |
| अध्याय 13. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-AI) युग में श्रम व्यवस्था: संकट या उत्प्रेरक? | 123 |
| MCQs के उत्तर                                                                                        | 128 |

# अभ्यास 2025

## ऑल इंडिया प्रीलिम्स

### (GS+CSAT) मॉक टेस्ट सीरीज

**3 टेस्ट**

|                     |                      |                  |
|---------------------|----------------------|------------------|
| टेस्ट 1<br>6 अप्रैल | टेस्ट 2<br>27 अप्रैल | टेस्ट 3<br>11 मई |
|---------------------|----------------------|------------------|

Register at: [www.visionias.in/abhyas](http://www.visionias.in/abhyas)

- UPSC प्रारंभिक पाठ्यक्रम का पूरा कवरेज
- मानसिक तत्परता के लिए परीक्षा जैसा माहौल
- अखिल भारतीय रैंकिंग
- VisionIAS पोस्ट टेस्ट विश्लेषण
- लाइव टेस्ट चर्चा
- अंग्रेजी/हिंदी में उपलब्ध

Agartala | Agra | Ahmedabad | Aizawl | Ajmer | Aligarh | Amritsar | Ayodhya | Bareilly | Bathinda | Bengaluru | Bhopal | Bhubaneswar | Bikaner | Bilaspur | Chandigarh | Chennai | Chhatrapur | Chhatrapati Sambhaji Nagar | Coimbatore | Cuttack | Dehradun | Delhi | Dhanbad | Dharamshala | Dharwad | Durgapur | Faridabad | Gangtok | Gaya | Ghaziabad | Gorakhpur | Gurugram | Guwahati | Gwalior | Haldwani | Haridwar | Hazaribagh | Hisar | Hyderabad | Imphal | Indore | Itanagar | Jabalpur | Jaipur | Jalandhar | Jamnagar | Jamshedpur | Jhansi | Jodhpur | Kanpur | Kochi | Kohima | Kolkata | Kota | Kozhikode | Kurukshetra | Leh | Lucknow | Ludhiana | Madurai | Mandi | Meerut | Moradabad | Mumbai | Muzaffarpur | Mysuru | Nagpur | Nashik | Navi Mumbai | Noida | Orai | Panaji | Panipat | Patiala | Patna | Prayagraj | Puducherry | Pune | Raipur | Rajkot | Ranchi | Rohtak | Roorkee | Sambalpur | Shillong | Shimla | Siliguri | Srinagar | Surat | Thane | Thiruvananthapuram | Tiruchirappalli | Tirupati | Udaipur | Vadodara | Varanasi | Vijayawada | Visakhapatnam | Warangal

## अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थी,

आर्थिक सर्वेक्षण को बेहतर तरीके से समझना जरूरी है। अतः आर्थिक सर्वेक्षण को अधिक व्यापक और आसान तरीके से समझने के लक्ष्य के साथ इस डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित नए खंड शामिल किए गए हैं:



**आर्थिक सर्वेक्षण को समझें:** यह खंड, आर्थिक सर्वेक्षण क्या है और इसके महत्व का अवलोकन प्रदान करता है। यह आर्थिक सर्वेक्षण की आगे के विश्लेषणों के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है।



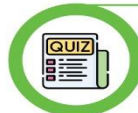
**प्रिकैप:** इसके जरिए प्रत्येक अध्याय के आरंभ में एक स्नैपशॉट दिया गया है, जिसमें अध्याय में शामिल विचारों और विषय-वस्तु पर प्रकाश डाला गया है।



**बजट में क्या कहा गया है?:** यह खंड आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट के बीच संबंधों का विश्लेषण तथा व्याख्या करता है। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि कैसे यह सर्वेक्षण बजट के लिए व्यापक आर्थिक संदर्भ प्रदान करता है।



**शब्दावली:** इसमें अध्याय में प्रयुक्त प्रमुख टर्म या पद का संग्रह है (प्रत्येक अध्याय के अंत में)।



**क्विज़ और मुख्य परीक्षा के प्रश्न:** प्रत्येक अध्याय को बेहतर तरीके से समझने और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखने के लिए, अध्यायों के अंत में एक क्विज़ (MCQ) और मुख्य परीक्षा के प्रश्न जोड़े गए हैं। MCQ के उत्तर डॉक्यूमेंट के अंत में दिए गए हैं।

**LIVE/ONLINE**  
Classes Available

www.visionias.in



## Foundation Course GENERAL STUDIES PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI: 4 MAR, 2 PM | 11 MAR, 5 PM | 13 MAR, 11 AM | 18 MAR, 8 AM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 25 MAR, 8 AM

हिन्दी माध्यम DELHI: 25 फरवरी, 8 AM | 25 मार्च, 2 PM

AHMEDABAD: 4 JAN

BENGALURU: 30 MAR

BHOPAL: 25 FEB

CHANDIGARH: 18 JUN

HYDERABAD: 3 MAR

JAIPUR: 5 APR

JODHPUR: 17 MAR

LUCKNOW: 9 APR

PUNE: 4 MAR

## फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

► प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 25 फरवरी, 8 AM | 25 मार्च, 2 PM

JAIPUR: 10 अप्रैल

JODHPUR: 17 मार्च

प्रवेश प्रारम्भ

BHOPAL | LUCKNOW



Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

f /visionias.upsc

yt /c/VisionIASdelhi

ig /c/VisionIASdelhi

ts /t.me/s/VisionIAS\_UPSC

## आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को समझें

# आर्थिक सर्वेक्षण को समझें

## आर्थिक सर्वेक्षण क्या है?



यह भारत के विकास पथ का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें हमारे राष्ट्र के प्रति वैश्विक आशावाद को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, इसमें अवसंरचना पर ध्यान देने के साथ ही कृषि एवं उद्योग जैसे क्षेत्रों में विकास और भविष्योन्मुखी क्षेत्रों पर भी बल दिया गया है।

## इसे कौन तैयार करता है?

- वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (DEA) के आर्थिक प्रभाग (Economic Division) द्वारा,
- यह मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है।



## प्रस्तुति और तैयारी

- यह बजट प्रस्तुत किए जाने के एक दिन पहले जारी किया जाता है।
- यह देश में वार्षिक आर्थिक विकास का सारांश प्रस्तुत करता है और अर्थव्यवस्था की लघु एवं मध्यम अवधि की संभावनाओं को रेखांकित करता है।
- आगामी वर्ष के बजट से पहले इसे संसद में पेश किया जाता है।



## बजट के लिए नीतिगत परिप्रेक्ष्य

- वित्त मंत्रालय के एक प्रमुख दस्तावेज के रूप में, आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए विस्तृत सांख्यिकीय डेटा प्रदान करता है।
- यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आधिकारिक मार्गदर्शिका है और आम तौर पर यह केंद्रीय बजट के लिए नीतिगत परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।



## आर्थिक परिदृश्य

- आर्थिक सर्वेक्षण देश की आर्थिक प्रवृत्तियों को उजागर करता है। ये प्रवृत्तियां संसाधनों को जुटाने के प्रयासों और बजट में उनके आवंटन में वृद्धि को प्रेरित करती हैं।
- यह सर्वेक्षण कृषि और औद्योगिक उत्पादन, बुनियादी ढांचे, रोजगार, वित्त की आपूर्ति, व्यापार, विदेशी मुद्रा भंडार और अन्य प्रासंगिक आर्थिक कारकों के रुझानों का विश्लेषण करता है। ये सभी कारक बजट को प्रभावित करते हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण बजट से कैसे संबंधित है?

## अध्याय 1: अर्थव्यवस्था की स्थिति: पुनः तेज गति की ओर (State of the economy: Getting back into the fast lane)

### परिचय

- वैश्विक आर्थिक स्थितियां आर्थिक संवृद्धि में बदलाव, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव और विकसित होती मौद्रिक नीतियों से आकार ग्रहण करती हैं। ये सभी कारक घरेलू मुद्रास्फीति, व्यापार संतुलन और पूंजी प्रवाह को प्रभावित करते हैं।
- वर्तमान में, यह अंतर्संबंध अप्रत्याशित भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधानों और जलवायु संबंधी उतार-चढ़ाव के कारण जटिल हो गया है।

### अध्याय का प्रीकैप

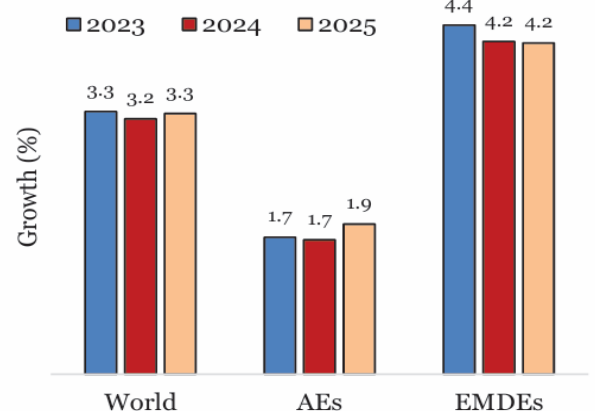
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>वैश्विक आर्थिक परिदृश्य</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>स्थिर वैश्विक संवृद्धि</li> <li>सेवा क्षेत्र की स्थिर संवृद्धि</li> <li>अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति की दर लगातार नीचे की ओर जा रही है</li> <li>भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं के बीच मौद्रिक नीति को आसान बनाना</li> </ul>                                             | <b>घरेलू अर्थव्यवस्था</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>महामारी-पश्चात लोचशील आर्थिक रिकवरी</li> <li>वित्त वर्ष 2025 में कृषि की बेहतर संभावनाएं</li> <li>विनिर्माण क्षेत्र में मध्यम स्तर की वृद्धि हुई</li> <li>सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि</li> </ul>      |
| <b>कई मोर्चों पर अर्थव्यवस्था स्थिरता और समावेशिता को दर्शाती है</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन</li> <li>मुद्रास्फीति - अस्थिर खाद्य कीमतों के साथ निम्न और स्थिर कोर मुद्रास्फीति का संयोजन</li> <li>सेवा व्यापार और रिकॉर्ड धन विप्रेषण द्वारा बाह्य क्षेत्र की स्थिरता की सुरक्षा</li> </ul> | <b>रोजगार संबंधी रुझान</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर लगातार कम हो रही है</li> <li>भारत में औपचारिक क्षेत्र ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है</li> <li>भारत के श्रम बाजार में AI का समेकन</li> </ul> |

### वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

#### स्थिर वैश्विक संवृद्धि और विविध क्षेत्रीय गतिशीलता

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 2024 और 2025 में क्रमशः 3.2 प्रतिशत एवं 3.3 प्रतिशत की संवृद्धि का अनुमान लगाया था।
- अगले पांच वर्षों में वैश्विक संवृद्धि औसतन 3.2 प्रतिशत के आसपास रहने की उम्मीद है। यह ऐतिहासिक मानकों के हिसाब से सामान्य है।
- उच्च व्याज दरों के बावजूद, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 2024 की पहली तिमाही में स्थिर वृद्धि देखी गई थी। ऐसा मुद्रास्फीति में नरमी और रोजगार एवं उपभोग में निरंतर वृद्धि के कारण हुआ है।

चार्ट 1.2: कंट्री ग्रुप्स में स्थिर विकास की संभावना



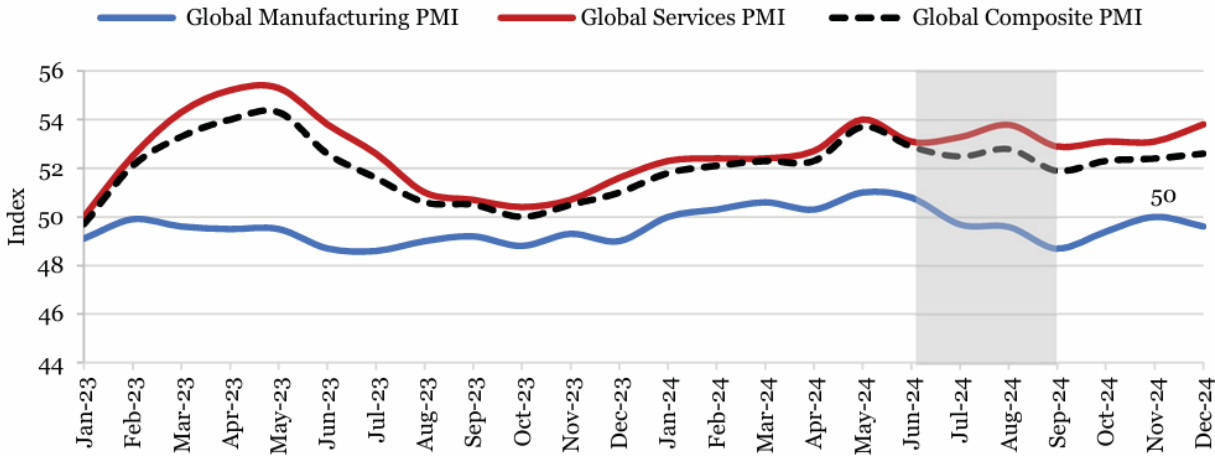
स्रोत: आईएमएफ डब्ल्यूईओ (जनवरी 2025)

नोट: एईएस- उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, ईएमडीई- उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं।

## सेवा क्षेत्र की स्थिर वृद्धि: विनिर्माण क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां

- वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI)<sup>1</sup> लगातार चौदहवें महीने (दिसंबर 2024 तक) विस्तार क्षेत्र में रहा है।
- सेवा क्षेत्र लगातार मजबूती प्रदर्शित कर रहा है, जबकि विनिर्माण PMI में संकुचन का संकेत मिला है।

चार्ट I.5: नवंबर 2024 में वैश्विक विनिर्माण स्थिरता



स्रोत: ब्लूमबर्ग

## मुद्रास्फीति संबंधी दबाव कम हो रहे हैं, लेकिन समकालिक मूल्य दबाव का जोखिम बना हुआ है

- अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति की दरों में लगातार गिरावट आई है, जो केंद्रीय बैंक के लक्ष्य स्तरों के करीब पहुंच रही है।
- यह दुनिया भर में सख्त मौद्रिक नीति व्यवस्थाओं और उच्च स्तर की आर्थिक अनिश्चितता के अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं का परिणाम है।
- इसके परिणामस्वरूप, 2023 में ईंधन की कीमतों में कमी के कारण मूल्य दबाव कम हुआ है।
- 2024 में, यह वस्तुओं की मुद्रास्फीति में व्यापक कमी के कारण हुआ है।

## भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के लिए जोखिम पैदा करती रहेंगी

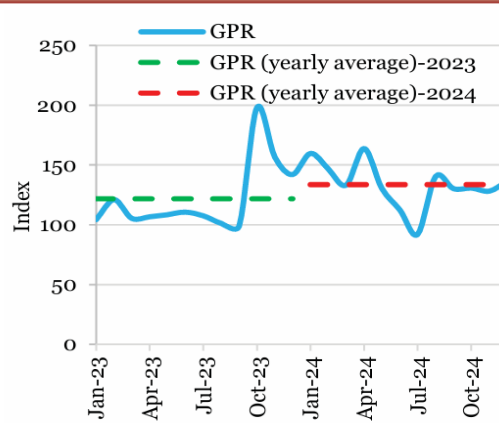
- वर्तमान में जारी संघर्ष (मध्य पूर्व, रूस-यूक्रेन आदि) के कारण विकास, मुद्रास्फीति, वित्तीय बाजारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के समक्ष जोखिम पैदा हो रहे हैं।
- ऊर्जा अवसंरचना को कोई भी नुकसान वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित कर सकता है और अनिश्चितता बढ़ा सकता है।
- स्वेज नहर के मार्ग से होने वाले व्यापार के बाधित होने के कारण केप ऑफ गुड होप के मार्ग से फिर से व्यापार होने लगा है। इससे औसत शिपिंग समय 10 दिन से अधिक हो गया है।
- भू-राजनीतिक आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक उच्च बना हुआ है।
- विश्व व्यापार अनिश्चितता सूचकांक बढ़ गया है, जो व्यापार संबंधी तनावों और नीतिगत बदलावों से प्रेरित है।
- G20 आयात प्रतिबंध अब 12.7% आयात को प्रभावित करते हैं, जो 2015 के स्तर से तीन गुना अधिक है।
- लंबी अनिश्चितता और बढ़ते व्यापार प्रतिबंध लागत बढ़ा सकते हैं, निवेश में बाधा डाल सकते हैं, नवाचार को बाधित कर सकते हैं और वैश्विक आर्थिक संवृद्धि को कमजोर कर सकते हैं।

<sup>1</sup> Purchasing Managers' Index

## वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है

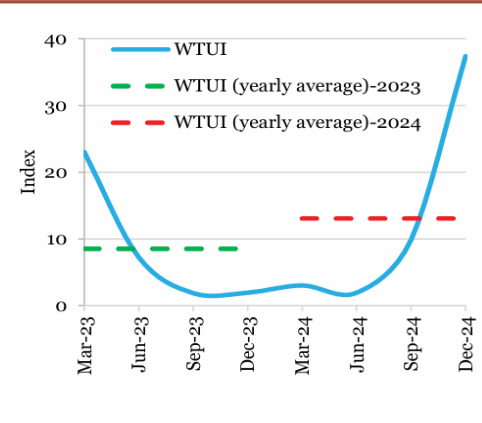
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान है।
- मांग पक्ष**
  - ऐसा अनुमान है कि ग्रामीण मांग में सुधार के कारण स्थिर कीमतों पर निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) 7.3% बढ़ जाएगा। साथ ही, सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) (स्थिर कीमतों पर) 6.4% बढ़ेगा।
- आपूर्ति पक्ष**
  - वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (GVA) भी 6.4% बढ़ने का अनुमान है।
  - कृषि क्षेत्रक वित्त वर्ष 2025 में 3.8% की वृद्धि के साथ वापसी कर सकता है।
  - निर्माण गतिविधियों और उपयोगिता सेवाओं द्वारा समर्थित, औद्योगिक क्षेत्रक वित्त वर्ष 2025 में 6.2% की वृद्धि कर सकता है।
  - वित्तीय, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाओं, लोक प्रशासन आदि द्वारा संचालित सेवा क्षेत्रक 7.2% की दर से वृद्धि करेगा।

**चार्ट I.18: भू-राजनीतिक जोखिम (जीपीआर) सूचकांक वर्ष 2024 में अधिक है**



स्रोत: आर्थिक नीति अनिश्चितता  
<https://www.policyuncertainty.com/gpr.html>

**चार्ट I.19: 2024 में बढ़ा हुआ विश्व व्यापार अनिश्चितता सूचकांक (डब्ल्यूटीयूआई)**



स्रोत: आर्थिक नीति अनिश्चितता  
<https://worlduncertaintyindex.com/data/>

## महामारी-पश्चात लोचशील आर्थिक रिकवरी

- समग्र परिदृश्य उत्साहजनक है।
- कुल GVA ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में महामारी-पूर्व की प्रवृत्ति को पार कर लिया है और यह अब वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में प्रवृत्ति से ऊपर है।
- कृषि क्षेत्रक मजबूत बना हुआ है। यह लगातार प्रवृत्ति स्तरों से ऊपर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।
- औद्योगिक क्षेत्रक ने भी महामारी-पूर्व प्रक्षेपवक्र (Trajectory) के ऊपर अपनी पैठ बना ली है।
- हालिया वर्षों में मजबूत संवृद्धि दर ने सेवा क्षेत्रक को अपने प्रवृत्ति स्तरों के करीब ला दिया है।

## वित्त वर्ष 2025 में कृषि की बेहतर संभावनाएं

- 2024-25 के लिए कृषि उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 लाख मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर पर होने का अनुमान है। यह 2023-24 की तुलना में 5.7% अधिक है।
  - कारण: अनुमानित वृद्धि मुख्य रूप से चावल, मक्का, मोटे अनाज (मिलेट्स) और तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के कारण है।
- 2024 में एक सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून ने जलाशयों में जल स्तर में सुधार किया है। इससे रबी फसल उत्पादन के दौरान सिंचाई के लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित हुआ है।

## विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में नरमी हुई, लेकिन सकारात्मक उम्मीदें दिखाई दी

- सबसे पहले, गंतव्य देशों से कमजोर मांग और प्रमुख व्यापारिक देशों में आक्रामक व्यापार एवं औद्योगिक नीतियों के कारण विनिर्माण निर्यात में काफी गिरावट आई है।
- दूसरा, औसत से अधिक मानसून के मिश्रित प्रभाव रहे हैं, हालांकि इसने जलाशयों को फिर से भर दिया है और कृषि में योगदान दिया है। हालांकि, इसने खनन, निर्माण और कुछ हद तक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को बाधित भी किया है।
- तीसरा, पिछले और वर्तमान वर्षों में सितंबर एवं अक्टूबर के बीच उत्सवों के समय में भिन्नता के कारण वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में वृद्धि में मामूली मंदी आई है।

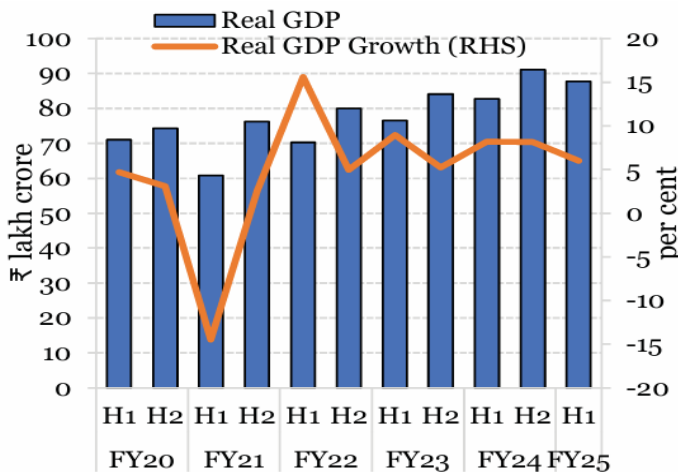
## सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि

- वित्त वर्ष 2025 में सेवा क्षेत्र का अच्छा प्रदर्शन रहा है।
- एयर कार्गो गतिविधि में दोहरे अंकों में वृद्धि हुई, जबकि बंदरगाह यातायात स्थिर रहा।
- सूचना प्रौद्योगिकी (IT) कंपनियों ने भी पिछली तिमाही की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया।

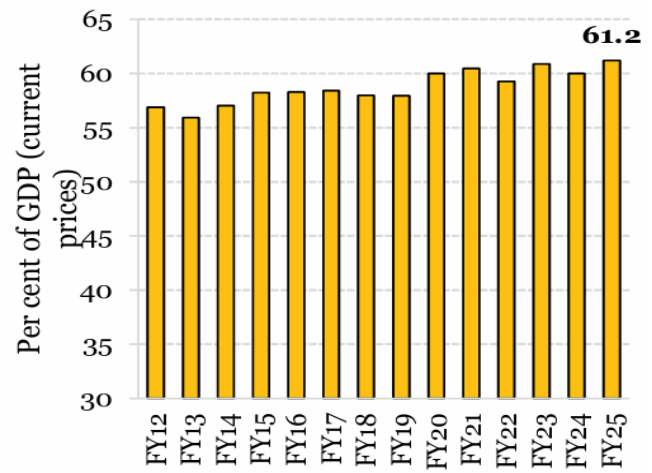
## व्यय श्रेणियों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का विश्लेषण

- स्थिर (2011-12) कीमतों पर भारत की GDP वित्त वर्ष 2025 की पहली और दूसरी तिमाही में क्रमशः 6.7% व 5.4% बढ़ी थी। इसका अर्थ यह है कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में वास्तविक GDP वृद्धि 6.0% रही है।

चार्ट 1.29: वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में जीडीपी वृद्धि 6.0 प्रतिशत रही



चार्ट 1.30: सभी वर्षों में पहली छमाही में निजी उपभोग का उच्चतम हिस्सा



स्रोत: विवरण 13 (स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का वार्षिक और त्रैमासिक अनुमान) और विवरण 14 (वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का वार्षिक और त्रैमासिक अनुमान, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) पर आधारित गणना

# ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

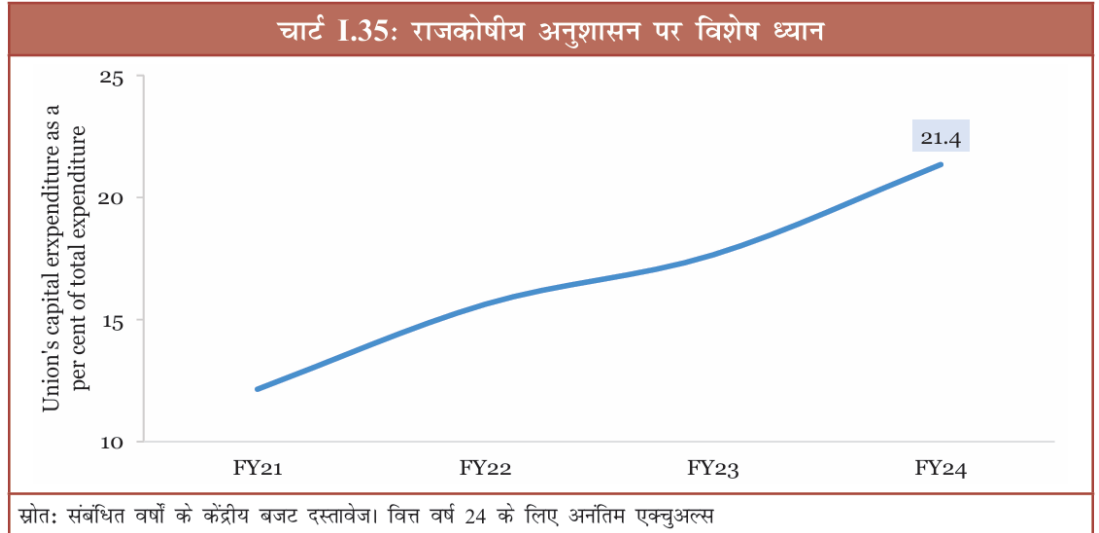
देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं  
 ✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र

|      |                           |                          |
|------|---------------------------|--------------------------|
| 2025 | ENGLISH MEDIUM<br>9 MARCH | हिन्दी माध्यम<br>9 मार्च |
| 2026 | ENGLISH MEDIUM<br>9 MARCH | हिन्दी माध्यम<br>9 मार्च |

## कई मोर्चों पर अर्थव्यवस्था, स्थिरता और समावेशिता से अभिलक्षित होती है

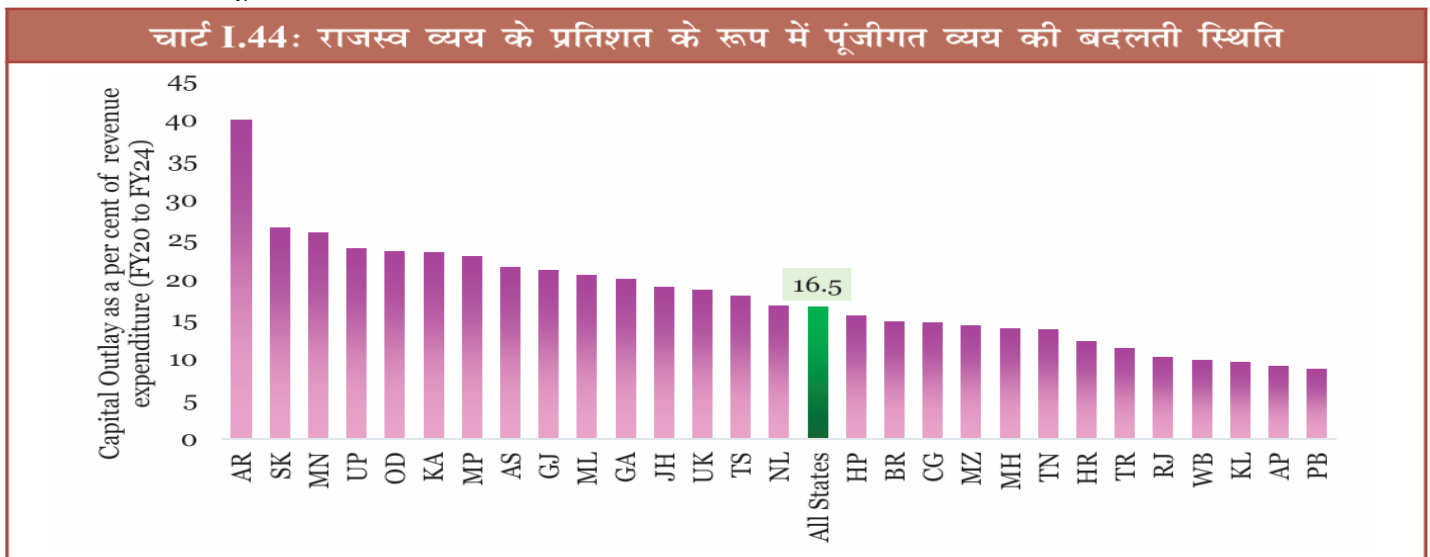
### सार्वजनिक वित्त में सुधार व्यापक आर्थिक स्थिरता का समर्थन करेगा

- कोविड-19 महामारी के बाद से, विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन ने सामान्य सरकारी अधिव्यय (Dissaving) को नियंत्रित करने में मदद की है।
- यह अर्थव्यवस्था में समग्र बचत को बनाए रखने में अधिक महत्व रखता है। वहीं निजी कॉर्पोरेट बचत GDP के लगभग 14% के आसपास बनी हुई है। लगातार सामान्य सरकारी अधिव्यय के परिणामस्वरूप, विदेशी वित्त-पोषण पर अधिक निर्भरता हो सकती है।
- पिछले चार वर्षों में विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन ने समग्र बचत-निवेश अंतर को बढ़ने से रोका है। साथ ही, इसने चालू खाता घाटे के सुगम वित्त-पोषण को सुनिश्चित किया है, भले ही घरेलू बचत दर में कमी आई हो।
- केंद्र सरकार की राजकोषीय व्यवस्था
  - राजकोषीय अनुशासन से केंद्र सरकार के संकेतकों में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है।
  - व्यय की गुणवत्ता में वित्त वर्ष 2021 से लगातार सुधार हुआ है। व्यय की गुणवत्ता केंद्र के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय द्वारा अनुमानित है।



### राज्यों के वित्त में परिवर्तनीय स्वरूप

- व्यय की गुणवत्ता में राज्यों ने काफी भिन्नता प्रदर्शित की है। इस गुणवत्ता को वित्त वर्ष 2024 में समाप्त होने वाले पांच वर्षों में राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत परिव्यय द्वारा मापा गया है।



स्रोत: आरबीआई ई-स्टेट्स डेटाबेस। वित्त वर्ष 2024 के लिए संशोधित अनुमान

## मुद्रास्फीति - अस्थिर खाद्य कीमतों के साथ कम और स्थिर कोर मुद्रास्फीति का संयोजन

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में बदलाव के रूप में मापी जाने वाली **खुदरा हैडलाइन मुद्रास्फीति**, वित्त वर्ष 2024 के **5.4%** से कम होकर अप्रैल-दिसंबर 2024 में **4.9%** हो गई थी।
  - CPI मुद्रास्फीति **4 (+/- 2)%** की सीमा के ऊपरी स्तर पर है।
- उपभोक्ता **खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI)** द्वारा मापी जाने वाली **खाद्य मुद्रास्फीति**, वित्त वर्ष 2024 के **7.5%** से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर) में **8.4%** हो गई है।

## सेवा व्यापार और रिकॉर्ड धन विप्रेषण द्वारा बाह्य क्षेत्र की स्थिरता की सुरक्षा

- व्यापारिक:** अप्रैल-दिसंबर 2024 में भारत का व्यापारिक निर्यात **1.6% सालाना बढ़ा** है। हालांकि, गैर-पेट्रोलियम निर्यात (समान तुलनात्मक आधार पर) **7.1%** बढ़ा है।

- सेवा:** भारत के मजबूत सेवा निर्यात ने देश को वैश्विक सेवा निर्यात में **7वां सबसे बड़ा हिस्सा** हासिल करने में मदद की है, जो इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।

- विप्रेषण:** विश्व बैंक के अनुसार, OECD अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार सृजन में तेजी के कारण भारत दुनिया में विप्रेषण प्राप्त करने वाला शीर्ष प्राप्तकर्ता था।

- चालू खाता घाटा (CAD):** यह

वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के **1.2 प्रतिशत** तक अपेक्षाकृत रूप से सीमित रहा है।

- सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** FDI प्रवाह अप्रैल-नवंबर 2024 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर **17.9%** बढ़ा है।

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)** प्रवाह 2024 की दूसरी छमाही में अस्थिर रहा है। इसका मुख्य कारण वैश्विक भू-राजनीतिक और मौद्रिक नीति में परिवर्तन है।

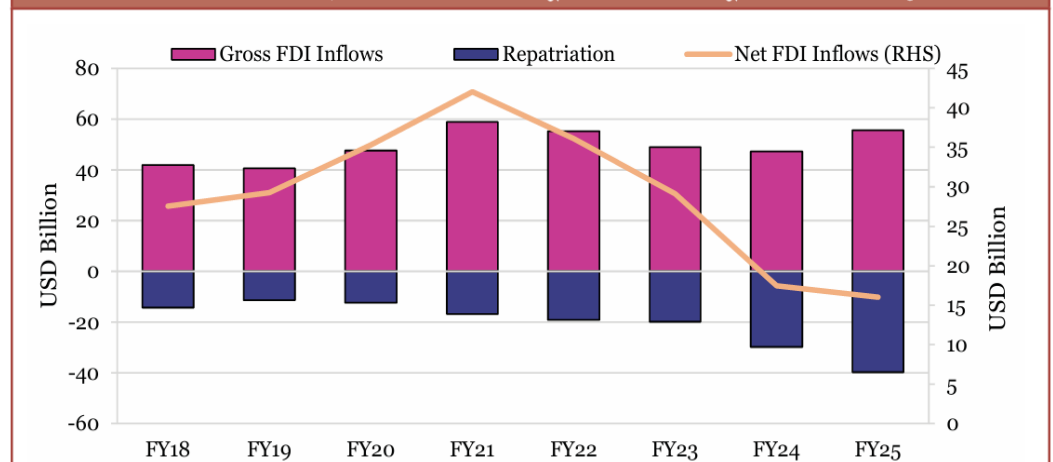
- विदेशी मुद्रा भंडार:** यह जनवरी 2024 के अंत में **616.7 बिलियन अमरीकी डॉलर** था, जो बढ़कर सितंबर 2024 में **704.9 बिलियन अमरीकी डॉलर** हो गया था। 3 जनवरी, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, यह **634.6 बिलियन अमरीकी डॉलर** है।

- भारत का विदेशी मुद्रा भंडार **90% बाह्य ऋण को कवर करने और 10 महीने से अधिक का आयात कवर प्रदान करने के लिए पर्याप्त** है। इससे बाह्य सुभेद्यताओं से बचाव होता है।

- आगे की राह**

- अल्पावधि में,** निर्यात बाजारों में विविधता लाना आवश्यक है, जबकि **मध्यम अवधि** के प्रयासों के तहत बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- दीर्घावधि में,** भारत को जैव प्रौद्योगिकी और अर्धचालक जैसे उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में स्वयं को एक **रणनीतिक भागीदार** के रूप में स्थापित करना होगा।
- रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी अंतरिक्ष, अर्धचालक, क्वांटम प्रौद्योगिकी और उन्नत दूरसंचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसर प्रदान करती है।

चार्ट 1.49: सकल एफडीआई प्रवाह मजबूत रहने के बावजूद प्रत्यावर्तन में वृद्धि

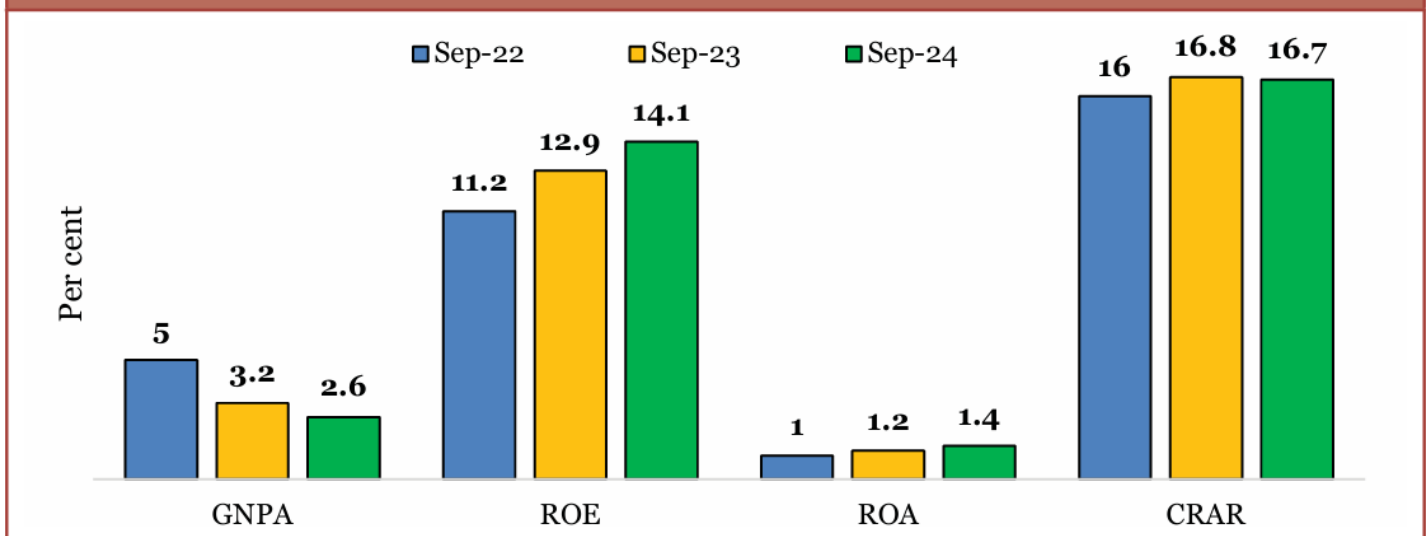


स्रोत: आरबीआई बुलेटिन तालिका संख्या 34 से एफडीआई आंकड़ों पर आधारित गणना

## ऋण वितरण में सामान्य वृद्धि के बीच वित्तीय क्षेत्रक की संभावनाएं

- RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR), दिसंबर 2024 के अनुसार-
  - बैंकिंग प्रणाली में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NAP) घट कर सकल ऋण और अग्रिम का 2.6 प्रतिशत रह गई हैं। यह 12 वर्षों के निचले स्तर पर है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) के लिए जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR) सितंबर 2024 तक 16.7 प्रतिशत था। यह मानक से काफी ऊपर है।
  - वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही के दौरान SCBs की लाभप्रदता में सुधार हुआ है। इससे कर भुगतान के बाद लाभ (PAT) में साल-दर-साल 22.2% की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत, इक्विटी पर लाभांश (RoA) और परिसंपत्ति पर लाभांश (RoA) में साल-दर-साल आधार पर सुधार हुआ है।

चार्ट 1.51: स्थिर बैंकिंग प्रणाली संकेतक



स्रोत: आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के विभिन्न संस्करण

## रोजगार संबंधी रुझान

- हालिया वर्षों में भारत के श्रम बाजार की वृद्धि को महामारी के बाद के सुधार और बेहतर औपचारिकता से सहायता मिली है।
- वर्ष 2023-24 की वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 2017-18 के 6 प्रतिशत से लगातार कम होकर 2023-24 में 3.2 प्रतिशत हो गई थी।
  - श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) और कामगार जनसंख्या अनुपात (WPR) में भी वृद्धि हुई है।
- भारत में औपचारिक क्षेत्रक में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के निवल सव्सक्रिप्शंस वित्त वर्ष 2019 के 61 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 131 लाख हो गए थे।
- भारत के श्रम बाजार में AI के एकीकरण की मदद से उत्पादकता बढ़ाने, कार्यबल की गुणवत्ता में वृद्धि करने और रोजगार सृजन के अवसर उत्पन्न होते हैं। हालांकि, इसके लिए शर्त यह है कि मजबूत संस्थागत फ्रेमवर्क के माध्यम से प्रणालीगत चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाए।
  - भारत एक युवा और अनुकूल कार्यबल के साथ एक सेवा आधारित अर्थव्यवस्था है। भारत के लिए AI को अपनाने आदि से आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने और श्रम बाजार के परिणामों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
  - AI-संवर्द्धित परिदृश्य में सफल होने के लिए शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण होगा, ताकि श्रमिकों को आवश्यक योग्यताओं से लैस किया जा सके।

## दृष्टिकोण और भावी संभावनाएं

- निकट भविष्य की वैश्विक संवृद्धि प्रवृत्ति स्तर से कुछ कम रहने की संभावना है। सेवा क्षेत्रक वैश्विक विस्तार को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें भारत में उल्लेखनीय लोचशीलता देखने को मिली है।
- वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति संबंधी दबाव कम हो रहे हैं। हालांकि, मध्य-पूर्व में तनाव और वर्तमान रूस यूक्रेन संघर्ष जैसे संभावित भू-राजनीतिक व्यवधानों के कारण समकालिक मूल्य दबावों का जोखिम बना हुआ है।
- केंद्रीय बैंकों ने अधिक उदार मौद्रिक नीतियों को अपनाया है।
  - हालांकि, विकास की अनिवार्यताओं और अवस्फीति की गति के आधार पर दरों में कटौती की गति क्षेत्रों में भिन्न होती है, जिससे आर्थिक सुधार में संभावित अंतर पैदा होता है।
- उच्च सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और बेहतर होती व्यावसायिक उम्मीदों से समर्थित निवेश गतिविधि में तेजी आने की संभावना है।
- हालिया दिनों में वैश्विक ऊर्जा और वस्तुओं की कीमतों में कमी आई है। इससे कोर मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान आसान हो गया है।
  - हालांकि, व्यापक वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण जोखिम बने हुए हैं।
- घरेलू अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत बने हुए हैं, जिसमें मजबूत बाह्य खाता, संतुलित राजकोषीय समेकन और स्थिर निजी उपभोग शामिल हैं। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि वित्त वर्ष 2026 में संवृद्धि दर 6.3 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत के बीच रहेगी।

## बजट में क्या कहा गया है?

- प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए 2025 में राज्यों का इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स लॉन्च किया जाएगा।
- मेक इन इंडिया: LED/LCD TV के लिए ओपन सेल, वस्त्र उद्योग के लिए करघे, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों की लिथियम-आयन बैटरी हेतु पूंजीगत वस्तुओं को छूट।
- व्यापार सुविधा: अंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा तय की गई है। स्वीकृति के बाद भौतिक तथ्यों की स्वैच्छिक घोषणा तथा ब्याज सहित लेकिन बिना जुर्माने के शुल्क भुगतान का नया प्रावधान किया गया है।
- अंतिम उपयोग के लिए विस्तारित समय: छह महीने से एक वर्ष तक का विस्तारित समय दिया गया है। इससे लागत और आपूर्ति की अनिश्चितता को देखते हुए परिचालन लचीलापन मिलेगा।

## शब्दावली

| शब्द/ पद                       | अर्थ                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सकल मूल्य वर्धन (GVA)          | आउटपुट (मूल मूल्यों पर) से मध्यवर्ती उपभोग (क्रेता मूल्यों पर) घटाकर GVA प्राप्त किया जाता है।                                                                              |
| प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)   | FDI से तात्पर्य किसी अन्य देश के निवेशक, कंपनी या सरकार द्वारा किसी विदेशी कंपनी या परियोजना में ली गई स्वामित्व हिस्सेदारी से है।                                          |
| निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE)   | PFCE को निवासी परिवारों और परिवारों की सेवा करने वाली गैर-लाभकारी संस्थाओं (NPISH) द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम उपभोग पर किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। |
| सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) | GFCF भवन, मशीनरी और उपकरण जैसी अचल संपत्तियों में नए निवेश का मूल्य है।                                                                                                     |
| श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)     | श्रम बल सहभागिता दर (LFPR) कुल श्रम बल और कुल कार्यशील आयु जनसंख्या के अनुपात को दर्शाती है।                                                                                |
| कामगार जनसंख्या अनुपात (WPR)   | WPR को कुल आबादी में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।                                                                                        |



## अपने सीखने के कौशल का परीक्षण कीजिए

### MCQs

1. भारत के आर्थिक प्रदर्शन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की वास्तविक GDP संवृद्धि 6.4% अनुमानित है।
  - स्थिर मूल्यों पर निजी अंतिम उपभोग व्यय में 7.3% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
  - औद्योगिक क्षेत्रक की वृद्धि दर निर्माण गतिविधियों, बिजली, गैस और जल आपूर्ति से प्रेरित होती है।
- उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीनों
- इनमें से कोई भी नहीं

2. भारत के रोजगार रुझान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 2023-24 में भारत की बेरोजगारी दर में कमी आई है।
  - वित्त वर्ष 2024 में निवल EPFO सदस्यता में वृद्धि के साथ भारत के औपचारिक क्षेत्रक का विस्तार हुआ है।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1, न ही 2

3. वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- भू-राजनीतिक आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक 2023 की तुलना में 2024 में बढ़ गया।
  - विश्व व्यापार अनिश्चितता सूचकांक 2023 की तुलना में 2024 में कम हो गया।
  - 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.3% बढ़ी, जो IMF के 3.2% के अनुमान से अधिक है।
  - मध्य पूर्व में तनाव के कारण स्वेज नहर मार्ग से व्यापार बाधित हो गया है।
- उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- केवल तीन
- सभी चारों

4. विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक में भारत के आर्थिक प्रदर्शन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- भारत विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) में सबसे तेज वृद्धि दर्ज कर रहा है।
- सेवा क्षेत्रक की वृद्धि दर 7.2% रहने की उम्मीद है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1, न ही 2

5. भारत में पूंजीगत व्यय (CAPEX) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

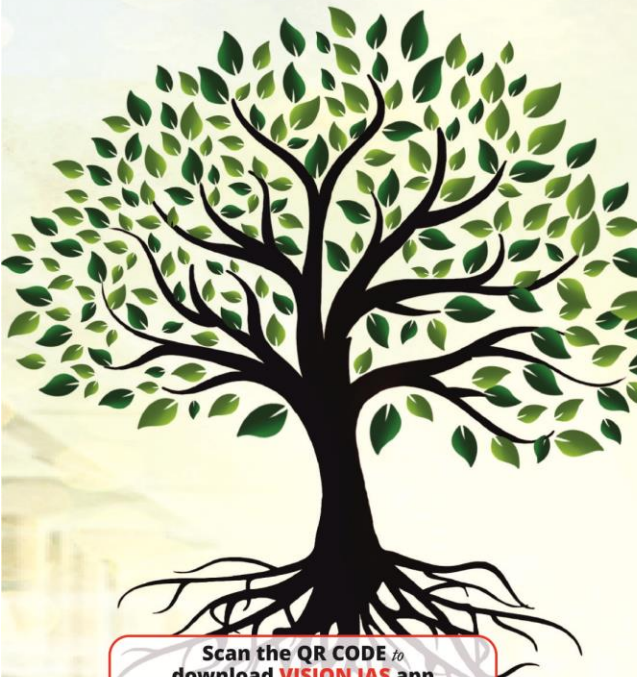
- वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2024 तक पूंजीगत व्यय (CAPEX) में लगातार सुधार हुआ है।
- आम चुनावों के बाद, जुलाई-नवंबर 2024 के दौरान पूंजीगत व्यय में साल-दर-साल (YOY) 8.2% की वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1, न ही 2

मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न

- हालिया वर्षों में केंद्र सरकार का राजकोषीय अनुशासन किस तरह विकसित हुआ है? पूंजीगत व्यय और समग्र आर्थिक स्थिरता पर इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए। (150 शब्द)
- भारत के बाह्य क्षेत्रक की स्थिरता सुनिश्चित करने में सेवाओं में व्यापार और धन विप्रेषण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये कारक चालू खाता घाटे के प्रबंधन में किस प्रकार योगदान करते हैं? (250 शब्द)



# फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2026

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसेट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसेट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

Scan the QR CODE to download VISION IAS app



**DELHI: 25 फरवरी, 8 AM | 25 मार्च, 2 PM** **JAIPUR: 10 अप्रैल**

**JODHPUR: 17 मार्च** **प्रवेश प्रारम्भ** **BHOPAL | LUCKNOW**

## अध्याय 2: मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्रक का विकास: अन्योन्याश्रित संबंध (Monetary and financial sector developments: The cart and the horse)

### परिचय

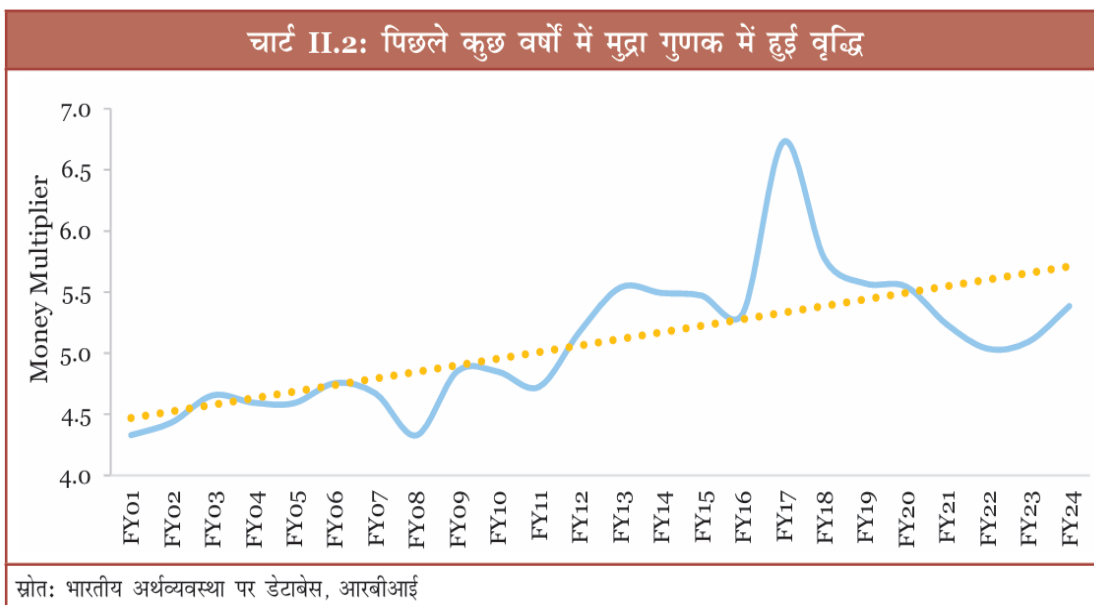
- वित्तीय संस्थाएं आर्थिक गतिविधियों के लिए बचत, निवेश और ऋण की सुविधा प्रदान करके देश की आर्थिक संवृद्धि की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- प्रचलित मौद्रिक नीतियां वित्तीय मध्यस्थता और आर्थिक विकास के बीच परस्पर क्रिया को प्रभावित करती हैं।

### अध्याय का प्रीकैप

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>बैंकिंग क्षेत्रक का प्रदर्शन</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs)<sup>2</sup> की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPAs) अनुपात में गिरावट आई है।</li> <li>CRAR<sup>3</sup> अपेक्षित मानदंडों से काफी अधिक है।</li> <li>बैंक ऋण में रुझान</li> </ul> | <b>इन्सॉल्वेंसी कानून की सार्थकता</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड (IBS), 2016</li> <li>IBC फ्रेमवर्क समय के साथ निरंतर बेहतर रूप से विकसित होता जा रहा है।</li> <li>MSMEs के लिए प्री-पैक व्यवस्था।</li> </ul> |
| <b>बीमा क्षेत्रक</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>कुल बीमा प्रीमियम में वृद्धि हुई।</li> <li>जीवन बीमा पैठ में मामूली गिरावट आई।</li> <li>देश में बीमा घनत्व में मामूली वृद्धि देखी गई।</li> </ul>                                                                                | <b>भारत के वित्तीय क्षेत्रक से संबंधित जोखिम</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ऋण उपलब्ध कराने में बैंकों का पारंपरिक प्रभुत्व घटने लगा है।</li> <li>विभिन्न प्रकार के वित्तीय नवाचार।</li> <li>वित्तीयकरण (Financialization)।</li> </ul>         |

### मौद्रिक विकास

- मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य: आर्थिक संवृद्धि के लक्ष्य को बरकरार रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, क्योंकि संधारणीय विकास के लिए स्थिर मूल्य आवश्यक हैं।
- इस स्थिरता को प्राप्त करने के लिए RBI विभिन्न नीतिगत साधनों का उपयोग करता है, जैसे- ब्याज दरों में बदलाव, खुले बाजार के परिचालन (OMO)<sup>4</sup> का संचालन, नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) में बदलाव करना, आदि।



<sup>2</sup> Scheduled Commercial Banks

<sup>3</sup> Capital to Risk Asset Ratio

<sup>4</sup> Open Market Operations

- RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अक्टूबर 2024 की अपनी बैठक में नीतिगत रुख को 'विड्रॉअल ऑफ एकोमोडेशन' से बदलकर 'न्यूट्रल' करने का निर्णय लिया।
- दिसंबर 2024 में, MPC ने CRR को 4.5% से घटाकर निवल मांग का 4% करने की घोषणा की। इस निर्णय से बैंकिंग प्रणाली में लगभग 1.16 लाख करोड़ रुपये की तरलता आने की उम्मीद है।
- किसी देश का मुद्रा गुणक (मनी मल्टीप्लायर: MM) निम्नलिखित दो मुख्य कारकों से प्रभावित होता है:
  - व्यक्तियों (और व्यवसायों) के पास मौजूद नकदी की मात्रा से, और
  - बैंकों द्वारा रखी गयी आरक्षित निधियों की मात्रा से।
    - जब लोग अपने पास अधिक नकदी रखते हैं, तो बैंकिंग प्रणाली धन का सृजन नहीं कर पाती है, जिसके परिणामस्वरूप गुणक प्रभाव कम हो जाता है।
  - बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंक (जैसे- RBI) के पास रखे गए आरक्षित धन को भी एक प्रकार की "लीकेज" माना जाता है, जिससे मनी मल्टीप्लायर और भी कम हो जाता है।
    - भारत में, बैंकों को अपनी जमा राशि का एक हिस्सा CRR (नकद आरक्षित अनुपात) के रूप में RBI के पास रखना पड़ता है।

## वित्तीय मध्यस्थता (Financial Intermediation)

- मौद्रिक नीति समिति (MPC)<sup>5</sup> द्वारा निर्धारित नीतिगत दरें वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से वास्तविक अर्थव्यवस्था तक पहुंचती हैं, क्योंकि ये मध्यस्थ अपनी ऋण और जमा दरों को उसी अनुसार समायोजित करते हैं। इनमें बैंक, पूंजी बाजार, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड और अन्य वित्तीय संस्थान शामिल होते हैं।
- CRR और SLR संबंधी अनिवार्यताएं वित्तीय मध्यस्थों की ऋण देने की क्षमता को प्रभावित करती हैं।

**"You are as strong as your Foundation"**

# FOUNDATION COURSE

## GENERAL STUDIES

### PRELIMS CUM MAINS

## 2026, 2027 & 2028



Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains Exam

- Includes Pre Foundation Classes
- Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims & Essay
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2026, 2027 & 2028

**Live - online / Offline Classes**

Scan the QR CODE to download **VISION IAS** app





**DELHI: 4 MAR, 2 PM | 11 MAR, 5 PM | 13 MAR, 11 AM | 18 MAR, 8 AM**

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): **25 MAR, 8 AM**

**हिन्दी माध्यम DELHI: 25 फरवरी, 8 AM | 25 मार्च, 2 PM**

**AHMEDABAD: 4 JAN | BENGALURU: 30 MAR | BHOPAL: 25 FEB | CHANDIGARH: 18 JUN**

**HYDERABAD: 3 MAR | JAIPUR: 5 APR | JODHPUR: 17 MAR | LUCKNOW: 9 APR | PUNE: 4 MAR**

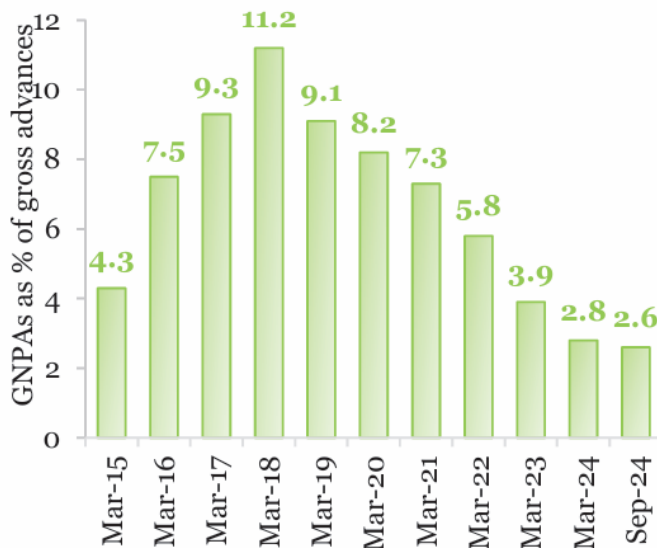
<sup>5</sup> Monetary Policy Committee

## बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन और ऋण उपलब्धता

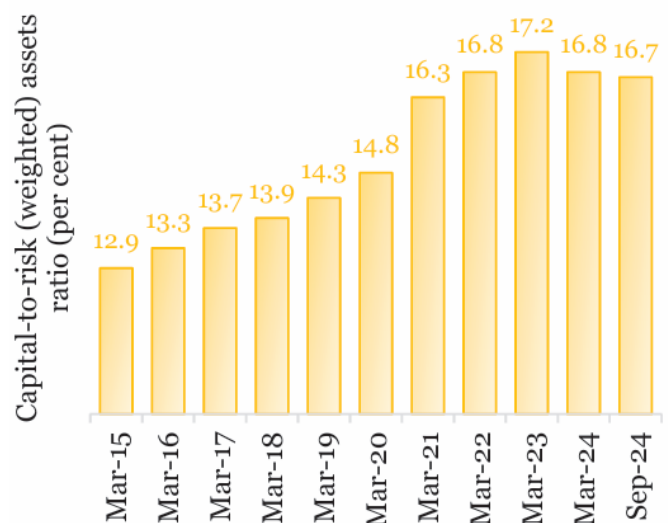
### बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) अनुपात वित्त वर्ष 2018 के अपने अधिकतम स्तर से लगातार घट रहा है और सितंबर 2024 के अंत में 12 साल के निचले स्तर 2.6% पर आ गया है।
- पुनर्गठित मानक अग्रिम (RSA)<sup>6</sup> अनुपात SCBs के लिए मार्च 2022 में 1.8% से घटकर सितंबर 2024 के अंत में 0.7% हो गया है। RSA अनुपात कुल सकल ऋण और अग्रिमों में RSA का हिस्सा होता है।
- सितंबर 2024 के अंत में, SCBs का CRAR 16.7% था। साथ ही, सभी बैंकों ने 8% की कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET-1) अनिवार्यता को पूरा किया है।

चार्ट II.3क: एससीबी के जीएनपीए में गिरावट



चार्ट II.3ख: सीआरएआर अपेक्षित मानदंडों से काफी अधिक है



स्रोत: आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, विभिन्न मुद्दे

## मासिक समसामयिकी रिवीजन कक्षाएं 2025

GS प्रीलिम्स और मेन्स

हिन्दी माध्यम

English Medium

31 JAN | 5 PM

25 JAN | 5 PM

**VISIONIAS**  
INSPIRING INNOVATION



► Live/Online Classes are available

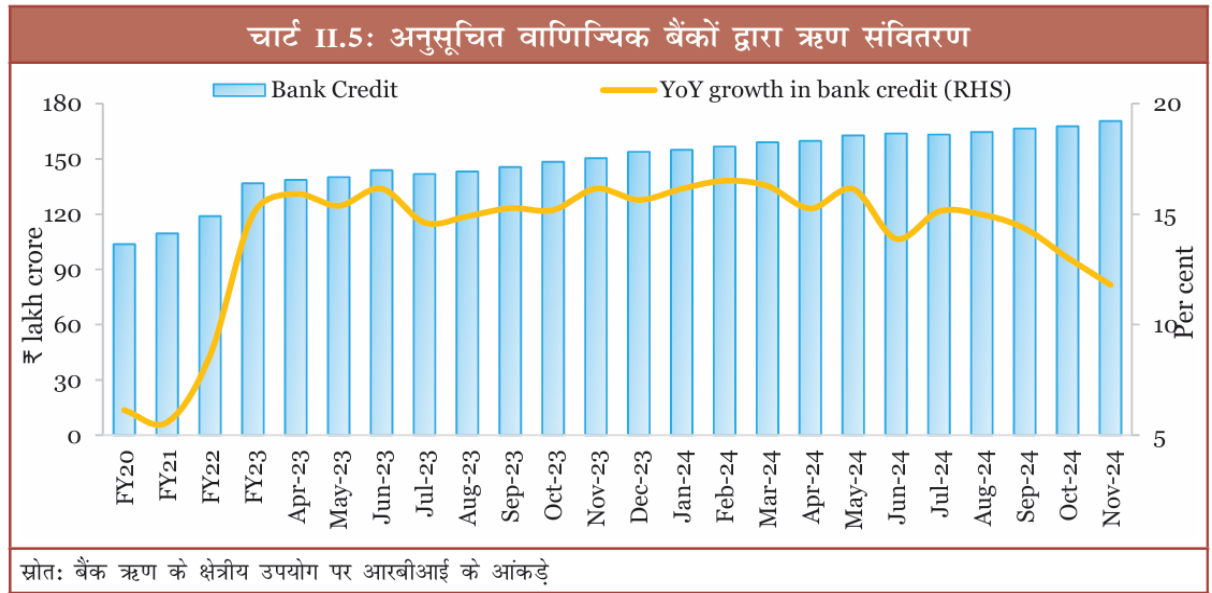
<sup>6</sup> Restructured Standard Advances

## बैंक ऋण में रुझान

- नवंबर 2024 के अंत तक, **SCBs** की कुल जमाराशियों में वर्ष-दर-वर्ष **11.1%** की वृद्धि हुई है। बैंक ऋण में वृद्धि, जमाराशियों में वृद्धि के करीब पहुंचने लगी है।

- नवंबर 2024 के अंत में, समग्र बैंक ऋण में वृद्धि एक वर्ष पहले इसी अवधि के 15.2% से घटकर **11.8%** (वर्ष-दर-वर्ष) हो गयी है।

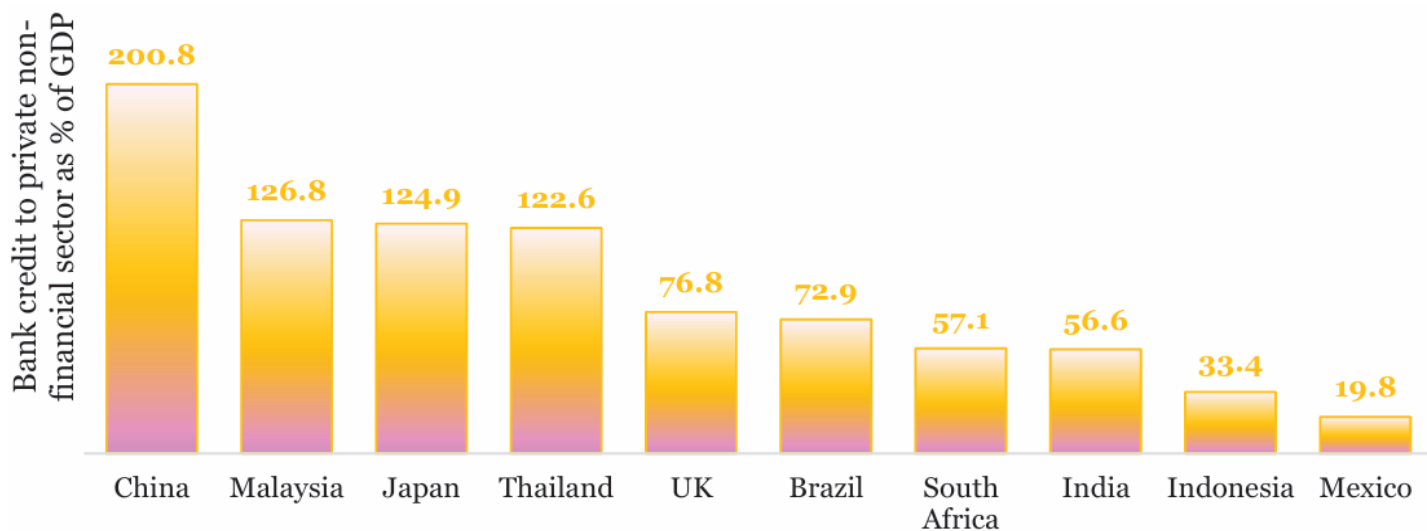
- दिसंबर 2024 में, **MPC** ने 1 से 3 वर्ष और 3 से 5 वर्ष की परिपक्वता वाली विदेशी



मुद्रा अनिवासी [FCNR(B)] जमा पर ब्याज दर की सीमा में वृद्धि की घोषणा की है।

- 2006 और 2012 के बीच ऋण/ GDP अंतर** (अर्थात् ऋण-GDP अनुपात और इसकी दीर्घकालिक प्रवृत्ति के बीच का अंतर) सकारात्मक था, जो अत्यधिक ऋण वृद्धि को दर्शाता है।
- विभिन्न देशों के बीच तुलना** से पता चलता है कि भारत में निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र का बैंक ऋण-GDP का अनुपात वस्तुतः अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है।

## चार्ट II.7: जीडीपी<sup>11</sup> के प्रतिशत के रूप में निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र के लिए बैंक ऋण की क्रॉस-कट्री तुलना



स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक

## ग्रामीण वित्तीय संस्थाएं (Rural Financial Institutions: RFIs)

- इस बहु-एजेंसी प्रणाली में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs)<sup>7</sup>, ग्रामीण सहकारी बैंक (RCBs)<sup>8</sup>, SCBs, लघु वित्त बैंक, NBFCs, सूक्ष्म वित्त संस्थान और स्थानीय क्षेत्र के बैंक शामिल हैं।
- वर्ष 2006 में 133 RRBs थे। इनके प्रदर्शन में सुधार के लिए कुछ विलय, परिसमापन और सम्मेलन के बाद 2023 में इनकी संख्या घटकर 43 हो गई।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की परिसंपत्ति गुणवत्ता, सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (GNPA) द्वारा मापी जाती है। यह वित्त वर्ष 2023 में 7.3% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 6.1% हो गई।

## बैंकों द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग

- भारत में बैंकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) एप्लीकेशन उपयोग किए जा रहे हैं, जैसे कि क्रेडिट अंडरराइटिंग, नियामक पूंजी योजना, तरलता प्रबंधन, धोखाधड़ी का पता लगाना और रोकथाम, जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन।
- AI और लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM)<sup>9</sup> ने इंटरैक्टिव चैटबॉट और व्यक्तिगत सहायता के माध्यम से ग्राहक सेवा को बेहतर बनाया है।
- ब्लॉकचेन सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल लेनदेन सुनिश्चित करता है।
- चुनौती: AI प्रणालियों की ब्लैक-बॉक्स प्रकृति, इस बात को मुश्किल बना सकती है कि हम प्रणाली की विश्वसनीयता का आकलन कैसे करें या इसके निर्णयों को चुनौती कैसे दें।
- RBI ने वित्तीय क्षेत्रक में फ्रेमवर्क फॉर रिस्पांसिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (FREE-AI) तैयार करने के लिए एक समिति की स्थापना की घोषणा की है।

## इन्सॉल्वेंसी कानून की प्रभावकारिता

- सितंबर 2024 तक, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकप्टसी कोड (IBS), 2016 के तहत अनुमोदित 1,068 समाधान योजनाओं के परिणामस्वरूप लेनदारों को 3.6 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। यह परिसमापन मूल्य का 161% और उचित मूल्य का 86.1% है।
- अगले दशक में 7-8% की वृद्धि हासिल करने के लिए निरंतर विकसित और बेहतर होता IBC फ्रेमवर्क जरूरी होगा।
- आगे की राह: प्रणाली में समय संबंधी दक्षता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित नवाचारों का उपयोग करना होगा:
  - MSMEs के लिए प्री-पैक व्यवस्थाएं।
  - क्षमता निर्माण के तहत इन्सॉल्वेंसी से संबंधित पेशेवरों को कानूनी, वित्तीय और उद्योग से जुड़ी बुनियादी समझ प्रदान करना।
  - न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी को कम करना।

## पूंजी बाजार का विकास

- पूंजी बाजार भारत की आर्थिक संवृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी निर्माण, घरेलू बचत का वित्तीयकरण और संपत्ति सृजन को बढ़ावा देता है।
- निवेशकों की भागीदारी इसमें महत्वपूर्ण योगदानकर्ता रही है। निवेशकों की संख्या वित्त वर्ष 2020 के 4.9 करोड़ से बढ़कर 31 दिसंबर, 2024 तक 13.2 करोड़ हो गई है।

<sup>7</sup> Regional Rural Banks

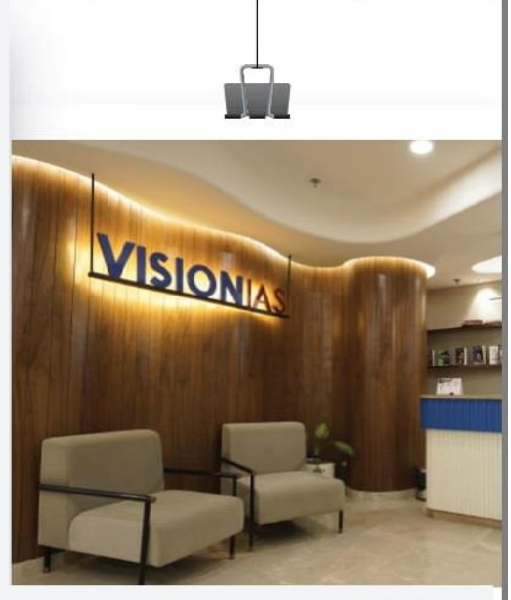
<sup>8</sup> Rural Cooperative Banks

<sup>9</sup> Rural Cooperative Banks

- प्राथमिक बाजार: अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच प्राथमिक बाजार (इक्विटी और ऋण) से कुल 11.1 लाख करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई गई। यह पूरे वित्त वर्ष 24 के दौरान जुटाई गई राशि से 5% अधिक है।
- कॉर्पोरेट ऋण बाजार: अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच जारी किए गए कॉर्पोरेट बॉण्ड का मूल्य 7.3 लाख करोड़ रुपये रहा। अतः इसका औसत मासिक मूल्य लगभग 0.8 लाख करोड़ रुपये रहा।
- इक्विटी बाजार के विपरीत, भारत में ऋण बाजार अभी भी अल्प-पूंजीकृत है।
  - सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, भारत में कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार केवल 18% है, जबकि कोरिया में यह 80% और चीन में 36% है।

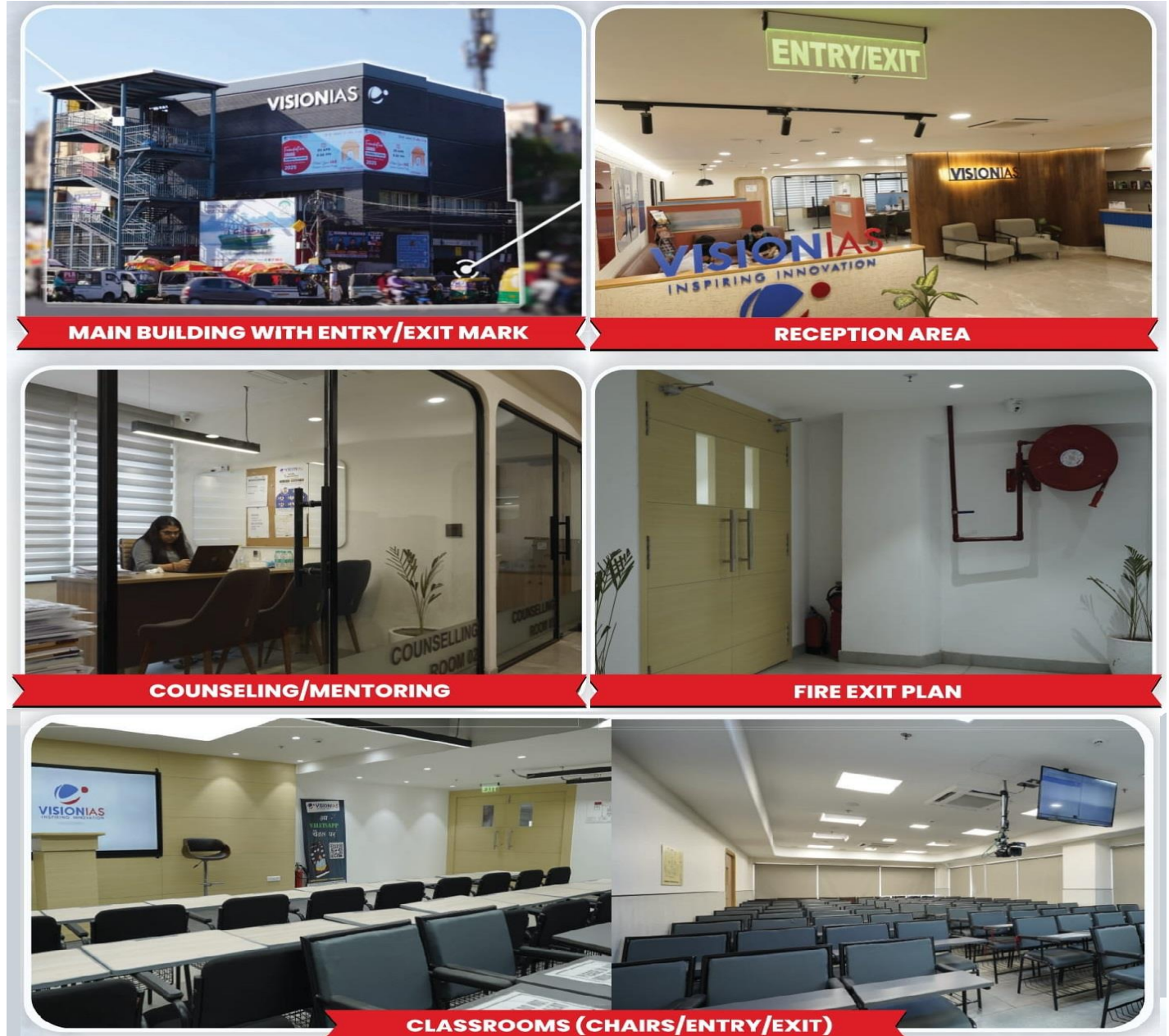
# ऑफलाइन क्लासरूम, मेंटरिंग SUPPORT SYSTEM & FACILITIES

VISIONIAS MUKHERJEE NAGAR (GTB NAGAR CENTRE)



## द्वितीयक बाजार: अस्थिरता के बीच सकारात्मक प्रदर्शन

- दीर्घकालिक आधार पर, भारतीय बाजार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से रहे हैं।
- पिछले दस वर्षों (मार्च 2014 से) में निफ्टी 50 का चक्रवृद्धि वार्षिक रिटर्न 8.8% (USD के अनुसार समायोजित) रहा है।
- यह सकारात्मक प्रदर्शन मजबूत लाभप्रदता में वृद्धि, डिजिटल वित्तीय अवसंरचना में तीव्र विस्तार, निवेशकों के बढ़ते आधार और उत्पादों और प्रक्रियाओं में बड़े सुधारों से प्रेरित था।



क्लासरूम प्रोग्राम : **Vision IAS** तैयारी के विभिन्न चरणों में सहायता और मार्गदर्शन के लिए अभ्यर्थियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है :

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा): लगभग 12-14 महीने में सम्पूर्ण सिलेबस कवरेज
- CSAT क्लासेज
- करेंट अफेयर्स क्लासेज- मासिक करेंट अफेयर्स रिवीजन, PT365, Mains365
- निबंध लेखन
- एथिक्स (Ethics)- एथिक्स क्रेश कोर्स, एथिक्स केस स्टडीज
- GS मेंस एडवांस कोर्स

## गिफ्ट सिटी (GIFT city)

- एक एकीकृत विनियामक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA)<sup>10</sup> भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) के भीतर वित्तीय संस्थानों, सेवाओं और उत्पादों के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार है।
- GIFT-IFSC एक प्रमुख IFSC के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है। साथ ही, यह "ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 36 (GFCI 36)" में अपनी रैंकिंग में पांच स्थानों का सुधार करते हुए 52वें स्थान पर पहुंच गया है।
- यह फिनटेक रैंकिंग में भी चार स्थान की छलांग लगाकर 45वें स्थान पर आ गया है।

**ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज (All India Test Series) :** इस परीक्षा में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु हर तीन में से दो चयनित अभ्यर्थियों द्वारा इसे चुना जाता रहा है। VisionIAS पोस्ट टेस्ट एनालिसिस ठोस सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराता है एवं प्रदर्शन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है। उत्तर लेखन में सुधार एवं मार्गदर्शन के लिए Vision IAS के Innovative Assessment System™ द्वारा अभ्यर्थी को फीडबैक दिया जाता है।

- ऑल इंडिया सामान्य अध्ययन (GS Mains) टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- CSAT टेस्ट सीरीज
- वैकल्पिक विषय टेस्ट सीरीज— दर्शनशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समाजशास्त्र
- संधान टेस्ट सीरीज
- ओपन टेस्ट (Open Test)
- Abhyaas— Abhyaas Prelims & Mains

**मेंटरिंग कार्यक्रम — UPSC** सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार की एकेडेमिक या गैर-एकेडेमिक समस्या के समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए मेंटर की भूमिका बढ़ गई है। इसलिए Vision IAS प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम लेकर आया है।

- दक्ष (Daksha): आगामी वर्षों में मुख्य परीक्षा देने वाले
- लक्ष्य (Lakshya): मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए।
- लक्ष्य प्रीलिम्स एवं मंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम।

**करेंट अफेयर्स (Current Affairs)—** सिविल सेवा परीक्षा में प्रायः प्रश्नों को करेंट अफेयर्स से जोड़कर पूछा जाता है। इसलिए Vision IAS द्वारा प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक आधार पर करेंट अफेयर्स के अलग-अलग स्रोत अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिनमें टॉपिक के स्टैटिक के साथ करेंट अफेयर्स के टॉपिक में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों, सरकारी प्रकाशनों एवं वेब साइट का विश्लेषण सम्मिलित होता है।

- मासिक मैगजीन
- वीकली फोकस
- न्यूज टुडे
- PT 365
- Mains 365

**स्टडी मैटेरियल—** सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए Vision IAS द्वारा विभिन्न मैटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं।

- क्लासरूम स्टडी मैटेरियल
- वेल्यू एडेड मैटेरियल
- मासिक मैगजीन, वीकली फोकस, न्यूज टुडे
- PT 365 एवं Mains 365
- केन्द्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण सारांश
- विगत वर्षों के प्रश्नों (PYQs) का विस्तृत विश्लेषण
- टॉपर्स कॉपी

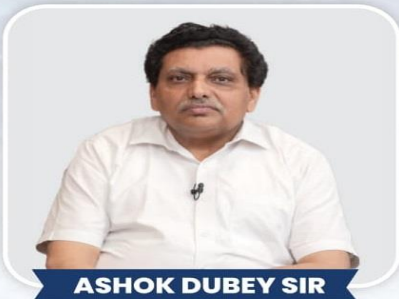
**Student Wellness Cell —** देश की प्रतिष्ठित सेवा एवं उसकी भर्ती प्रक्रिया कई बार बोझिल हो जाती है, जिससे अभ्यर्थी चिंता, तनाव, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। जिसे ध्यान में रखकर Vision IAS द्वारा स्टूडेंट वेलनेस सेल की स्थापना की गई है। इसमें अभ्यर्थी प्रशिक्षित काउंसलर और प्रोफेशनल मनोविशेषज्ञ से मिलकर अपनी समस्या साझा करते हुए समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

<sup>10</sup> International Financial Services Centres Authority

## बीमा क्षेत्रक में विकास

- भारत का बीमा बाजार लगातार वृद्धि कर रहा है।
- वित्त वर्ष 2024 में कुल बीमा प्रीमियम 7.7% बढ़कर 11.2 लाख करोड़ रुपये हो गया है। हालांकि, बीमा पैठ 4% (FY23) से घटकर 3.7% (FY24) पर आ गया है।
- जीवन बीमा पैठ वित्त वर्ष 23 के 3% से मामूली रूप से घटकर वित्त वर्ष 24 में 2.8% हो गया है, जबकि गैर-जीवन बीमा पैठ 1% पर स्थिर रहा है।
- देश में बीमा घनत्व वित्त वर्ष 23 के 92 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 95 अमेरिकी डॉलर हो गया।
- समग्र बीमा पैठ दर 3.7% है, जो वैश्विक औसत 7% से कम है। अतः बीमा कवरेज काफी कम है, जो बीमा कंपनियों के लिए अपनी पहुंच का विस्तार करने के अवसर प्रस्तुत करता है।
- आगे की राह: बीमा संबंधी सीमित जागरूकता और पहुंच वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों को टारगेट करके बीमा कंपनियां अपना ग्राहक आधार बढ़ा सकती हैं और विकास को बढ़ावा दे सकती हैं।

## अनुभवी फैकल्टी का मार्गदर्शन

**ASHOK DUBEY SIR****MRITYUNJAY SIR****RAJEEV RANJAN SIR****SUNIL KUMAR SINGH SIR****1  
AIR****Aditya Srivastava****= हिंदी माध्यम टॉपर =****53  
AIR****मोहन लाल****136  
AIR****अर्पित कुमार****1  
AIR****Shubham Kumar**  
UPSC CSE 2020**454  
AIR****Bajarang Prasad**  
UPSC CSE 2022**468  
AIR****Vikas Gupta**  
UPSC CSE 2022**605  
AIR****Jatin Parashar**  
UPSC CSE 2022

## पेंशन क्षेत्रक में विकास

- विश्व आर्थिक मंच (WEF) के अनुसार, इतिहास में पहली बार, वैश्विक स्तर पर 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या 5 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों की संख्या से अधिक हो गई है।
- मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, 2024 के अनुसार भारत का समग्र सूचकांक मूल्य 2023 के 45.9 से थोड़ा घटकर 2024 में 44 हो गया है।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) की शुरुआत के बाद से भारत के पेंशन क्षेत्रक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- सितंबर 2024 तक, ग्राहकों की कुल संख्या 783.4 लाख तक पहुंच गई है, जो सितंबर 2023 के 675.2 लाख से 16% की वर्ष-दर-वर्ष (YoY) वृद्धि को दर्शाती है।

## भारत के वित्तीय क्षेत्रक के साइबर सुरक्षा संबंधी पहलू

- तकनीकी प्रगति के साथ भारत का वित्तीय क्षेत्रक डिजिटल परिवर्तन से गुजर रहा है। इससे कार्यकुशलता और पहुंच बढ़ी है, लेकिन साथ ही साइबर खतरों का जोखिम भी बढ़ गया है।
- साइबर खतरों में फ़िशिंग और रैनसमवेयर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ़ सर्विस (DDoS) हमले, SMS और नकली/दुर्भावनापूर्ण मोबाइल एप्लीकेशन शामिल हैं।
- भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) के अनुसार, साइबर सुरक्षा घटनाओं की संख्या 2020, 2021 और 2022 के दौरान क्रमशः 11.6 लाख, 14 लाख और 13.9 लाख रही।
- रिपोर्ट से पता चलता है कि रिपोर्ट की गई सभी साइबर घटनाओं में से लगभग 20% साइबर हमले वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाते हैं। इनसे बैंक सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।
- IMF की वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, साइबर हमलों के परिणामस्वरूप अत्यधिक वित्तीय नुकसान हुआ है, जो 2017 के बाद से चार गुना बढ़कर 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
- भारत की स्थिति: वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (GCI)<sup>11</sup> 2024 में भारत की टियर 1 रैंकिंग, 100 में से 98.49 के सराहनीय स्कोर के साथ, इसकी साइबर सुरक्षा क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाती है।

## भारत के वित्तीय क्षेत्रक से संबंधित जोखिम

- ऋण देने में बैंकों का पारंपरिक दबदबा घट रहा है और वित्तीय क्षेत्रक के अन्य प्रतिभागी एवं उत्पाद इस भूमिका को तेजी से निभा रहे हैं।
- वित्तीय नवाचारों जैसे कि UPI, ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (OCEN) और T+1 सेटलमेंट ने भारत में ऋण तक पहुंच को काफी आसान बना दिया है।
- अत्यधिक वित्तीयकरण से अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। भारत जैसे निम्न-मध्यम आय वाले देश के लिए इसकी लागत विशेष रूप से अधिक हो सकती है।
- आगे की राह:
  - वित्तीय बाजारों को अर्थव्यवस्था की पूंजी आवश्यकताओं और समग्र आर्थिक वृद्धि के अनुरूप ही बढ़ना चाहिए, न कि इससे तेज।
  - बैंकों को अपने प्राथमिक ऋण सृजन कार्य को जारी रखते हुए, नए युग की घरेलू और डिजिटल अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है।

<sup>11</sup> Global Cybersecurity Index

## आगे की राह और दृष्टिकोण

- नीति और समष्टि आर्थिक परिणामों को आकार देने में वित्तीय बाजारों का प्रभुत्व एक महत्वपूर्ण जोखिम है, जिससे सावधान रहने की आवश्यकता है। नीति और समष्टि आर्थिक परिणामों को आकार देने की प्रक्रिया 'वित्तीयकरण (Financialisation)' के रूप में जानी जाती है।
- वित्तीयकरण के परिणाम उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, जहाँ इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के ऋण में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इनमें से कुछ विनियामकों की निगरानी के तहत आते हैं और कुछ नहीं।
- भारत अपनी वित्तीय प्रणाली को 2047 के लिए अपनी आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए भारत को वित्तीय क्षेत्र के विकास और संवृद्धि के साथ-साथ वित्तीयकरण के बीच बेहतर संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।
- इसका अर्थ यह है कि भारत को अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपना मार्ग निर्धारित करना होगा, जिसमें घरेलू वित्तीय बचत के स्तर, निवेश आवश्यकताओं और वित्तीय साक्षरता के स्तर जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस क्षेत्र में प्रोत्साहन राष्ट्रीय संवृद्धि से जुड़ी आकांक्षाओं के साथ एक प्रमुख नीति प्राथमिकता के रूप में संरेखित हों।

## बजट में क्या कहा गया है?

### वित्तीय क्षेत्र में सुधार और विकास

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'ग्रामीण क्रेडिट स्कोर' फ्रेमवर्क।
- NaBFID अवसंरचना विकास के लिए कॉर्पोरेट बॉण्ड हेतु 'आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा (Partial Credit Enhancement Facility)' स्थापित करेगा।
- संशोधित केंद्रीय KYC रजिस्ट्री 2025 में शुरू की जाएगी।
- बीमा क्षेत्र के लिए FDI की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी।

## शब्दावली

| शब्द/ पद                                                | अर्थ                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मनी मल्टीप्लायर (MM)                                    | मुद्रा गुणक यह बताता है कि बैंकों द्वारा रखी गई आरक्षित निधियों की मात्रा को देखते हुए मुद्रा आपूर्ति में कितनी वृद्धि हो सकती है।                    |
| गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA)                          | भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, भारत में कोई भी ऋण या अग्रिम जो 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है, उसे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) माना जाता है। |
| जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR) | CRAR किसी बैंक की कुल पूंजी का उसकी जोखिम-भारित परिसंपत्ति और वर्तमान देनदारियों का अनुपात है।                                                        |
| बीमा घनत्व (Insurance Density)                          | यह किसी देश में एकत्रित बीमा प्रीमियम और उसकी जनसंख्या का अनुपात है।                                                                                  |
| बीमा पैठ (Insurance Penetration)                        | यह किसी देश में GDP के सापेक्ष भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम का प्रतिशत है।                                                                             |
| T+1 निपटान                                              | भारत में T+1 निपटान ट्रेडिंग डे एक (T+1) पर व्यापारों के निपटान की प्रक्रिया है। यानी, शेयर बाजार में सौदा होने के एक दिन बाद उसका निपटान होना।       |



## अपने सीखने के कौशल का परीक्षण कीजिए

### MCQs

1. भारत के बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. बैंक ऋण स्थिर दर से बढ़ रहा है तथा चालू वित्त वर्ष में बैंक ऋण में वृद्धि, बैंक जमा-राशि में वृद्धि के अनुरूप हो रही है।
  2. वित्त वर्ष 2018 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (GNPAs) का अनुपात लगातार बढ़ रहा है।उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
  - (a) केवल 1
  - (b) केवल 2
  - (c) 1 और 2 दोनों
  - (d) न तो 1, न ही 2
2. अन्य देशों की तुलना में भारत के बैंकिंग ऋण के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
  - (a) भारत में निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र को बैंक ऋण अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक है।
  - (b) भारत में निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र को बैंक ऋण इंडोनेशिया और मैक्सिको जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (EMEs) की तुलना में अधिक है।
  - (c) भारत में निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र को बैंक ऋण तथा सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है, लेकिन इंडोनेशिया और मैक्सिको की तुलना में अधिक है।
  - (d) भारत में निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र को बैंक ऋण तथा सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात इंडोनेशिया और मैक्सिको सहित उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक है।
3. वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए:
  - (a) यह विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है।
  - (b) यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है।
  - (c) यह एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी की जाती है।
  - (d) यह संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास द्वारा जारी की जाती है।
4. भारत के वित्तीय क्षेत्र में साइबर घटनाओं के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. रिपोर्ट की गई सभी साइबर घटनाओं में से पांचवाँ हिस्सा वित्तीय संस्थानों से संबंधित है, जिसमें बैंक सबसे अधिक प्रभावित हैं।
  2. रिपोर्ट की गई सभी साइबर घटनाओं में से 1% से भी कम वित्तीय संस्थाओं से संबंधित हैं।
  3. वित्तीय संस्थानों में साइबर हमलों में 2017 के बाद से चार गुना कमी आई है।उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
  - (a) केवल 1
  - (b) केवल 2
  - (c) केवल 3
  - (d) कोई नहीं

5. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन 'वित्तीयकरण' की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ रूप से परिभाषित करता है?
- वित्तीयकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें आर्थिक और सामाजिक परिणामों को आकार देने में वित्तीय बाजारों, वित्तीय उद्देश्यों, वित्तीय संस्थानों और वित्तीय अभिकर्ताओं का महत्व बढ़ जाता है।
  - वित्तीयकरण का तात्पर्य वित्तीय बाजारों की भूमिका में कमी तथा नीति एवं समष्टि आर्थिक परिणामों को आकार देने में विनिर्माण उद्योगों के बढ़ते प्रभुत्व से है।
  - वित्तीयकरण का तात्पर्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय बाजारों पर कम निर्भरता के कारण सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के ऋण में कमी से है।
  - वित्तीयकरण का तात्पर्य उस प्रवृत्ति से है, जिसमें वित्तीय बाजार किसी देश के विकास और संवृद्धि के आर्थिक परिणामों को निर्धारित करने में कम भूमिका निभाते हैं।

### मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न

- ऋण में वृद्धि, परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता के संदर्भ में भारत के बैंकिंग क्षेत्र में प्रमुख विकास पर चर्चा कीजिए। ये विकास वित्तीय प्रणाली के समग्र स्वास्थ्य में कैसे योगदान करते हैं? (250 शब्द)
- भारत के बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। सरकार और वित्तीय संस्थान आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने और असमानताओं को कम करने के लिए वित्तीय समावेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं? (150 शब्द)



# पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम

## सिविल सेवा परीक्षा 2024

### प्रवेश प्रारंभ

#### पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की विशेषताएं

**हिंदी और अंग्रेजी माध्यम**

**प्रवेश प्रारंभ**

**प्री-DAF सेशन:** यह DAF में भरे जाने वाले एक-एक पॉइंट की सूक्ष्म समझ और व्यक्तित्व के वांछित गुणों को प्रतिबिंबित करने के लिए सावधानीपूर्वक DAF एंट्री में सहायक है।

**DAF एनालिसिस सेशन:** अपेक्षित प्रश्नों एवं उनके उत्तरों के बारे में सीनियर एक्सपर्ट्स और फैकल्टी मेंबरों के साथ DAF को लेकर गहन विश्लेषण और चर्चा।

**एलोक्यूशन सेशन:** इसमें डिस्कशन और पीयर लर्निंग की सहायता से कम्युनिकेशन स्किल का विकास करने तथा उसे बेहतर बनाने एवं व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास किया जाएगा।

**मॉक इंटरव्यू सेशन:** व्यक्तित्व परीक्षण की तैयारी को और बेहतर बनाने तथा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सीनियर एक्सपर्ट्स और फैकल्टी मेंबरों, भूतपूर्व ब्यूरोक्रेट्स एवं शिक्षाविदों के साथ मॉक इंटरव्यू सेशन।

**व्यक्तिगत मेंटरशिप और मार्गदर्शन:** हमारे डेडिकेटेड सीनियर एक्सपर्ट्स के सहयोग से व्यक्तित्व परीक्षण की समग्र तैयारी व बेहतर प्रबंधन तथा अपने प्रदर्शन को अधिकतम करना।

**करेंट अफेयर्स की कक्षाएं:** करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक व्यापक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए।

**टॉपर्स और कार्यरत ब्यूरोक्रेट्स के साथ इंटरैक्शन:** प्रश्नों के ठोस समाधान, इंटरव्यू लैनिंग एवं टॉपर्स और कार्यरत ब्यूरोक्रेट्स के अनुभव से प्रेरणा लेने के लिए इंटरैक्टिव सेशन।

**प्रदर्शन का मूल्यांकन और फीडबैक:** अपने मजबूत एवं सुधार करने वाले पक्षों की पहचान करने के साथ-साथ उनमें आगे और सुधार करने एवं उन्हें बेहतर बनाने के लिए पॉजिटिव फीडबैक।

**मॉक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग:** स्व-मूल्यांकन के लिए इंटरव्यू सेशन का वीडियो भी दिया जाएगा।



Scan QR CODE to watch How to Prepare for UPSC Personality Test

**DAF एनालिसिस और मॉक इंटरव्यू से संबंधित जानकारी के लिए सम्पर्क करें**

7042413505, 9354559299

interview@visionias.in

अधिक जानकारी और रजिस्टर करने के लिए

QR dksM स्कैन करें



## अध्याय 3: बाह्य क्षेत्रक: FDI को व्यवस्थित रूप देना (External sector: Getting FDI right)

### परिचय

- नवंबर 2024 तक, वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता (GEPU)<sup>12</sup> सूचकांक उच्च स्तर पर बना हुआ था, जो चल रही वैश्विक आर्थिक नीतिगत चिंताओं को दर्शाता है।
- इसी तरह, व्यापार नीति अनिश्चितता (TPU)<sup>13</sup> सूचकांक दिसंबर 2023 से बढ़ा है। ऐसा मुख्यतः प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक तनाव और नीतिगत परिवर्तनों के चलते हुआ है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विभिन्न वैश्विक सूचकांकों का उपयोग करते हुए विशेष रूप से भारत के लिए एक नीति अनिश्चितता सूचकांक विकसित किया है।
  - यह सूचकांक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के कारण उत्पन्न नीतिगत अनिश्चितता का आकलन करने के लिए 'गूगल ट्रेंड्स' से इंटरनेट सर्च डेटा का इस्तेमाल करता है।

### अध्याय का प्रीकैप

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>वैश्विक व्यापार</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>व्यापार मार्ग में व्यवधान</li> <li>वैश्विक व्यापार के विस्तार की उम्मीद है।</li> <li>क्षेत्रीय व्यापार समझौते (RTAs) बढ़े हैं।</li> <li>गैर-प्रशुल्क उपायों (NTMs) का प्रभाव</li> </ul> | <b>भारत के व्यापार प्रदर्शन में रुझान</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>निर्यात की तुलना में कुल आयात में वृद्धि।</li> <li>कपड़ा निर्यात</li> <li>वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है।</li> <li>ईज ऑफ डूइंग बिजनेस</li> </ul> |
| <b>भुगतान संतुलन</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>चालू खाता</li> <li>पूंजी और वित्तीय खाता</li> <li>विदेशी मुद्रा भंडार</li> <li>बाह्य ऋण की स्थिति</li> </ul>                                                                              | <b>FDI प्रवाह का प्रदर्शन</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>सकल FDI प्रवाह में रुझान</li> <li>सेवा क्षेत्रक FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है।</li> <li>चिंताएँ</li> </ul>                                                             |

### वैश्विक व्यापार गतिशीलता

- नवंबर 2023 में लाल सागर में शुरू हुए व्यवधानों ने व्यापार करने वाले मार्गों में बदलाव करने पर मजबूर किया। इससे व्यापार लागत और डिलीवरी समय में बढ़ोतरी हुई।
- होर्मुज जलडमरूमध्य में इसी तरह के संघर्ष ने ऊर्जा व्यापार को बाधित किया है और कीमतों में वृद्धि की है। होर्मुज जलडमरूमध्य से वैश्विक पेट्रोलियम तरल खपत का 21% हिस्सा गुजरता है।
- इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन ने अनिश्चितताओं को बढ़ाया है।
  - उदाहरण के लिए- पनामा नहर में हाल ही में आए सूखे ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को खतरे में डाल दिया। इससे इस नहर से गुजरने वाले वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 5% प्रभावित हुआ।
- वैश्विक व्यापार देशों के आपसी संबंधों में प्रमुख भूमिका निभा रहा है।
  - उदाहरण के लिए- रूस और चीन की यूरोपीय संघ पर तथा अमेरिका की चीन पर व्यापार निर्भरता में गिरावट आई है। इसके विपरीत, रूस और वियतनाम की चीन पर व्यापार निर्भरता में वृद्धि दर्ज की गई है।

<sup>12</sup> Global Economic Policy Uncertainty

<sup>13</sup> Trade Policy Uncertainty

- गैर-प्रशुल्क उपायों (NTMs)<sup>14</sup> सहित सरकारी हस्तक्षेप भू-राजनीतिक विचारों के कारण द्विपक्षीय व्यापार पैटर्न में बदलाव को मजबूत करते हैं।
- NTMs में वृद्धि, जो कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद शुरू हुई थी, वह रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष होने से और बढ़ गई।

### 2024 में वैश्विक व्यापार निष्पादन

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) डेटाबेस 2024 की तीसरी तिमाही में वैश्विक माल निर्यात और आयात सूचकांकों में क्रमशः 3.5% और 3% की साल-दर-साल (YoY) वृद्धि दर्शाता है (मौसमी रूप से समायोजित, 2005 Q1=100)।
- परिणामस्वरूप, वैश्विक व्यापार 2022 के अपने रिकॉर्ड को पार कर जाएगा। यह 2024 में लगभग 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा।
- कुल मिलाकर, 2024 में वैश्विक व्यापार में लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (या 3.3%) की वृद्धि होने की उम्मीद है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का योगदान लगभग 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा।

चार्ट III.3: 2024 में वैश्विक व्यापार में उछाल



स्रोत: डब्ल्यू टी ओ आँकड़े

**VISION IAS**  
INSPIRING INNOVATION

**विश्वक रिवीजन क्लासेस**

**GS प्रीलिम्स**

**UPSC CSE 2025**

**11 फरवरी, दोपहर 1 बजे**

लाइव/ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

<sup>14</sup> Non-Tariff Measures

## प्रशुल्क नीतियां

- प्रभावी क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (RTAs)<sup>15</sup> की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। 1990 में इनकी संख्या 22 थी जो 2024 में बढ़कर 369 हो गई।
- WTO के तहत मुक्त व्यापार पर बढ़ते जोर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों में बढ़ते हुए सहयोग से देशों के बीच सीमा शुल्क में कमी आयी है।
  - उदाहरण के लिए- 2000 और 2024 के बीच, भारत में शुल्क योग्य मदों पर औसत टैरिफ दरें 48.9% से घटकर 17.3% हो गई, जबकि चीन में वे 16.4% से घटकर 8.3% हो गई।
- 2012 और 2022 के बीच, कृषि, विनिर्माण और प्राकृतिक संसाधनों में सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN)<sup>16</sup> और अधिमान्य टैरिफ में गिरावट आई है।
- व्यापक स्तर पर, भारत की आयात शुल्क नीति समय के साथ विकसित हुई है। इसके तहत घरेलू नीतिगत लक्ष्यों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में समन्वित करने की आवश्यकता के साथ संतुलित किया गया है।

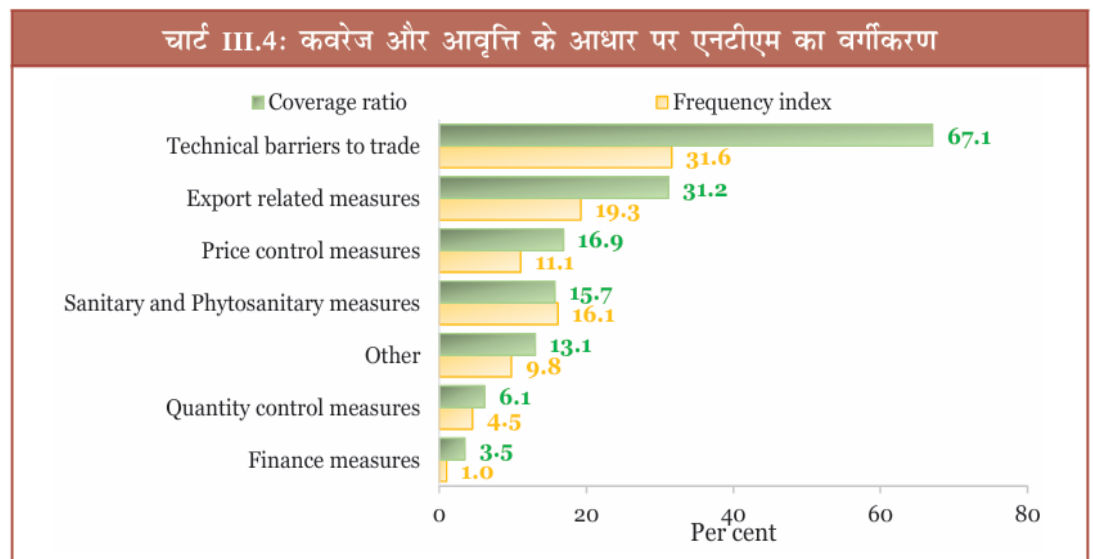
## गैर-प्रशुल्क उपाय (NTM)

- ग्लोबल ट्रेड अलर्ट डेटाबेस से पता चलता है कि 2020 और 2024 के बीच, व्यापार और निवेश से संबंधित 26,000 से अधिक नए प्रतिबंध वैश्विक स्तर पर लगाए गए हैं।
- व्यापार में तकनीकी बाधाएं (TBT) 31.6% उत्पाद लाइनों को प्रभावित करती हैं, जिसमें वैश्विक व्यापार का 67.1% शामिल है (दिसंबर 2024 तक)।

### NTMs का प्रभाव

- हालांकि, कई NTMs का उद्देश्य मुख्य रूप से लोक स्वास्थ्य या पर्यावरण की रक्षा करना है। हालांकि, वे सूचना, अनुपालन और प्रक्रियात्मक लागतों को बढ़ाकर व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
- शोध से पता चला है कि NTMs का FDI पर सकारात्मक असर पड़ता है।

- उदाहरण के लिए- यदि किसी उत्पाद पर लागू NTMs की औसत संख्या 2.5 से बढ़कर 3.5 NTMs प्रति उत्पाद हो जाती है, तो FDI 12% तक बढ़ सकता है।
- ऐसा इसलिए है, क्योंकि यदि किसी कंपनी को लगे कि किसी NTMs का पालन करने का खर्च निर्यात लागत से ज्यादा है, तो वह FDI के जरिए उस बाधा को पार करना बेहतर समझेगी।



<sup>15</sup> Regional Trade Agreements

<sup>16</sup> Most Favoured Nation

## भारत के व्यापार प्रदर्शन में रुझान

- वित्त वर्ष 2025 के पहले नौ महीनों में भारत के कुल निर्यात (माल+सेवाएं) में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। यह 6% की वार्षिक वृद्धि के साथ 602.6 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया है।
- अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान कुल आयात 6.9% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 682.2 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया।
- निर्यात की तुलना में समग्र आयात में अधिक उल्लेखनीय वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2025 की अवधि के दौरान समग्र व्यापार घाटा 2023 में 69.7 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 79.5 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
- अंतर्राष्ट्रीय वस्तु कीमतों में गिरावट के कारण पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात के मूल्य में गिरावट के कारण व्यापारिक निर्यात में साल-दर-साल 1.6% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई।
- गैर-तेल, गैर-स्वर्ण वस्तुओं के आयात में वृद्धि के कारण व्यापारिक आयात में वृद्धि हुई।

### कपड़ा निर्यात

- भारत विश्व स्तर पर कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है।
- कपड़ा और परिधान उद्योग सकल घरेलू उत्पाद में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% का योगदान देता है।
- यह कृषि के बाद सबसे बड़े रोजगार सृजनकर्ताओं में से एक है। इसमें 45 मिलियन से अधिक लोग सीधे तौर पर रोजगार पाते हैं, जिनमें कई महिलाएं और ग्रामीण आबादी शामिल हैं।
- भारत ने 2023 में 34 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के कपड़ा वस्तुएं निर्यात की, जिसमें परिधान निर्यात बास्केट का 42% था।

### नए बाजारों में भारत के निर्यात का विविधीकरण

- 1994 और 2022 के बीच, भारत ने न केवल नए बाजार बनाए हैं, बल्कि कुछ नए उत्पाद श्रेणियों में बाजार का लीडर भी बन गया है।
  - उदाहरण के लिए- भारत शिपिंग जहाजों (लगभग 33% बाजार हिस्सेदारी के साथ) का एक शीर्ष निर्यातक है।
- इसी तरह, यह लौह और इस्पात आधारित मिश्र धातुओं का एक प्रमुख निर्यातक है, जो 1994 से पहले एक अज्ञात बाजार था।
- इस विविधीकरण के लिए प्रमुख वस्तुओं (PCs)<sup>17</sup> से जुड़े उपलब्ध आंकड़ों का अध्ययन किया गया है।
  - 20 PCs का चयन दो मानदंडों के आधार पर किया गया। सबसे पहले, PCs को नए खोजे गए बाजारों की संख्या के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया गया था। दूसरा, PCs का निर्यात मूल्य 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक था।
- विविधीकरण की यह रणनीति बाजार में उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों को कम करती है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य में एक अधिक प्रतिस्पर्धी देश के रूप में स्थापित करती है।

### वैश्विक चुनौतियों के बीच सेवा व्यापार लचीला बना रहा

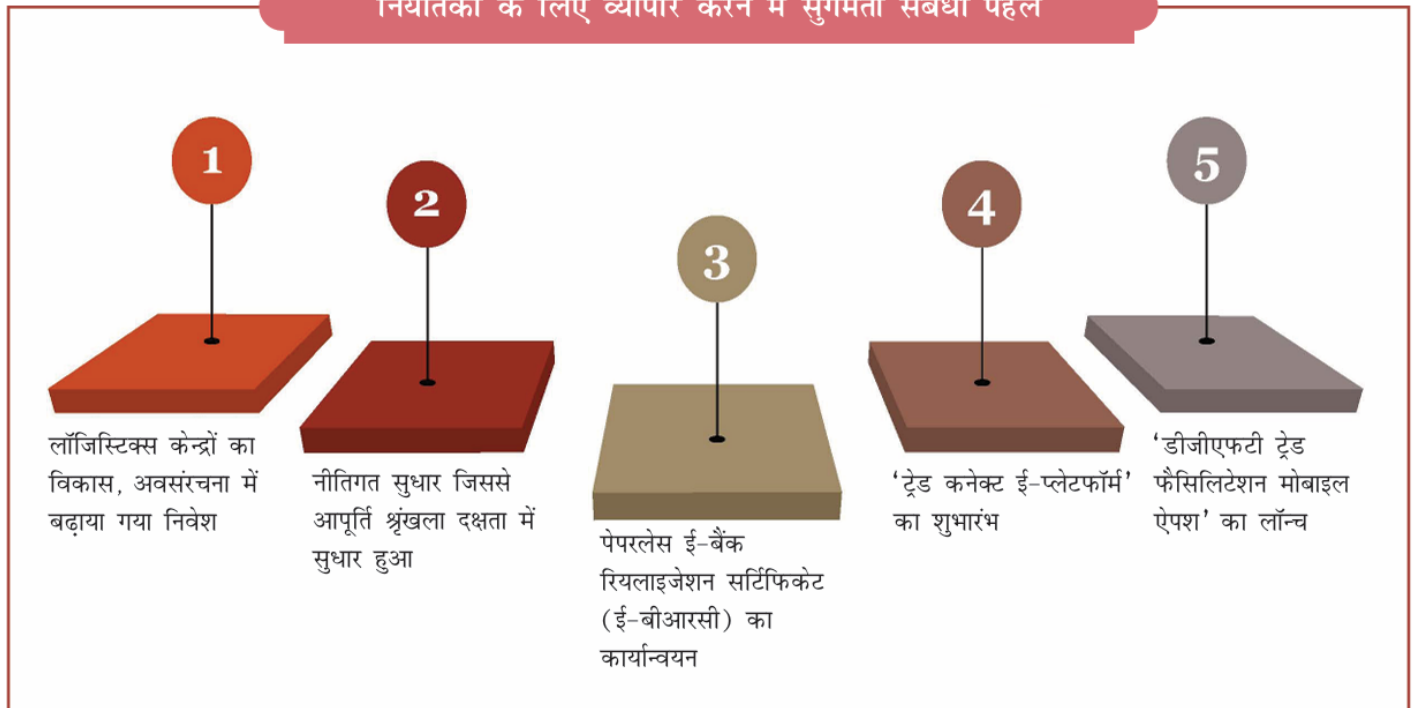
- प्रतिकूल भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.6% की दर से बढ़ा।
- सेवा निर्यात में वृद्धि के कारण, निवल सेवा प्राप्तियां वित्त वर्ष 2024 के पहले नौ महीनों में 120.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 131.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गईं।
- वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2005 में 1.9% थी, जो 2023 में बढ़कर 4.3% हो गई।
  - दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में, भारत की हिस्सेदारी वैश्विक निर्यात की 10.2% है। यह भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनाता है।
  - 'अन्य व्यावसायिक सेवा क्षेत्र' भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें भारत की दुनिया में हिस्सेदारी 7.2% है। यह भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनाता है।

## भारत का ई-कॉमर्स निर्यात

- पिछले कुछ वर्षों में भारत के ई-कॉमर्स उद्योग ने तेजी से विस्तार किया है।
  - ऑनलाइन पेमेंट, स्थानीयकृत वितरण सेवाओं, ग्राहकों के साथ डेटा-संचालित आदान-प्रदान और डिजिटल मार्केटिंग जैसे प्रौद्योगिकी-संचालित प्रगति इसके प्रमुख कारक हैं।
- एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का B2C ई-कॉमर्स बाजार 2022 में 83 बिलियन अमरीकी डॉलर का था। 2026 तक इसके 150 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है, जो 15.9% की CAGR दर्शाता है।
  - हालांकि, वर्तमान बाजार के आकार के अनुसार, भारत का ई-कॉमर्स बाजार वैश्विक बाजार का एक छोटा हिस्सा (लगभग 1.5%) है।

## ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस

### निर्यातकों के लिए व्यापार करने में सुगमता संबंधी पहल



## भुगतान संतुलन: चुनौतियों के बीच सुदृढ़

- वैश्विक व्यापार और निवेश माहौल में अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत का भुगतान संतुलन (BoP) स्थिर बना हुआ है।
  - इसकी प्रमुख वजहें हैं: सेवाओं के निर्यात में लचीलापन, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, विदेशी पोर्टफोलियो में नए सिरे से निवेश और FDI प्रवाह में सुधार।



UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2025 के लिए  
रणनीतिक रिवीजन, प्रैक्टिस और परामर्श हेतु  
**5 माह का कार्यक्रम**

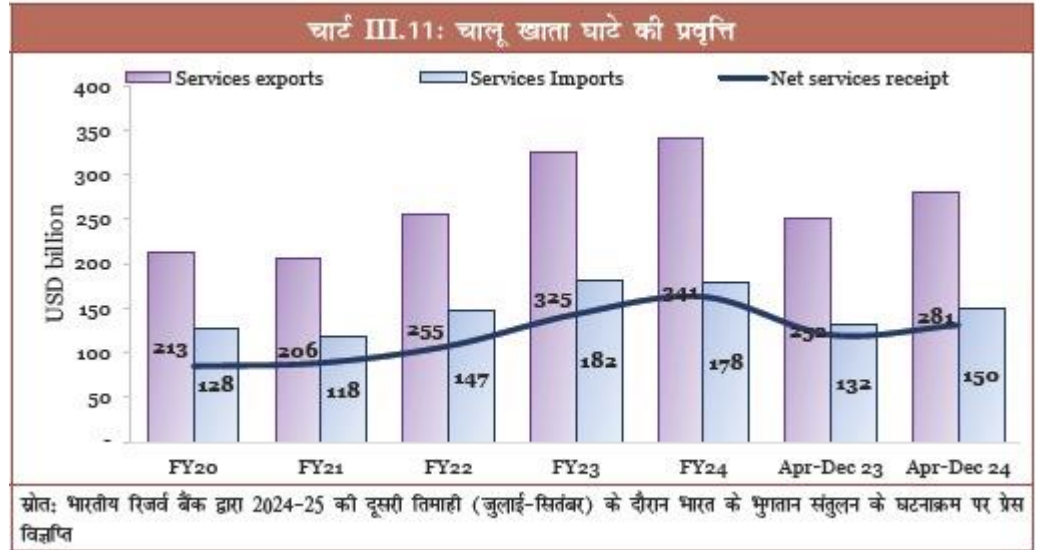
[www.visionias.in](http://www.visionias.in)  
8468022022

लक्ष्य प्रीलिम्स और मेन्स इंटीग्रेटेड मेंटॉरिंग प्रोग्राम 2025

**15 मार्च 2025**

## चालू खाता

- भारत का चालू खाता घाटा (CAD) वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में घटकर GDP का 1.2% हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 1.3% था।
- चालू खाता घाटे में हालिया वृद्धि का मुख्य कारण वस्तु व्यापार घाटे में वृद्धि है, जो वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में 64.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 75.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- भारत का CAD अन्य G-20 अर्थव्यवस्थाओं, जैसे कि ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में अपेक्षाकृत नियंत्रित रहा। इन देशों को वस्तुओं की उच्च कीमतों और कमजोर वैश्विक मांग सहित समान बाह्य दबावों का सामना करना पड़ा है।
- निजी अंतरण भुगतान, मुख्य रूप से विदेशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा भेजा गया धन, शुद्ध अंतरण का बड़ा हिस्सा था। यह वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में 28.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 31.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।



## पूंजी और वित्तीय खाता

- वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही से लेकर वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही तक की अवधि में, भारत ने आम तौर पर पूंजी खाते में अधिशेष दर्ज किया है। इसका मुख्य कारण FDI, FPI और बाह्य ऋणों से मजबूत पूंजी प्रवाह रहा है।
- इन निवेशों ने भारत की बाह्य आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाए रखने और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने में मदद की है।

# A.I.T.S

GS PRELIMS TEST SERIES 2025

## ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम

कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली

5 फंडामेंटल टेस्ट

30 टेस्ट

15 एप्लाइड टेस्ट

10 फुल लेंथ टेस्ट

**2025**  
**ENGLISH MEDIUM**  
**9 MARCH**

**हिन्दी माध्यम**  
**9 मार्च**

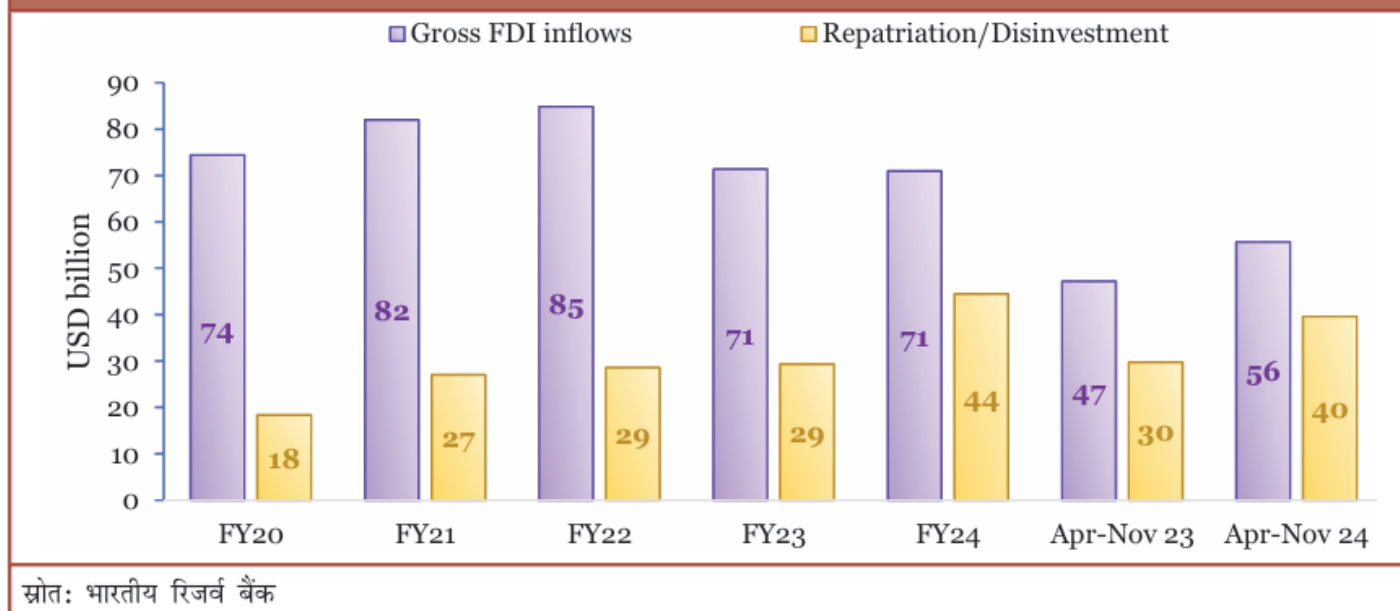
**2026**  
**ENGLISH MEDIUM**  
**2 MARCH**

**हिन्दी माध्यम**  
**2 मार्च**

## FDI प्रवाह का कार्य निष्पादन

- वित्त वर्ष 2025 में भारत में FDI में सुधार देखा गया, जिसमें सकल FDI अंतर्वाह वित्त वर्ष 2024 के पहले 8 महीनों में 47.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की समान अवधि में 55.6 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। यह साल-दर-साल (YoY) आधार पर 17.9% की वृद्धि दर्शाता है।

चार्ट III- 14: सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में रुझान



- वर्ष 2000 से लेकर 2024 तक भारत में FDI प्रवाह 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। इससे भारत की स्थिति एक सुरक्षित और महत्वपूर्ण वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में मजबूत हुई है।
- क्षेत्रीय दृष्टिकोण से, सेवा क्षेत्र FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है, जो वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में कुल इक्विटी अंतर्वाह का 19.1% था।
- चिंताएँ: हाल के वर्षों में भारत के FDI अंतर्वाह में गिरावट को लेकर चिंताएँ बढ़ी हैं।
  - हालांकि, एक व्यापक विश्लेषण से पता चला है कि वैश्विक स्तर पर FDI अंतर्वाह आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ती उधारी लागतों से बाधित हुआ है।
- भारत चालू खाता घाटे की स्थिति में है। भारत की अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए यहां निवेश करने की आवश्यकता अधिक है।
- घरेलू बचत के साथ पर्याप्त विदेशी बचत को शामिल करना पूंजी निर्माण की संभावनाओं को बढ़ा सकता है।

## पोर्टफोलियो प्रवाह निष्पादन

- आय में वृद्धि में गिरावट, उच्च मूल्यांकन, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और चीन में हालिया घटनाओं के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने भारतीय इक्विटी से बड़ी मात्रा में धन निकाला है।
- संचयी आधार पर, अप्रैल-दिसंबर 2024 के बीच भारत में निवल FPI अंतर्वाह 10.6 बिलियन अमरीकी डॉलर पर सिमट गया। हालांकि, इससे पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 31.7 बिलियन डॉलर था।
- पोर्टफोलियो प्रवाह में अस्थिरता यह दर्शाती है कि भारत के इक्विटी और बॉन्ड बाजार वैश्विक घटनाक्रमों के प्रति संवेदनशील है।
- फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें और भारत-अमेरिका के बीच ब्याज दर का अंतर के बारे में निवेशकों की धारणा भारत में FPIs अंतर्वाह के प्रमुख चालक हैं। इसलिए FPI ऋण प्रवाह और भारत तथा अमेरिका के बीच प्रतिफल विभेदक<sup>18</sup> के रुझानों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

<sup>18</sup> Yield Differential

- भारत की सरकारी प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि से सरकार के लिए उधार लेने की लागत कम होने के मामले में सकारात्मक बाह्य प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि बढ़ी हुई और सीमित आपूर्ति गतिशीलता के कारण प्रतिफल में गिरावट आई है।
- भारतीय बांड्स का वैश्विक सूचकांकों में शामिल होना यह संकेत देता है कि विदेशी निवेशकों के बीच भारतीय सरकारी बांड्स को अपने निवेश पोर्टफोलियो में शामिल करने की रुचि बढ़ रही है।

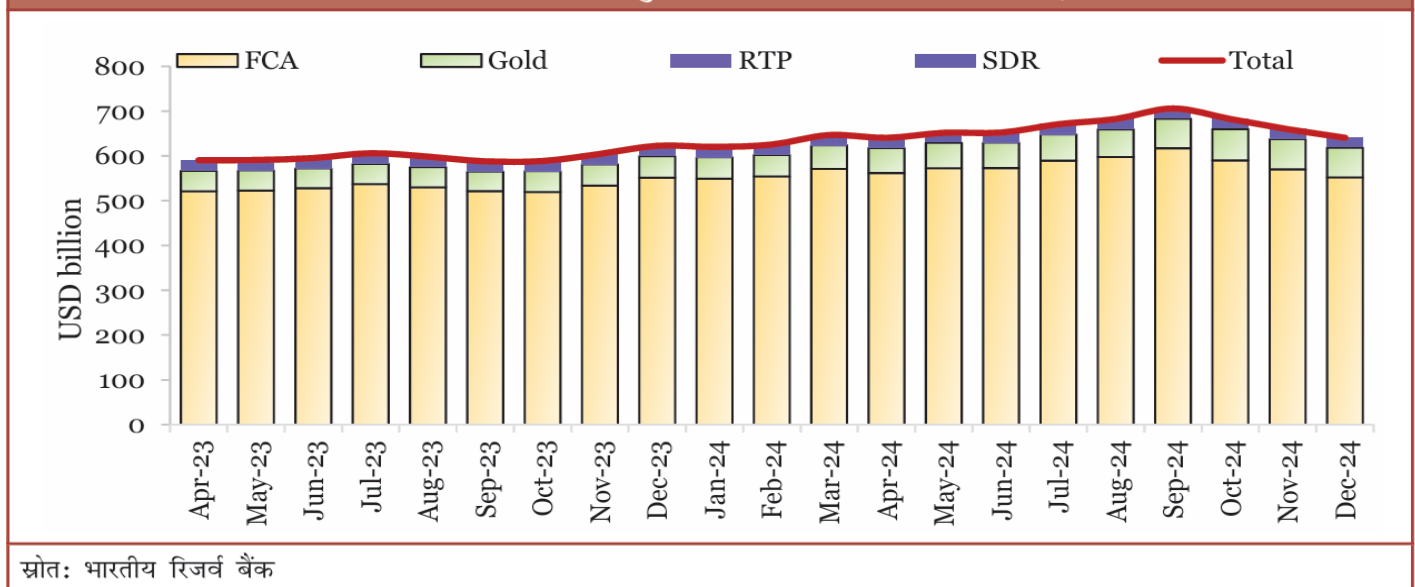
## अन्य

- **NRI जमा**, बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB)<sup>19</sup> और अल्पकालिक व्यापार ऋण ने भारत के पूंजी खाते में अतिरिक्त बफर का योगदान दिया है।
  - अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक ECB बढ़कर 9.2 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2.8 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो विदेशी स्रोतों से उधार लेने की अधिक इच्छा को दर्शाता है।
  - अनिवासी भारतीय (NRI) जमा में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसका निवल प्रवाह बढ़कर 10.2 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

## विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि

- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (FCA)<sup>20</sup>, स्वर्ण, विशेष आह्रण अधिकार (SDR)<sup>21</sup> और IMF में रिजर्व ट्रेंच स्थिति (RTP) शामिल हैं।
- दिसंबर 2024 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमरीकी डॉलर तक कम हो गया।
  - यह भंडार भारत के लगभग 90% बाह्य ऋण को कवर करने के लिए पर्याप्त है।
- 2024 तक, भारत दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में शामिल हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद वैश्विक स्तर पर भारत चौथे स्थान पर है।
- 2024 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 27.1 बिलियन अमरीकी डॉलर की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
  - इस वृद्धि में बड़ी हिस्सेदारी FCA की रही। इससे भारत की समग्र रिजर्व स्थिति मजबूत हुई।

चार्ट III.19: विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में उतर-चढ़ाव



<sup>19</sup> External Commercial Borrowings

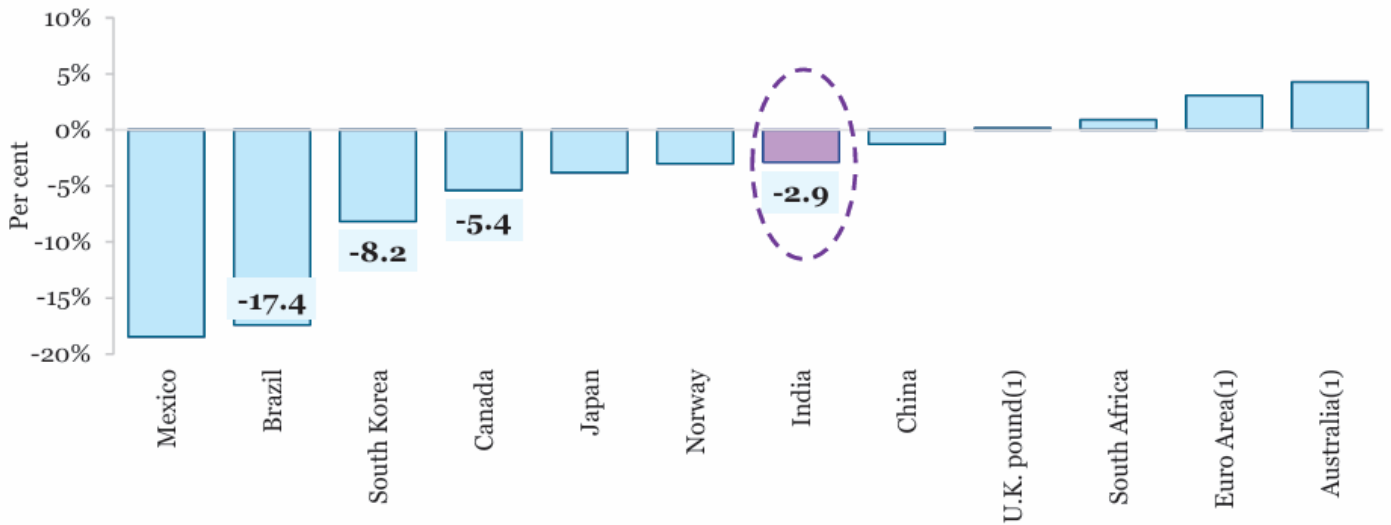
<sup>20</sup> Foreign Currency Assets

<sup>21</sup> Special Drawing Rights

## विनिमय दर

- भारतीय रुपये (INR) का मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित होता है, जिसका कोई लक्ष्य या विशिष्ट स्तर या बैंड नहीं होता।
- विभिन्न घरेलू और वैश्विक कारक, जैसे- डॉलर इंडेक्स की गति, पूंजी प्रवाह में रुझान, व्याज दरों का स्तर, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, चालू खाता घाटा, आदि भारतीय रुपये की विनिमय दर को निर्धारित करते हैं।

चार्ट III.20: अप्रैल से दिसंबर 2024 तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले प्रमुख देशों की द्विपक्षीय विनिमय दरों में परिवर्तन<sup>22</sup>



स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

- प्रभावी विनिमय दरें किसी अर्थव्यवस्था के व्यापार योग्य क्षेत्र की बाहरी प्रतिस्पर्धात्मकता मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक बन गई हैं।
  - भारतीय रुपये के लिए नाममात्र की प्रभावी विनिमय दर (NEER)<sup>22</sup> अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच 90-92 की सीमा में स्थिर बनी रही।
  - वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER)<sup>23</sup>, जो मुद्रा की वास्तविक क्रय शक्ति को दर्शाती है, अप्रैल 2024 में 103.2 से बढ़कर दिसंबर 2024 में 107.2 हो गई।

## विदेशी ऋण की स्थिति

- पिछले कुछ वर्षों में भारत का विदेशी ऋण स्थिर रहा है।
  - विदेशी ऋण की इस स्थिर स्थिति ने वैदेशिक क्षेत्र की स्थिरता को बनाए रखने में मदद की है, खास तौर पर तब जब दुनिया के बाकी हिस्से भू-राजनीतिक प्रतिकूलताओं से प्रभावित हैं।
- सभी मुद्राओं में, विदेशी ऋण मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर (53.4%) में अंकित रहा। इसके बाद INR (31.2%), SDR (5%) और यूरो (3%) का स्थान रहा।

## आगे की राह और दृष्टिकोण

- भारत को निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए व्यापार लागत को कम करना और सुविधा में सुधार करना जारी रखना चाहिए। इससे भारत को प्रतिस्पर्धी बने रहने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

<sup>22</sup> Nominal Effective Exchange Rate

<sup>23</sup> Real Effective Exchange Rate

- राज्य शासन चलाता है, जबकि निजी क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है।
- यदि ये दोनों ही अभिकर्ता गुणवत्ता और दक्षता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो व्यापार तनाव और संरक्षणवाद के बावजूद, भारत विदेशी बाजारों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है और पूंजी निर्माण के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए संसाधन सृजित कर सकता है।

## बजट में क्या कहा गया है?

- निर्यात संवर्धन मिशन:** इसके तहत क्षेत्रीय और मंत्रालय स्तर के लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। निर्यात ऋण तक आसान पहुंच को सुगम बनाया जाएगा। क्रॉस-बॉर्डर फैक्ट्रिंग समर्थन दिया जाएगा। गैर-प्रशुल्क बाधाओं से निपटने में MSMEs की सहायता की जाएगी।
- भारत ट्रेडनेट:** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाएगा। यह व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तीय समाधान के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। इसके अलावा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण का समर्थन किया जाएगा।
- GCC के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क:** इसके तहत उभरते हुए टियर-2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।
- रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) को बढ़ावा:** जहाज निर्माण और जहाज तोड़ने के लिए 10 वर्षों तक कर छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही, मरम्मत के लिए आयातित रेलवे सामान के निर्यात की समय सीमा बढ़ाई जाएगी।
- निर्यात संवर्धन:** हस्तशिल्प और चमड़ा क्षेत्रों के लिए शुल्क मुक्त इनपुट्स प्रदान किए जाएंगे।

## शब्दावली

| शब्द/ पद                          | अर्थ                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गैर-प्रशुल्क उपाय (NTMs)          | ये प्रशुल्कों के अलावा ऐसे नीतिगत उपाय होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं। इनके माध्यम से यह तय किया जाता है कि कौन-सा देश, क्या और कितना व्यापार करेगा।        |
| क्षेत्रीय व्यापार समझौता (RTA)    | यह दो या दो से अधिक सरकारों के बीच एक समझौता होता है, जो सभी सदस्य देशों के लिए व्यापार के नियम तय करता है।                                                                             |
| मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN)           | यह सिद्धांत कहता है कि अगर एक WTO सदस्य किसी देश को व्यापार में कोई विशेष सुविधा देता है, तो वह सुविधा सभी WTO सदस्यों को देनी होगी।                                                    |
| भुगतान संतुलन (BoP)               | भुगतान संतुलन (BoP) किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी देश की अर्थव्यवस्था के शेष विश्व के साथ आर्थिक लेन-देन (अर्थात् निवासी और अनिवासी संस्थाओं के बीच लेन-देन) का विवरण प्रदान करता है। |
| चालू खाता घाटा (CAD)              | CAD निर्यात के कारण प्राप्त धनराशि और आयात के कारण बाहर जाने वाली धनराशि के बीच का अंतर होता है।                                                                                        |
| नाममात्र प्रभावी विनिमय दर (NEER) | NEER वह असमायोजित भारित औसत दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं के एक बास्केट के साथ विनिमय किया जाता है।                                                                  |
| वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) | यह किसी मुद्रा के मूल्य को विदेशी मुद्राओं के औसत मूल्य के मुकाबले मापी गया समायोजित दर होती है, जिसे मूल्य अपस्फीतिकारक या लागत सूचकांक से समायोजित किया जाता है।                      |



## अपने सीखने के कौशल का परीक्षण कीजिए

### MCQs

1. वैश्विक व्यापार व्यवधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. लाल सागर में व्यवधानों के कारण माल भेजने के समय में बढ़ोतरी हुई है और शिपिंग लागत बढ़ गई है।
  2. होर्मुज जलडमरूमध्य में संघर्षों ने वैश्विक ऊर्जा व्यापार को बाधित किया है और पेट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि की है।
  3. जलवायु परिवर्तन ने वैश्विक व्यापार में अनिश्चितताओं को बढ़ाया है।उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
  - (a) केवल 1
  - (b) केवल 2
  - (c) केवल 3
  - (d) कोई नहीं
2. गैर-प्रशुल्क उपायों (NTMs) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. कृषि और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रक NTMs से सबसे अधिक प्रभावित हैं।
  2. NTM का विनिर्माण क्षेत्रों पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा है।उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
  - (a) केवल 1
  - (b) केवल 2
  - (c) 1 और 2 दोनों
  - (d) न तो 1, न ही 2
3. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. भारत ने अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक FDI प्रवाह में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर लिया है।
  2. वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण हाल के वर्षों में FDI प्रवाह में कमी आई है।उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
  - (a) केवल 1
  - (b) केवल 2
  - (c) 1 और 2 दोनों
  - (d) न तो 1, न ही 2
4. भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 12 महीने के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है।
  2. भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में मुख्य रूप से स्वर्ण और SDR शामिल हैं।उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
  - (a) केवल 1
  - (b) केवल 2
  - (c) 1 और 2 दोनों
  - (d) न तो 1, न ही 2

5. भारत के विदेशी ऋण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- हाल के वर्षों में भारत का विदेशी ऋण तेजी से बढ़ रहा है।
  - भारत का विदेशी ऋण प्रबंधनीय अनुपात के साथ स्थिर बना हुआ है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1, न ही 2

### मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न

- भारत के चालू खाता प्रदर्शन और वैश्विक व्यापार चुनौतियों के बीच इसके लचीलेपन को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। (150 शब्द)
- वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच भारत की आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की भूमिका का आकलन कीजिए। (150 शब्द)



# अभ्यास 2025

## ऑल इंडिया प्रीलिम्स

### (GS+CSAT) मॉक टेस्ट सीरीज



3 टेस्ट

|                     |                      |                  |
|---------------------|----------------------|------------------|
| टेस्ट 1<br>6 अप्रैल | टेस्ट 2<br>27 अप्रैल | टेस्ट 3<br>11 मई |
|---------------------|----------------------|------------------|

Register at: [www.visionias.in/abhyas](http://www.visionias.in/abhyas)

ऑफलाइन\* मोड  
100+ शहरों में

- 🔴 UPSC प्रारंभिक पाठ्यक्रम का पूरा कवरेज
- 🔴 मानसिक तत्परता के लिए परीक्षा जैसा माहौल
- 🔴 अखिल भारतीय रैंकिंग
- 🔴 VisionIAS पोस्ट टेस्ट विश्लेषण
- 🔴 लाइव टेस्ट चर्चा
- 🔴 अंग्रेजी/हिंदी में उपलब्ध

Agartala | Agra | Ahmedabad | Aizawl | Ajmer | Aligarh | Amritsar | Ayodhya | Bareilly | Bathinda | Bengaluru | Bhilai | Bhopal | Bhubaneswar | Bikaner | Bilaspur | Chandigarh | Chennai | Chhatarpur | Chhatrapati Sambhaji Nagar | Coimbatore | Cuttack | Dehradun | Delhi | Dhanbad | Dharamshala | Dharwad | Durgapur | Faridabad | Gangtok | Gaya | Ghaziabad | Gorakhpur | Gurugram | Guwahati | Gwalior | Haldwani | Haridwar | Hazaribagh | Hisar | Hyderabad | Imphal | Indore | Itanagar | Jabalpur | Jaipur | Jalandhar | Jammu | Jamshedpur | Jhansi | Jodhpur | Kanpur | Kochi | Kohima | Kolkata | Kota | Kozhikode | Kurukshetra | Leh | Lucknow | Ludhiana | Madurai | Mandi | Meerut | Moradabad | Mumbai | Muzaffarpur | Mysuru | Nagpur | Nashik | Navi Mumbai | Noida | Orai | Panaji | Panipat | Patiala | Patna | Prayagraj | Puducherry | Pune | Raipur | Rajkot | Ranchi | Rohtak | Roorkee | Sambalpur | Shillong | Shimla | Siliguri | Srinagar | Surat | Thane | Thiruvananthapuram | Tiruchirappalli | Tirupati | Udaipur | Vadodra | Varanasi | Vijayawada | Visakhapatnam | Warangal

## अध्याय 4: कीमतें और मुद्रास्फीति: उतार-चढ़ाव को समझना (Prices and Inflation: Understanding the Dynamics)

### परिचय

- वैश्विक मुद्रास्फीति आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और भू-राजनीतिक तनावों के कारण 2022 में चरम (8.7%) पर पहुंच गई थी, लेकिन नीतिगत उपायों के कारण 2024 में यह घटकर 5.7% रह गई।
- भारत में, खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 की 5.4% से घटकर वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर) में 4.9% हो गई। कोर मुद्रास्फीति एक दशक के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई, जबकि आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, मांग-आपूर्ति असंतुलन और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण खाद्य मुद्रास्फीति (जैसे- प्याज और टमाटर की कीमतें, दालें आदि) बढ़ गई।
- भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं का हिस्सा लगभग 2/5 हिस्सा होता है। इसलिए, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI)<sup>24</sup> खुदरा मुद्रास्फीति का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है।

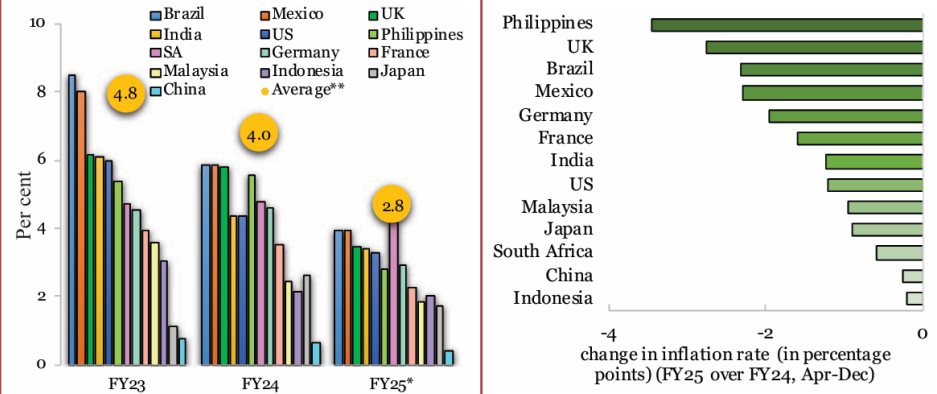
### अध्याय का प्रीकैप

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>वैश्विक मुद्रास्फीति के रुझान</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>हेडलाइन मुद्रास्फीति दर में गिरावट</li> <li>कोर मुद्रास्फीति में कमी</li> <li>खाद्य मुद्रास्फीति में कमी</li> </ul> | <b>घरेलू मुद्रास्फीति के रुझान</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति में गिरावट</li> <li>खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट</li> <li>खाद्य मुद्रास्फीति स्थिर रही (अधिक रही)</li> <li>चरम मौसम की स्थिति सब्जी उत्पादन को प्रभावित करती है</li> <li>खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक उपाय</li> </ul> |
| <b>परिदृश्य</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति</li> <li>मुद्रास्फीति दर अनुमान</li> <li>हेडलाइन मुद्रास्फीति</li> </ul>                                     | <b>मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>जलवायु-प्रतिरोधी फसल किस्में विकसित करना</li> <li>किसानों का प्रशिक्षण</li> <li>बेहतर डेटा संग्रह</li> </ul>                                                                                                                                              |

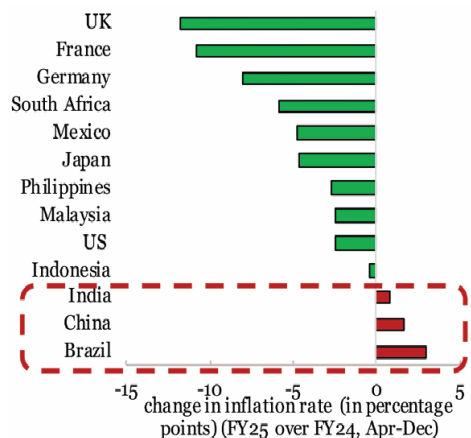
### वैश्विक मुद्रास्फीति

- हेडलाइन मुद्रास्फीति दर: मौद्रिक नीति में समकालिक सख्ती, केंद्रीय बैंकों द्वारा व्याज दरों में वृद्धि और वित्त वर्ष 24 तथा वित्त वर्ष 25 के दौरान वैश्विक स्तर पर स्थिर उत्पादन के कारण इसमें गिरावट दर्ज की गई।
- कोर मुद्रास्फीति (अस्थिर खाद्य और ऊर्जा कीमतों को छोड़कर): अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में कमी और सभी क्षेत्रों में प्रभावी नीतिगत उपाय के कारण अधिकतर देशों में कोर मुद्रास्फीति में कमी आई है। (इन्फोग्राफिक देखिए)
- खाद्य मुद्रास्फीति: ब्राजील, भारत और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को छोड़कर अन्य देशों में अनुकूल विकास स्थितियों की वजह से उत्पादन में वृद्धि हुई और वैश्विक आपूर्ति भी बनी रही। इस वजह से खाद्य मुद्रास्फीति में कमी दर्ज की गई है। (इन्फोग्राफिक देखिए)

<sup>24</sup> Consumer Food Price Index

**चार्ट IV.2: कोर मुद्रास्फीति भी कम हुई है**


स्रोत: ब्लूमबर्ग और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  
नोट: \*वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति दर अप्रैल से दिसंबर 2024 तक है, जापान, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर नवंबर 2024 तक है। \*\* देशों का साधारण औसत चार्ट IV.2 में प्रस्तुत किया गया है।

**चार्ट IV.3 (ख): कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अलग-अलग प्रवृत्ति आलेख**


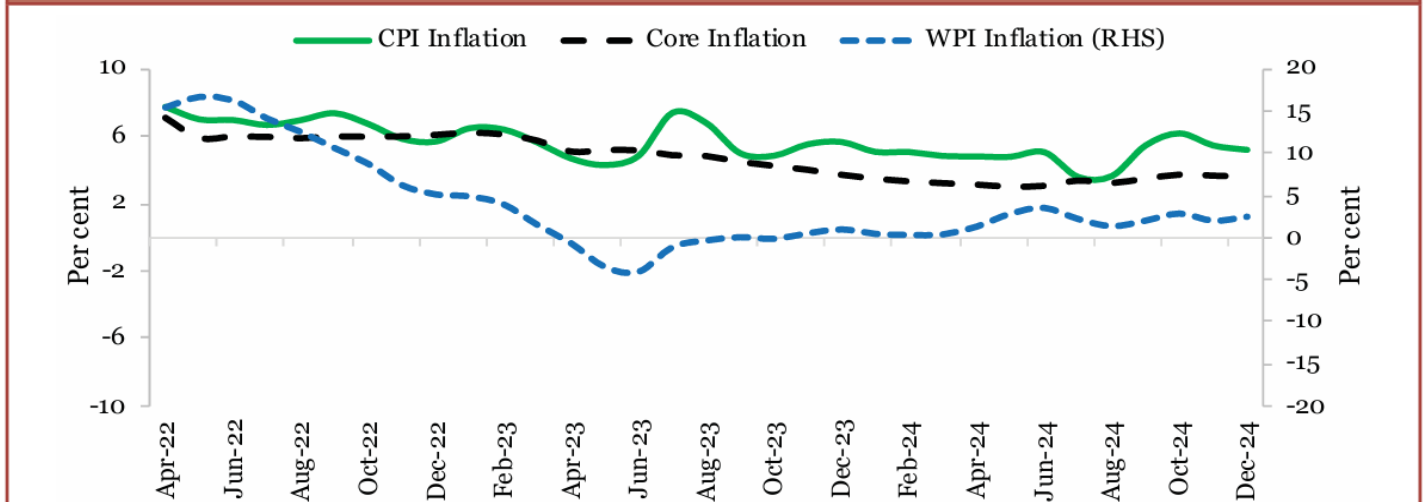
## घरेलू मुद्रास्फीति के रुझान

### हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति:

- भारत की हेडलाइन मुद्रास्फीति {उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)<sup>25</sup> द्वारा मापन} वित्त वर्ष 24 की तुलना में वित्त वर्ष 25 में कम दर्ज की गई।
- हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट में योगदान देने वाले कारक:
  - कोर मुद्रास्फीति में कमी: यह वित्त वर्ष 24 और वित्त वर्ष 25 के बीच 0.9 प्रतिशत अंक कम हुई। कोर सेवा-मुद्रास्फीति में कमी की वजह कोर मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई। कोर सेवा-मुद्रास्फीति, कोर वस्तुओं की मुद्रास्फीति से कम थी।
  - ईंधन मूल्य मुद्रास्फीति में कमी आई जिससे, पारिवारिक बजट पर दबाव कम हुआ।

### खुदरा मुद्रास्फीति

इनपुट कीमतों में कमी के कारण खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई। जैसा कि थोक मूल्य मुद्रास्फीति से परिलक्षित होता है, जो वित्त वर्ष 24 में अपस्फीति (deflationary) स्थिति (-0.7%) में थी और वित्त वर्ष 25 में भी कम रही।

**चार्ट IV.4: हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति नियंत्रण में**


स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

## खाद्य मुद्रास्फीति {उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) द्वारा मापन}

- खाद्य मुद्रास्फीति के स्थिर या घटते वैश्विक रुझान के विपरीत, यह पिछले दो वर्षों से भारत में उच्च बनी हुई है। इसकी मुख्य वजह चरम मौसम की घटनाओं के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और फसल की उपज में कमी है।

- CFPI: वित्त वर्ष 24 की 7.5% से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 8.4% हो गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से कुछ खाद्य पदार्थों विशेष रूप से सब्जियों (टमाटर, प्याज) और दालों (अरहर दाल) की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई।

- जब सब्जियों और दालों को CPI बास्केट से बाहर रखा जाता है, तो वित्त वर्ष 2025 के लिए औसत खाद्य मुद्रास्फीति दर 4.3% थी, जो समग्र खाद्य मुद्रास्फीति से 4.1% भी कम है।
- सबसे अधिक अस्थिर मूल्य वाली सब्जियों- टमाटर, प्याज और आलू (TOP) को

| बॉक्स IV.1: खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक कदम |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| खाद्य वस्तुएं                                                         | लिए गए कदम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अनाज                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>24 जून 2024 से 31 मार्च 2025 तक गेहूं पर स्टॉक सीमा लागू की गई।</li> <li>खुले बाजार की बिक्री योजना: केंद्रीय पूल से गेहूं और चावल दिया गया</li> <li>भारत ब्रांड के अन्तर्गत गेहूं के आटे और चावल की बिक्री।</li> </ul>                                                                                                                             |
| दालें                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>भारत ब्रांड के अन्तर्गत चना दाल, मूंग दाल और मसूर दाल की बिक्री</li> <li>21 जून 2024 से 30 सितंबर 2024 तक तुअर और देसी चना पर स्टॉक सीमा लगाई गई।</li> <li>31 मार्च 2025 तक देसी चना, तुअर, उड़द और मसूर के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई।</li> <li>20 फरवरी 2025 तक पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई।</li> </ul>                    |
| सब्जियां                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्याज का बफर स्टॉक: मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत कुल 4.7 लाख मीट्रिक टन रबी प्याज की खरीद की गई है।</li> <li>13 सितंबर 2024 से प्याज पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क।</li> <li>सितंबर-दिसंबर 2024 तक 35 रुपये प्रति किलोग्राम प्याज की रियायती दर पर बिक्री।</li> <li>अक्टूबर 2024 में 65 रुपये प्रति किलोग्राम टमाटर की रियायती दर पर बिक्री।</li> </ul> |
| स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो की विभिन्न विज्ञापितियाँ                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

खाद्य मुद्रास्फीति से बाहर करने पर वित्त वर्ष 25 में औसत खाद्य मुद्रास्फीति दर 6.5% थी।

- विगत तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) में टमाटर और प्याज, दोनों मामले में घरेलू खपत इसके उत्पादन से कम रही है।
- चरम मौसम की स्थिति
  - चक्रवात, भारी बारिश, ओलावृष्टि, सूखा, लू आदि से सब्जी उत्पादन, कीमतें (मुख्य रूप से प्याज और टमाटर) और आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है, जिससे खुदरा कीमतें प्रभावित होती हैं।
    - 2023-24 में ग्री-मानसून सीजन के दौरान बेमौसम बारिश के कारण बागवानी उत्पादक प्रमुख राज्यों में फसलों को नुकसान पहुंचा। इससे बागवानी वस्तुओं में मुद्रास्फीति उच्च रही।

## आगे की राह और परिदृश्य

- उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (CPI): RBI और IMF, दोनों ने अनुमान लगाया है कि भारत की CPI वित्त वर्ष 26 में धीरे-धीरे कम होकर लक्ष्य के अनुरूप हो जाएगी।
- मुद्रास्फीति दर: IMF ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2025 में 4.4% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% की मुद्रास्फीति दर रहने का अनुमान लगाया है।
- हैडलाइन मुद्रास्फीति: RBI को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26 में हैडलाइन मुद्रास्फीति 4.2% रहेगी, यदि मानसून सामान्य रहता है या कोई बाहरी संकट नहीं आता है या कोई सख्त नीतिगत कार्रवाई नहीं की जाती है।
  - विश्व बैंक के कम्पोजिट मार्केट्स आउटलुक के अनुसार, 2025 में कम्पोजिट की कीमतों में 5.1% और 2026 में 1.7% की कमी आने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण तेल की कम कीमतें तथा धातुओं और कृषि कच्चे माल की स्थिर कीमतें होंगी।
  - बहुमूल्य धातुओं में सोने की कीमतों में कमी आने का अनुमान है, जबकि चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी होने का अनुमान है।

- धातुओं और खनिजों की कीमतों में गिरावट आने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण लौह अयस्क और जस्ता की कीमतों में कमी है।
- 2024-25 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में 5.7% की वृद्धि होने का अनुमान है।
- 2023-24 की तुलना में चावल उत्पादन में 5.9% की वृद्धि हो सकती है, जबकि तुअर उत्पादन में 2.5% की वृद्धि हो सकती है।

### दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें

- जलवायु-अनुकूल फसल किस्में: भारत दलहन और तिलहन के उत्पादन में लगातार कमी तथा टमाटर और प्याज के उत्पादन में उतार-चढ़ाव का सामना कर रहा है। ऐसे में, जलवायु-अनुकूल फसल किस्में विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे उपज में वृद्धि हो और फसल क्षति कम हो।
- नियमित प्रशिक्षण: किसानों को सर्वोत्तम पद्धतियों, उच्च उपज और रोग प्रतिरोधी बीज किस्मों की खेती करने तथा दालों, टमाटर तथा प्याज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में कृषि तकनीकों में सुधार के लिए लक्षित उपाय करने पर प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।
- डेटा संग्रहण: कीमतों, स्टॉक, भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं की निगरानी करने तथा उपलब्ध डेटा के आधार पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों में मजबूत डेटा-संग्रहण और विश्लेषण प्रणालियों को लागू करना चाहिए।

### बजट में क्या कहा गया है?

**दलहन में आत्मनिर्भरता:** तुअर, उड़द और मसूर के उत्पादन पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा-

- जलवायु अनुकूल बीजों का विकास और वाणिज्यिक तौर पर उपलब्धता सुनिश्चित करना,
- खाद्य में प्रोटीन सामग्री बढ़ाना
- उत्पादकता बढ़ाना
- फसल कटाई के बाद भंडारण एवं प्रबंधन में सुधार, किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना।

### शब्दावली

| शब्द/ पद                                            | अर्थ                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मुद्रास्फीति                                        | किसी निश्चित समयावधि में कीमतों में वृद्धि की दर।                                                                                                                                  |
| हेडलाइन मुद्रास्फीति                                | बास्केट में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन।                                                                                                                                     |
| कोर मुद्रास्फीति                                    | इसमें खाद्य एवं ईंधन मदों को हेडलाइन मुद्रास्फीति से बाहर रखा जाता है।                                                                                                             |
| खुदरा मुद्रास्फीति                                  | इसे उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (CPI) के रूप में भी जाना जाता है, यह उस दर को मापती है जिस पर उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें समय के साथ बढ़ती या घटती हैं। |
| उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI)                 | 'खाद्य और पेय पदार्थ' के लिए CPI के समान; हालांकि इसमें अल्कोहल पेय और तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई आदि शामिल नहीं किए जाते हैं।                                                      |
| मूल्य स्थिरीकरण कोष (Price Stabilization Fund: PSF) | प्याज, आलू और दालों जैसी महत्वपूर्ण कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमत में अस्थिरता को कम करने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत 2014-15 में इसकी स्थापना की गई।                  |



## अपने सीखने के कौशल का परीक्षण कीजिए

### MCQs

1. खुदरा मुद्रास्फीति के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
  1. 2022 से 2025 तक इसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है।
  2. यह मुख्यतः कोर मुद्रास्फीति में कमी और ईंधन मूल्य मुद्रास्फीति में कमी द्वारा जनित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
    - (a) केवल 1
    - (b) केवल 2
    - (c) 1 और 2 दोनों
    - (d) न तो 1, न ही 2
2. निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जारी की जाती है?
  1. विश्व आर्थिक परिदृश्य
  2. वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
  3. ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन
  4. यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांकनीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
  - (a) 1 और 2 दोनों
  - (b) 1, 2, 3
  - (c) कोई नहीं
  - (d) उपर्युक्त सभी
3. कोर मुद्रास्फीति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. यह हेडलाइन मुद्रास्फीति के समान ही है।
  2. इसके आकलन में खाद्यान्न और ईंधन की कीमतें भी शामिल हैं।
  3. यह स्थिर नहीं होती है, क्योंकि यह अस्थायी आघातों से प्रभावित होती रहती है।उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
  - (a) केवल एक
  - (b) केवल दो
  - (c) कोई नहीं
  - (d) सभी तीनों
4. उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. यह वित्त वर्ष 2024 के 7.5% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 8.4% हो गया है।
  2. यह मुख्य रूप से कुछ खाद्य पदार्थों, विशेषकर सब्जियों और दालों की कीमतों से प्रभावित होता है।उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
  - (a) केवल 1
  - (b) केवल 2
  - (c) 1 और 2 दोनों
  - (d) न तो 1, न ही 2

5. भारत में अनाज से संबंधित खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु, निम्नलिखित में से कौन-सा उपाय नहीं अपनाया गया है?
- गेहूं पर स्टॉक सीमा लगाना।
  - भारत ब्रांड के तहत गेहूं के आटे और चावल की बिक्री।
  - गेहूं का प्रशुल्क मुक्त आयात।
  - केंद्रीय पूल से गेहूं और चावल की बिक्री।

### मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न

- भारत में खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाले कारकों पर प्रकाश डालते हुए, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने के लिए उठाए जा सकने वाले उपायों का सुझाव दीजिए।
- हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। घरेलू मुद्रास्फीति में कमी के लिए उत्तरदायी कारणों पर चर्चा कीजिए।



# Vision Publication

## Igniting Passion for Knowledge..!

### Explore Our Latest Publications



**Empower Learners**



**Stay Current**



**Foster In-Depth Understanding**



**Support Last-Minute Prep**



Scan the QR code to explore our collection and start your journey towards success.

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =



**53 AIR**  
मोहन लाल



**136 AIR**  
अर्पित कुमार



**238 AIR**  
विपिन दुबे



**257 AIR**  
मनीषा धावले



**313 AIR**  
मयंक दुबे



**517 AIR**  
देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें



**53 AIR**  
मोहन लाल



**Toppers' Talk**



**UPSC CSE 2026 सामान्य अध्ययन**



**UPSC Prelims 2025 10 years PYQ**



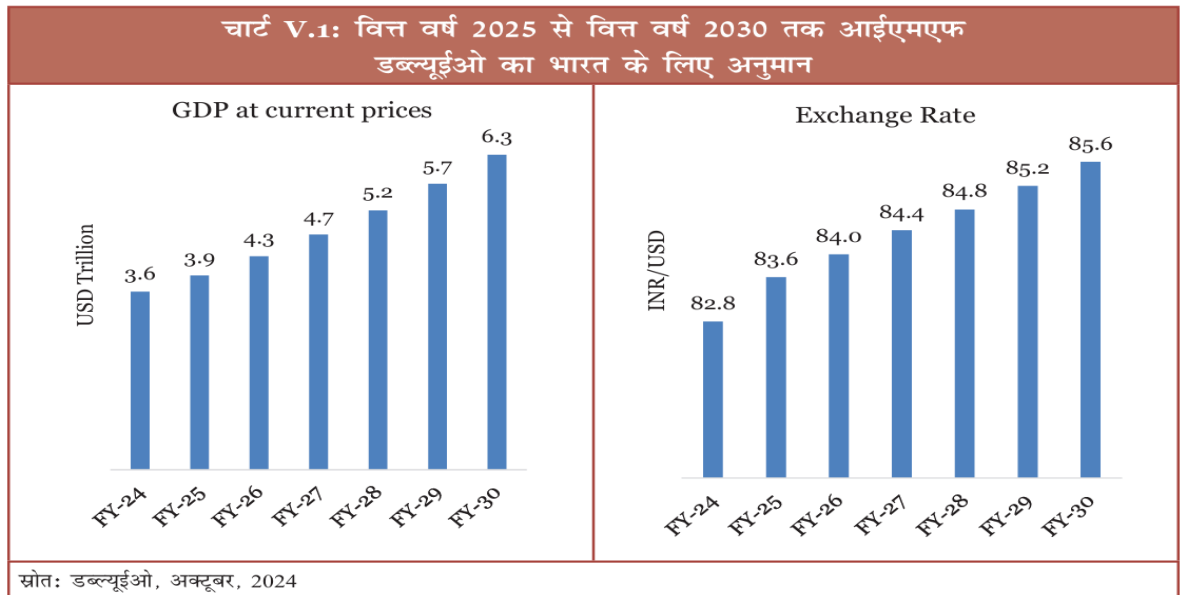
**Master Classes Series करेंट अफेयर्स**

## अध्याय 5: मध्यम अवधि का परिदृश्य: गैर-विनियमन से विकास को बढ़ावा (Medium Term Outlook: Deregulation Drives Growth)

### परिचय

- भारत को 2047 तक विकसित भारत बनने की अपनी आर्थिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक या दो दशक तक स्थिर मूल्यों पर औसतन 8% की वृद्धि दर प्राप्त करने की आवश्यकता है।
- इसके लिए भारत को GDP के 35% तक निवेश बढ़ाने, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और AI, रोबोटिक्स और जैव प्रौद्योगिकी जैसी तकनीकों में निवेश करने की जरूरत है।
  - इसके अतिरिक्त, इसे सालाना 7.85 मिलियन नई गैर-कृषि नौकरियां पैदा करनी होंगी, 100% साक्षरता हासिल करनी होगी और 2030 तक भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के विश्व आर्थिक परिदृश्य<sup>26</sup> में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2028 तक भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और वित्त वर्ष 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 6.307 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा।



- भारत के लिए मध्यम अवधि के विकास दृष्टिकोण का मूल्यांकन एक नई वैश्विक

वास्तविकता- भू-आर्थिक विखंडन, चीन की विनिर्माण क्षमता और ऊर्जा संक्रमण के प्रयासों की चीन पर निर्भरता के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

### अध्याय का प्रीकैप

#### वर्तमान स्थिति

- भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए अगले दशक में 8% औसत वृद्धि का लक्ष्य रखा है।
- IMF का अनुमान है कि भारत वित्त वर्ष 2028 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर एवं वित्त वर्ष 2030 तक 6.307 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

#### भू-आर्थिक विखंडन (GEF)<sup>27</sup>

- GEF का प्रभाव: वैश्वीकरण के स्थान पर वैश्विक आर्थिक पुनर्संरखण, वैश्विक व्यापार और निवेश प्रतिबंधों में वृद्धि, केंद्रित FDI प्रवाह।

<sup>26</sup> World Economic Outlook

<sup>27</sup> Geo-Economic Fragmentation

### विनियमन और आर्थिक स्वतंत्रता: संवृद्धि के लिए उत्प्रेरक

- राज्यों को लागत-प्रभावशीलता के लिए विनियमों की व्यवस्थित समीक्षा करनी चाहिए, तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) 2.0 पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

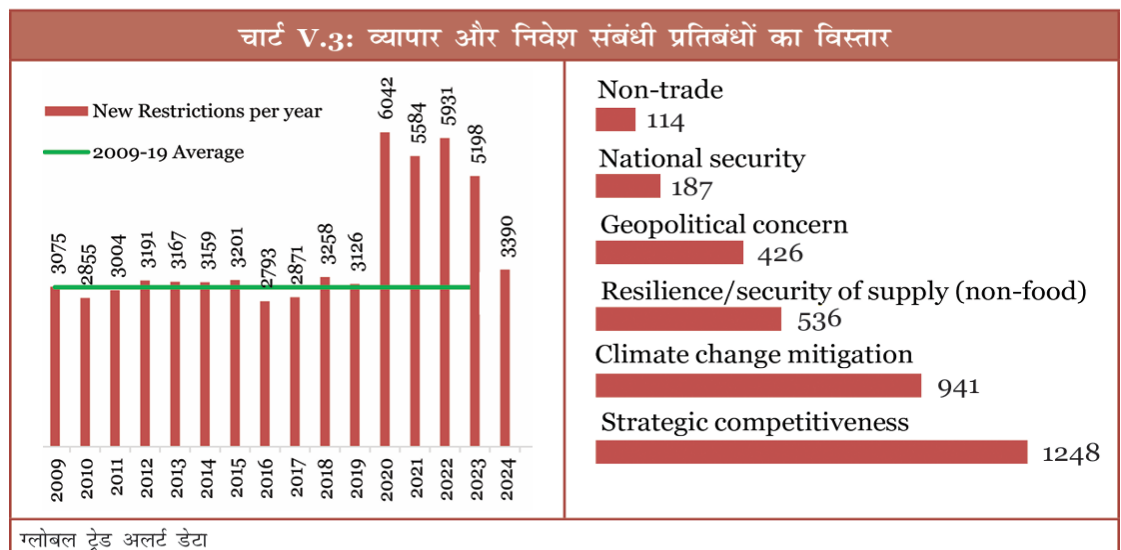
## भू-आर्थिक विखंडन - इस बार की स्थिति अलग हो सकती है

- भू-आर्थिक विखंडन (GEF):** यह उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें सरकारों और नीतिगत निर्णयों के कारण वैश्विक आर्थिक एकीकरण में कमी आती है या उसे उलट दिया जाता है। ये निर्णय आमतौर पर देशों द्वारा खुद के रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में व्यापार प्रतिबंध, निवेश पर नियंत्रण, प्रवासन पर सख्त नियम और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाएं आदि व्यवधान सम्मिलित हो सकते हैं।
- अति-वैश्वीकरण (Hyper-Globalization):** हाल के दशकों में, वैश्वीकरण ने वैश्विक व्यापार, निवेश और गरीबी में कमी के मामले में पर्याप्त वृद्धि की है। इस दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में तीन गुना बढ़ोतरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप 1.3 बिलियन लोग चरम गरीबी की स्थिति से बाहर निकलने में कामयाब हुए।
- प्रमुख वैश्वीकरण रुझान**
  - वर्ष 1980 में, वैश्विक व्यापार का विश्व सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 39. प्रतिशत का योगदान था। वर्ष 2012 तक, यह हिस्सेदारी बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई थी।
  - वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) अंतर्वाह 1980 में 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2019 में 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। यह बढ़ोतरी सीमा-पार निवेश में बहुराष्ट्रीय निगमों की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।
- ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वैश्वीकरण ने आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया है और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को बदला है। हालांकि, आगामी दो दशकों में आर्थिक विखंडन की संभावना अधिक है।

## भू-आर्थिक विखंडन के विकास संबंधी निहितार्थ

- बढ़ते व्यापार प्रतिबंध:** अक्टूबर 2023 और अक्टूबर 2024 के बीच, 169 नए व्यापार-प्रतिबंधात्मक उपायों को लागू करने से 887.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार प्रभावित हुआ। यह आंकड़ा पिछले वर्ष के 337.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफी अधिक है।
  - इसके परिणामस्वरूप ज्ञान के साझाकरण तथा सीमा-पार निवेश में कमी आयी।

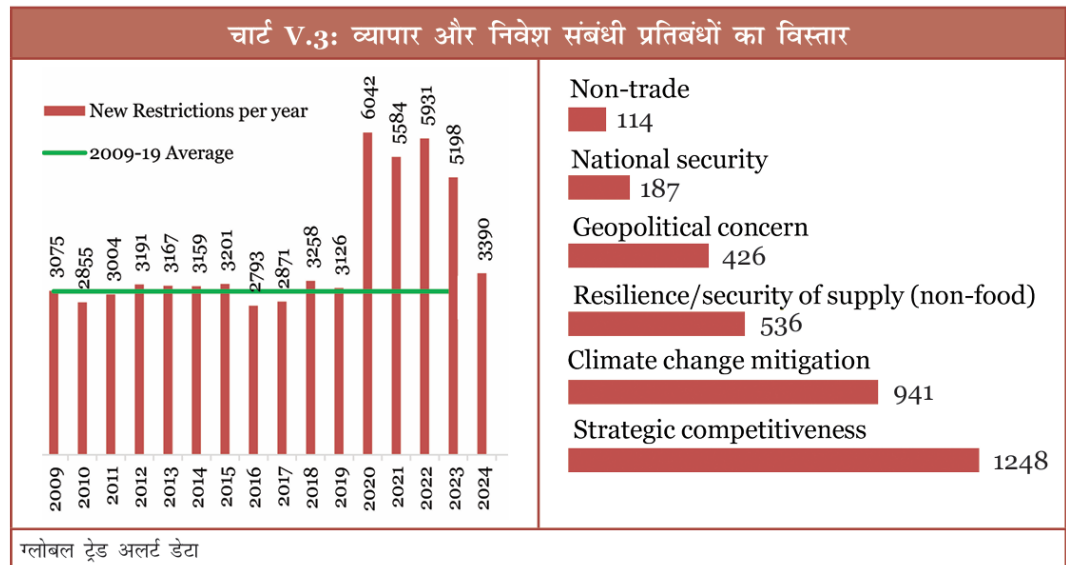
- FDI का संकेन्द्रण:** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) भू-राजनीतिक रूप से संरेखित देशों, खासकर रणनीतिक क्षेत्रों में तेजी से केन्द्रित हो रहा है। इससे उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान हो रहा है।
- उभरते बाजारों पर प्रभाव: फ्रेंड-शोरिंग** और "री-शोरिंग" के कारण उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन हानि (Output Losses) हो रही है।



- **वैश्विक उत्पादन हानि:** व्यापार विखंडन से वैश्विक उत्पादन में 0.2% (निम्न लागत समायोजन परिदृश्य में) से लेकर 7% (उच्च लागत समायोजन परिदृश्य में) तक की कमी आ सकती है।
  - यदि हम इसमें संभावित तकनीकी वियोजन को भी शामिल करते हैं तो, चुनिंदा देशों में उत्पादन हानि GDP के 8-12% तक पहुँच सकती है।
- **पूँजी प्रवाह में बदलाव:** इस तरह के परिणाम का व्यापक प्रभाव यह होगा कि जैसे-जैसे वैश्विक संवृद्धि दर की गति धीमी होती जाएगी, वैश्विक पूँजी का प्रवाह अधिक सतत विकास वाली अर्थव्यवस्थाओं की तरफ होता जाएगा।

## कमरे में हाथी और ड्रैगन

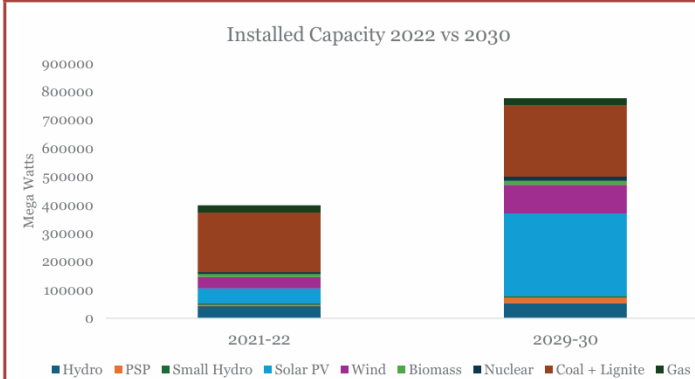
- वैश्विक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहाँ लंबे समय से चले आ रहे सिद्धांतों का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है और कुछ मामलों में, वे अपनी प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं।
- परिवर्तन के इस मोड़ पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन की बढ़ती भूमिका **आर्थिक परिदृश्य** को नया आकार दे रही है। इससे कई देश एक ऐसे **अनजाने माहौल में काम** कर रहे हैं जो उनके पहले के माहौल से बिल्कुल अलग है जहाँ **पारंपरिक नियमों पर पुनर्विचार** किया जा रहा है। उन्हें इस बात को लेकर अनिश्चितता है उनका भविष्य कैसा होगा।
- **चीन वैश्विक विनिर्माण और ऊर्जा संचरण परितंत्र में एक प्रमुख शक्ति है।** वह मुख्य संसाधनों जिन्हें आज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है, तक पहुँच और उन पर नियंत्रण करने के लिए अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और आर्थिक नीतियों का लाभ उठा रहा है।
- वर्ष 2000 में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में अधिक हिस्सेदारी प्राप्त की, जबकि दो दशकों के त्वरित विकास के बाद भी चीन की हिस्सेदारी केवल 6% थी। हालांकि, वर्ष 2030 तक **चीन द्वारा वैश्विक विनिर्माण का 45% उत्पादन किए जाने का अनुमान है**, जिससे वह अमेरिका और उसके सहयोगियों को पीछे छोड़ देगा।



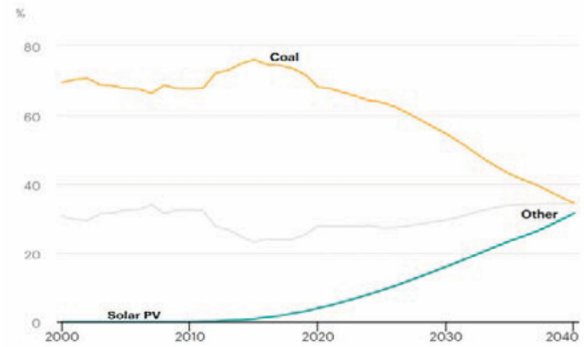
## जलवायु परिवर्तन, चीन और भूराजनीति

- जलवायु परिवर्तन का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता है। तापमान में 1°C की वृद्धि वैश्विक GDP को 12% तक कम कर सकती है। इसमें चरम मौसमी घटनाएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं।
- चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य G7 राष्ट्र वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 50% से अधिक के लिए उत्तरदायी हैं। हालांकि, इन सभी देशों ने 2050 तक निवल-शून्य उत्सर्जन प्राप्ति का लक्ष्य रखा है।
  - यद्यपि, पर्यावरणीय वस्तुओं और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को लेकर **व्यापार संघर्ष हरित ऊर्जा संक्रमण को धीमा कर सकता है** और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है।
- भारत का **"पंचामृत" फ्रेमवर्क 2030 तक** इसके ऊर्जा समिश्रण में बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी में काफी वृद्धि होने की संभावना है, जबकि कोयले और लिग्नाइट पर निर्भरता कम होगी।

### चार्ट V.7: भारत की संस्थापित क्षमता मिश्रण [ 2022 बनाम 2030 ]



### चार्ट V.8: विद्युत उत्पादन के हिस्से में परिवर्तन



स्रोत: इष्टतम उत्पादन मिश्रण 2020 संस्करण 2.0 पर रिपोर्ट, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय

### वैश्विक ऊर्जा संचरण में चीन की भूमिका

- **सौर ऊर्जा नेतृत्व:** चीन सौर फोटोवोल्टिक (PV) विनिर्माण में अग्रणी है। चीन सौर पैनल्स के विभिन्न पाटर्स का 80% से अधिक उत्पादन करता है। इसके अलावा, चीन सौर PV उपकरणों के दुनिया के शीर्ष 10 आपूर्तिकर्ताओं का केंद्र है।
  - इससे सौर ऊर्जा की लागत तो कम हो जाती है, लेकिन इससे आपूर्ति में व्यवधान का जोखिम बढ़ जाता है।
- **पवन ऊर्जा और बैटरी:** दुनिया की संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 60 प्रतिशत चीन से प्राप्त होता है। चीन में दुनिया की बैटरी विनिर्माण क्षमता का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
- **इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति श्रृंखला:** संपूर्ण EV आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का प्रभुत्व है। चीन बैटरी के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक दुर्लभ भू-मृदा खनिजों का 70% प्रसंस्कृत करता है।
  - इससे भारत के EV निर्माण को चुनौती मिलती है क्योंकि भारत इन खनिजों के लिए आयात पर निर्भर है। **निकेल, कोबाल्ट और लिथियम** जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर चीन का नियंत्रण भारत के लिए आपूर्ति जोखिम बढ़ाता है।
- **वैश्विक ऊर्जा संचरण से संबंधित मुद्दे:** IMF के अनुसार, महत्वपूर्ण खनिजों के व्यापार में व्यवधान से **2030** तक नवीकरणीय ऊर्जा और EV निवेश में **30%** तक की गिरावट आ सकती है।
  - स्वच्छ ऊर्जा का समर्थन करने वाली बहुपक्षीय संरचनाएं भी बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रही हैं।

### भारत की विकास संभावनाओं के निहितार्थ

- **भारत के ऊर्जा संचरण पर प्रभाव:** भारत का EV विनिर्माण आयातित खनिजों पर निर्भरता के कारण बाधित है। चीन निकल, कोबाल्ट और लिथियम जैसे प्रमुख खनिजों को नियंत्रित करता है, जिससे आपूर्ति संबंधी जोखिम पैदा होते हैं।
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME):** भारत में कई उद्यम विनियमन से बचने के लिए अपने आकार को जानबूझकर छोटा बनाकर रखते हैं। इसके कारण विकास, नवाचार और उत्पादकता पर नकारात्मक असर पड़ता है। जन विश्वास अधिनियम जैसे प्रयासों का उद्देश्य नियमों को आसान बनाना एवं MSMEs की मदद करना है।
- **वर्तमान विनियमनों से जुड़ी चुनौतियां:** विनियमन लागत को बढ़ाते हैं और विकास को सीमित करते हैं। फैक्ट्री नियम इकॉनमी ऑफ स्केल को हतोत्साहित करते हैं, जबकि ओवरटाइम और अनुपालन कानून रोजगार सृजन और नवाचार में बाधा डालते हैं।
- **गोल्ड-प्लेटेड नियम:** अवास्तविक धारणाओं पर आधारित अत्यधिक प्रतिबंधात्मक नियम व्यवसायों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सरल बनाने से आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है।

## आगे की राह और दृष्टिकोण

### राज्यों के लिए व्यवस्थित गैर-विनियमन

- गैर-विनियमन के लिए क्षेत्रों की पहचान करना: राज्यों को भूमि, स्थानीय व्यापार और श्रम कानूनों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा उन अनावश्यक विनियमों को हटाना चाहिए जो लागत और देरी को बढ़ाते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) 2.0 जैसी पहल इस बदलाव को आगे बढ़ा सकती है।
- विनियमन की लागत का अनुमान लगाना: राज्यों को विनियम लागू करने से पहले उनकी लागत का अनुमान लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए- फैक्ट्री सेटबैक रूल्स के कारण भूमि का नुकसान होता है और नौकरियों में कटौती होती है, जिससे अवसर लागत बढ़ जाती है।
  - राज्यों को अनावश्यक पर्यावरणीय वर्गीकरण के कारण अनुमोदन में होने वाली देरी जैसे अनपेक्षित परिणामों को भी ध्यान में रखना चाहिए।
- डिजाइन सुधार विकल्प: गैर-विनियमन को प्रत्येक विनियमन के प्रभाव का मूल्यांकन करके और राज्य की क्षमता पर विचार करके सावधानीपूर्वक डिजाइन करना चाहिए। राज्य की सीमित क्षमता के कारण अवास्तविक अपेक्षाएं और अनुपालन प्रक्रियाएं बोझिल हो सकती हैं।
- अन्य राज्यों से सीखना: एक राज्य दूसरे राज्यों के सफल सुधारों को अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा ने IT उद्योगों में महिलाओं से नाइट शिफ्ट में काम कराने के लिए आवश्यक नियमों में संशोधन किया है।
- विश्व की बेहतरीन कार्य पद्धतियों से सीखना: राज्य वैश्विक उदाहरणों जैसे कि यू.एस. ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट, यूनाइटेड किंगडम की 'वन-इन, टू-आउट' नीति और न्यूजीलैंड के विनियमन मंत्रालय जैसे वैश्विक उदाहरणों से सीख लेकर इन मॉडलों को भारत के संदर्भ में लागू कर सकते हैं।

तालिका V.1: व्यवसायों को प्रभावित करने वाले विनियमन क्षेत्रों और प्रावधानों की सूची

| क्षेत्र                 | विनियमनों के उदाहरण                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| विधिक स्थिति और प्रशासन | नगरपालिका संबंधी विधि, नागरिक चार्टर, सार्वजनिक सेवा सवितरण में जवाबदेही |
| भूमि                    | भू-राजस्व, भूमि सुधार, नगर एवं राष्ट्र योजना बनाना, भूमि सीमा            |
| भवन एवं निर्माण         | नगर एवं राष्ट्र योजना बनाना, भवन उपनियम, अग्नि संरक्षा विधि              |
| श्रम                    | संघ संहिताओं, फैक्ट्रियों, सविदा श्रमिक, दुकानों के विधि के अंतर्गत नियम |
| जन-उपयोगी सेवाएं        | जल, विद्युत, भवन संबंधी उपविधियां, नगरपालिका संबंधी विधि                 |
| परिवहन                  | मोटर वाहन विधियां, मोटर परिवहन श्रमिक विधियां, माल की ढुलाई              |
| लॉजिस्टिक्स             | वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीतियां, भवन संबंधी उपनियम                    |
| क्रय और विक्रय          | कृषि उपज एवं पशुधन बाजार समिति कानून                                     |
| पर्यावरण जल             | वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विधिया                         |
| क्षेत्र विशेष           | उत्पाद शुल्क, खाद्य सुरक्षा, विधिक माप विज्ञान                           |

### ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) 2.0 के पक्ष में तर्क

- मानकों और नियंत्रणों का उदारीकरण: भारतीय राज्य महिलाओं को विशिष्ट कारखाना प्रक्रियाओं में भाग लेने पर 139 पुराने प्रतिबंध लगाते हैं। हालांकि, साक्ष्यों से पता चला है कि इससे कोई स्वास्थ्य जोखिम नहीं है। राज्यों को उच्च वेतन वाली भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी को सक्षम करने के लिए इन नियमों पर फिर से विचार करना चाहिए।
- पार्किंग मानदंडों को तर्कसंगत बनाना: सख्त पार्किंग नियमों के कारण व्यावसायिक इमारतों को अनावश्यक रूप से अतिरिक्त मंजिलें बनानी पड़ती हैं। इससे लागत बढ़ती है और भूमि का दुरुपयोग होता है। इन मानकों में बदलाव से भूमि का उचित उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से पर्यटन, आतिथ्य और IT जैसे प्रमुख क्षेत्रों में।
- शास्तियों और प्रवर्तन के लिए विधिक रक्षोपाय निर्धारित करना: कई राज्यों में दंड लगाने के लिए उचित प्रक्रियाएं जैसे कारण बताओ नोटिस या तर्कपूर्ण आदेश का प्रावधान नहीं है। इससे गलत निर्णय और निवेश जोखिम बढ़ते हैं। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने से कानूनी जोखिम कम हो सकते हैं, रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सकता है और विकास को बढ़ावा मिल सकता है।
- प्रशुल्कों और शुल्कों को कम करना: भारत में उच्च बिजली शुल्क उद्योगों को कम प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। उदाहरण के लिए, वियतनाम उत्पादन लागत से 10% कम शुल्क लेता है। प्रशुल्क कम करने से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

- जोखिम-आधारित विनियमन लागू करना: भारतीय राज्यों में भवन सुरक्षा नियमों के प्रवर्तन में निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का सफलतापूर्वक उपयोग करते हैं। निजी इकाइयों को शामिल करने से प्रवर्तन की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार किया जा सकता है।

## बजट में क्या कहा गया है?

- राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन - "मेक इन इंडिया" को आगे बढ़ाना: इस पहल का उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लागत पर ध्यान केंद्रित करना; मांग आधारित नौकरियों हेतु भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करना; जीवंत और गतिशील MSME क्षेत्र का विकास करना, जलवायु अनुकूल विकास के लिए स्वच्छ तकनीक विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
  - इस मिशन के तहत लघु, मध्यम और बृहत उद्योगों को नीतिगत समर्थन, कार्यान्वयन रोडमैप एवं बेहतर प्रशासन आदि प्रदान किया जाएगा।
- हस्तांतरण मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को सरल बनाना: एक नई योजना के तहत, अब अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिए आर्म्स लेंथ प्राइस का निर्धारण 3 साल की ब्लॉक अवधि के लिए किया जा सकेगा।
- सुरक्षित बंदरगाह नियमों का दायरा बढ़ाया गया: इसका उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना और अंतर्राष्ट्रीय कराधान में निश्चितता प्रदान करना है।

## शब्दावली

| शब्द/ पद                    | अर्थ                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भू-आर्थिक विखंडन (GEF)      | यह प्रक्रिया वैश्विक आर्थिक एकीकरण की नीति के विपरीत है। मौजूदा दौर में यह व्यापार, पूंजी और प्रवासन के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया आकार दे रही है।                                                           |
| ऊर्जा संचरण प्रौद्योगिकियाँ | ये ऐसी प्रौद्योगिकियाँ हैं, जो जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में बदलाव लाने में सहायक होती हैं। चीन इन प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से सौर पैनल्स और बैटरी के निर्माण में अग्रणी है। |
| ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB)   | यह एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य विनियमों को सरल बनाकर और भारत में व्यवसायों के संचालन को आसान बनाकर कारोबारी माहौल को बेहतर बनाना है।                                                                                |
| गैर-विनियमन                 | यह व्यवसायों पर सरकारी विनियमनों को हटाने या कम करने की प्रक्रिया है।                                                                                                                                                   |



**VISION IAS**  
INSPIRING INNOVATION

# SANDHAN

**Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज**

(UPSC प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस और समग्र तैयारी हेतु  
ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

|             |                                         |                                        |             |                                         |                                        |
|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>2025</b> | <b>ENGLISH MEDIUM</b><br><b>9 MARCH</b> | <b>हिन्दी माध्यम</b><br><b>9 फरवरी</b> | <b>2026</b> | <b>ENGLISH MEDIUM</b><br><b>2 मार्च</b> | <b>हिन्दी माध्यम</b><br><b>2 मार्च</b> |
|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|



## अपने सीखने के कौशल का परीक्षण कीजिए

### MCQs

1. भारत के आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. वित्त वर्ष 2030 तक भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 2.2% हो जाने का अनुमान है।
  2. सर्वेक्षण में आर्थिक संवृद्धि को गति देने के लिए लोगों और संगठनों पर भरोसा करने के महत्व का उल्लेख किया गया है।
  3. IMF ने अनुमान लगाया है कि अगले पांच वर्षों में भारत की मुद्रास्फीति दर में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
  - (a) केवल एक
  - (b) केवल दो
  - (c) सभी तीनों
  - (d) कोई नहीं
2. भारतीय रुपये के लिए विनिमय दर प्रक्षेपण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. IMF को उम्मीद है कि अगले पांच वर्षों में रुपये में औसतन 3.3% प्रति वर्ष की गिरावट आएगी।
  2. वित्त वर्ष 2024 तक तीन दशकों में रुपये में औसतन 3.3% प्रतिवर्ष की दर से गिरावट आई।उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
  - (a) केवल 1
  - (b) केवल 2
  - (c) 1 और 2 दोनों
  - (d) न तो 1, न ही 2
3. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन वैश्विक चरम गरीबी दरों की प्रवृत्ति का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
  1. प्रतिदिन 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात 1981 के 42% से घटकर 2019 में 8.4% हो गया।
  2. यह गिरावट मुख्य रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र आर्थिक संवृद्धि के कारण हुई।उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
  - (a) केवल 1
  - (b) केवल 2
  - (c) 1 और 2 दोनों
  - (d) न तो 1, न ही 2
4. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
  1. भू-आर्थिक विखंडन (GEF) वैश्विक आर्थिक एकीकरण के बाजार-संचालित उलटफेर को संदर्भित करता है।
  2. GEF वैश्वीकरण का स्थान ले रहा है, जिससे आसन्न आर्थिक पुनर्संरचना और पुनः समायोजन हो रहा है।
  3. अनुमान है कि 2030 तक चीन की वैश्विक विनिर्माण में 45% की हिस्सेदारी होगी, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों कई ज्यादा होगी।
  4. चीन सोलर पैनल उत्पादन में लगभग 80% हिस्सेदारी रखता है और दुनिया की बैटरी विनिर्माण क्षमता में अग्रणी है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चारों

5. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. भारत की स्थापित क्षमता में अक्षय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी 2030 तक कम होने की उम्मीद है।
2. भारत की स्थापित क्षमता में कोयले और लिग्नाइट की हिस्सेदारी 2030 तक तेजी से घटने का अनुमान है।
3. भारत में अक्षय ऊर्जा की ओर बदलाव के लिए देश के ऊर्जा मिश्रण में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीनों
- (d) कोई नहीं

मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न

1. भू-आर्थिक विखंडन (GEF) वैश्विक व्यापार और निवेश प्रवाह को कैसे प्रभावित करता है? भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए इसके निहितार्थों पर चर्चा कीजिए।
2. भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनना है। इसके लिए 8% की संवृद्धि दर हासिल करना जरूरी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन-सी प्रमुख चुनौतियां मौजूद हैं एवं कौन-से सुधार आवश्यक हैं?

# फास्ट ट्रेक कोर्स 2025

## सामान्य अध्ययन प्रीलिम्स

कला एवं संस्कृति

भूगोल

राज्यव्यवस्था

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

पर्यावरण

भारत का इतिहास

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

अर्थव्यवस्था

इसमें निम्नलिखित शामिल है:

- पर्सनल स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस तक पहुंच
- प्रीलिम्स सिलेबस के लिए विस्तृत, प्रासंगिक और अपडेटेड स्टडी मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी
- PT 365 की कक्षाएं
- सेक्शनल मिनी टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव करेंट अफेयर्स

**प्रवेश प्रारंभ**  
Available in English & हिन्दी

**Live/Online**  
Classes available



## अध्याय 6: निवेश और अवसंरचना: अनवरत रहे (Investment and Infrastructure: Keeping It Going)

### परिचय

- पिछले पांच वर्षों में सरकार का मुख्य ध्यान भौतिक, डिजिटल और सामाजिक अवसंरचना में सार्वजनिक व्यय बढ़ाने, मंजूरी में तेजी लाने, कार्यान्वयन में सुधार करने एवं संसाधन जुटाने पर था।
- प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय FY20 से FY24 तक **38.8% की दर से बढ़ा है।**
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP)<sup>28</sup>** को FY20 से FY25 तक लगभग 111 लाख करोड़ रुपये के अवसंरचना निवेश के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था। यह परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए एक केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है।

### अध्याय का प्रीकैप

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>वर्तमान स्थिति</b> <ul style="list-style-type: none"><li>अवसंरचना क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है।</li><li>राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन शुरू की गई है।</li></ul> | <b>भौतिक संपर्क: विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों में विकास</b> <ul style="list-style-type: none"><li>रेलवे, सड़क, नागर विमानन, बंदरगाह और पोत परिवहन तथा ऊर्जा।</li></ul> |
| <b>डिजिटल संपर्क</b> <ul style="list-style-type: none"><li>दूरसंचार, सूचना और प्रौद्योगिकी।</li></ul>                                                                         | <b>ग्रामीण अवसंरचना</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता।</li><li>शहरी, पर्यटन और अंतरिक्ष अवसंरचना।</li></ul>                        |
| <b>शहरी अवसंरचना</b> <ul style="list-style-type: none"><li>पहलें और स्थिति।</li></ul>                                                                                         | <b>पर्यटन अवसंरचना</b> <ul style="list-style-type: none"><li>शुरू की गई विविध पहलें।</li></ul>                                                                       |
| <b>अंतरिक्ष अवसंरचना</b> <ul style="list-style-type: none"><li>अंतरिक्ष संपत्तियां, अंतरिक्ष विज्ञान 2047.</li></ul>                                                          |                                                                                                                                                                      |

### भौतिक कनेक्टिविटी: अवसंरचना क्षेत्र में विकास

#### रेलवे क्षेत्र

##### वर्तमान स्थिति

- अप्रैल से अक्टूबर 2024 के बीच, **17 नई बंदे भारत ट्रेनों की जोड़ी** नेटवर्क में शामिल की गई और 228 कोच निर्मित किए गए।
- भारतीय रेलवे ने **2029-30 तक 30 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा** स्थापित करके नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है।

##### रेल प्रणाली से जुड़ी प्रमुख पहलें

- गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (GCT)<sup>29</sup>**: 91 GCTs चालू किए गए हैं और 31 अक्टूबर 2024 तक 234 स्थानों को मंजूरी दी गई है।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)**: PPP मॉडल के तहत 16,434 करोड़ रुपये लागत की 17 परियोजनाएं पूरी की गई हैं और 16,614 करोड़ रुपये लागत की 8 परियोजनाएं अभी भी प्रगति पर हैं।
- मुख्य परियोजनाएं**: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना, समर्पित मालवाहक गलियारे (DFCs)<sup>30</sup> आदि।

<sup>28</sup> National Infrastructure Pipeline

<sup>29</sup> Gati shakti multi-modal Cargo Terminal

<sup>30</sup> Dedicated Freight Corridors

## रेलवे में यात्रियों हेतु सुविधाएं बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

- **अमृत भारत स्टेशन योजना:** रेलवे स्टेशनों में सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु 1,337 स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए चुना गया है।
- **वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना:** यह योजना 1,900 स्टेशनों पर लागू की गई है। इसके तहत 2,163 आउटलेट्स स्थापित किए गए हैं, जो 79,380 स्थानीय कारीगरों को उनके उत्पादों की बिक्री का अवसर प्रदान करते हैं।

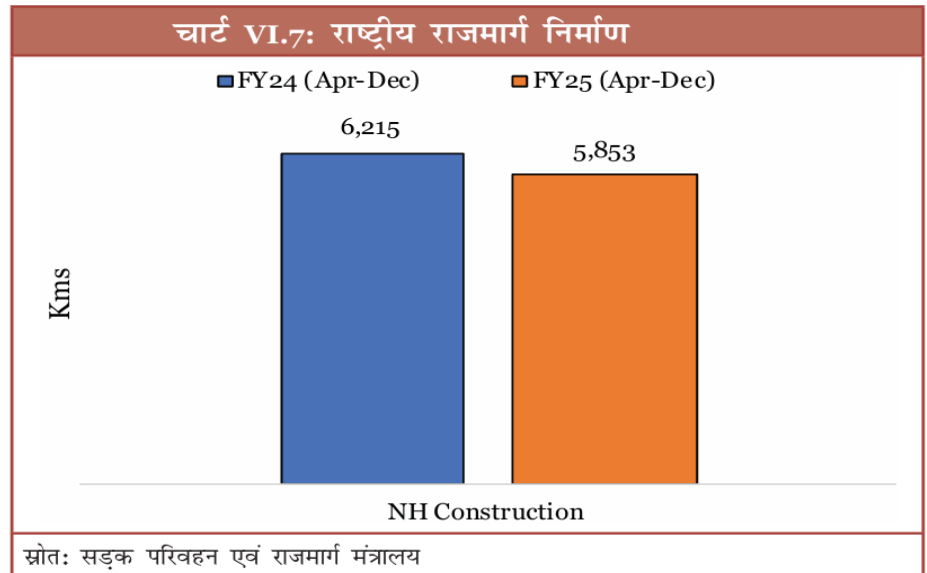
## रेलवे में सिग्नलिंग प्रणाली में सुधार हेतु प्रमुख पहलें

- **कवच:** यह स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। इसमें नवंबर 2024 तक 1,547 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।
- **इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (EI):** FY25 में 227 स्टेशनों पर EI प्रणाली स्थापित की गई है। इससे कुल 3,576 स्टेशनों तक इसकी कवरेज बढ़ गई है।
- **ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग (ABS):** उच्च घनत्व वाले रूट्स की क्षमता बढ़ाने के लिए ABS प्रणाली स्थापित की जा रही है।

## सड़क परिवहन

### वर्तमान स्थिति

- भारत में कुल **63.4 लाख कि.मी.** सड़क नेटवर्क है, जिसमें 1,46,195 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम** उन्नत औद्योगिक शहरों के निर्माण का लक्ष्य रखता है। इससे उन्हें प्रमुख विनिर्माण और निवेश केंद्र बनाया जा सकेगा।
- **राष्ट्रीय राजमार्गों के जरिए कुल सड़क माल** यातायात का लगभग **40% वहन** किया जाता है।
- FY25 में **5,853 कि.मी.** राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया था।



### राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास: परियोजना-आधारित दृष्टिकोण से गलियारा-आधारित दृष्टिकोण की ओर प्रगति।

- **भारतमाला परियोजना:** इसे अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना है।
- **राष्ट्रीय उच्च गति गलियारे (HSCs)<sup>31</sup>:** HSCs की लंबाई 2014 में 93 किलोमीटर से बढ़कर 2024 में 2,474 किलोमीटर हो गई है।

### सड़क कनेक्टिविटी में लॉजिस्टिक्स दक्षता के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलें

- **उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली:** लगभग 4,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया सुविधा स्थापित की गई है।
- **मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स (MMLPs):** दिसंबर 2024 तक चेन्नई, इंदौर, नागपुर, जालना, जोगीघोषा और बेंगलुरु में छह MMLPs स्वीकृत किए गए हैं।
- **वाहन स्कैपिंग नीति; रोपवे परियोजनाओं का विकास:** इससे संबंधित 15 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

<sup>31</sup> High-Speed Corridors

## नागर विमानन

### वर्तमान स्थिति

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सहित हवाई अड्डा संचालक और डेवलपर्स FY20 से FY25 के बीच 91,000 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजीगत व्यय योजना को लागू कर रहे हैं।
- FY24 में हवाई अड्डों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़कर 8.0 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गई है।

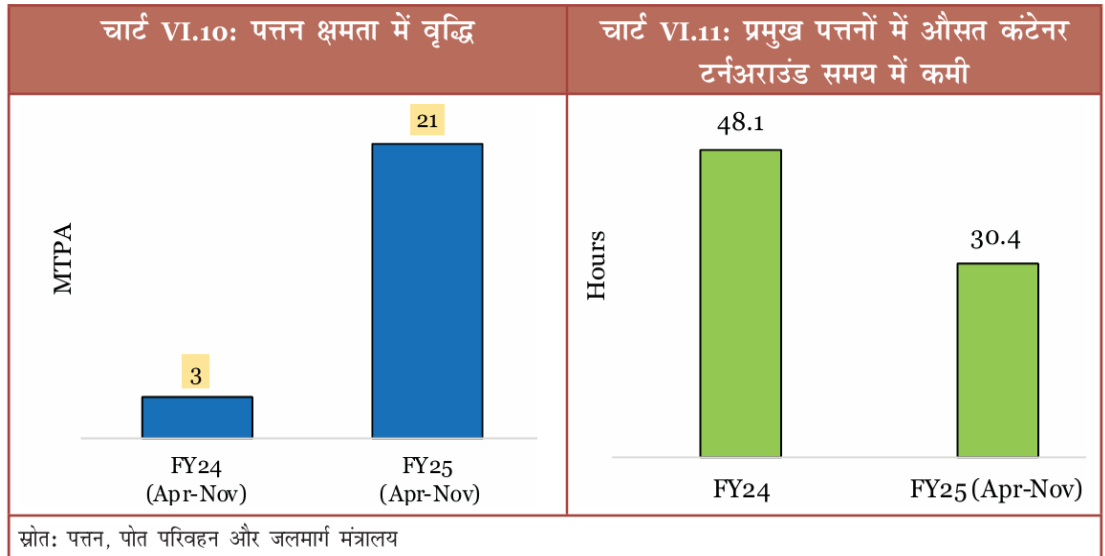
### प्रमुख पहलें

- उड़ान योजना: 88 हवाई अड्डों (जिनमें 2 जल एरोड्रोम और 13 हेलीपोर्ट भी शामिल हैं) को जोड़ने वाले 619 मार्ग परिवहन के लिए अब तक चालू हो चुके हैं।

## बंदरगाह और पोत परिवहन

### वर्तमान स्थिति

- प्रमुख बंदरगाहों में परिचालन दक्षता में सुधार हुआ है और कंटेनर टर्नअराउंड समय में कमी आई है। कंटेनर टर्नअराउंड समय FY24 में 48.1 घंटे से घटकर FY25 (अप्रैल-नवंबर) में 30.4 घंटे हो गया है।
- सागरमाला कार्यक्रम के तहत बंदरगाह आधुनिकीकरण और बंदरगाह-आधारित औद्योगीकरण में उच्चतम परियोजना पूर्णता दर हासिल की गई है।



### बंदरगाह क्षेत्रक में प्रमुख उपलब्धियां और पहलें अवसंरचना का विकास

- वधावन मेगा पोर्ट: इसे 76,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ विकसित किया जा रहा है। इसमें 9 कंटेनर टर्मिनल और अनेक बर्थ शामिल होंगे।

### बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण

- बंदरगाह-आधारित औद्योगीकरण: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 राज्यों में 28,602 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों के विकास को मंजूरी दी है। साथ ही, 8 अतिरिक्त परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है।

### अंतर्राष्ट्रीय लिंकेज

- चाबहार बंदरगाह और INSTC: चाबहार स्थित शाहिद बेहेश्ती पोर्ट, INSTC (अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा) के माध्यम से मुंबई को यूरेशिया से जोड़ता है।
- गलेथिया की खाड़ी (ग्रेट निकोबार द्वीप पर) अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट: भारत के पूर्वी तट के बंदरगाहों और पड़ोसी देशों से कार्गो ट्रांसशिपमेंट को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई गई है।

### अंतर्देशीय जलमार्ग परिवर्तन: प्रमुख परियोजनाएं और पहलें

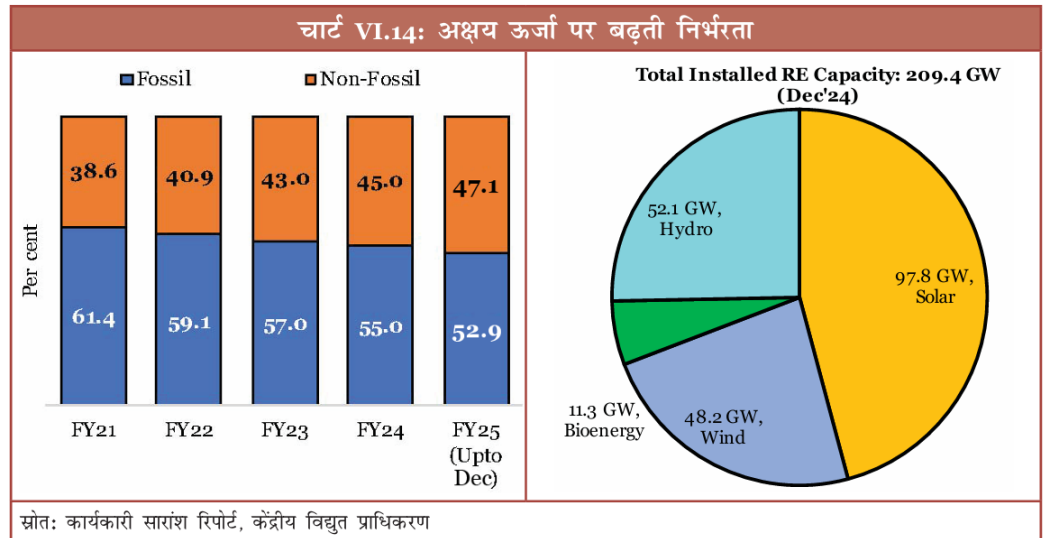
- हरित नौका दिशा-निर्देश: इसे वर्ष 2024 में शुरू किया गया था। इसके तहत अगले दस वर्षों में 1,000 अंतर्देशीय जहाजों को हरित बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

- कार्गो संवर्धन योजना: इस पहल का उद्देश्य कार्गो मालिकों को कार्गो को रेल और सड़क से अंतर्देशीय जलमार्गों पर स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

## विद्युत क्षेत्रक

### वर्तमान स्थिति

- नवंबर 2024 तक स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 7.2% वार्षिक वृद्धि के साथ 456.7 गीगावाट तक पहुंच गई थी।
- भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी अब 47% हो गई है।
- कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में 15.8% वार्षिक दर से वृद्धि दर्ज की गई है।



### प्रमुख पहलें

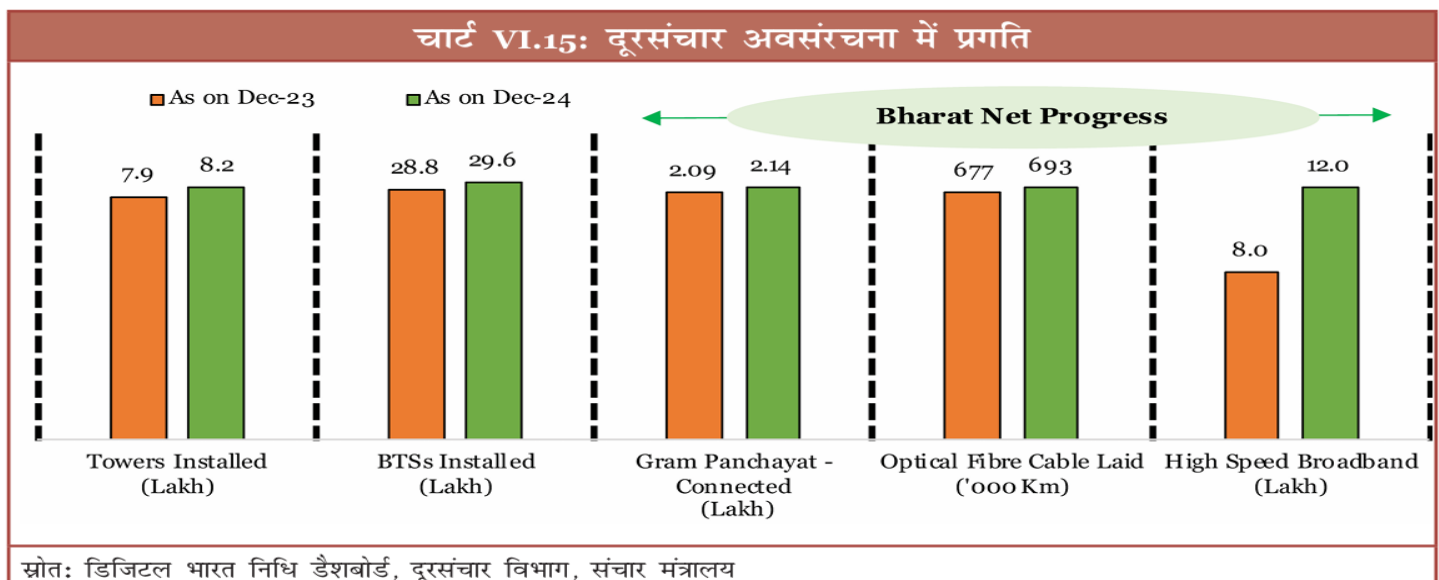
- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY), एकीकृत विद्युत विकास योजना (IPDS), प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आदि।
- पुनर्गठित वितरण क्षेत्रक योजना, प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), EV चार्जिंग के लिए अलग से विद्युत कनेक्शन, जो 2070 तक भारत के नेट जीरो लक्ष्य का समर्थन करता है आदि।

## डिजिटल कनेक्टिविटी

### दूरसंचार क्षेत्रक

### वर्तमान स्थिति

- 31 अक्टूबर 2024 तक, 5G सेवाएं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की जा चुकी हैं।



## प्रमुख पहलें

- **भारत नेट परियोजना:** सभी ग्राम पंचायतों और गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए।
- **दूरसंचार विकास:** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए।
- **आकांक्षी जिला योजना:**
  - **502-गांव योजना:** 215 टावर चालू किए गए हैं, जिनके तहत 4 राज्यों के 112 जिलों में 251 गांवों को कवर किया गया है।

## सूचना प्रौद्योगिकी

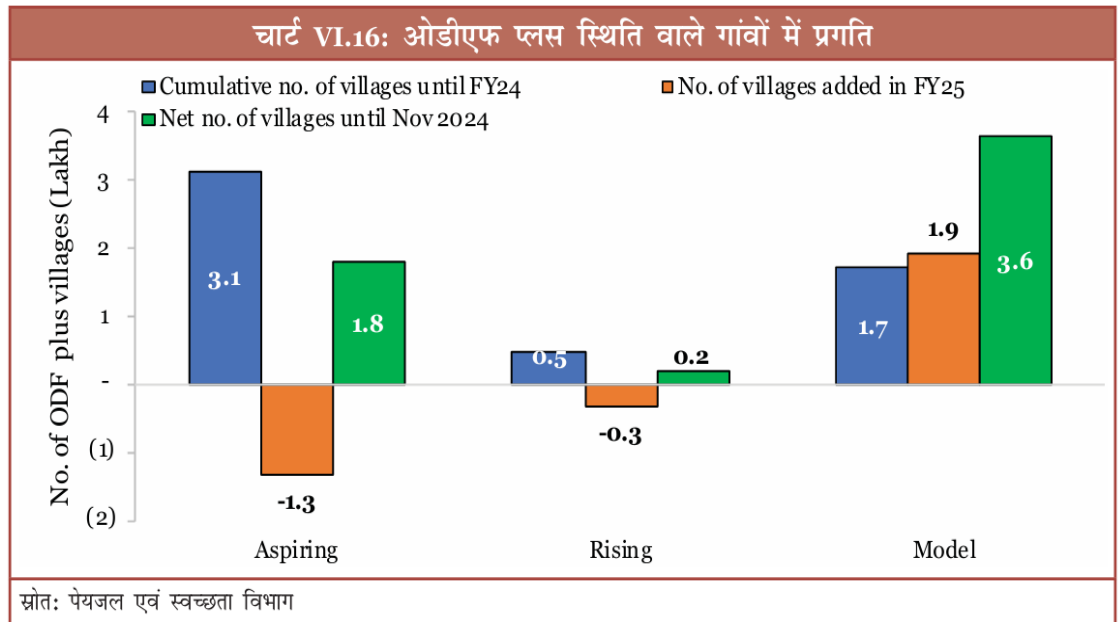
### वर्तमान स्थिति

- नवंबर 2024 तक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) **मेघराज** नामक GI क्लाउड पहल के तहत अपने क्लाउड पर 1,917 एप्लिकेशन को सहायता प्रदान कर रहा है।
  - मेघराज का उद्देश्य केंद्रीय और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के विभागों को क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से ICT सेवाएं प्रदान करना है।
- भारत का डेटा सेंटर बाजार 2023 के 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2032 तक 11.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है।

## ग्रामीण अवसंरचना

### ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता स्थिति और पहलें

- **जल जीवन मिशन (2019):** 2019 से 12 करोड़ से अधिक परिवारों को नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया गया है।
  - **100% कवरेज प्राप्त करने वाले राज्य:** अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना और मिजोरम।
  - **100% कवरेज प्राप्त करने वाले केंद्र शासित प्रदेश:** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली एवं दमन व दीव, तथा पुदुचेरी।



**स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) चरण II:** अप्रैल-नवंबर 2024 के दौरान 1.92 लाख गांवों को मॉडल श्रेणी में ODF+ घोषित किया गया था। इससे कुल ODF+ गांवों की संख्या बढ़कर 3.64 लाख हो गई है।

## शहरी अवसंरचना

- **स्वच्छ भारत मिशन - शहरी**
  - 'कचरा मुक्त शहरों' के लक्ष्य के तहत कचरा प्रबंधन और स्वच्छता प्रथाओं को संश्लेषणीयता एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया है।
- **प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (2015):** शहरी क्षेत्रों में 89 लाख से अधिक मकान निर्मित किए गए हैं।
- **शहरी परिवहन:** मेट्रो और रैपिड रेल प्रणाली 29 शहरों में चालू या निर्माणाधीन अवस्था में है। 23 शहरों में 1010 कि.मी. मेट्रो परिवहन चालू है, जबकि अतिरिक्त 980 कि.मी. अभी निर्माणाधीन है।

- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT/ अमृत): नल से जल कवरेज 70% और सीवरेज कवरेज 62% तक बढ़ाया गया है।
- स्मार्ट सिटीज़ मिशन: 13 जनवरी 2025 तक, 1.64 लाख करोड़ रुपये की 8,058 परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इनमें से 1.50 लाख करोड़ रुपये की 7,479 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

#### शहरी परिवर्तन को आगे बढ़ाने वाली पहलें

- डेटा स्मार्ट सिटीज़ कार्यनीति: डेटा-आधारित गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डेटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क शुरू किया गया है। यह शहरों की डेटा समाधान अपनाने की क्षमता का मूल्यांकन करता है। यह प्रणालीगत व क्षेत्रक आधारित स्तंभों पर केंद्रित है।
- राष्ट्रीय शहरी लर्निंग मंच: यह शहरी स्थानीय निकायों के लिए क्षमता निर्माण का एक डिजिटल मंच है।
- अर्बन लर्निंग इंटरनशिप कार्यक्रम (TULIP): इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। यह युवाओं को शहरी निकायों के साथ जोड़ता है। साथ ही, शहरी परिवर्तन में कौशल और अनुभव बढ़ाने के लिए इंटरनशिप के अवसर प्रदान करता है।

#### पर्यटन अवसंरचना

##### स्थिति और पहलें

- तीर्थस्थल पुनरुद्धार और आध्यात्मिक संवर्धन योजना (PRASHAD): इसे चुने हुए तीर्थस्थलों और विरासत शहरों में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए शुरू किया गया है।
  - दिसंबर 2024 तक, 48 परियोजनाओं में से 26 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
- स्वदेश दर्शन योजना 2.0 (2022): इसे संधारणीय और जिम्मेदारीपूर्ण पर्यटन स्थलों के विकास के लिए शुरू किया गया है। दिसंबर 2024 तक 76 में से 75 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

#### अंतरिक्ष अवसंरचना

##### स्थिति और पहलें

- भारत के पास वर्तमान में 56 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियां मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - 19 संचार उपग्रह;
  - 9 नेविगेशन उपग्रह;
  - 4 वैज्ञानिक उपग्रह; तथा
  - 24 भू-प्रेक्षण उपग्रह।
- सरकार का अंतरिक्ष विज़न 2047 निम्नलिखित चार परियोजनाओं को शामिल करता है:
  - गगनयान अनुवर्ती मिशन: यह भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा।
  - चंद्रयान-4 लूनर सैंपल रिटर्न मिशन।
  - वीनस ऑर्बिटर मिशन।
  - नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का विकास।

#### आगे की राह और दृष्टिकोण

- नेट ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना आवश्यक है।
- परिवहन क्षेत्रक का आधुनिकीकरण: एकीकृत मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तेजी से निर्माण, मौजूदा भौतिक संसाधनों का आधुनिकीकरण आदि जरूरी है। इससे दक्षता और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
- निजी क्षेत्रक की भागीदारी: महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। परियोजनाओं के नियोजन, वित्त-पोषण, निर्माण, रखरखाव, मुद्रांतरण और प्रभाव मूल्यांकन में निजी क्षेत्रक की भागीदारी आवश्यक है।
  - सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन जैसी व्यवस्थाएं शुरू की हैं। इससे अवसंरचना विकास में निजी क्षेत्रक के निवेश को सुगम बनाया जा सकेगा।

## बजट में क्या कहा गया है?

व्यय:

- परिवहन: 5,48,649 करोड़ रुपये;
- ऊर्जा: 81,174 करोड़ रुपये;
- सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार: 95,298 करोड़ रुपये;
- ग्रामीण विकास: 2,66,817 करोड़ रुपये;
- शहरी विकास: 96,777 करोड़ रुपये।

## अपने सीखने के कौशल का परीक्षण कीजिए

### MCQs

- निम्नलिखित पहलों और उनके उद्देश्यों पर विचार कीजिए:
  - कवच – स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली
  - गति शक्ति – बहु-मॉडल लॉजिस्टिक्स और अवसंरचना विकास
  - हरित नौका – अंतर्देशीय जलपोतों को हरित (पर्यावरण-अनुकूल) बनाना  
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?
    - केवल 1 और 2
    - केवल 2 और 3
    - 1, 2 और 3
    - केवल 1 और 3
- निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के अंतरिक्ष विज्ञान 2047 का हिस्सा नहीं है?
  - भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन
  - चंद्रयान-4 लूनर सैंपल रिटर्न मिशन
  - मार्स सैंपल रिटर्न मिशन
  - वीनस ऑर्बिटर मिशन
- निम्नलिखित कार्यक्रमों और उनके फोकस क्षेत्रों पर विचार कीजिए:
  - उड़ान योजना – अल्पसेवित हवाई सेवा वाले क्षेत्रों में किफायती हवाई यात्रा।
  - प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती आवासीय सुविधा।
  - स्वदेश दर्शन – केवल तीर्थ स्थलों का विकास।उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?
  - केवल एक
  - केवल दो
  - सभी तीनों
  - कोई नहीं

4. अमृत भारत स्टेशन योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यह पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास पर लक्षित है।
  - यह केवल प्रमुख महानगरीय स्टेशनों पर केंद्रित है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
  - केवल 2
  - 1 और 2 दोनों
  - न तो 1, न ही 2

5. भारतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है?
- कार्गो परिवहन को बेहतर बनाने के लिए जलमार्गों का विकास।
  - पूरे भारत में विस्तृत रेलवे नेटवर्क का विकास।
  - कॉरिडोर-आधारित दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास।
  - राजमार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना को बढ़ावा देना।

### मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न

- ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना विकास समावेशी विकास के लिए आवश्यक है। जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, और PMGSY जैसी योजनाओं की ग्रामीण अवसंरचना में सुधार तथा उनके सामाजिक-आर्थिक विकास पर प्रभाव की चर्चा कीजिए।
- डिजिटल कनेक्टिविटी पर बढ़ते फोकस के साथ, भारतनेट और 5G रोलआउट जैसी पहलें भारत के संचार परिदृश्य में सुधार कर रही हैं। भारत में डिजिटल अवसंरचना विस्तार से संबंधित चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिए।

## UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

**7 in Top 10 | 79 in Top 100 Selections in CSE 2023**

from various programs of VISIONIAS

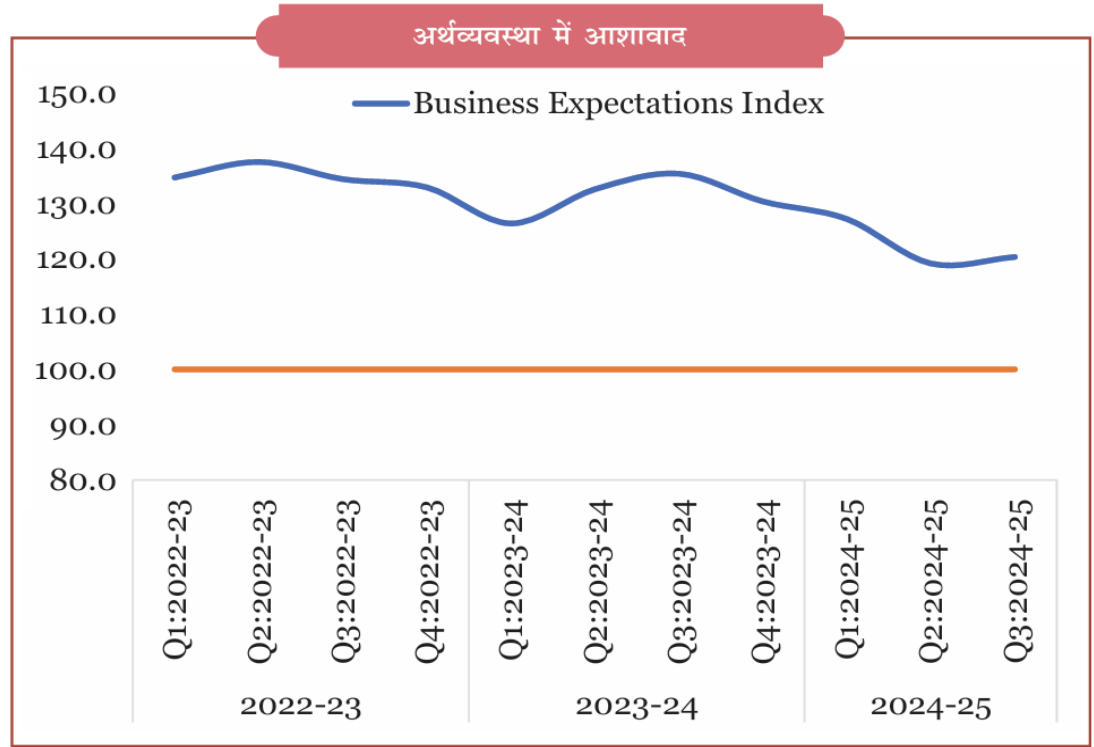
### हिन्दी माध्यम में 35+ चयन

|                 |                     |                 |                  |                  |                      |              |                     |                  |
|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 53<br>AIR       | 136<br>AIR          | 238<br>AIR      | 257<br>AIR       | 313<br>AIR       | 517<br>AIR           | 541<br>AIR   | 551<br>AIR          | 555<br>AIR       |
| मोहन लाल        | अर्पित कुमार        | विपिन दुबे      | मनीषा धार्व      | मयंक दुबे        | देवेश पाराशर         | शिवम अग्रवाल | मोहन मंगवा          | ईश्वर लाल गुर्जर |
| 556<br>AIR      | 563<br>AIR          | 596<br>AIR      | 616<br>AIR       | 619<br>AIR       | 633<br>AIR           | 642<br>AIR   | 697<br>AIR          | 747<br>AIR       |
| शुभम रघुवंशी    | अजित सिंह खदा       | के परीक्षित     | रवि गंगवार       | भानु प्रताप सिंह | मैत्रेय कुमार शुक्ला | शशांक चौहान  | प्रीतेस सिंह राजपूत | नीरज धाकड़       |
| 758<br>AIR      | 776<br>AIR          | 793<br>AIR      | 798<br>AIR       | 816<br>AIR       | 850<br>AIR           | 854<br>AIR   | 856<br>AIR          | 885<br>AIR       |
| सोफिया सिद्दीकी | पटेल दीप राजेशकुमार | अशोक सोनी       | विनोद कुमार मीणा | पवन कुमार        | भारती साहू           | सविन गुर्जर  | रजनीश पटेल          | पूरन प्रकाश      |
| 913<br>AIR      | 916<br>AIR          | 929<br>AIR      | 941<br>AIR       | 952<br>AIR       | 954<br>AIR           | 961<br>AIR   | 962<br>AIR          | 964<br>AIR       |
| पायल ग्वालवंशी  | नीलेश               | प्रेम सिंह मीणा | प्रदुम्न कुमार   | संदीप कुमार मीणा | कर्मवीर नरवदिया      | अभिषेक मीणा  | सविन कुमार          | नीरज सांगरा      |

## अध्याय 7: उद्योग: समग्र व्यवसायिक सुधार (Industry: All About Business Reforms)

### परिचय

- भारत के विनिर्माण क्षेत्रक में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार नीतियां और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान जैसी चुनौतियां निर्यात मांग को प्रभावित कर रही हैं। वित्त वर्ष 2025 में बिजली और विनिर्माण क्षेत्रक में 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
- वैश्विक विनिर्माण में चीन की 28.8% हिस्सेदारी की तुलना में भारत की हिस्सेदारी 2.8% है। इसमें भारत के पास विकास के महत्वपूर्ण अवसर हैं।
- सीमेंट, इस्पात, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रक विकास संचालक के रूप में उभरे हैं। साथ ही, PLI जैसी सरकारी योजनाएं विकास को गति दे रही हैं।



### अध्याय का प्रीकैप

#### आउटकमस

- भारत के विनिर्माण क्षेत्रक में बढ़ोतरी हो रही है। वित्त वर्ष 2025 में इसमें 6.2% की वृद्धि का अनुमान है।
- वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी 2.8% है। इसमें भी उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।
- भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार नीतियां और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान प्रमुख चुनौतियां बने हुए हैं।

#### उद्योग

- सीमेंट:** भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है।
- इस्पात उद्योग:** राष्ट्रीय इस्पात नीति और सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसी नीतियों से विकास को बढ़ावा मिला है।
- रसायन और पेट्रो रसायन उद्योग:** भारत अपनी पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स की 45% आवश्यकता के लिए आयात पर निर्भर है।
- पूंजीगत वस्तुएं:** सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी अंतराल को दूर करने के लिए स्मार्ट विनिर्माण और उद्योग 4.0 को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स:** भारत अपने 99% स्मार्टफोन का निर्माण करता है।
- वस्त्र उद्योग:** यह एक प्रमुख रोजगार क्षेत्रक है। यह विनिर्माण GVA में 11% का योगदान देता है।
- फार्मास्यूटिकल्स:** वित्त वर्ष 2024 में 4.17 लाख करोड़ रुपये के कारोबार के साथ भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है।

### नवाचार

- WIPO 2022 के अनुसार पेटेंट दाखिल करने में भारत विश्व स्तर पर छठे स्थान पर है।
- राष्ट्रीय IPR नीति 2016 और हाल ही में पेटेंट नियम में किए गए बदलावों ने इस प्रक्रिया को सरल बना दिया है।

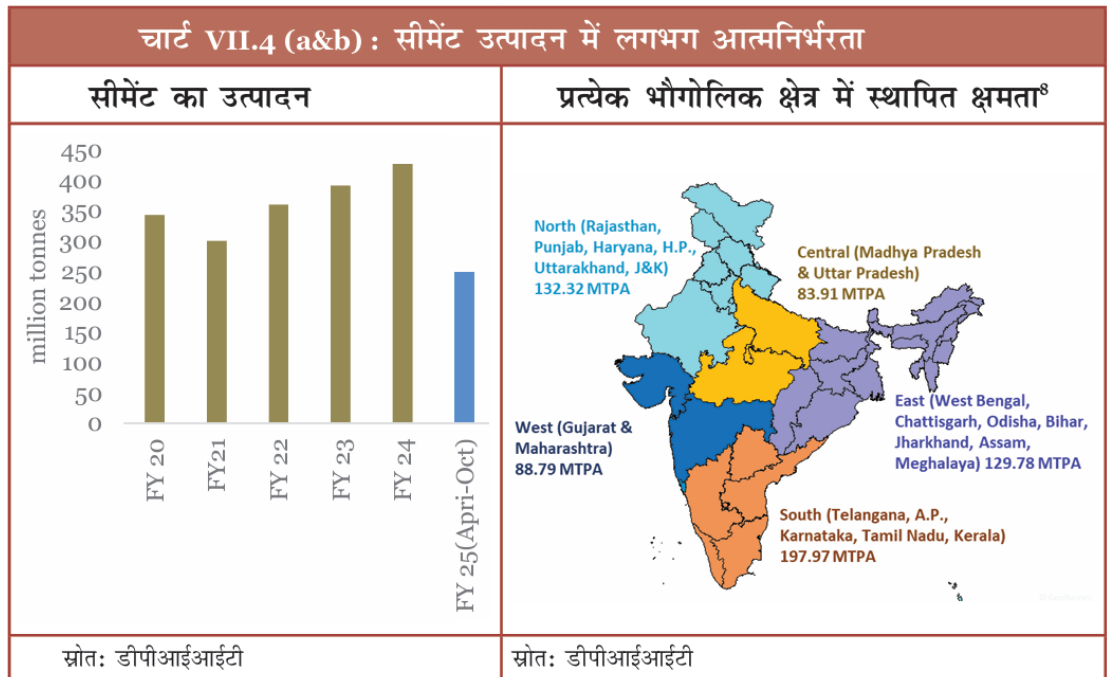
### औद्योगिक उत्पादन में राज्यवार पैटर्न

- औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताएं हैं। भारत के औद्योगिक मूल्य का 43% हिस्सा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से आता है।

## मुख्य निविष्ट उद्योग (Core Input Industries)

### सीमेंट

- भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। भारत में प्रति व्यक्ति सीमेंट खपत 290 किलोग्राम है, जबकि वैश्विक औसत 540 किलोग्राम है।
- भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अन्य राज्यों में केंद्रित है। इस उद्योग में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।
- राजमार्ग, रेलवे, आवास और ग्रामीण विकास जैसी सरकारी परियोजनाएं सीमेंट की मांग को बढ़ावा दे रही हैं।
- सीमेंट उद्योग का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है।



## PHILOSOPHY/ दर्शनशास्त्र

by

**ANOOP KUMAR SINGH**

### Classroom Features:

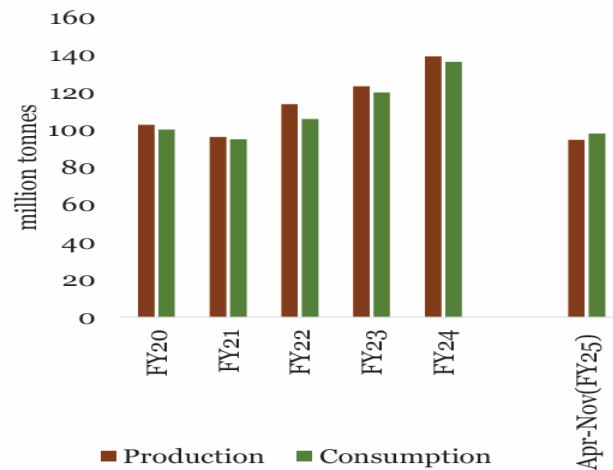
- Comprehensive, Intensive & Interactive Classroom Program
- Step by Step guidance to aspirants for understanding the concepts
- Develop Analytical, Logical & Rational Approach
- Effective Answer Writing
- Revision Classes
- Printed Notes
- All India Test Series Included

**Offline Classes @**
**JAIPUR | PUNE | AHMEDABAD**

## इस्पात

- भारत में स्टील क्षेत्रक में निरंतर वृद्धि, राष्ट्रीय इस्पात नीति और PLI योजनाओं जैसी सरकारी नीतियों तथा आवास और बुनियादी ढांचे के विकास आदि उपायों की वजह से संभव हुई है।
- सरकार की स्टील स्कैप रीसाइक्लिंग नीति कुशल रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देती है। इससे ऊर्जा का उपयोग 40%, पानी के उपयोग में 40% और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 58% तक की कमी आती है।
- स्टील स्कैप रीसाइक्लिंग नीति कुशल पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती है, और उच्च गुणवत्ता वाले स्कैप की उपलब्धता ग्रीन स्टील (पर्यावरण-अनुकूल इस्पात) की ओर बढ़ने और भविष्य में उद्योग की वृद्धि के लिए आवश्यक है।

इस्पात के उत्पादन और खपत में निरंतर वृद्धि



## रसायन और पेट्रोसायन उद्योग

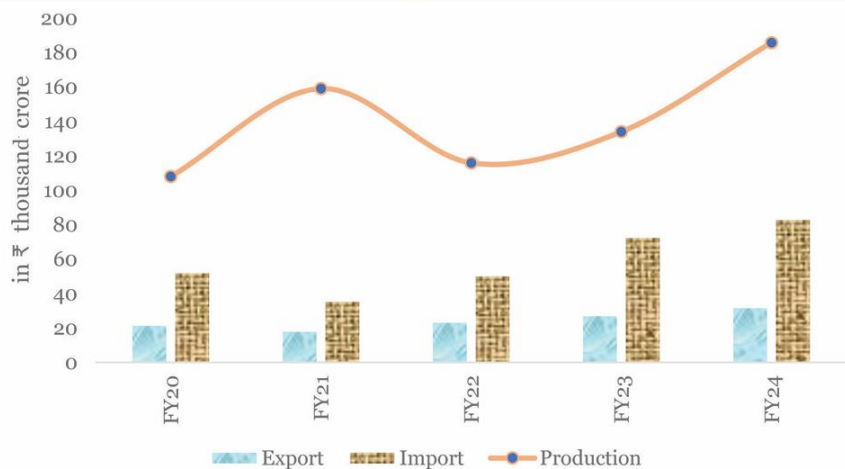
- वित्त वर्ष 2023 में विनिर्माण GVA<sup>32</sup> में रसायन क्षेत्रक का योगदान 9.5% था। भारत इन उत्पादों का शुद्ध आयातक है, जो पेट्रोकेमिकल मध्यवर्ती के लगभग 45% के लिए आयात पर निर्भर करता है।

## पूँजीगत वस्तुएं

यह क्षेत्रक प्रौद्योगिकी अंतराल के कारण उच्च-स्तरीय मशीनरी के आयात पर निर्भर है।

- इसे हल करने के लिए, सरकार ने पूँजीगत वस्तु क्षेत्रक की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए जारी योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है।
- इस दूसरे चरण में वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार, उन्नत उत्कृष्टता केंद्रों और सामान्य इंजीनियरिंग सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- सरकार स्मार्ट विनिर्माण और उद्योग 4.0 को भी बढ़ावा देते हुए, विभिन्न संस्थानों में

चार्ट VII.7: पूँजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ रहा है



स्रोत: उद्योग संघ जैसे आईएमटीएमए, टीएजीएमए, एएफटीपीआई, पीएमएमआई, पीपीएमआई, टीएमएमए और आईपीएमए

SMEs को नई तकनीकों को अपनाने में मदद करने के लिए SAMARTH/ समर्थ उद्योग केंद्र स्थापित कर रही है।

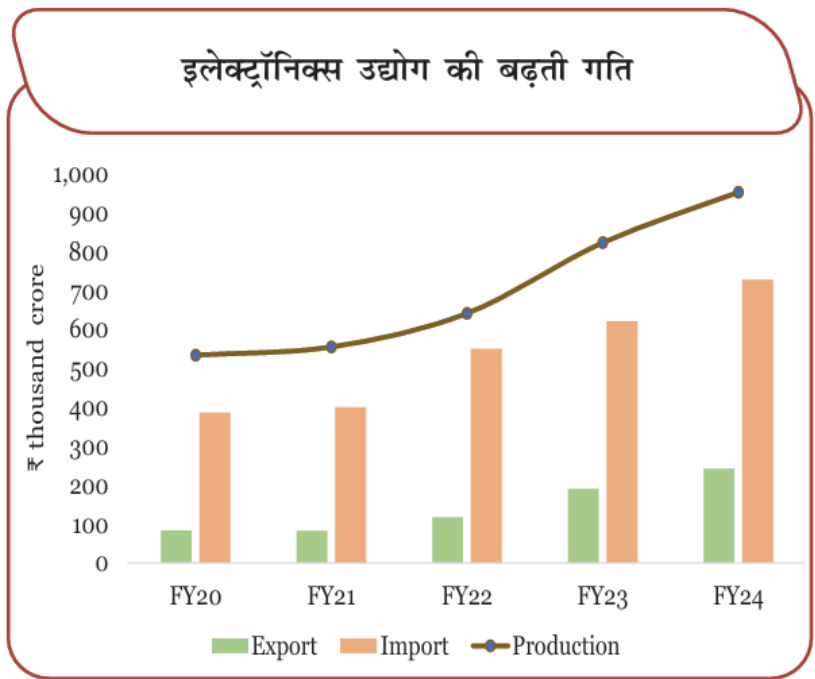
## ऑटोमोबाइल उद्योग

- भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। वित्त वर्ष 2024 में इसकी घरेलू बिक्री में 12.5% की वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र की संभावनाओं को पहचानते हुए, सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।

<sup>32</sup> Gross Value Added

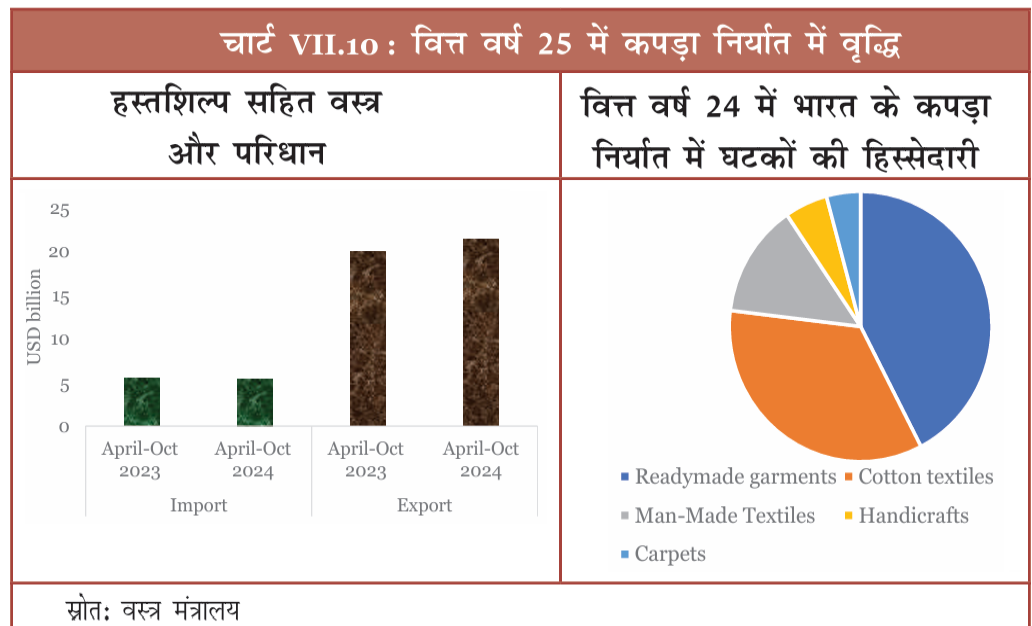
## इलेक्ट्रॉनिक्स

- भारत अब अपने **99% स्मार्टफोन** का उत्पादन घरेलू स्तर पर करता है, जिससे आयात पर निर्भरता में भारी कमी आई है। यह वृद्धि को बड़े घरेलू बाजार, कुशल प्रतिभा और कम लागत वाले श्रम से प्रेरित है। उदाहरण के लिए, PLI योजना ने मोबाइल फोन के आयात को वित्त वर्ष 2015 में बाजार मूल्य के 78% से घटाकर वित्त वर्ष 2023 में बाजार मूल्य के केवल 4% करने में मदद की।
- मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया** जैसे कार्यक्रमों ने बेहतर बुनियादी ढांचे, व्यापार करने में आसानी और कई प्रोत्साहनों के साथ घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया है। इसने विदेशी निवेश भी आकर्षित किया है।
- हालांकि, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार की वैश्विक हिस्सेदारी केवल 4% है। यह मुख्य रूप से असेंबलिंग पर केंद्रित है। इसमें उपकरणों के डिजाइन और घटकों के निर्माण में सीमित प्रगति हुई है।



## कपड़ा उद्योग

- भारत में कपड़ा उद्योग एक प्रमुख रोजगार प्रदाता है। यह भारत के विनिर्माण GVA में लगभग 11% का योगदान देता है।
- भारत **जूट का एक शीर्ष उत्पादक** है तथा कपास, रेशम और मानव निर्मित रेशों में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है।
- भारत कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। इसकी वैश्विक व्यापार में 4% हिस्सेदारी है।
- वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में हस्तशिल्प सहित कपड़ा और परिधान की हिस्सेदारी लगभग 8% रही।
- भारत सूती वस्त्रों से परे अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने का प्रयास कर रहा है। जैसे-जैसे **मानव निर्मित रेशों (MMF)** की वैश्विक मांग बढ़ती है, भारत सूती वस्त्रों के साथ-साथ अपनी MMF हिस्सेदारी को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।



- भारत का **तकनीकी वस्त्र क्षेत्र** तेजी से बढ़ रहा है, जो विश्व स्तर पर पांचवें स्थान पर है। इसमें PLI योजना और 68 उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के माध्यम से सरकार समर्थन कर रही है।

## चुनौतियां:

- MSME क्षेत्र का वर्चस्व उत्पादन का पैमाना और दक्षता सीमित करता है; इसकी खंडित प्रकृति लॉजिस्टिक को बढ़ाती है; कपास पर निर्भरता प्रतिस्पर्धा को सीमित करती है; सीमित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश; तकनीकी उन्नति की कमी; आयातित मशीनों पर निर्भरता; महत्वपूर्ण रूप से कौशल की कमी उत्पादकता और नवाचार में बाधा डालती है।

## फार्मास्यूटिकल्स

- भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग, मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल उद्योग है।
- सरकारी पहलें जैसे कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) और फार्मास्यूटिकल उद्योग को मजबूत करने की योजना (SPI) का उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और की-स्टार्टिंग मटेरियल्स (KSMs), ड्रग इंटरमीडिएट्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स (APIs) के आयात पर निर्भरता को कम करना है।
- भारत के चिकित्सा उपकरणों की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी 1.5% है। यह एशिया में जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद चौथे स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर, भारत शीर्ष 20 चिकित्सा उपकरण बाजारों में से एक है।
- भारत अपनी पहली स्वदेशी रूप से विकसित CAR-T सेल थेरेपी की स्वीकृति के साथ सेल और जीन थेरेपी में प्रगति कर रहा है।
- नई दवाओं तक पहुंच में तेजी लाने के लिए, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने अब उन दवाओं के लिए स्थानीय क्लिनिकल ट्रायल में छूट की अनुमति दी है जो पहले से ही अमेरिका, यू.के., जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और EU में स्वीकृत हैं।

## बढ़ते नवाचार

- वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग 2015 के 81वें स्थान से बढ़कर 2024 में 39वें स्थान पर पहुंच गई है।
- भारत में एक मजबूत बौद्धिक संपदा (IP) इकोसिस्टम है, जो पेटेंट दाखिल करने के लिए वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर है (WIPO 2022)।
- पेटेंट के लिए प्रमुख क्षेत्रों में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और बायोमेडिकल, तथा संचार शामिल हैं।
- राष्ट्रीय IPR नीति 2016 के बाद से, भारत ने पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है। इसके अलावा, 2024 के पेटेंट संशोधन नियमों ने पेटेंट फाइलिंग और रखरखाव प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया है।
- प्रमुख हस्तक्षेप:
  - स्टार्ट-अप्स, SMEs, महिलाओं और शैक्षणिक संस्थानों के लिए पेटेंट परीक्षण में तेजी।
  - स्टार्ट-अप्स और MSMEs के लिए शुल्क में कमी।
  - दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटलीकरण, AI/ML खोज प्रणाली और आभासी रूप में सुनवाई।

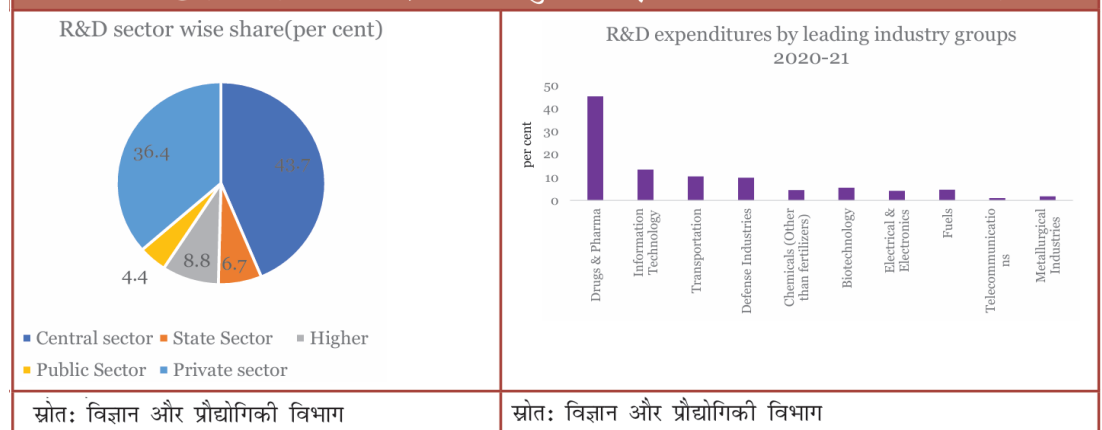
IP संरक्षण योजना और मार्गदर्शन के लिए IP सारथी चैटबॉट के माध्यम से स्टार्ट-अप्स को सहायता प्रदान करना।

## चुनौतियां:

- भारत का अनुसंधान एवं विकास सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 0.64% है। यह अधिकतर सरकारी वित्त-पोषण पर निर्भर

है। यह चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुसंधान एवं विकास पर किए जाने वाले खर्च से बहुत कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, गूगल और अमेजन जैसी कंपनियां कुल अनुसंधान एवं विकास का 70% वित्त पोषित करती हैं।

चार्ट VII.13 (a & b) : निजी क्षेत्र का अनुसंधान एवं विकास व्यय कम और केंद्रित है



- भारत में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास कम है तथा यह फार्मास्यूटिकल्स, IT, परिवहन, रक्षा और जैव प्रौद्योगिकी जैसे कुछ क्षेत्रों तक ही केंद्रित है।
- सार्वजनिक क्षेत्र का अनुसंधान एवं विकास मुख्यतः रक्षा, ईंधन और धातु विज्ञान पर केंद्रित है।
- भारत के अनुसंधान एवं विकास में पारंपरिक रूप से व्यावहारिक शोध की अपेक्षा बुनियादी अनुसंधान पर अधिक जोर दिया जाता है, जिससे निजी निवेश सीमित हो जाता है।

## सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs)

भारत के विकास में **MSME क्षेत्र** महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्यमिता को बढ़ावा देता है और कम पूंजी लागत पर रोजगार के अवसर पैदा करता है। नवंबर 2024 तक, MSMEs में **23.24 करोड़ लोग** कार्यरत हैं, जो कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है।

### प्रमुख हस्तक्षेप:

- **उद्यम पंजीकरण पोर्टल:** स्व-घोषणा प्रणाली के साथ MSMEs के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया। उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2.39 करोड़ से अधिक अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक रूप दिया गया।
- **क्रेडिट गारंटी योजना का पुनर्गठन:** MSEs के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में 2 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण सुविधा के लिए 9,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें ऋण सीमा में वृद्धि और गारंटी शुल्क में कमी की गई है।
- **TReDS प्लेटफॉर्म:** सरकारी विभागों और बड़ी कंपनियों जैसे खरीदारों द्वारा MSMEs को समय पर भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।
- **आत्मनिर्भर भारत कोष (SRI फंड):** संभावित विस्तार वाले MSMEs को इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ लॉन्च किया गया।
- **MSME समाधान और चैंपियंस/ CHAMPIONS (उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं का सृजन और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग) पोर्टल:** यह MSEs को शिकायत दर्ज करने तथा सरकारी संस्थाओं और बड़े खरीदारों से प्राप्त भुगतान पर नज़र रखने के लिए एक मंच प्रदान करता है। साथ ही, विलंबित भुगतान संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करता है।
- **MSE-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP):** इसके तहत प्रौद्योगिकी, कौशल और उत्पादकता में सुधार के लिए सामान्य सुविधा केंद्रों (CFCs) के माध्यम से देश भर में MSME क्लस्टर विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

## औद्योगिक उत्पादन में राज्यवार पैटर्न

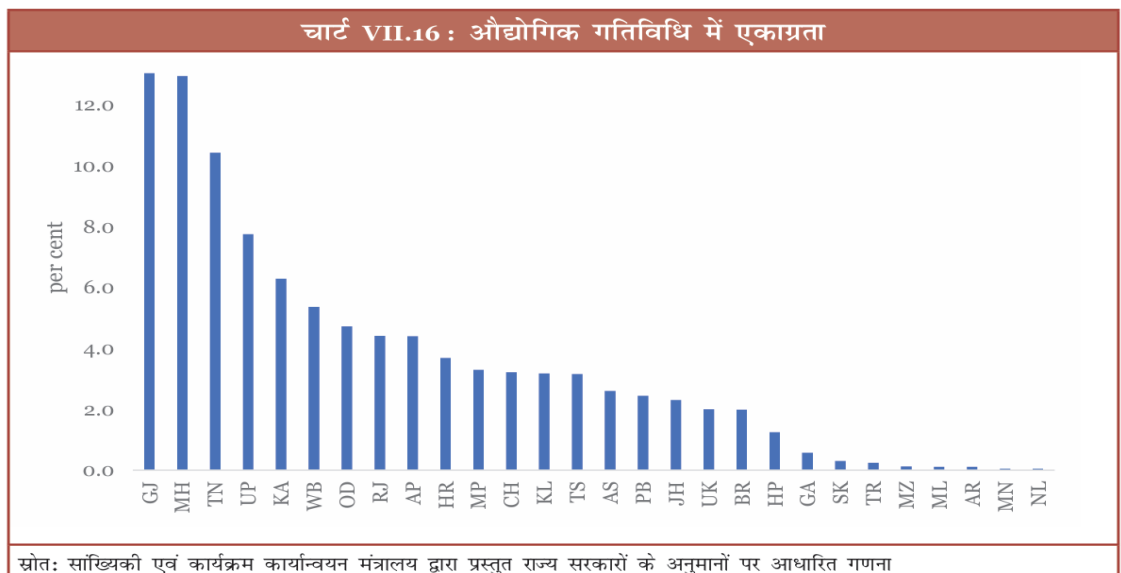
- भारतीय राज्यों में विकास संबंधी काफी असमानताएं हैं। कई राज्य कृषि, विनिर्माण, पर्यटन और वित्त जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

- उदाहरण के लिए, भारत के औद्योगिक मूल्य में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का योगदान 43% है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य केवल 0.7% का योगदान देते हैं।

- मुख्य बिंदु:

- औद्योगिक निर्भरता: उच्च औद्योगिक

हिस्सेदारी का मतलब हमेशा उच्च आय नहीं होता। उदाहरण के लिए- गुजरात और हिमाचल प्रदेश ने औद्योगिक निर्भरता का उपयोग कर अधिक आय प्राप्त की है, जबकि कुछ अन्य राज्यों को इसका लाभ नहीं मिला।





- **खनन क्षेत्र:** औद्योगिक उत्पादन में खनन की हिस्सेदारी 8% है। पांच राज्य (असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा) खनन GSVA में 60% का योगदान करते हैं।
- **कारखाना और लघु उद्यम:** तमिलनाडु में कारखानों का संकेन्द्रण सबसे अधिक है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में गैर-निगमित विनिर्माण इकाइयां अधिक हैं।
- **राज्य-स्तरीय नीतियां:** राज्य सुधार, बुनियादी ढांचा और मानव विकास औद्योगिक विकास को गति देते हैं। जिन राज्यों ने मजबूत सुधार लागू किए हैं, वहां प्रगति देखी गई है।
- **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस:** बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) राज्यों को चार समूहों में वर्गीकृत करता है: शीर्ष उपलब्धि प्राप्त करने वाले, सफल होने वाले, महत्वाकांक्षी और उभरते हुए पारिस्थितिकी तंत्र।

## आगे की राह और दृष्टिकोण

- पिछले दशक में रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और मशीनरी जैसे उद्योगों में वृद्धि हुई है। हालांकि भारत अभी भी कोयला, पूंजीगत वस्तुओं और रसायनों के लिए आयात पर निर्भर है।
- औद्योगिक विकास के लिए विनियमन में ढील, अधिक अनुसंधान एवं विकास, नवाचार और कुशल कार्यबल की आवश्यकता है। कपड़ा और MSMEs जैसे क्षेत्रों को वित्त, अनुपालन और बाजार पहुंच में सहायता की आवश्यकता है।
- राज्यवार औद्योगिक मजबूती और कमजोरियां अलग-अलग हैं, जिसमें व्यावसायिक विनियमन औद्योगिक प्रगति को प्रभावित करते हैं। इसलिए, **जमीनी स्तर पर सुधार** महत्वपूर्ण हैं।
- इस वैश्विक परिवेश में, भारत के विनिर्माण लक्ष्यों को हासिल करने में सरकारों, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों और वित्तीय हितधारकों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होगी।

## बजट में क्या कहा गया है?

- **नवाचार में निवेश:**
  - **अनुसंधान, विकास और नवाचार:** निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
  - **डीप टेक फंड ऑफ फंड्स:** अगली पीढ़ी के स्टार्ट-अप्स को उत्प्रेरित करने के लिए।
- MSMEs के लिए गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में वृद्धि।

## शब्दावली

| शब्द/ पद                     | अर्थ                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आपूर्ति शृंखला व्यवधान       | वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में अक्सर बाहरी कारकों के कारण होने वाली रुकावटें, जैसे महामारी, प्राकृतिक आपदाएं या राजनीतिक घटनाएं।                                    |
| कोर इनपुट उद्योग             | समग्र अर्थव्यवस्था के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र, जैसे सीमेंट, इस्पात, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स। ये विनिर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। |
| स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग      | विनिर्माण प्रक्रिया में स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग दक्षता में सुधार और लागत में कमी लाने के लिए किया जाता है। |
| प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) | इसका तात्पर्य किसी विदेशी कंपनी या परियोजना में किसी अन्य देश के निवेशक, कंपनी या सरकार द्वारा की गई स्वामित्व हिस्सेदारी से है।                                     |

**मानव निर्मित फाइबर (MMF)**

ये मनुष्य द्वारा बनाए गए फाइबर हैं। MMF कार्बनिक या अकार्बनिक हो सकते हैं। कार्बनिक MMF को लकड़ी जैसी प्राकृतिक सामग्री से बनाया जा सकता है, या इन्हें सिंथेटिक पॉलीमर से बनाया जा सकता है।

**अपने सीखने के कौशल का परीक्षण कीजिए****MCQs****1. भारत के सीमेंट उद्योग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है।
  2. भारत में प्रति व्यक्ति सीमेंट की खपत वैश्विक औसत से अधिक है।
  3. राजमार्ग और रेलवे जैसी सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भारत में सीमेंट की मांग को बढ़ा रही हैं।
- उपर्युक्त कथनों में से कितने सही **नहीं** हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) उपर्युक्त सभी
- (d) कोई नहीं

**2. भारत के इस्पात उद्योग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. भारत में इस्पात की मांग राष्ट्रीय इस्पात नीति और PLI योजनाओं जैसी सरकारी नीतियों से प्रेरित है।
  2. स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति का उद्देश्य हरित इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देना है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

**3. भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. भारत अपने 99% स्मार्टफोन का निर्माण करता है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होती है।
  2. भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 10% हिस्सेदारी रखता है।
  3. यह क्षेत्र मुख्य रूप से असेंबलिंग पर ध्यान केंद्रित करता है और इसने डिजाइन और घटकों के निर्माण में सीमित प्रगति की है।
- उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) उपर्युक्त सभी
- (d) कोई नहीं

4. भारत के कपड़ा उद्योग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत जूट, कपास और रेशम का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है।
2. भारत के विनिर्माण GVA में भारत के कपड़ा उद्योग की हिस्सेदारी 11% है।
3. वैश्विक स्तर पर भारत के कपड़ा निर्यात बाजार की हिस्सेदारी 10% से अधिक है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) उपर्युक्त सभी
- (d) कोई नहीं

5. भारत के राज्यवार औद्योगिक पैटर्न के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु कुल मिलाकर भारत के औद्योगिक मूल्य में 43% का योगदान करते हैं।
2. भारत के पूर्वोत्तर राज्य भारत के औद्योगिक उत्पादन में 5% का योगदान करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न

1. सीमेंट, स्टील और फार्मास्यूटिकल्स जैसे प्रमुख उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के विनिर्माण क्षेत्रक के लिए चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा कीजिए। PLI योजना जैसी सरकारी पहलें इस क्षेत्रक के विकास में कैसे योगदान दे सकती है?
2. भारत के विनिर्माण क्षेत्रक में वित्त वर्ष 2025 में मजबूत वृद्धि होने की संभावना है। इस वृद्धि को आगे बढ़ाने में बिजली, निर्माण और तकनीकी प्रगति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

**LIVE/ONLINE**  
Classes Available  
www.visionias.in



# Foundation Course

## GENERAL STUDIES

### PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

**DELHI: 4 MAR, 2 PM | 11 MAR, 5 PM | 13 MAR, 11 AM | 18 MAR, 8 AM**

**GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 25 MAR, 8 AM**

**हिन्दी माध्यम DELHI: 25 फरवरी, 8 AM | 25 मार्च, 2 PM**

**AHMEDABAD: 4 JAN**

**BENGALURU: 30 MAR**

**BHOPAL: 25 FEB**

**CHANDIGARH: 18 JUN**

**HYDERABAD: 3 MAR**

**JAIPUR: 5 APR**

**JODHPUR: 17 MAR**

**LUCKNOW: 9 APR**

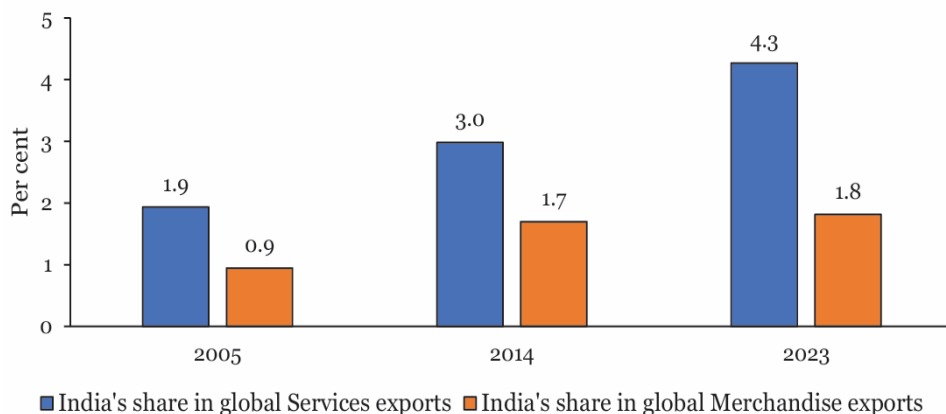
**PUNE: 4 MAR**

## अध्याय 8: सेवा: दिग्गजों के समक्ष नई चुनौतियां (Services: New Challenges for the Old War Horse)

### परिचय

- सेवा क्षेत्रक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 62% का योगदान देता है, तथा **चीन, थाईलैंड और भारत** जैसे मध्यम आय वाले देशों में संवृद्धि को गति प्रदान करता है।
- भू-राजनीतिक संकटों, संरक्षणवाद, युद्धों और जलवायु चुनौतियों के कारण **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएँ** बड़े व्यवधानों का सामना कर रही हैं। इससे वैश्विक सेवा क्षेत्रक के समक्ष जोखिम पैदा हो रहा है।
- विनिर्माण और सेवाएँ परस्पर अधिक जुड़ती जा रही हैं। **डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** जैसी तकनीकें सेवा क्षेत्रक की मांग को नया रूप दे रही हैं।
- पिछले दो दशकों में वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है, जिससे व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में उतार-चढ़ाव से निपटने में मदद मिली है।
- भारत 4.3% हिस्सेदारी के साथ वैश्विक सेवा निर्णय में सातवें स्थान पर है। वैश्विक सेवा निर्यात में सर्वोच्च रैंकिंग वाले देश हैं; संयुक्त राज्य अमेरिका (13%), यूनाइटेड किंगडम (7.4%), जर्मनी (5.5%) तथा आयरलैंड, चीन और फ्रांस (प्रत्येक की 5% हिस्सेदारी)।

चार्ट VIII.2: वैश्विक सेवाओं और व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी



स्रोत: यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट

### अध्याय का प्रीकैप

#### आउटकम

- वित्त वर्ष 2014 में जीवीए में सेवा क्षेत्रक का योगदान 50.6% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 55.3% हो गया।
- वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 4.3% है, और इस मामले में दुनिया भर में भारत 7वें स्थान पर है।
- सेवा क्षेत्रक अब भारत के लगभग 30% कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है।

#### मुख्य क्षेत्रकों का प्रदर्शन

- रेलवे:** वित्त वर्ष 24 में यात्री यातायात में 8% की वृद्धि दर्ज की गई।
- सड़क परिवहन:** परिवहन क्षेत्रक के GVA में 78% की हिस्सेदारी है।
- विमानन:** भारत वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक संवृद्धि दर्ज करने वाला विमानन बाजार है।
- पत्तन (पोर्ट), जलमार्ग और पोत-परिवहन:** मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के माध्यम से समुद्री क्षेत्रक के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- पर्यटन और आतिथ्य:** देश के सकल घरेलू उत्पाद में कोविड महामारी से पहले के 5% के योगदान को फिर से हासिल करना।
- दूरसंचार:** 5G के तेजी से विस्तार के साथ दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार बन गया।

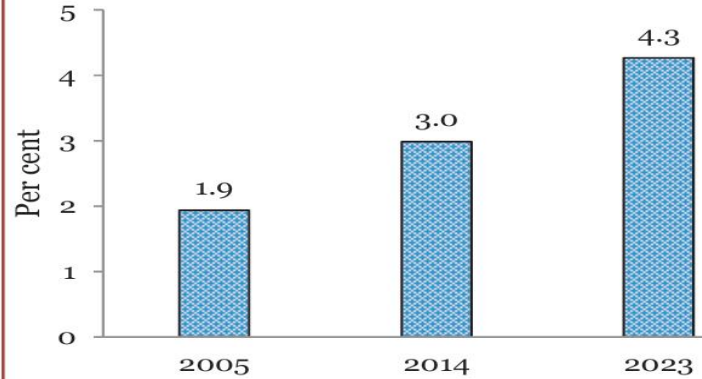
#### राज्यवार विश्लेषण

- कर्नाटक और महाराष्ट्र संयुक्त रूप से भारत के कुल सेवा क्षेत्रक GVA (सकल राज्य मूल्य वर्धन) में 25% से अधिक का योगदान करते हैं, जबकि 19 अन्य राज्य केवल 25% का योगदान करते हैं।

## भारत में सेवा क्षेत्रक का प्रदर्शन

- कुल GVA में सेवा क्षेत्रक का योगदान वित्त वर्ष 14 के 50.6 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 55.3 प्रतिशत (पहला अग्रिम अनुमान) हो गया।
- यह क्षेत्रक लगभग 30 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार भी प्रदान करता है।
- यह विनिर्माण के सेवाकरण के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देता है, अर्थात् विनिर्माण उत्पादन और उत्पादन के बाद मूल्य संवर्धन में सेवाओं के उपयोग में वृद्धि करता है।

वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी



## सेवाओं संबंधी व्यापार

- भारत से सेवा निर्यात में कंप्यूटर और व्यावसायिक सेवाओं का लगभग 70% योगदान है। वित्त वर्ष 25 (अप्रैल-सितंबर) में सेवा निर्यात संवृद्धि दर के मामले में भारत शीर्ष पांच देशों में शामिल था।
- सेवा निर्यात के लिए कार्य-नीति: सेवाओं को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से प्रत्येक श्रेणी की अपनी नीतिगत सिफारिशें शामिल हैं। ये चार श्रेणियां हैं; बचाव (Defend), तेजी लाना (Accelerate), परिवर्तन (Transform) और अप्रयुक्त (Untapped)।

चार्ट VIII.9: कार्यनीतिक सिफारिशों का सारांश

### बचाव करना

(वैश्विक क्षेत्रीय उपस्थिति को बनाए रखना और बाजार विकास को बढ़ाना)

#### कंप्यूटर एवं सूचना सेवाएँ

(फोकस क्षेत्र: अनुसंधान एवं विकास, नवाचार, कोशल उन्नयन, वैश्विक साझेदारियाँ)

#### पेशेवर, वैज्ञानिक और व्यापारिक सेवाएँ

(फोकस क्षेत्र: अनुसंधान एवं विकास, परामर्श, इंजीनियरिंग, वैश्विक बाजार पहुंच)

### तेजी लाना

(वैश्विक विकास को गति देने के लिए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना)

#### परिवहन

(फोकस क्षेत्र: स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, अवसरचना, क्षेत्रीय विस्तार)

#### व्यापार और मरम्मत

(फोकस क्षेत्र: ई-कॉमर्स, स्वचालन, निर्यात बाजार विकास)

#### शिक्षा

(फोकस क्षेत्र: ऑनलाइन शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार)

#### वित्तीय सेवाएँ

(फोकस क्षेत्र: फिनटेक, डिजिटल सेवाएँ, वैश्विक बाजार पहुंच)

### परिवर्तन

(उत्पादकता, नवाचार और वैश्विक पहुंच को बढ़ावा देना)

#### यात्रा

(फोकस क्षेत्र: प्रीमियम पर्यटन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्थिरता)

#### स्वास्थ्य

(फोकस क्षेत्र: टेलीमेडिसिन, चिकित्सा पर्यटन, स्वास्थ्य तकनीक नवाचार)

#### वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवाएँ

(फोकस क्षेत्र: कल्याण पर्यटन, डिजिटल सामग्री, फिटनेस)

### अप्रयुक्त

(बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना, दक्षता और स्थिरता सुनिश्चित करना)

#### बीमा और पेंशन सेवाएँ

(फोकस क्षेत्र: डिजिटल बीमा, ग्राहक-केंद्रित उत्पाद)

#### ऑडियो-विजुअल और संबंधित सेवाएँ

(फोकस क्षेत्र: विशिष्ट सामग्री, वैश्विक प्लेटफॉर्म, स्थानीयकरण)

#### दूरसंचार

(फोकस क्षेत्र: 5 जी, स्मार्ट सिटीज, अवसरचना, निर्यात)

#### डाक एवं कूरियर

(फोकस क्षेत्र: डिजिटलीकरण, दक्षता, एकीकरण)

स्रोत: पंत. एस. शर्मा. पी. गुप्ता. ए और अग्रवाल पी. (2024, दिसंबर)। संभावित

सेवा उप-क्षेत्रों की पहचान: जीवीए, निर्यात और रोजगार डेटा से अंतर्दृष्टि। [वर्किंग पेपर] नीति आयोग. <https://tinyurl.com/vxbbs5vj>

## अलग-अलग सेवा क्षेत्रों में प्रगति

### रेलवे

- भारतीय रेलवे वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 24 में यात्री यातायात में 8% और माल ढुलाई राजस्व में 5.2% की वृद्धि दर्ज की है।
- यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार 7,325 स्टेशनों पर सुविधाओं को अपग्रेड कर रही है, जिसमें ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड, वाई-फाई और डिजिटल घड़ियां लगाना शामिल है।
- आरक्षित टिकट बुकिंग में ई-टिकटिंग का प्रतिशत 86 प्रतिशत तक पहुंच गई है जबकि अनारक्षित टिकटों में ई-टिकटिंग 33% तक पहुंच गई है।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, भारत की विरासत को प्रदर्शित करने वाली भारत गौरव ट्रेनों ने विभिन्न पर्यटन स्थलों पर 1,91,033 पर्यटकों को ले जाने के लिए कुल 325 यात्राएं संचालित की हैं।

### सड़क परिवहन

- परिवहन सेवाओं में सड़क परिवहन सबसे अधिक GVA उत्पन्न करता है (कुल GVA का 78%)।
- सरकार ने FASTag के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन को अपनाया है, जिससे टोल प्लाजा पर औसत प्रतीक्षा समय 734 सेकंड से घटकर 47 सेकंड रहा गया है।
- सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक कार्यनीति शुरू की है, जिसमें सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना भी शामिल है।
- ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र तथा राज्य/जिला स्तर पर ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरकार अभय परियोजना के साथ ट्रक चालकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने तथा चालकों के लिए नेत्र परीक्षण और हेल्थ चेकअप प्रदान करने जैसी पहलों के माध्यम से सड़क सुरक्षा की दिशा में भी कार्य कर रही है।

### विमानन

- भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला विमानन बाजार है। हवाई यातायात में पर्याप्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, भारतीय एयरलाइनों ने वैश्विक स्तर पर विमानों के लिए सबसे बड़े ऑर्डर दिए हैं।
- सरकार मूल उपकरण विनिर्माताओं को भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने और इस क्षेत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए प्रोत्साहित करके रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) उद्योग को बढ़ावा दे रही है।
- ड्रोन, लीजिंग और MRO जैसे नए क्षेत्रक भी वृद्धि कर रहे हैं। अक्टूबर 2024 तक, भारत में 140 ड्रोन प्रशिक्षण संगठन, 26,000 से अधिक पंजीकृत ड्रोन और PLI योजना के तहत 60.6 करोड़ वितरित किए गए थे।
- पीएम गति शक्ति पहल का उद्देश्य पूरे देश में एक निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी नेटवर्क तैयार करना है। इस पहल के तहत, विमानन क्षेत्रक को रेलवे, सड़क और जलमार्ग जैसे परिवहन के अन्य साधनों के साथ एकीकृत किया जा रहा है।

# ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

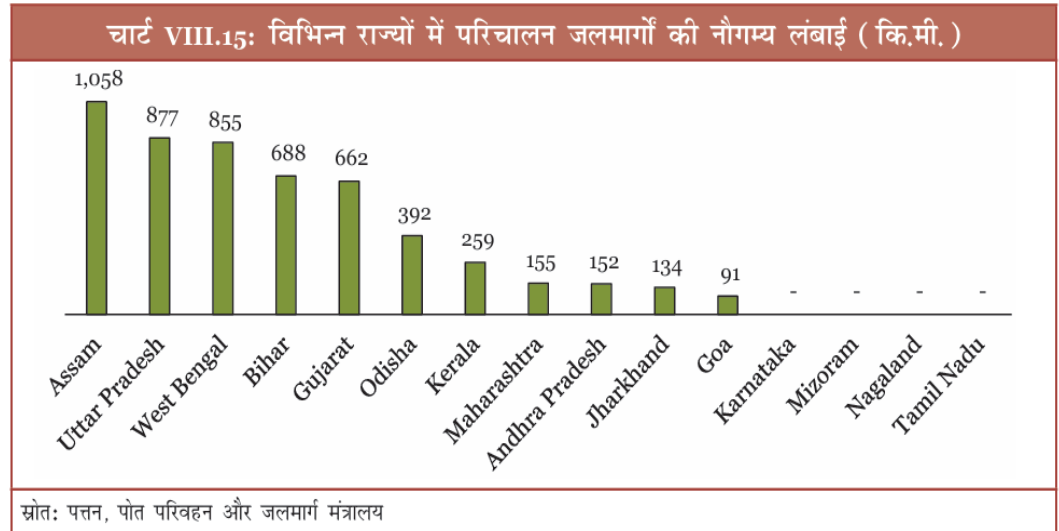
देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं  
✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र

|      |                           |                          |
|------|---------------------------|--------------------------|
| 2025 | ENGLISH MEDIUM<br>9 MARCH | हिन्दी माध्यम<br>9 मार्च |
| 2026 | ENGLISH MEDIUM<br>9 MARCH | हिन्दी माध्यम<br>9 मार्च |

## पत्तन, जलमार्ग और पोत परिवहन: अवसरों की अधिकता

- भारत के प्रमुख पत्तन बढ़ती व्यापार मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं।
- भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक भारतीय जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष पांच स्थान दिलाने के उद्देश्य से **मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन वर्ष 2047** का शुभारंभ किया है।

- अंतर्देशीय जल परिवहन में 14,850 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों के साथ महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता है। अक्टूबर 2024 तक, भारत में 4,800 किलोमीटर से अधिक लंबे 26 चालू जलमार्ग होंगे। भारत में जलमार्गों की कुल नौगम्य लंबाई लगभग 14,850



किमी है। अक्टूबर 2024 तक, देश में 4,800 किलोमीटर से अधिक के 26 जलमार्ग चालू हैं। इसका मतलब है कि पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है।

- सरकार राष्ट्रीय जलमार्गों पर **नदी कूज पर्यटन** को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास कर रही है। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में राष्ट्रीय जलमार्गों पर यात्रियों की आवाजाही 3-36 करोड़ से अधिक थी।

## पर्यटन और आतिथ्य

- वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का योगदान कोविड महामारी से पहले के स्तर 5 प्रतिशत पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2023 में पर्यटन क्षेत्र में 7.6 करोड़ नौकरियां सृजित हुईं।
- भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन (ITA) 2023 में महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच गया है। वर्ष 2023 में विश्व में कुल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में भारत का 1.45 प्रतिशत हिस्सा था।
- पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। **विश्व में पर्यटन से आय प्राप्तियों का 1.8 प्रतिशत भारत को प्राप्त हुआ और वर्ष 2023 के दौरान विश्व पर्यटन प्राप्तियों में दुनिया भर में 14 वें स्थान पर पहुंच गया।**

## रियल एस्टेट: अर्थव्यवस्था का निर्माण

- भारत के रियल एस्टेट बाजार में आर्थिक स्थिरता और सकारात्मक बाजार परिस्थितियों के कारण कार्यालय की मांग के साथ-साथ आवासीय बिक्री में भी मजबूत प्रदर्शन देखा गया।
- 2024 के वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत 89 देशों में से **31वें स्थान पर रहा**। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, सड़क नेटवर्क में वृद्धि और कनेक्टिविटी में सुधार के कारण रियल एस्टेट की मांग न केवल टियर 1 और टियर 2 शहरों में बल्कि पूरे देश में उभर रही है।
- रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम ने रियल एस्टेट क्षेत्र की पारदर्शिता और परियोजना वितरण में सुधार किया है।
- जीएसटी ने राज्यों में एक एकीकृत कर प्रणाली लागू करके रियल एस्टेट लेनदेन में कराधान संरचना को सरल बनाने में मदद की है।
- रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs) ने वाणिज्यिक रियल एस्टेट बाजार में नकदी बढ़ाने और संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करने में सहायता की है।
- अनुमोदन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म ने देरी को कम किया है और पारदर्शिता बढ़ाई है। बिलडिंग प्लान को प्रस्तुत करने और मंजूरी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन से देरी में कमी आई है और प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आई है।

## सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाएँ

- भारतीय IT/ITeS उद्योग की वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्थिति है और निर्यात बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
- घरेलू बाजार में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 24 में 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा। इस क्षेत्रक ने वित्त वर्ष 2024 में 60,000 कर्मचारियों को जोड़कर अपने कुल कार्यबल को 5.43 मिलियन तक पहुंचा दिया।
- एंजल टैक्स (स्टार्टअप में निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर) को समाप्त करने से देश की वैश्विक इनोवेशन और उद्यमशीलता प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- डेटा सेंटर निर्यात और ई-कॉमर्स के लिए कर राहत जैसे कुछ अन्य सुधारों का उद्देश्य आईटी सेवाओं और वैश्विक व्यापार को समर्थन देना है।

## वैश्विक क्षमता केंद्र {ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स: (GCCs)<sup>33</sup>}

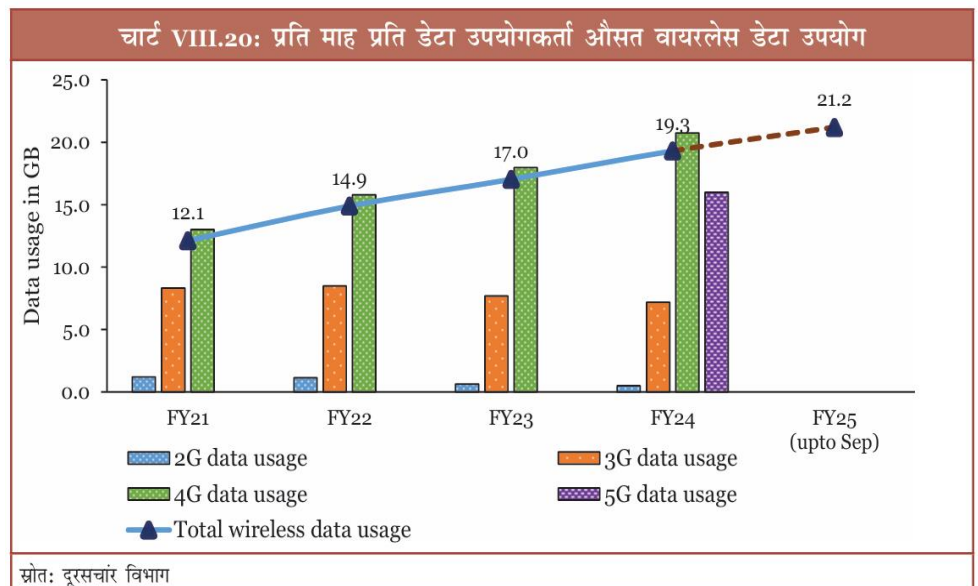
- ये अपनी तकनीकी गतिविधियों को भारत में स्थापित करके तकनीकी परिदृश्य को बदल रहे हैं।
- विशेष रूप से एयरोस्पेस, रक्षा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रकों में इनकी भूमिका स्पष्ट रूप से दिख रही है, जहाँ कंपनियाँ अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म, उत्पाद और तकनीक विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (AI & ML) को अपनाने के साथ-साथ AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, भारत की मजबूत मध्य-प्रबंधन प्रतिभा का लाभ उठाकर वैश्विक क्षमता केंद्र इस क्षेत्र को बढ़ा रही है।

## भारतीय सेवा क्षेत्रक में AI का उपयोग

- **वित्त:** SBI अपने SBI इंटेलिजेंट असिस्टेंट (SIA) चैटबॉट का उपयोग ग्राहकों को सहायता प्रदान करने के लिए कर रहा है। इसी तरह बैंक धोखाधड़ी का पता लगाने और जोखिम प्रबंधन के लिए भी AI का उपयोग कर रहा है।
- **दूरसंचार:** AI ग्राहक सहायता, नेटवर्क प्रबंधन और रखरखाव में सहायता करता है। दूरसंचार कंपनियाँ नेटवर्क को प्रबंधित करने और समस्याओं का पहले से पता लगाने के लिए AI-संचालित प्लेटफॉर्म का उपयोग करती हैं।
- **रिटेल और ई-कॉमर्स:** AI व्यक्तिगत मार्केटिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करता है।
- **परिवहन और लॉजिस्टिक्स:** AI ऑपरेशन, रूट प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स वितरण में सटीकता को बढ़ाता है। वेयरहाउस (फुलफिलमेंट सेंटर) में AI-संचालित सिस्टम प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हैं और लागत कम करते हैं।

## दूरसंचार

- भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। भारत में 1.18 बिलियन से अधिक फोन सब्सक्राइबर्स और 941 मिलियन ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता हैं।
- भारत, मोबाइल डेटा उपयोग में अग्रणी देश है और यहां दुनिया में सबसे कम डेटा दरें हैं। विश्व भर में सबसे तेज 5G रोलआउट की भारत की उपलब्धि दूरसंचार क्षेत्र में इसकी तकनीकी प्रगति को उजागर करती है।
- **C-DOT (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स)** विदेशी प्रौद्योगिकियों पर



<sup>33</sup> Global Capability Centers

निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी दूरसंचार तकनीक विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। C-DOT के प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं:

- सी-डॉट ने स्वदेशी 4G और 5G कोर नेटवर्क विकसित करने, वैश्विक विक्रेताओं पर निर्भरता कम करने और दूरसंचार आयात में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- सी-डॉट ने क्वांटम एन्क्रिप्शन समाधान विकसित किया है, जो सरकार और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए सुरक्षित संचार सुनिश्चित करता है।
- नागरिकों के लिए जियो-टारगेटेड और ऑटोमेटेड पूर्व चेतावनी अलर्ट जैसी प्रौद्योगिकियों ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भारत की तैयारियों को मजबूत किया है।
- दूरसंचार बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और जोखिमों को कम करने के लिए स्वदेशी साइबर सुरक्षा उपकरण बनाए।
- रणनीतिक क्षेत्रों में सुरक्षित संचार (पाठ, छवि, ऑडियो और वीडियो) के लिए SAMVAD ऐप लॉन्च किया। सी-डॉट ने टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो फाइल्स को साझा करने के लिए सुरक्षित कॉल और चैट प्रदान करने हेतु SAMVAD ऐप विकसित किया है।
- अपने सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम (C-DOT Collaborative Research Program: CCRP) के माध्यम से सी-डॉट औद्योगिक जगत के लोगों के साथ साझेदारी करके स्वदेशी दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देता है।
- स्टार्टअप में इनोवेशन और आइडियाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हारनेसिंग इनोवेशंस (NIDHI) और आविष्कार कार्यक्रम शुरू किया गया है।

### ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC):

- मौजूदा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कुछ बड़ी कंपनियों का दबदबा है, जिससे छोटे विक्रेताओं (जैसे, MSMEs, स्थानीय खुदरा विक्रेता, कारीगर) के लिए अवसर सीमित हो जाते हैं।
- ONDC अधिक समावेशी और इंटर-ऑपरेबल डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम प्रस्तुत करता है, जो समान अवसर को बढ़ावा देता है और बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर निर्भरता को कम करता है।
  - उदाहरण के लिए: इस प्लेटफॉर्म से 190 से अधिक नेटवर्क भागीदार जुड़े हुए हैं, जिनमें 7,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठन और 400 से अधिक स्वयं सहायता समूह शामिल हैं।
- नए आयाम
  - सेवा के रूप में लॉजिस्टिक्स: ONDC 1,200 से अधिक शहरों में फर्ट, मिडिल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को एकीकृत करती है।
  - वित्तीय सेवाएं: यह ऋण सेवाओं, eKYC, तथा कम ब्याज दरों पर पर्सनल लोन और कम लागत पर स्वास्थ्य बीमा जैसे वित्तीय उत्पादों को एकीकृत करता है।
  - AI संचालित भाषा अनुवाद के लिए भाषिणी के साथ सहयोग और व्यवसायों के लिए सारथी ऐप।
  - महत्व:
    - आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम, विस्तार योग्य और लागत कम करने में सक्षम।
    - सिंगल पॉइंट पर एकीकृत होने से व्यवसाय संचालन आसान होता है।

### सेवा क्षेत्रक के प्रदर्शन का राज्यवार विश्लेषण

- सेवा क्षेत्रक का योगदान: वित्त वर्ष 2023 के लिए सभी राज्यों में कुल सेवा क्षेत्रक GSVA (सकल राज्य मूल्य वर्धन) में कर्नाटक और महाराष्ट्र का योगदान एक चौथाई से अधिक है। ये राज्य तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात के साथ मिलकर सेवा क्षेत्रक के GVA का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा साझा करते हैं।
- 19 राज्य सामूहिक रूप से सेवा क्षेत्रक के GVA में केवल 25% का योगदान देते हैं।
- क्षेत्रीय असमानताएं: कई पूर्वोत्तर राज्य प्राकृतिक अवस्थिति से जुड़ी बाधाओं की वजह से सरकारी संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। ये बाधाएं बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण और वाणिज्यिक सेवाओं में बाधा डालती हैं।

### सेवा क्षेत्रक और औद्योगिक प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की श्रेणियां:

- उच्च औद्योगिक GSVA: गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य उद्योग में उत्कृष्ट हैं, लेकिन इनके सेवा क्षेत्रक का आकार छोटा है।
  - ये राज्य औद्योगीकरण को बढ़ावा देकर आगे बढ़ सकते हैं, जिससे उनके सेवा क्षेत्रकों को विकसित करने में मदद मिलेगी।



- **मजबूत सेवा क्षेत्रक:** कर्नाटक, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में सेवा क्षेत्रक उत्कृष्ट है, लेकिन इनका औद्योगिक प्रदर्शन औसत है।
  - ये अर्थव्यवस्थाएं काफी हद तक सेवा क्षेत्रक-संचालित और शहरीकृत हैं।
- **दोहरी ताकत (उद्योग और सेवा क्षेत्रकों में मजबूत):** महाराष्ट्र और तमिलनाडु में औद्योगिक और सेवा क्षेत्रक, दोनों मजबूत हैं, जिनमें विनिर्माण, व्यापार और वित्तीय सेवाओं को एकीकृत करने वाली विविधता वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं।
- **सुधार की क्षमता वाले राज्य:** अरुणाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में व्यवसायिक माहौल में सुधारों के माध्यम से विकास की अधिक क्षमता है।

## आगे की राह और दृष्टिकोण

- **कार्यबल के कौशल में सुधार करना:** AI और डिजिटल परिवर्तन का लाभ उठाने के लिए, सभी क्षेत्रों में कार्यबल को कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है।
- **विनियामकीय व्यवस्था में सुधार:** जटिल प्रक्रियाओं और नियमों को सरल बनाने की तत्काल आवश्यकता है जो जमीनी स्तर पर विनिर्माण और सेवा क्षेत्रकों, दोनों के विकास में बाधा डालते हैं।

## बजट में क्या कहा गया है?

- **बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा:** बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रत्येक मंत्रालय 3 साल की ऐसी परियोजनाएं तैयार करेगा जिन्हें पीपीपी मोड में लागू किया जा सकता है।
  - राज्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और वे पीपीपी प्रस्ताव तैयार करने के लिए IIPDF (इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड) योजना से सहायता मांग सकते हैं।
- **बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को सहायता:** पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन हेतु राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज रहित ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

## शब्दावली

| शब्द/ पद                                                | अर्थ                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जीवीए/ GVA (सकल मूल्य वर्धन)                            | यह वह मूल्य है जिसे उत्पादकों ने उन वस्तुओं और सेवाओं में जोड़ा है जिसे उन्होंने खरीदा है। जब वे अपना माल बेचते हैं, तो उत्पादकों की आय उनकी लागत से अधिक होनी चाहिए, और दोनों के बीच का अंतर उनके द्वारा जोड़ा गया मूल्य होता है।                         |
| सेवा क्षेत्रक                                           | यह अर्थव्यवस्था का एक व्यापक क्षेत्रक है जिसमें व्यापार, वित्त, पर्यटन, परिवहन, संचार जैसी सेवाएं प्रदान करने वाले उद्योग शामिल हैं।                                                                                                                       |
| विनिर्माण का सेवाकरण (Servicification of Manufacturing) | यह विनिर्माण प्रक्रियाओं (उत्पादन से लेकर उत्पादन के बाद तक) में सेवाओं का बढ़ता उपयोग है। यह विनिर्माण क्षेत्रक में मूल्य-संवर्द्धन को बढ़ाता है।                                                                                                         |
| वैश्विक क्षमता केंद्र (Global Capability Centers: GCCs) | ये पूर्ण स्वामित्व वाले और एकीकृत केंद्र हैं, जिन्हें आमतौर पर उन जगहों पर स्थापित किया जाता है जहाँ बड़ी संख्या में प्रतिभा मौजूद होती है। इनका उद्देश्य सहयोगी और वितरित टीमों का उपयोग करके महत्वपूर्ण मूल्य और बौद्धिक संपदा (IP) विकसित करना होता है। |



|                             |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) | यह ऐसी प्रौद्योगिकी है जो मशीनों को मानव बुद्धि का अनुकरण करने में सक्षम बनाती है। यह प्रौद्योगिकी आईटी और व्यावसायिक सेवाओं जैसे कौशल-आधारित क्षेत्रों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाएगी।            |
| वर्कफोर्स स्किलिंग          | वर्कफोर्स स्किलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कार्यबल को प्रशिक्षित और विकसित किया जाता है ताकि वह अलग-अलग क्षेत्रों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा कर सके, विशेष रूप से AI जैसी तकनीकी प्रगति के संदर्भ में। |

## अपने सीखने के कौशल का परीक्षण कीजिए

### MCQs

- वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  - भारत ने पिछले दो दशकों में लगातार शीर्ष पाँच वैश्विक सेवा निर्यातकों में अपना स्थान बनाए रखा है।
  - 2023 में, भारत वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% की हिस्सेदारी के साथ सातवें स्थान पर रहा।
  - 2023 में वैश्विक सेवा निर्यात में संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे अधिक 13% थी।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

  - केवल एक
  - केवल दो
  - सभी तीनों
  - कोई नहीं
- भारत के सेवा क्षेत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  - भारत के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में सेवा क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 14 के 50.6% से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 55% हो गया।
  - सेवा क्षेत्र में भारत में कुल कार्यबल का लगभग 40% नियोजित है।
  - विनिर्माण क्षेत्र के सेवाकरण (सर्विसिफिकेशन) की अवधारणा उत्पादन और उत्पादन के बाद के मूल्य संवर्धन, दोनों में सेवा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को संदर्भित करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

  - केवल एक
  - केवल दो
  - सभी तीनों
  - कोई नहीं
- भारत के सेवा क्षेत्र निर्यात के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  - भारत के कुल सेवा क्षेत्र निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं का हिस्सा लगभग 50% है।
  - वित्त वर्ष 25 में सेवा क्षेत्र निर्यात वृद्धि के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष पांच देशों में शामिल था।
  - वित्त वर्ष 23 में जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का योगदान 6.5% था, जो कोविड महामारी से पहले के स्तर से अधिक था।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

  - केवल एक
  - केवल दो
  - सभी तीनों
  - कोई नहीं

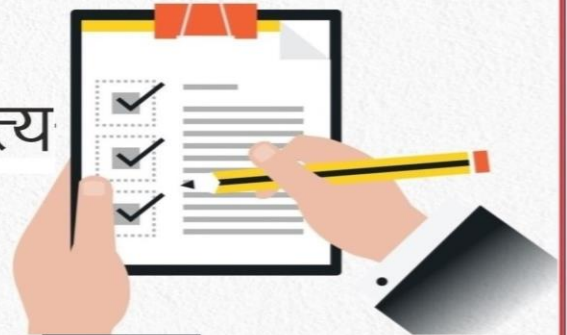
4. भारत के परिवहन क्षेत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है?
- (a) परिवहन सेवाओं के कुल GVA में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी सबसे कम है।  
(b) भारत का विमानन बाज़ार वैश्विक स्तर पर सबसे धीमी गति से वृद्धि करने वाले बाजारों में शामिल है।  
(c) भारत के अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली में 25,000 किलोमीटर से अधिक नौगम्य जलमार्ग है।  
(d) मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 का लक्ष्य 2047 तक भारत को विश्व के शीर्ष 5 जहाज-निर्माण और जहाज-मरम्मत केंद्रों में स्थान दिलाना है।
5. भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2024 में भारत 89 देशों में से 31वें स्थान पर है।  
2. रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) के लागू होने से रियल एस्टेट पारदर्शिता में भारत की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1  
(b) केवल 2  
(c) 1 और 2 दोनों  
(d) न तो 1, न ही 2

### मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न

1. रोजगार और सकल मूल्य वर्धन (GVA) में सेवा क्षेत्र के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत की आर्थिक संवृद्धि में इस क्षेत्र की भूमिका का परीक्षण कीजिए।  
2. आर्थिक विकास और वैश्विक व्यापार को मजबूत करने में भारत की लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी आधारित सेवाओं के महत्व पर चर्चा कीजिए।

## ऑप्शनल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज़

- ✓ भूगोल ✓ समाजशास्त्र  
✓ दर्शनशास्त्र ✓ हिंदी साहित्य  
✓ राजनीति विज्ञान एवं  
अंतर्राष्ट्रीय संबंध

**2025****ENGLISH MEDIUM  
9 MARCH****हिन्दी माध्यम  
9 मार्च****2026****ENGLISH MEDIUM  
9 MARCH****हिन्दी माध्यम  
9 मार्च**

## अध्याय 9: कृषि और खाद्य प्रबंधन: भविष्य का क्षेत्र (Agriculture and Food Management: Sector of the Future)

### परिचय

- भारत के कृषि क्षेत्रक ने वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2023 तक सालाना औसतन 5% की दर से वृद्धि दर्ज की है। यह वृद्धि दर कृषि में मौजूद चुनौतियों के बावजूद इसके लचीलेपन को दर्शाती है।
- इसका प्रमुख कारण अनुकूल मौसम पैटर्न, उन्नत कृषि पद्धतियां और सरकारी सहायता है। इसके अतिरिक्त, इसमें अन्य तत्वों जैसे- उच्च फसल मूल्य, ऋण तक आसान पहुंच, संधारणीयता एवं उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करना आदि ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- 'कृषि और संबद्ध गतिविधियां' क्षेत्रक ने वित्त वर्ष 2024 (अनुमानित) में देश की GDP में लगभग 16% का योगदान दिया है। ज्ञातव्य है कि देश की लगभग 46.1% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है।
- तिलहन में 1.9% की वृद्धि चिंता का विषय है, क्योंकि भारत खाद्य तेल के लिए आयात पर निर्भर है। हालांकि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रक समग्र कृषि विकास के प्रमुख चालक बन गए हैं।
- भारत विश्व के कुल अनाज उत्पादन का 11.6% उत्पादित करता है, लेकिन इसकी फसल उत्पादकता अन्य प्रमुख उत्पादक देशों की तुलना में काफी कम है।

### अध्याय का प्रीकैप

#### आउटकमस

- वित्त वर्ष 2024 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध गतिविधियों का हिस्सा लगभग 16% था।
- बागवानी, पशुधन और मत्स्य पालन जैसे उच्च मूल्य वाले क्षेत्रकों ने कृषि विकास को गति प्रदान की है।
- भारत विश्व के कुल अनाज उत्पादन का 11.6% उत्पादित करता है, लेकिन इसकी फसल उत्पादकता अन्य प्रमुख उत्पादक देशों की तुलना में काफी कम है।

#### फोकस के प्रमुख क्षेत्र

- फसल उत्पादन, वर्षा और सिंचाई प्रणाली, कृषि मशीनीकरण आदि।
- कृषि विपणन अवसंरचना, कृषि में जलवायु कार्रवाई आदि।

#### खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

यह विनिर्माण क्षेत्रक में रोजगार देने वाला बड़ा क्षेत्रक है। यह कुल रोजगार में 12.41% का योगदान देता है और साथ ही महत्वपूर्ण मात्रा में निर्यात भी करता है।

VISIONIAS  
INSPIRING INNOVATION  
**DAKSHA MAINS**  
MENTORING PROGRAM 2024

## दक्ष : मुख्य परीक्षा 2025 के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम

(मुख्य परीक्षा 2025 के लिए स्ट्रेटेजिक रिवीजन / प्रैक्टिस  
और आवश्यक सुधार हेतु मेंटरिंग कार्यक्रम)



दिनांक  
13 जनवरी

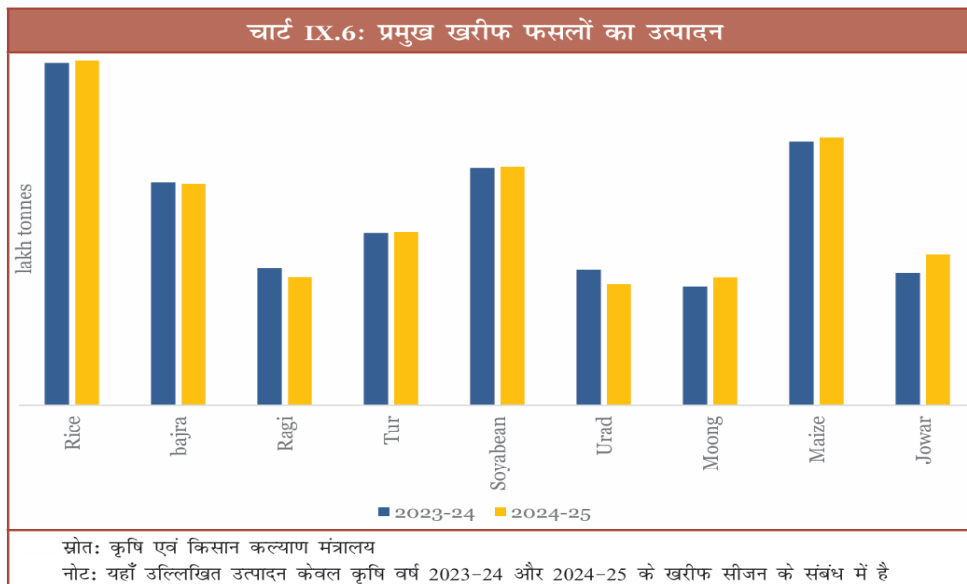
अवधि  
3 महीने

हिन्दी/English माध्यम

For any assistance call us at:  
+91 8468022022, +91 9019066066

## फसल उत्पादन: उत्पादकता वृद्धि, फसल विविधीकरण और इनपुट के उपयोग में दक्षता को प्रोत्साहन देना

- फसल उत्पादकता गुणवत्ता वाले बीजों, सिंचाई, जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य, कटाई के पश्चात् की अवसंरचना और सुलभ बाजार पर गहन रूप से निर्भर होती है।
- इसके अतिरिक्त, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसी कृषि मूल्य नीतियां भी किसानों को बाजार मूल्य की अस्थिरता से बचाकर सूचित निर्णय लेने में मदद करती है। साथ ही, किसानों को फसल विविधीकरण और संधारणीय प्रथाओं को अपनाने हेतु प्रेरित भी करती हैं।
- सरकार ने आवश्यक फसलों के लिए MSP को बढ़ाया है। इसके अंतर्गत, सरकार ने वित्त वर्ष 2025 में दलहन, तिलहन और पोषक अनाजों के लिए MSP में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। इसके परिणामस्वरूप, किसानों को उनकी फसलों का बेहतर मूल्य मिला है।
  - उदाहरण के लिए- मसूर के लिए MSP में 89% की वृद्धि की गई है, जबकि रेपसीड के लिए 98% की प्रभावी वृद्धि की गई है।



## बीज-गुणवत्ता और उर्वरकों का उपयोग: महत्वपूर्ण विभेदक

- मृदा क्षरण, विशेष रूप से जैविक कार्बन की कमी, भारतीय कृषि के समक्ष एक प्रमुख चुनौती है।
- भारत की कई मृदाओं में जैविक कार्बन, बोरॉन, आयरन और सल्फर जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की कमी है। इससे उनकी उर्वरता, उत्पादकता और समग्र कृषि संधारणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- प्रमुख हस्तक्षेप:
  - जलवायु परिवर्तन-रोधी बीज किस्मों का विकास करके उन्हें किसानों के लिए जारी किया गया है। कुल जारी 2,593 नई किस्मों में से 2,177 किस्में जलवायु संबंधी चुनौतियों का समाधान करती हैं।
  - बीज बैंक स्थापित किए गए हैं, और उष्णता-तनाव वाले क्षेत्रों में गर्मी-सहन करने वाली गेहूं की किस्मों को व्यापक रूप से अपनाया गया है।
  - हाल ही में, उपयोग हेतु प्रस्तुत 'यूरिया गोल्ड' में यूरिया को सल्फर के साथ मिश्रित किया जा रहा है। इससे उर्वरकों की बर्बादी कम होती है और पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण होता है।
  - उर्वरक के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए ड्रोन और फर्टिगेशन तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है।
    - फर्टिगेशन उर्वरक उपयोग की एक विधि है। इसमें ड्रिप प्रणाली द्वारा सिंचाई हेतु उपलब्ध जल में उर्वरक को मिलाया जाता है।
  - PM-PRANAM/ पीएम प्रणाम (धरती माता के पुनरुद्धार, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए कार्यक्रम) पहल: इसके तहत राज्यों को नैनो यूरिया, नैनो डाई अमोनियम फास्फेट (DAP) एवं जैविक उर्वरकों जैसे वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

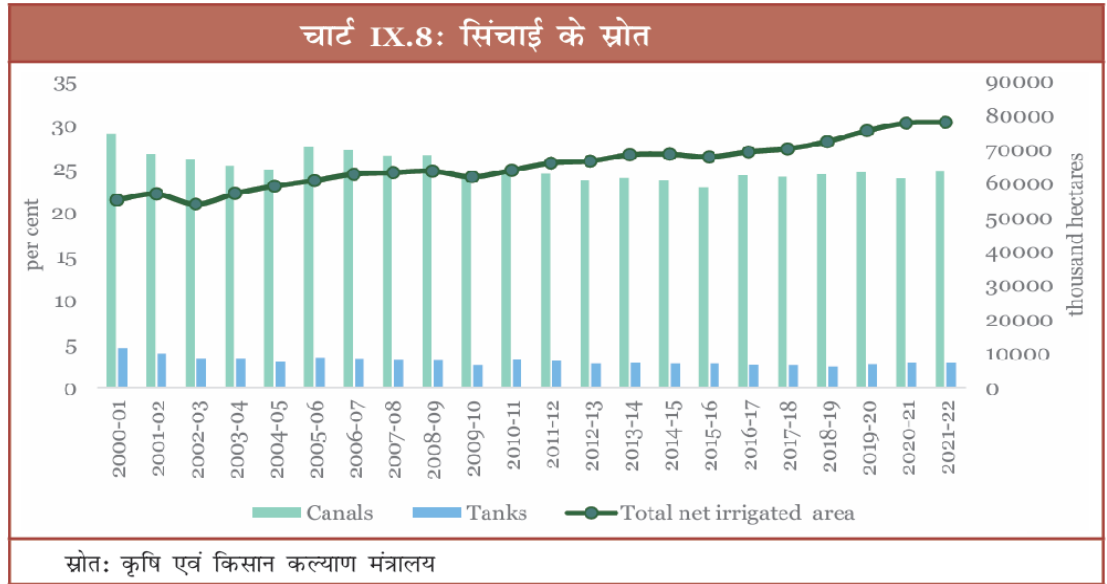
## वर्षा और सिंचाई प्रणाली: दक्षता का निर्माण एवं कवरेज का विस्तार

- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: विशेष रूप से कृषि पद्धतियों के संबंध में जलवायु परिवर्तन का वर्षा के पैटर्न पर गहन प्रभाव पड़ता है। ये पद्धतियां लगातार और पूर्वानुमानित मौसम की स्थिति पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं।

- उदाहरण के लिए- भारत में 85% किसान लघु किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। वे जलवायु परिवर्तन से अधिक प्रभावित होते हैं।

#### • कवरेज:

- वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2021 के बीच सकल फसली क्षेत्र में सिंचाई कवरेज 49.3% से बढ़कर 55% हो गया था।
- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में सिंचाई कवरेज उच्च (98% तक) है,



जबकि झारखंड व असम में यह 20% से भी कम है।

- कृषि में जल के उपयोग को कम करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का विस्तार किया जा रहा है। हालांकि, अभी भी यह संयुक्त राज्य अमेरिका (68.6%) और चीन (13.7%) जैसे देशों की तुलना में काफी कम है। भारत के सिंचित क्षेत्र का 8% ही सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में आता है।
- फसल की पैदावार पर प्रभाव: अध्ययनों से पता चला है कि वर्षा की कमी और तापमान में वृद्धि के कारण फसलों की पैदावार में गंभीर रूप से गिरावट आती है। इसके अतिरिक्त, यह संभावना भी प्रकट की गई है कि भारत में 2099 तक फसल उत्पादकता में 8-12% की गिरावट आ सकती है।
- प्रमुख हस्तक्षेप:
  - सरकार प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 'प्रति बूंद अधिक फसल योजना' के माध्यम से जल दक्षता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।
  - सूक्ष्म सिंचाई निधि के तहत किसानों को 2% ब्याज सब्सिडी दी जा रही है।
  - वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में एकीकृत किया गया है। इस कार्यक्रम को कृषि प्रणालियों के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों के विकास एवं संरक्षण के लिए लागू किया गया है।
  - जल निकायों के कार्यालय के लिए समुदाय-संचालित व प्रौद्योगिकी-सक्षम मॉडल ग्रामीण जल संरक्षण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही, भूजल पुनर्भरण में भी सहायता कर सकता है। इसके अलावा, यह विविध उपकरणों जैसे- CLART GIS और AVNI/ अवनी ग्रामीण ऐप आदि का इस्तेमाल करके भूजल निकायों के पुनर्भरण में सहायता कर सकता है।

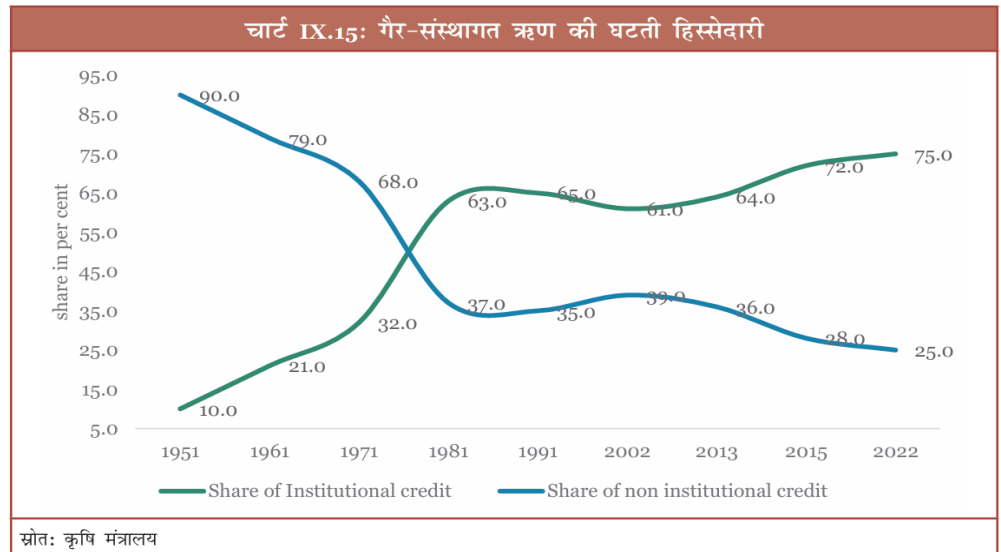
### कृषि ऋण: एक महत्वपूर्ण इनपुट

- सभी किसानों खासकर लघु और सीमांत किसानों को पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान करना, कृषि उत्पादकता एवं आय में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।
- कृषि के लिए बुनियादी स्तर के ऋण में सालाना 12.98% की दर से वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें लघु और सीमांत किसानों को दिए जाने वाले ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह वित्त वर्ष 2015 के 3.46 लाख करोड़ रुपये (41%) से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 14.39 लाख करोड़ रुपये (57%) हो गया था।

#### प्रमुख हस्तक्षेप:

- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना ने किसानों को अल्पकालिक पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने में मदद की है। इस योजना के तहत 7.75 करोड़ सक्रिय खाते हैं और 9.81 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं।

- संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसानों को 7% की रियायती दर पर ऋण दिया जाता है। यदि किसान समय पर ऋण चुकाते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 3% की छूट भी मिलती है।
- किसान ऋण पोर्टल के माध्यम से दावों (क्लेम) का निपटान तेजी से किया जा रहा है। इससे त्वरित लेन-देन संभव हुआ है और किसानों को कृषि ऋण तक बेहतर पहुंच मिली है।
- बैंकों के लिए उनके समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (ANBC)<sup>34</sup> कुल ऋण राशि का 40% प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (जैसे कृषि) को देना अनिवार्य किया गया है।
- इन सभी उपायों के कारण किसानों की गैर-संस्थागत ऋण स्रोतों पर निर्भरता 1950 के 90% से घटकर वित्त वर्ष 2022 में लगभग 25% रह गई थी।
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से सुरक्षा के लिए फसल बीमा प्रदान किया जा रहा है।



#### भूमि पट्टे के अभिनव तरीके - केरल का मामला

- आदर्श कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2016 का उद्देश्य भूमिहीन और सीमांत किसानों के लिए भूमि पट्टे तक पहुंच में सुधार करने हेतु भूमि पट्टे को वैध और सुविधाजनक बनाना है। साथ ही, इसका अन्य उद्देश्य भूमि मालिकों के अधिकारों की रक्षा करना भी है।
- केरल ने भूमि पट्टे का एक अभिनव मॉडल पेश किया है। इसमें स्वयं सहायता समूह (SHG) बागवानी खेती के लिए भूमि पट्टे पर लेते हैं। इस व्यवस्था में पट्टेदार भू-स्वामी को या तो लाभ का एक हिस्सा साझा करता है या फिर निश्चित मुआवजा देता है।
- इस समझौते को ग्राम पंचायत द्वारा नोटरीकृत किया जाता है। इससे SHGs को ऋण और बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ मिल जाता है।
- यह 3 से 5 साल का मॉडल भूमि की देखभाल, कृषि दक्षता और कम आय वाले किसानों की भूमि तक पहुंच में सुधार करता है। इस योजना में शामिल 85% से अधिक सदस्य निर्धन वर्ग से हैं।

## कृषि यंत्रीकरण: पहुंच को सुगम बनाना

मशीनरी की उच्च लागत लघु किसानों के बीच कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण बाधा प्रस्तुत करती है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स और फार्म मशीनरी बैंक किसानों को सस्ती दर पर उपकरणों की सुविधा प्रदान करते हैं।

#### मुख्य हस्तक्षेप:

- कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन के तहत राज्य सरकारों की कस्टम हायरिंग सेंटर्स स्थापित करने और प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता की जा रही है।
- सरकार द्वारा संचालित एक नई योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिन्हें वे किसानों को किराए पर दे सकते हैं। इसके लिए SHGs को 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

<sup>34</sup> Adjusted Net Bank Credit

## कृषि विस्तार: सक्षमकर्ता

कृषि विस्तार सेवाएं ज्ञान व आधुनिक तकनीक के प्रसार, उत्पादकता बढ़ाने और संधारणीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

मुख्य हस्तक्षेप:

- सरकार उत्पादकता और संधारणीयता में सुधार के लिए कृषि विस्तार पर उप-मिशन (SMAE)<sup>35</sup> के माध्यम से कृषि विस्तार सेवाओं को बढ़ावा दे रही है।
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA)<sup>36</sup> प्रशिक्षण, प्रदर्शन, किसान कार्यक्रमों और कृषि विद्यालयों के माध्यम से आधुनिक कृषि तकनीकों को साझा कर रही है।
- "किसान कॉल सेंटर" किसानों को 22 भाषाओं में सहायता प्रदान करता है। इससे वे अपनी समस्याओं का आसानी से समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

## कृषि विपणन अवसंरचना में सुधार

मुख्य हस्तक्षेप:

- कृषि विपणन अवसंरचना (AMI)<sup>37</sup> उप-योजना के तहत भंडारण सुविधाओं, बाजार अवसंरचना और मोबाइल पोस्ट हार्वेस्ट प्रणालियों के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- कृषि अवसंरचना कोष (AIF)<sup>38</sup>, प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड स्टोरेज जैसी परियोजनाओं के लिए मध्यम अवधि के वित्त-पोषण के साथ फसल कटाई के बाद के प्रबंधन का समर्थन करता है।
- कृषि विपणन में सुधार के लिए सरकार ने e-NAM योजना शुरू की है। यह योजना ग्रेडिंग, छंटाई और पैकेजिंग के लिए मुफ्त सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर फंडिंग एवं अवसंरचना प्रदान करती है।

## कृषि में जलवायु का प्रभाव

- ICAR (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) ने 51 संकेतकों का उपयोग करके कृषि संधारणीयता के एक समग्र सूचकांक की गणना की है। इस सूचकांक का औसत अनुमानित मूल्यांक 0.49 है, जो दर्शाता है कि भारतीय कृषि मध्यम रूप से संधारणीय है।
- इसमें मिजोरम, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड जैसे राज्यों का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।
- इसके विपरीत, राजस्थान में सबसे कम संधारणीय कृषि पद्धतियां हैं।
- उच्च संधारणीयता स्कोर वाले राज्यों में बेहतर फसल विविधीकरण, बेहतर अवसंरचना, कृषि ऋण और संधारणीय इनपुट पाया गया है।
- सिंधु-गंगा के मैदान (उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार व हरियाणा) और झारखंड एवं असम जैसे चावल उगाने वाले राज्य जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।

### संधारणीय खेती को प्रोत्साहन देना: प्रमुख उपाय



<sup>35</sup> Sub-Mission on Agricultural Extension

<sup>36</sup> Agricultural Technology Management Agency

<sup>37</sup> Agriculture Marketing Infrastructure

<sup>38</sup> Agriculture Infrastructure Fund

## संबद्ध क्षेत्रक: सहनशीलता तैयार करने की क्षमता

- पशुपालन क्षेत्रक कृषि विकास का एक प्रमुख कारक बन गया है। इसकी कृषि सकल मूल्य वर्धित (GVA)<sup>39</sup> में हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2015 के 24.38% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 30.23% हो गई है।
- इसका कुल उत्पादन 17.25 लाख करोड़ रुपये (205.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच गया है। इसमें केवल दुग्ध उद्योग का योगदान 11.16 लाख करोड़ रुपये (133.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर) रहा है, जो धान व गेहूं जैसी प्रमुख फसलों के योगदान से अधिक है।
- प्रमुख हस्तक्षेप:
  - देशी गोजातीय नस्लों के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुधन स्वास्थ्य व रोग नियंत्रण कार्यक्रम, IVF प्रौद्योगिकी संवर्धन और ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय AI तकनीशियनों (MAITRI/ मैत्री) की व्यवस्था स्थापित की गई है।
- मत्स्य पालन:
  - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) का उद्देश्य जलीय कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है।
  - मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF)<sup>40</sup> बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता प्रदान करता है।
  - इस क्षेत्रक ने आधुनिक तकनीकों जैसे कि केज कल्चर, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS), और बायो फ्लोक को अपनाया है। साथ ही, कोल्ड स्टोरेज और विपणन अवसंरचना में सुधार भी किया है।
    - इससे मछली उत्पादन वित्त वर्ष 2014 के 95.79 लाख टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 184.02 लाख टन हो गया था।
  - प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना ने राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसने केवल 4 महीनों में 16.35 लाख से अधिक हितधारकों को संगठित किया है।

## सहकारी समितियां: बेहतर सेवा के लिए संस्था को मजबूत बनाना

भारत में सहकारी समितियां कृषि, ऋण, आवास और महिला कल्याण जैसे क्षेत्रकों में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। साथ ही, किसानों और लघु उद्यमियों को ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा भी देती हैं

### मुख्य हस्तक्षेप

- सरकार ने प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS)<sup>41</sup> के लिए मॉडल उपनियम लागू किए हैं। PACS का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। नई बहुउद्देशीय PACS, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियां स्थापित की जा रही हैं।
- अन्य पहलों में PACS को कॉमन सर्विस सेंटर्स में बदलना शामिल है, ताकि वे वित्त संबंधी सेवाओं के अलावा अन्य सेवाएं प्रदान कर सकें। इसके अलावा, पेट्रोल आउटलेट स्थापित करना और आसान बैंकिंग पहुंच के लिए सहकारी समितियों के भीतर माइक्रो-ATMs स्थापित करना भी शामिल है।
- PACS अब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में कार्य कर रही हैं, जो किसानों को महत्वपूर्ण कृषि सेवाएं प्रदान करने के प्रति समर्पित हैं। घर-घर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 1,723 माइक्रो-ATMs स्थापित किए गए हैं।

## खाद्य प्रसंस्करण उद्योग: अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण

- भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित विनिर्माण क्षेत्रक में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। यह इस क्षेत्रक में कुल रोजगार में 12.41% का योगदान देता है।
- वित्त वर्ष 2024 में, प्रसंस्कृत खाद्य सहित कृषि-खाद्य निर्यात कुल 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो भारत के कुल निर्यात का 11.7% था।

<sup>39</sup> Gross Value Added

<sup>40</sup> Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund

<sup>41</sup> Primary Agricultural Credit Societies



### • प्रमुख हस्तक्षेप:

- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY): यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए अवसंरचना के आधुनिकीकरण, आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार, फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने, प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ावा देने और निर्यात बढ़ाने पर केंद्रित है।
- खाद्य प्रसंस्करण के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना: इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रांडिंग और विपणन पहलों को सुविधाजनक बनाकर वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी खाद्य प्रसंस्करण लीडर्स तैयार करना है।
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (PMFME) योजना: यह योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण व्यवसायों को स्थापित करने या उन्नत करने के लिए तकनीकी, वित्तीय और व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है।

## खाद्य प्रबंधन: खाद्य सुरक्षा को सक्षम बनाना

इसका उद्देश्य सभी को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इससे एक स्वस्थ जीवन सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह खाद्य उपलब्धता, पहुंच, उचित उपयोग और दीर्घकालिक स्थिरता पर केंद्रित है।

### मुख्य हस्तक्षेप:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत सरकार ने कल्याण आधारित नीति से अधिकार-आधारित नीति की ओर रुख किया है।
- सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में सुधार के लिए 100% e-KYC को अनिवार्य किया है। इससे एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना को समर्थन मिलेगा।
- सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट (e-NWR)-आधारित प्लेज फाइनेंसिंग के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGS-NPF) का शुभारंभ किया गया। यह योजना लघु किसानों को संग्रहीत उपज के लिए ऋण प्राप्त करने, फसल कटाई-पश्चात ऋण को बढ़ावा देने और आय में सुधार करने में मदद करेगी।
- भारत में खाद्यान्न भंडारण को बढ़ाने के लिए किए उपाय
  - भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से स्टील के साइलोज़ का निर्माण किया जा रहा है।
  - सरकार साइलोज़ के लिए हब और स्पोक मॉडल के तहत क्षमता का निर्माण कर रही है। इसमें स्पोक से हब तक परिवहन सड़क मार्ग से और हब से हब तक परिवहन रेल मार्ग द्वारा किया जाएगा।
  - सरकार दूरदराज के क्षेत्रों में भंडारण में सुधार के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से मोबाइल स्टोरेज यूनिट्स के एक प्रकार फ्लोस्पैन के उपयोग की संभावना तलाश रही है।
  - सरकार अनाज गोदामों का आधुनिकीकरण करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ मिलकर 'स्मार्ट वेयरहाउसेज' का परीक्षण कर रही है। 'स्मार्ट वेयरहाउसेज' भंडारण की स्थिति की निगरानी और सुधार के लिए सेंसर्स का उपयोग करते हैं, जिससे नुकसान कम होता है।

## आगे की राह और दृष्टिकोण

- भारत का कृषि क्षेत्रक आर्थिक संवृद्धि और खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि, इसे जलवायु परिवर्तन और जल संकट जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी, यह उत्पादकता बढ़ाने और किसानों के कल्याण का समर्थन करने वाली पहलों के कारण मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
- कृषि की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए भारत को अनाज के अधिक उत्पादन, दालों और खाद्य तेल के कम उत्पादन जैसे मुद्दों का समाधान करना चाहिए। साथ ही, मृदा स्वास्थ्य, मूल्य जोखिम और जल उपयोग पर नीतियों में सुधार करना चाहिए। इससे उत्पादकता बढ़ेगी और घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी।

## बजट में क्या कहा गया है?

- प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना- कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम: यह कार्यक्रम मौजूदा योजनाओं के समावेशन और विशिष्ट उपायों के माध्यम से ऐसे 100 जिलों को कवर करेगा, जहां उत्पादकता कम, फसल तीव्रता मध्यम और ऋण से जुड़े मापदंड औसत से कम हैं।
- दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन: अगले 4 वर्षों के दौरान केंद्रीय एजेंसियों (NAFED और NCCF) द्वारा 3 दालों की असीमित खरीद की जाएगी, बशर्ते किसान इन एजेंसियों के साथ पंजीकरण कराएं और समझौते करें।
- बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा।
- सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से दिए जाने वाली ऋण राशि में बढ़ोतरी करने की बात कही है।

## शब्दावली

| शब्द/ पद                         | अर्थ                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| फसल विविधीकरण                    | यह कृषि में लचीलापन बढ़ाने और एक ही तरह की फसल उगाने की जगह अलग-अलग प्रकार की फसलें उगाने की प्रथा है।                                                         |
| बीज बैंक                         | ये ऐसे संस्थान हैं, जो पौधों की आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने और भविष्य में रोपण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने हेतु बीजों का भंडारण करते हैं। |
| सूक्ष्म सिंचाई निधि (MIF)        | यह कृषि में ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियों जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कोष है।                                               |
| प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS) | ये किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान करने वाली सहकारी समितियां होती हैं।                                                                    |
| सामान्य सेवा केंद्र (CSCs)       | ये ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल और अन्य आवश्यक सेवाएं, जैसे बैंकिंग एवं ई-गवर्नेंस प्रदान करने वाले केंद्र हैं।                                                |

## अपने सीखने के कौशल का परीक्षण कीजिए

### MCQs

- निम्नलिखित में से कौन-से कारक भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं?
  - गुणवत्तापूर्ण बीज और सिंचाई
  - उन्नत फसल कटाई उपरांत अवसंरचना
  - कुशल जल प्रबंधन
  - उपर्युक्त सभी
- प्रति बूंद अधिक फसल और सूक्ष्म सिंचाई निधि जैसे हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
  - फसल विविधीकरण बढ़ाना
  - सिंचाई दक्षता में सुधार करना
  - बीज उत्पादन का विस्तार करना
  - किसानों को ऋण उपलब्ध कराना
- निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारत में जलवायु परिवर्तन और कृषि के बीच संबंधों का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
  - जलवायु परिवर्तन का भारतीय कृषि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
  - तापमान और वर्षा में वृद्धि से कृषि उत्पादकता में कमी आने की संभावना होती है।
  - जलवायु परिवर्तन से केवल फसल की पैदावार प्रभावित होगी, पशुधन क्षेत्रक प्रभावित नहीं होगा।
  - जलवायु परिवर्तन के कारण भारत की कृषि उत्पादकता में सुधार होने की उम्मीद है।

4. कृषि में सहकारी समितियां क्या भूमिका निभाती हैं?
- (a) वे प्रत्यक्ष रूप से कृषि उत्पादन का प्रबंधन करती हैं।  
 (b) वे ऋण और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता एवं संसाधन प्रदान करती हैं।  
 (c) वे केवल खाद्य प्रसंस्करण और विपणन पर ध्यान केंद्रित करती हैं।  
 (d) वे सरकारी कृषि योजनाओं की जगह लेती हैं।
5. संधारणीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उपायों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- परम्परागत कृषि विकास योजना
  - मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक खेती पर केंद्रित है
  - मृदा स्वास्थ्य कार्ड
  - राष्ट्रीय बांस मिशन
- उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
- (a) केवल 1  
 (b) केवल 2  
 (c) केवल 3  
 (d) उपर्युक्त सभी।

### मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न

- भारत के कृषि क्षेत्रक में फसल उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने के समक्ष चुनौतियों एवं सरकारी हस्तक्षेपों पर चर्चा कीजिए।
- भारत के कृषि विकास का समर्थन करने में मत्स्य पालन, पशुधन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे संबद्ध क्षेत्रों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इन क्षेत्रों के लिए प्रमुख हस्तक्षेप क्या हैं?

### हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =



मोहन लाल



अर्पित  
कुमार



विपिन  
दुबे



मनीषा  
धार्वे



मयंक  
दुबे



देवेश  
पाराशर

### UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें



मोहन लाल



UPSC  
CSE 2026  
सामान्य अध्ययन



UPSC  
Prelims 2025  
10 years PYQ



Master  
Classes Series  
करेंट अफेयर्स

## अध्याय 10: जलवायु और पर्यावरण: अनुकूलन की अनिवार्यता (Climate and Environment: Adaptation Matters)

### परिचय

- 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का भारत का लक्ष्य समावेशी, संधारणीय विकास पर केंद्रित है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद, भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत का मात्र एक-तिहाई है।
- देश का लक्ष्य निम्न-कार्बन उत्सर्जन आधारित विकास, ऊर्जा सुरक्षा, रोजगार सृजन, आर्थिक संवृद्धि और पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना है।
  - हालांकि, इसमें कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं, विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के संदर्भ में, जिसमें भंडारण सीमाएं और खनिज संसाधनों की उपलब्धता जैसी समस्याएं शामिल हैं।
- भारत की जलवायु कार्यवाही का वित्त-पोषण मुख्यतः घरेलू स्तर पर किया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय निधियों का योगदान काफी कम है और जो धन खर्च किया भी गया है वह केवल शमन उपायों पर किया गया है।
  - उदाहरण के लिए, COP29 में प्रस्तावित जलवायु वित्त लक्ष्य<sup>42</sup> के तहत 2035 तक प्रति वर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य तय किया गया, जो कि वर्ष 2030 तक अनुमानित 5.1-6.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यक राशि से काफी कम है।

### अध्याय का प्रीकैप

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>अनुकूलन को सर्वाधिक प्राथमिकता देना</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>जलवायु अनुकूलन रणनीति: विविध भूगोल और जलवायु के कारण सुभेद्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।</li> <li>अनुकूलन संबंधी व्यय: वित्त वर्ष 2016 में GDP के 3.7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 5.6% हो गया।</li> </ul> | <b>प्रमुख अनुकूलन पहलें</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>कृषि: जलवायु-अनुकूल बीजों, भूजल संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य पर अनुसंधान।</li> <li>शहरी क्षेत्र: NMSH, अमृत (AMRUT) और स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से शहरी बाढ़, हीट-स्ट्रेस और भूजल की कमी के प्रति अनुकूलन।</li> <li>तटीय क्षेत्र: मिट्टी, तटीय विनियमन क्षेत्र और मैंग्रोव संरक्षण के माध्यम से चरम मौसमी घटनाओं का शमन।</li> <li>जल प्रबंधन: जल शक्ति अभियान, राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और फ्लडवॉच इंडिया ऐप।</li> </ul> |
| <b>एनर्जी ट्रांजिशन</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ऊर्जा के क्षेत्र में चुनौतियां: भारत में कोयले पर अत्यधिक निर्भरता है, जबकि विकसित देशों ने गैस की ओर रुख कर लिया है।</li> <li>एनर्जी ट्रांजिशन में प्रगति: गैर-जीवाश्म ईंधन से बिजली उत्पादन क्षमता का 46.8%।</li> </ul>            | <b>संधारणीय विकास के लिए जीवनशैली को अनुकूलित करना</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>पर्यावरण के अनुकूल जीवन-शैली (LiFE) मिशन: वैश्विक उपभोक्ताओं के लिए पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देता है।</li> <li>चक्रीय अर्थव्यवस्था की क्षमता: संसाधनों के पुनर्चक्रण से 2030 तक भारत के GDP (GDP) में 11% और 2050 तक 30% की बचत हो सकती है।</li> </ul>                                                                                                                           |

## पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम

### सिविल सेवा परीक्षा 2024

अधिक जानकारी और रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें

**हिंदी और अंग्रेजी माध्यम**

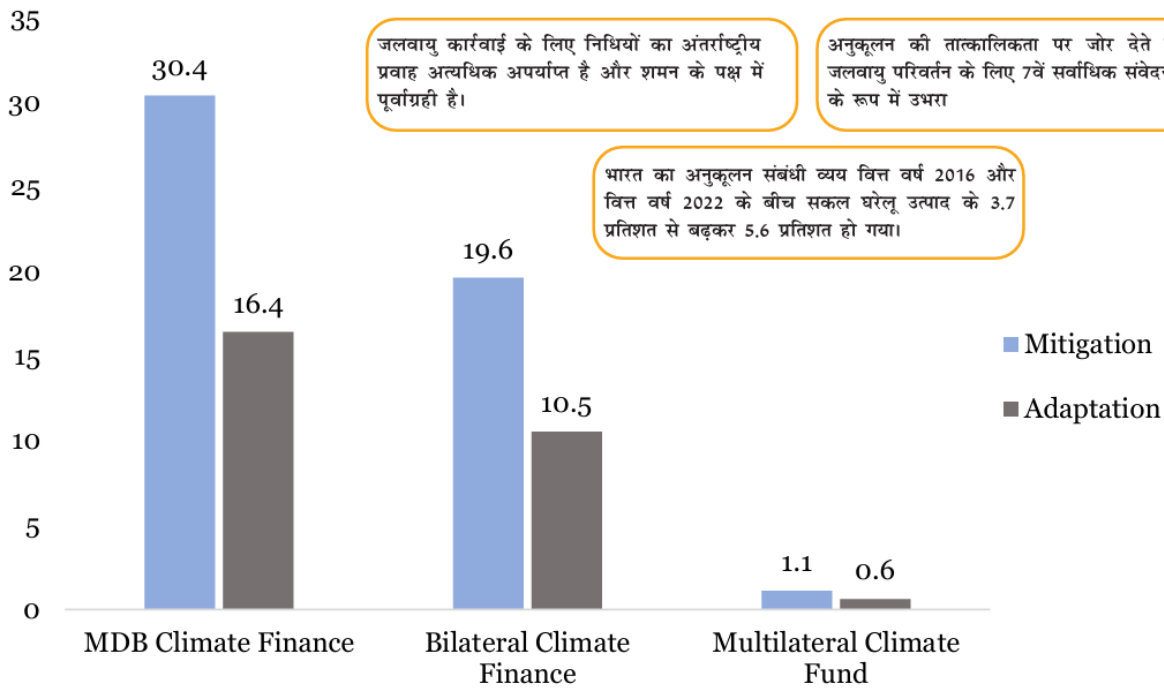
**प्रवेश प्रारंभ**

<sup>42</sup> Climate Finance Goal

## अनुकूलन को सर्वाधिक प्राथमिकता देना

- भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति सातवां सबसे अधिक संवेदनशील देश है, जो कि चरम मौसमी घटनाओं, समुद्र के बढ़ते स्तर, जैव विविधता की हानि और जल असुरक्षा जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनके चलते जीवन, आजीविका और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

### निधियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह में शमन पूर्वाग्रह



- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) अनुकूलन संबंधी रणनीतियों को सतत विकास लक्ष्यों के साथ एकीकृत करने के लिए **राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (NAP)** तैयार कर रहा है।
- भारत की अनुकूलन रणनीति क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप **नीतिगत परिवर्तन, अलग-अलग क्षेत्रों की रणनीतियों, लचीली अवसंरचना, अनुसंधान और वित्त-पोषण** पर केंद्रित है।
- अनुकूलन पर खर्च वित्त वर्ष 2016 में GDP के 3.7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 5.6% हो गया। यह खर्च मुख्य रूप से घरेलू संसाधनों से पूरा किया गया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
  - हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त-पोषण अभी भी अपर्याप्त है और अनुकूलन की तुलना में शमन पर अधिक केंद्रित है।

## विभिन्न क्षेत्रों में अनुकूलन

- कृषि:** भारत में जलवायु-अनुकूल बीजों के अनुसंधान एवं विकास, भूजल संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन के उपायों, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, तथा फसल पद्धतियों में बदलाव आदि पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- शहरी क्षेत्रों में अनुकूलन का निर्माण करना:** भारत बढ़ते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से शहरों में पड़ रही अत्यधिक गर्मी, शहरी बाढ़ और भूजल में गिरावट आदि समस्याओं से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

### प्रमुख हस्तक्षेप:

- राष्ट्रीय सतत आवास मिशन (NMSH)** इसके तहत अपशिष्ट, जल, ऊर्जा, परिवहन और शहरी नियोजन के माध्यम से निम्न-कार्बन उत्सर्जन आधारित शहरी विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है।

- **अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT/ अमृत)** के तहत जल आपूर्ति में सुधार, जल निकायों का कायाकल्प, भूजल पुनर्भरण, तथा हरित स्थानों और हरित परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
  - **अमृत 2.0** में जल के पुनः उपयोग और ग्रेवाटर प्रबंधन पर भी जोर दिया जा रहा है।
- **स्मार्ट सिटी मिशन** के तहत जीवन-यापन, आर्थिक संवृद्धि और संधारणीयता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। **शहरी नदी प्रबंधन योजना (URMP)** और **रिवर सिटीज अलायंस** के तहत 145 से अधिक शहरों में नदियों के सतत कायाकल्प की दिशा में काम किया जा रहा है।
- **वर्टिकल गार्डन्स** हीट आइलैंड्स और वायु प्रदूषण जैसी शहरी चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं। ये भवनों के तापीय प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं, कार्बन को अवशोषित करते हैं, और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं।
  - उदाहरण के लिए- **आयकर विभाग** ने **17 राज्यों** में वर्टिकल गार्डन बनाने के लिए बेकार **प्लास्टिक बोतलों** का उपयोग किया है।
- **भारत की ऊर्जा संरक्षण और सतत भवन संहिता (ECSBC) 2024** का उद्देश्य ऊर्जा कुशल भवनों को बढ़ावा देना है। इसमें **वर्टिकल गार्डन्स** जैसी हरित तकनीकों को शामिल करने की संभावना है, जो सिंगापुर, जापान और यूरोपीय संघ जैसे वैश्विक दृष्टिकोणों के अनुरूप है।

**तटीय क्षेत्रों में अनुकूलन:** भारत के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को चरम जलवायु घटनाओं और समुद्री जलस्तर में वृद्धि जैसी धीरे-धीरे असर दिखाने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा काफी बढ़ गया है।

- **प्रमुख हस्तक्षेप :**
  - **मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेड्स एंड टैंगिबल इनकम्स (मिष्ठी/ MISHTI)** का लक्ष्य 2028 तक भारत के तटों पर मैंग्रोव वनों का पुनरुद्धार करना, तटीय समुदाय की आजीविका, कार्बन प्रच्छादन (4.5 मिलियन टन) और प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा देना है।
  - इसका उद्देश्य **2028** तक भारत के तटीय क्षेत्रों में **मैंग्रोव वनों** की पुनर्बहाली करना है। यह योजना तटीय समुदाय की आजीविका को बढ़ावा देने, कार्बन प्रच्छादन को बढ़ाने (4.5 मिलियन टन तक) और **प्राकृतिक पर्यटन** को प्रोत्साहित कर रही है।
  - **मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और प्रबंधन** जैसी योजनाओं के माध्यम से भारत मैंग्रोव वनों का संरक्षण और संवर्धन कर रहा है। इस क्षेत्र के विकास हेतु भारत ने **तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना (2019)** जैसे विनियामकीय उपाय, वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 जैसे कानून लागू किए हैं।
  - **"भारत के तटीय समुदायों की जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना"** शीर्षक परियोजना का उद्देश्य समुदाय-आधारित और पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण के माध्यम से खासकर महिलाओं सहित सुभेद्य तटीय आबादी की प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करना है।

#### जल प्रबंधन के लिए अनुकूलन कार्रवाई

- **जल शक्ति अभियान (2019):** इस अभियान का उद्देश्य जल संकट/ वाटर स्ट्रेस से निपटना है। इसके तहत वर्षा जल संचयन, जल निकायों का मानचित्रण, वनीकरण और जागरूकता कार्यक्रम जैसे उपाय अपनाए गए हैं।
  - कैच द रेन-2024 अभियान में **"नारी शक्ति से जल शक्ति"** थीम के साथ जल संरक्षण में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया गया है।
- **राष्ट्रीय जलभूत मानचित्रण परियोजना (NAQUIM):** इसमें अब तक 25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया जा चुका है। इसके तहत राज्य स्तरीय कार्यान्वयन के लिए जल संरक्षण योजनाएं और पुनर्भरण संरचनाएं प्रदान की जा रही हैं।
- **भू-नीर पोर्टल:** यह पोर्टल केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने विकसित किया है। पोर्टल प्रभावी जलग्रहण प्रबंधन सुनिश्चित करता है, पारदर्शिता और संधारणीयता को बढ़ावा देता है।
- **फ्लडवॉच इंडिया ऐप (संस्करण 2.0):** यह प्रभावी बाढ़ प्रबंधन के लिए रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान, 592 स्टेशंस से निगरानी डेटा और जलाशयों में जल भंडारण के स्तर से संबंधित जानकारी प्रदान करता है।
- **राज्य-विशिष्ट उपाय:**
  - **जल संचय जन भागीदारी:** इसके तहत जल संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है।
  - **स्मार्ट लेबोरेटरीज ऑन क्लीन रिवर्स (SLCR):** भारत-डेनमार्क सहयोग के तहत वाराणसी में शुरू की गई इस प्रयोगशाला का उद्देश्य वरुणा नदी को फिर से जीवित करना है।
  - **मावरा बहुउद्देशीय जलाशय परियोजना (मेघालय):** इसका उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, जल स्रोतों का कायाकल्प और निम्नीकृत क्षेत्रों को पुनर्बहाल करना है।

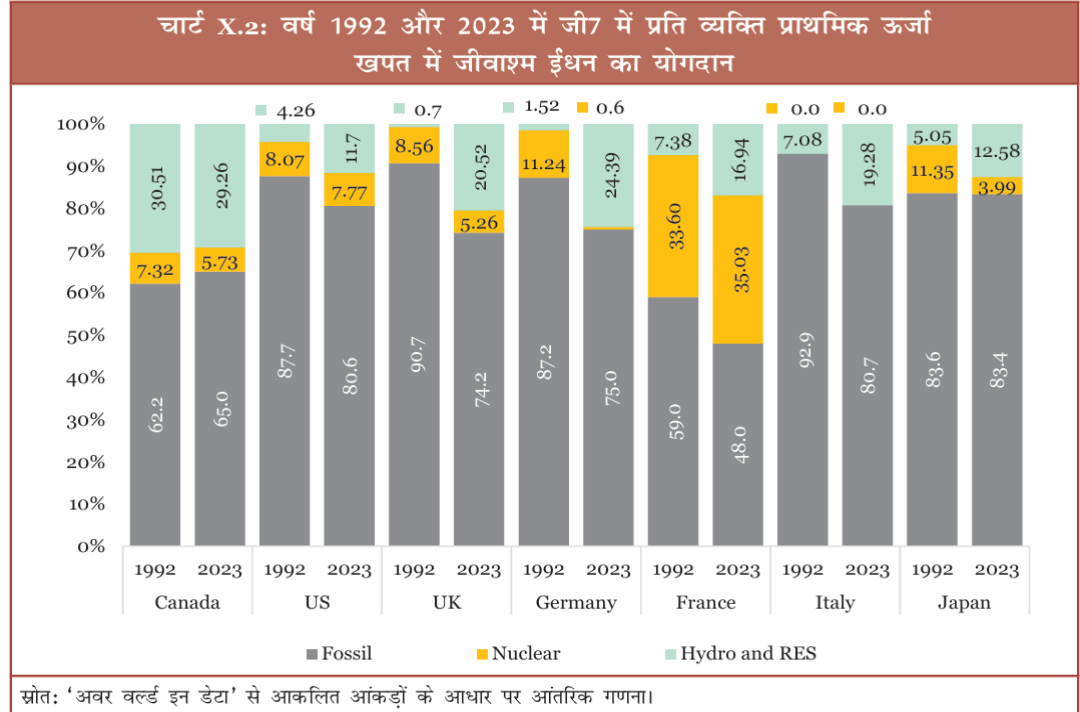
## ऊर्जा संचरण - विकसित देशों के अनुभव से सीखना और विकल्पों पर विचार करना

ऊर्जा संचरण (एनर्जी ट्रांजिशन) मुख्य रूप से वाणिज्यिक हितों से प्रेरित रहे हैं, न कि उत्सर्जन में कमी लाने के लिए। ऊर्जा सुरक्षा और वाणिज्यिक हित आज भी ऊर्जा संचरण की राह में प्रभावी कारक बने हुए हैं। उदाहरण के लिए- यूरोपीय संघ की REPowerEU योजना का उद्देश्य रूसी गैस पर निर्भरता को कम करना है।

### • G7 देशों की ऊर्जा खपत में

1992 से 2023 के बीच अधिक बदलाव नहीं हुआ है। वे अब भी मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन विशेष रूप से गैस पर निर्भर हैं।

- भारत को अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी ऊर्जा मांग लगातार बढ़ रही है। यद्यपि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, परन्तु इसके बावजूद ग्रिड एकीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अस्थिर ऊर्जा उत्पादन जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं।



- भारत के ऊर्जा सम्मिश्रण में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसके पास कोयले के विशाल भंडार हैं और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत सीमित हैं। भारत के पास वैश्विक कोयला भंडार का 10% है, लेकिन प्राकृतिक गैस भंडार का केवल 0.7% है।
  - भारत ने कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन की दक्षता बढ़ाने के लिए सुपर-क्रिटिकल, अल्ट्रा-सुपर-क्रिटिकल और एडवांस्ड अल्ट्रा-सुपर-क्रिटिकल कोयला संयंत्रों जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाया है।
- परमाणु ऊर्जा दरअसल ऊर्जा का एक स्वच्छ विकल्प प्रदान करती है, लेकिन इससे संबंधित सुरक्षा चिंताएं और आपूर्ति शृंखला की समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं।
  - इसके अतिरिक्त, सौर पैनल्स जैसी नवीकरणीय तकनीकों के लिए निपटान की चुनौतियां भी एक गंभीर मुद्दा है।
- AI और डेटा सेंटर्स की वजह से बढ़ती बिजली मांग के कारण जीवाश्म ईंधन, विशेष रूप से प्राकृतिक गैस का उपयोग बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि केवल नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्रों के माध्यम से उत्सर्जन की भरपाई करना प्रभावी समाधान नहीं हो सकता है।
- विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं दोनों में सुरक्षा, आर्थिक संवृद्धि और पर्यावरणीय लक्ष्यों के बीच तनाव है। इसके चलते सतत ऊर्जा को अपनाने की दिशा में चुनौतियों उत्पन्न हो रही है।

### भारत में ऊर्जा संचरण की दिशा में की गई प्रगति

- भारत ने ऊर्जा शमन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता (213,701 मेगावाट) का 46.8% गैर-जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। 2030 तक इसे 50% तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।
- ऊर्जा संचरण को बढ़ावा देने वाली नई पहलें और मौजूदा नीतियों/ योजनाओं संबंधी अद्यतन जानकारीयां:
  - नई सौर ऊर्जा योजना: प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान के तहत जनजातीय क्षेत्रों में 100,000 घरों का विद्युतीकरण, 63,000 गांवों, 1,500 बहुउद्देश्यीय केंद्रों और 2,000 सार्वजनिक संस्थानों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली सुनिश्चित करना है।

- **पीएम-सूर्य घर योजना:** इस योजना का उद्देश्य 2027 तक 10 मिलियन घरों में **रूफटॉप सोलर** लगाना है। इसका लक्ष्य 40-45 गीगावाट की क्षमता हासिल करना है।
- **अपतटीय पवन ऊर्जा:** गुजरात और तमिलनाडु में अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए 7,453 करोड़ रुपये के बजट के साथ व्यवहार्यता अंतराल वित्त-पोषण योजना शुरू की गई है।
- **हरित ऊर्जा गलियारा:** यह कई राज्यों में चल रही परियोजनाओं (GEC-I और GEC-II) के साथ **नवीकरणीय ऊर्जा ट्रांशमिशन को मजबूत करता है।**

- **राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम:** अपशिष्ट से ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस पहलों का समर्थन करता है, तथा संस्थापित क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

- **सौर पार्क और अल्ट्रा-मेगा सौर परियोजनाएं:** इसके तहत 40,000 मेगावाट क्षमता विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके तहत 39.9 गीगावाट

क्षमता वाले 55 सौर पार्कों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।

- **पीएम-कुसुम योजना:** इस योजना के तहत सौर ऊर्जा से चलने वाले **कृषि पंपों और ग्रिड से जुड़े संयंत्रों** के माध्यम से **34.8 GW** की सौर क्षमता को एकीकृत किया जाएगा।
- **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना:** इसका उद्देश्य गीगावाट पैमाने पर उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल की विनिर्माण क्षमता हासिल करना है।
- **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन:** इसका लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भी विकसित करने के साथ 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करना है।

#### सीखे गए सबक:

- विकसित अर्थव्यवस्थाओं का अनुभव दर्शाता है कि **विश्वसनीय विकल्पों के बिना तापीय ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने से जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं।**
- भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए **निम्न-कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की राह में आगे बढ़ना।** साथ ही, अपनी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों, प्रौद्योगिकियों और विशेषज्ञता का उपयोग करना होगा।
- **अल्प से मध्यम अवधि में,** भारत को **बैटरी स्टोरेज, ग्रिड अवसंरचना और महत्वपूर्ण खनिजों** सहित नवीकरणीय ऊर्जा के समक्ष चुनौतियों का समाधान करना होगा।

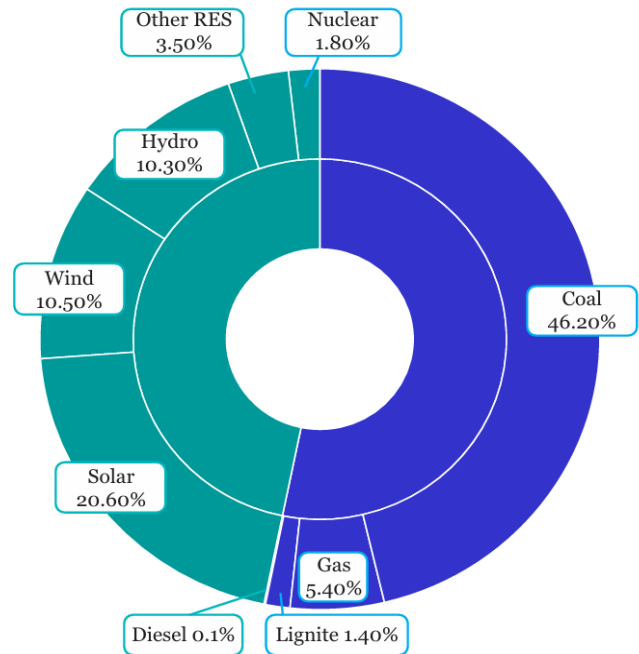
#### भारत की एनडीसी की ओर प्रगति

##### नवीकरणीय ऊर्जा

वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत के अद्यतन एनडीसी लक्ष्य की तुलना में, गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 30 नवंबर, 2024 तक 46.8 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

##### वन क्षेत्र

भारत के नवीनतम वन सर्वेक्षण 2024 के अनुसार, वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन सीओ<sub>2</sub> के समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के एनडीसी लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 2005 और वर्ष 2023 के बीच 2.29 बिलियन टन सीओ<sub>2</sub> के समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है।



#### भारत में वनों का बढ़ता कार्बन सिंक

- भारत के NDC का लक्ष्य वृक्षावरण के विस्तार के माध्यम से 2030 तक कार्बन सिंक को अतिरिक्त 2.5 से 3 बिलियन टन CO<sub>2</sub> के बराबर तक बढ़ाना है।
- **2024 वन सर्वेक्षण** के अनुसार, भारत का कार्बन सिंक 2023 में 30.43 बिलियन टन तक पहुंच गया, जो 2005 में 28.14 बिलियन टन था। यह 2.29 बिलियन टन की वृद्धि को दर्शाता है।
- FSI ने 2030 तक 31.71 बिलियन टन कार्बन सिंक का अनुमान लगाया है, जो NDC लक्ष्य के आस-पास है।

## हरित निवेश संबंधी वित्तीय विनियमन में विकास

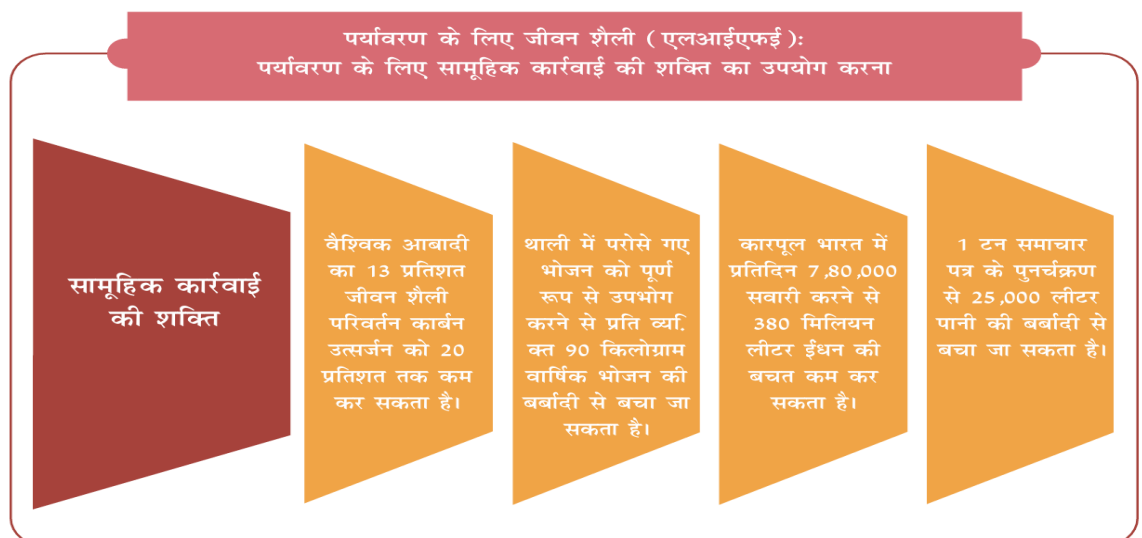
- बिजनेस रिस्पॉन्सबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट (BRSR): सेबी ने वित्तीय वर्ष 2023 से शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए BRSR के तहत ESG (पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन) मैट्रिक्स की रिपोर्टिंग को अनिवार्य किया है। इसमें ग्रीन हाउस गैस (GHG) उत्सर्जन, जल और ऊर्जा उपयोग, लैंगिक विविधता और समावेशन जैसे पहलुओं की जानकारी देनी होती है।
- हरित ऋण प्रतिभूति फ्रेमवर्क: सेबी ने संधारणीय परियोजनाओं को वित्त-पोषित करने के लिए 2023 में ट्रांजिशन, ब्लू, येलो और सर्कुलर इकोनॉमी बॉण्ड जैसी नई श्रेणियां शुरू की।
  - इसके तहत जारीकर्ताओं के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों तथा शमन योजनाओं का खुलासा करना अनिवार्य है।
- सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड्स (SGrBs): सरकार ने हरित अवसंरचना के वित्त-पोषण के लिए वित्त वर्ष 2023 में 16,000 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 24 में 20,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
- RBI द्वारा ग्रीन डिपॉजिट: RBI ने हरित परियोजनाओं के लिए जमा स्वीकार करने को प्रोत्साहित करने के लिए 'ग्रीन डिपॉजिट' शुरू किया है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण अब प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत आता है।

## सतत विकास के लिए जीवनशैली का अनुकूलन

- खाद्य अपशिष्ट और उत्सर्जन: हर साल वैश्विक खाद्यान्न का लगभग 17% बर्बाद हो जाता है। यह वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 8% से अधिक का योगदान देता है।
- आहार संबंधी प्राथमिकताओं का प्रभाव: डेयरी और मांस की खपत कम करने से उत्सर्जन में 66% की कमी आ सकती है। पादप आधारित आहार से व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट में सालाना 2.1 टन तक की कमी आ सकती है, जिसमें से वीगन आहार का प्रभाव सर्वाधिक है।
- मिशन लाइफ/ LiFE: इसे 2021 में COP26 में भारत ने लॉन्च किया था। यह पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने को प्रोत्साहित करता है।
  - उद्देश्य: इसका लक्ष्य 2022 से 2028 तक पर्यावरणीय कार्रवाई के लिए वैश्विक स्तर पर 1 बिलियन लोगों को संगठित करना और 2028 तक भारत के 80% गांवों और शहरी क्षेत्रों को पर्यावरण-अनुकूल बनाना है।
  - LiFE उपायों के सह-लाभ: संधारणीय प्रथाएं ऊर्जा असमानताओं को कम कर सकती हैं, वायु प्रदूषण को घटा सकती हैं, लागत में कमी ला सकती हैं और स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार कर सकती हैं।
  - संभावित बचत: 2030 तक LiFE उपायों के माध्यम से उपभोक्ता वैश्विक स्तर पर USD 440 बिलियन तक की बचत कर सकते हैं, जो कम उपभोग और कम कीमतों के कारण संभव होगा।

सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- उत्पाद शुल्क और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन: जीवाश्म ईंधन पर उच्च उत्पाद शुल्क और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन हरित विकल्पों को बढ़ावा देते हैं।
- इकोमार्क और स्टार-लेबलिंग: ये पहलें पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को प्रमाणित करती हैं और ऊर्जा दक्षता और इलेक्ट्रोमोबिलिटी संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देती हैं।



- **PAT योजना:** 'परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड' (PAT) योजना ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देती है।
- **अपशिष्ट प्रबंधन विनियम:** ये संधारणीय अपशिष्ट पद्धतियों को लागू करके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं।
- **ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम:** यह GCP पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक भागीदारी के साथ वृक्षारोपण जैसे स्वैच्छिक संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करता है।
- **एक पेड़ माँ के नाम:** यह एक वृक्षारोपण अभियान है, जो लोगों को प्रकृति का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा माताओं के प्रति गहरा श्रद्धा को दर्शाता है।
- **स्वच्छ भारत मिशन 2.0:** यह भारत की व्यापक स्वच्छता की पहुंच की दिशा में मौलिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह कार्यक्रम अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता संबंधी कार्यप्रणालियों को सतत और चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के साथ एकीकृत करता है।

## चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता

- चक्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य अपशिष्ट की मात्रा को न्यूनतम करना, मूल्यवान सामग्रियों की पुनर्प्राप्ति तथा कच्चे संसाधनों पर निर्भरता को कम करना है।
  - उदाहरण के लिए- 2030 तक, चक्रीय अर्थव्यवस्था से सकल घरेलू उत्पाद में 11% की बचत हो सकती है, और 2050 तक यह 30% पहुंच सकती है।
- भारत इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए **विनियमों, वित्तीय प्रोत्साहनों और जागरूकता अभियानों** का बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रहा है।
- भारत की **नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी** पहलों में ई-वेस्ट के पुनर्चक्रण की अहम भूमिका है। खासकर, भारत सौर पैनल्स और पवन ऊर्जा उपकरणों के नष्ट हो चुके हिस्सों को पुनः उपयोग में लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- सरकार पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए **कर छूट, सब्सिडी और कम ब्याज दर पर ऋण** जैसे प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।
- भारत की **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)** नीति निर्माताओं को उपभोग के बाद उत्पन्न अपशिष्ट के लिए उत्तरदायी बनाती है। इससे सतत डिजाइन, पुनर्चक्रण और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है।

## प्लास्टिक प्रदूषण

- प्लास्टिक जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। 2050 तक, वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में प्लास्टिक की हिस्सेदारी **15%** होगी।
- भारत में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक उपभोग की दर सबसे कम है।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016** का उद्देश्य प्लास्टिक अपशिष्ट का संधारणीय प्रबंधन करना है। इन नियमों के द्वारा स्थानीय निकायों को जुलाई 2022 से प्रदूषण को कम करने हेतु **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन करना होगा, खुले में प्लास्टिक जलाने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाना होगा और सिंगल-यूज वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना होगा।**

## वायु प्रदूषण

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार **विश्व की 99% आबादी**, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अनुशंसित सीमा से अधिक प्रदूषक वाली हवा में सांस लेती है।
- उत्तरी भारत में, विशेष रूप से दिल्ली और NCR में शीत ऋतु के दौरान वायु की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है, तथा पार्टिकुलेट मैटर का स्तर अक्सर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों से अधिक हो जाता है।
- **वाहनों यातायात, कृषि पद्धतियां, तथा खाना पकाने के लिए कोयले और लकड़ी के उपयोग के साथ-साथ भौगोलिक अवस्थिति और हवा की दिशा** जैसे कारक इस प्रदूषण को बढ़ाते हैं।
- **प्रमुख हस्तक्षेप**
  - **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP):** इसका लक्ष्य 130 शहरों में **वायु प्रदूषण को कम करना है।** इसमें राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर कार्य योजनाओं के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, AMRUT/ अमृत, SATAT/ सतत और नगर वन योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं के संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है।

- ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP): इसमें खराब वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता स्तरों के आधार पर निवारक उपायों को लागू किया जाता है।
- कृषि मशीनीकरण: "फसल अवशेषों के स्व-स्थाने प्रबंधन के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देना" योजना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पराली दहन की घटनाओं को कम करने हेतु मशीनरी और कस्टम हायरिंग सेंटर्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

## आगे की राह और दृष्टिकोण

भारत एक समग्र दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें शमन (उत्सर्जन में कमी) और अनुकूलन (जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रभावों के प्रति लचीलापन बनाना) दोनों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

### कुछ सुझाव:

- नीतिगत एकीकरण: लक्षित नीतियां, पर्याप्त वित्त-पोषण, और विकास कार्यक्रमों में अनुकूलन रणनीतियों को एकीकृत करना महत्वपूर्ण है। समाधान क्षेत्र-विशिष्ट होने चाहिए, तथा भारत की विविध भौगोलिक दशाओं के अनुरूप होने चाहिए।
- दक्षता और निम्न-उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियां: वर्तमान में मध्यम अवधि के लिए मौजूदा जीवाश्म ईंधन संसाधनों की दक्षता को अधिकतम करना और एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (AUSC) विद्युत संयंत्रों जैसी निम्न-उत्सर्जन वाली तापीय विद्युत प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाना जरूरी है।
- कृषि और जलवायु लचीलापन: जलवायु-अनुकूल बीजों का विकास और कृषि पद्धतियों में सुधार ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- जन जागरूकता: जलवायु शमन के लिए LIFE मिशन के माध्यम से जीवनशैली में बदलाव को प्रोत्साहित करना निम्न कार्बन व्यवहार अपनाने में सहायक हो सकता है।
  - पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय शिक्षा को शामिल करने से भावी पीढ़ी में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- अनुसंधान एवं विकास: बैटरी स्टोरेज प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय ऊर्जा अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए अनुसंधान में निवेश करना विश्वसनीय एवं संधारणीय ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

## बजट में क्या कहा गया है?

- विकासशील भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन: 2047 तक कम-से-कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास ऊर्जा संचरण संबंधी हमारे प्रयासों के लिए आवश्यक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे।

## शब्दावली

| शब्द/ पद                              | अर्थ                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जलवायु अनुकूलन                        | जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए किए गए समायोजन या रणनीतियां हैं, जैसे- कृषि पद्धति या अवसंरचना में बदलाव करना।                                      |
| ऊर्जा संचरण                           | यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जीवाश्म ईंधन के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ना।                                                  |
| पर्यावरण के लिए जीवन शैली (LiFE) मिशन | यह पहल कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए पर्यावरण-अनुकूल और संधारणीय जीवनशैली को बढ़ावा देती है।                                                                     |
| चक्रीय अर्थव्यवस्था                   | यह एक आर्थिक प्रणाली है जिसका उद्देश्य अपशिष्ट को न्यूनतम करना और संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इसमें संसाधनों का रीयूज, रीसाइकिलिंग, रिड्यूस शामिल है। |
| विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) | इसके तहत निर्माताओं को उनके उत्पादों के संपूर्ण जीवन-चक्र, विशेष रूप से उपभोग के बाद के निपटान के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।                                         |



## अपने सीखने के कौशल का परीक्षण कीजिए

### MCQs

1. भारत की जलवायु अनुकूलन रणनीति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. भारत का अनुकूलन पर खर्च वित्त वर्ष 2016 में GDP के 3.7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 5.6% हो गया है।
  2. अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त-पोषण के अधिकांश हिस्से का इस्तेमाल शमन के बजाय अनुकूलन उपायों किया जाता है।
  3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (NAP) बना रहा है।उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
  - (a) केवल 1
  - (b) केवल 2
  - (c) केवल 3
  - (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
2. भारत के ऊर्जा संचरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 46.8% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों पर आधारित है।
  2. भारत कोयले पर निर्भर है और इसके पास विश्व के प्राकृतिक गैस भंडार का केवल 0.7% है।
  3. भारत की ऊर्जा संचरण योजनाओं में अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्त-पोषण (VGF) योजना शामिल है।उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
  - (a) केवल 1
  - (b) केवल 2
  - (c) केवल 3
  - (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
3. भारत के पर्यावरण के लिए जीवनशैली (LiFE) मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. यह मिशन पर्यावरण-अनुकूल और प्रकृति के अनुरूप जीवनशैली को बढ़ावा देता है।
  2. इसका लक्ष्य 2030 तक खाद्य बर्बादी को 17% तक कम करना है।
  3. यह पहल 2030 तक वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं के लिए USD 440 बिलियन की बचत कर सकती है।उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
  - (a) केवल 1
  - (b) केवल 2
  - (c) केवल 3
  - (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

4. निम्नलिखित में से प्लास्टिक प्रदूषण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 2050 तक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में प्लास्टिक का योगदान 15% होगा।
  2. भारत में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक खपत दर 35 किलोग्राम है, जो विश्व में सबसे अधिक है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1
  - (b) केवल 2
  - (c) 1 और 2 दोनों
  - (d) न तो 1, न ही 2
5. भारत में वायु गुणवत्ता को सुधारने के संदर्भ में, निम्नलिखित हस्तक्षेपों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)
  2. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)
  3. कृषि अपशिष्ट के स्व-स्थाने प्रबंधन के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा
- उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
- (a) केवल 1 और 2
  - (b) केवल 2 और 3
  - (c) केवल 1 और 3
  - (d) उपर्युक्त सभी

### मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न

1. भारत की जलवायु अनुकूलन रणनीति और इसके सामने आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम कौन-कौन से हैं?
2. पर्यावरण के लिए जीवनशैली (LiFE) मिशन के तहत प्रमुख हस्तक्षेप जलवायु परिवर्तन का शमन करने और संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने में कैसे योगदान देते हैं?

# CSAT

## क्रैश कोर्स प्रीलिम्स 2025

(इसका उद्देश्य मूलभूत अवधारणाओं को रिवाइज करना और उन्हें सुदृढ़ करना, समस्या-समाधान क्षमताओं को बढ़ाना, विश्लेषणात्मक कौशल को बेहतर बनाना, समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना और प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए समझ कौशल में सुधार करना है।)

### प्रारंभ

English Medium

हिन्दी माध्यम

21 January, 1 PM

30 January, 1 PM

(Offline/Online)



## अध्याय 11: सामाजिक क्षेत्र: पहुंच का विस्तार करना और सशक्तिकरण को प्रोत्साहन (Social Sector: Extending Reach and Driving Empowerment)

### परिचय

- आर्थिक और सामाजिक विकास सतत और समावेशी आर्थिक संवृद्धि से शुरू होता है, जो विकसित भारत 2047 के विजन का केंद्र-बिंदु है।
- समावेशी विकास से स्वास्थ्य-देखभाल सेवा, शिक्षा, जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं और आजीविका के स्तर पर देश के नागरिकों के समग्र जीवन स्तर में भी सुधार होता है।
- आर्थिक संवृद्धि को सार्थक विकास में बदलने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य-देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसरों को बढ़ाने आदि पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

### अध्याय का प्रीकैप

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>आउटकम</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>सामाजिक सेवाओं पर व्यय में वृद्धि का रुझान दर्ज किया गया</li> <li>मासिक प्रति-व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE) में शहरी-ग्रामीण अंतर कम हुआ है</li> <li>असमानता कम हुई है</li> </ul> | <b>शिक्षा</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>स्कूली शिक्षा</li> <li>सामाजिक और भावनात्मक लर्निंग</li> <li>शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम</li> <li>डिजिटल प्रौद्योगिकी पहुंच में अंतर को दूर करना</li> <li>उच्चतर शिक्षा</li> </ul>                        |
| <b>स्वास्थ्य-देखभाल</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>सरकारी व्यय में वृद्धि हुई</li> <li>भविष्य के लिए स्वास्थ्य-देखभाल सेवा में परिवर्तन</li> <li>रूपांतरणकारी प्रौद्योगिकी</li> <li>मानसिक सेहतमंदी</li> </ul>        | <b>ग्रामीण अर्थव्यवस्था</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ग्रामीण बुनियादी ढांचा</li> <li>ग्रामीण प्रगति को बढ़ावा देने के लिए सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण</li> <li>ग्रामीण कल्याण: सामाजिक समावेशन, लिंग से जुड़े मुद्दे</li> <li>ग्रामीण आय में वृद्धि</li> </ul> |

### सामाजिक सेवा व्यय में रुझान

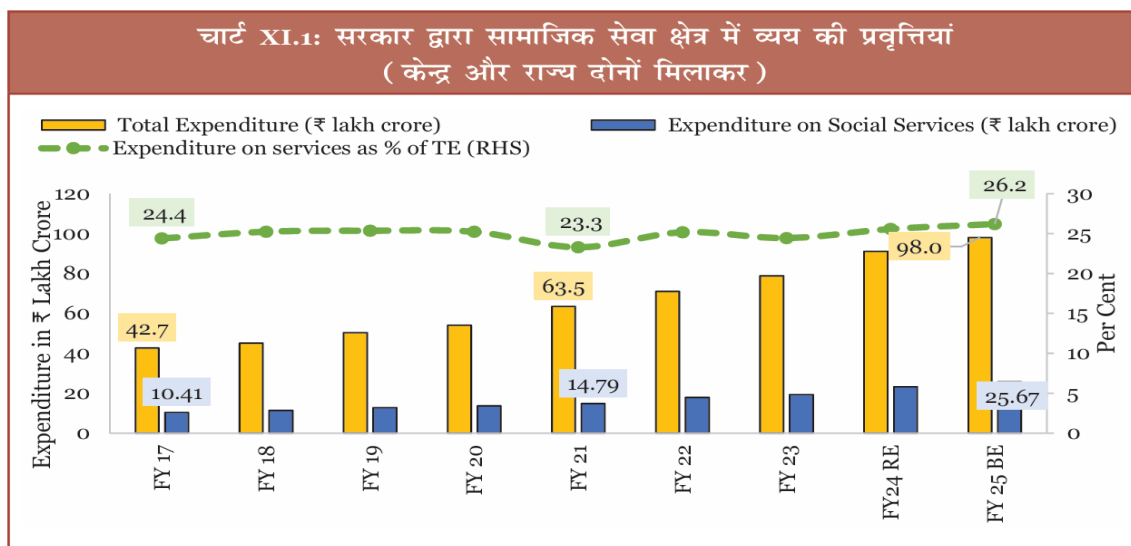
- सामाजिक सेवा व्यय (SSE): कुल व्यय (TE) के प्रतिशत के रूप में SSE वित्त वर्ष 21 के 23.3% से बढ़कर वित्त वर्ष 25 (बजट अनुमान) में 26.2% हो गया।

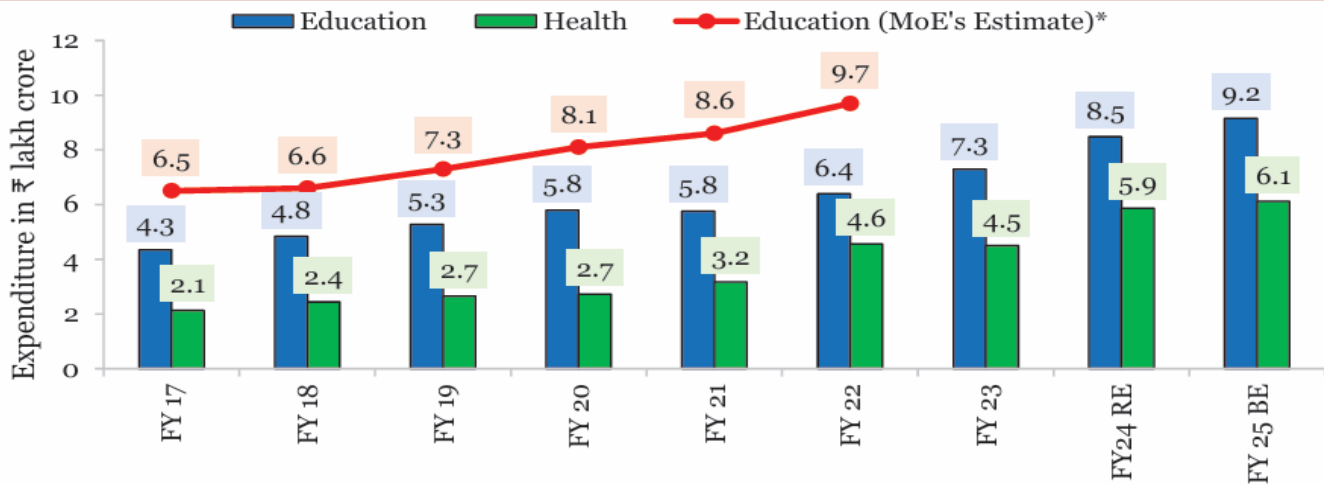
वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 25 (बजट अनुमान) तक, सामाजिक सेवा व्यय 15% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) से बढ़ा है।

- शिक्षा पर व्यय 12% की CAGR से बढ़कर वित्त वर्ष 21 के 5.8 लाख

करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 25 (बजट अनुमान) में 9.2 लाख करोड़ रुपये हो गया।

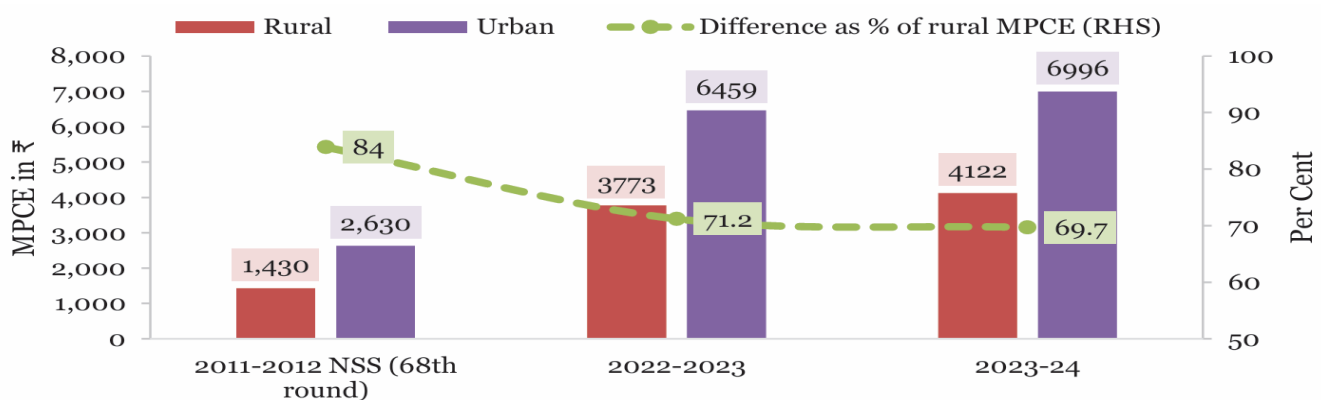
- स्वास्थ्य-देखभाल पर व्यय 18% CAGR की दर से बढ़कर वित्त वर्ष 21 के 3.2 लाख करोड़ रुपये से वित्त वर्ष 25 (बजट अनुमान) में 6.1 लाख करोड़ रुपये हो गया।



**चार्ट XI.2: शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय**


### घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24: आउटकम

- शहरी-ग्रामीण अंतर में कमी:
  - मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE) में शहरी-ग्रामीण अंतर 2011-12 के 84% से घटकर 2022-23 में 71% हो गया। यह 2023-24 में और कम होकर 70% हो गया।
  - औसत MPCE क्रमशः 4,122 रुपये और 6,996 रुपये अनुमानित है।
- असमानता में कमी: गिनी गुणांक में ग्रामीण क्षेत्रों (2022-23 के 0.266 से घटकर 2023-24 में 0.237) और शहरी क्षेत्रों (2022-23 के 0.314 से घटकर 2023-24 में 0.284) में सुधार दर्ज किए गए।
- असमानता में कमी की वजहें:
  - शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय बढ़ना; कल्याणकारी योजनाएं जैसे-मुफ्त खाद्यान्न वितरण या खाद्यान्न को सब्सिडी कीमत पर उपलब्ध कराना, सब्सिडी मूल्य पर रसोई गैस वितरण, बीमा कवर आदि।
  - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का पुनर्वितरण प्रभाव, विश्व बैंक द्वारा अध्ययन:
    - PDS/प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) सब्सिडी का बाजार-समतुल्य मूल्य, सभी परिवारों में औसतन प्रति व्यक्ति (अंतिम या सब्सिडी के बाद) नॉमिनल मासिक उपभोग व्यय (MPCE)<sup>43</sup> के 4% के बराबर है।

**चार्ट XI.3: उपभोग में शहरी-ग्रामीण अंतर में गिरावट**


स्रोत: एचसीईएस 2023-24, एमओएसपीआई

<sup>43</sup> Monthly Per Capita Expenditure



## शिक्षा: नए तरीकों की तलाश

- शिक्षा और मानव पूंजी विकास वास्तव में आर्थिक विकास के आधारभूत स्तंभों में शामिल हैं।
- नई शिक्षा नीति (NEP) में कहा गया है कि इसका उद्देश्य हमारे संविधान द्वारा परिकल्पित समतामूलक, समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध, उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिकों का निर्माण करना है।

## स्कूली शिक्षा

- NEP 2020 का लक्ष्य 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात (GER)<sup>44</sup> हासिल करना है।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा: 85% मस्तिष्क का विकास छह वर्ष की आयु से पहले होता है।
- उठाए गए कदम: आधारशिला, नवचेतना, प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क।

## स्कूल के बुनियादी ढांचे में प्रगति

- नामांकन: प्राथमिक स्तर पर (93%) सकल नामांकन अनुपात (GER) लगभग सार्वभौमिक है। माध्यमिक स्तर (77.4%) तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर (56.2%) पर अंतर को दूर करने के प्रयास चल रहे हैं।
- स्कूल छोड़ने की दर में लगातार कमी आ रही है, जो प्राथमिक स्तर पर 1.9%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.2% तथा माध्यमिक स्तर पर 14.1% है।

| वर्ष                                     | 2019,20 | 2021,22 | 2022,23 | 2023,24 |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| लड़कियों का शौचालय                       | 96.9    | 97.5    | 97      | 97.2    |
| लड़कों का शौचालय                         | 95.9    | 96.2    | 95.6    | 95.7    |
| हाथ धोने की सुविधा                       | 90.2    | 93.6    | 94.1    | 94.7    |
| पुस्तकालय/पठन कक्ष/पठन कोना              | 84.1    | 87.3    | 88.3    | 89      |
| बिजली                                    | 83.4    | 89.3    | 91.7    | 91.8    |
| एक वर्ष में विद्यालयों में चिकित्सा जाँच | 82.3    | 54.6    | 74.3    | 75.2    |
| कंप्यूटर                                 | 38.5    | 47.5    | 47.7    | 57.2    |
| इंटरनेट                                  | 22.3    | 33.9    | 49.7    | 53.9    |
| स्रोत: यूडोआईएसई+ 2023-24                |         |         |         |         |

## साक्षरता और संख्यात्मकता के माध्यम से लर्निंग की मजबूत नींव का निर्माण

- NEP 2020 में कहा गया है कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN)<sup>45</sup> शिक्षा और आजीवन लर्निंग की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।
- निपुण भारत (NIPUN) की शुरुआत यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि देश का प्रत्येक बालक 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक अनिवार्य रूप से FLN प्राप्त कर ले।
  - NIPUN से आशय है; नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी।
- शुरू की गई पहलें: पीयर टीचिंग जैसे नल्ली-काली (कन्नड़ में आनंददायक शिक्षा) कार्यक्रम, शिक्षा का प्रेरणा मॉडल (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक) आदि।

## फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

► प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 25 फरवरी, 8 AM | 25 मार्च, 2 PM

JAIPUR: 10 अप्रैल

JODHPUR: 17 मार्च

प्रवेश प्रारम्भ

BHOPAL | LUCKNOW



Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

f /visionias.upsc

yt /c/VisionIASdelhi

tg /c/VisionIASdelhi

l.me/s/VisionIAS\_UPSC

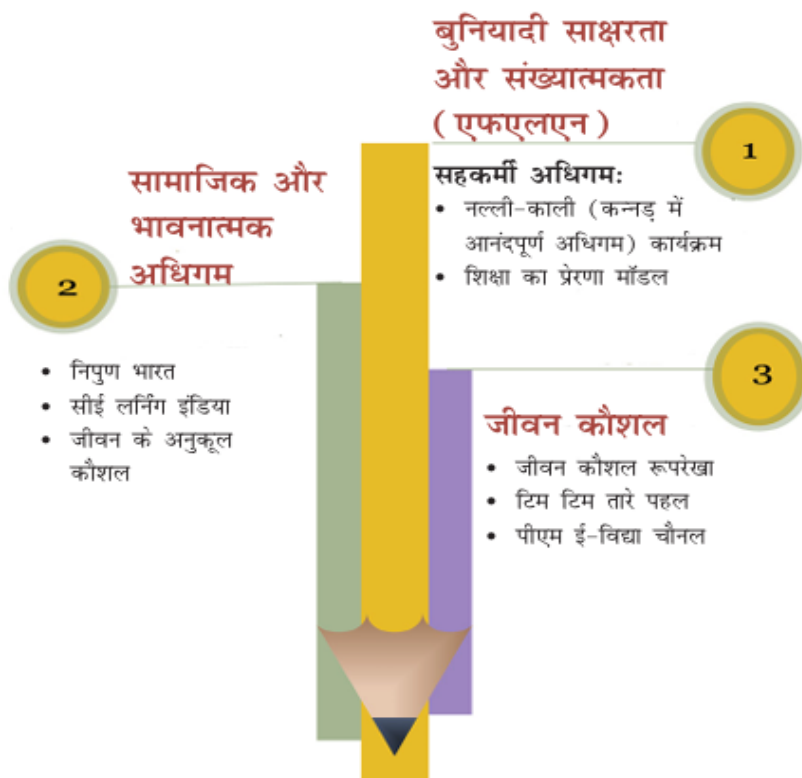
<sup>44</sup> Gross Enrolment Ratio

<sup>45</sup> Foundational literacy and numeracy

## दिमाग को सशक्त बनाना: सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा (SEL)<sup>46</sup> के साथ क्षमता को अनलॉक करना

- यूनेस्को के अनुसार सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा (SEL) “भावनाओं को पहचानने और नियंत्रित करने, दूसरों की देखभाल और उसके प्रति चिंता करने, सकारात्मक संपर्क स्थापित करने, जिम्मेदार निर्णय लेने और चुनौतीपूर्ण स्थितियों को प्रभावी ढंग से संभालने की क्षमता हासिल करने की एक प्रक्रिया है।”
- SEL पहलों में निवेश किए गए प्रत्येक डॉलर से अनुमानित 11 डॉलर का दीर्घकालिक आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, जिसके परिणाम मानसिक स्वास्थ्य-देखभाल, शिक्षा और रोजगारपरकता पर प्रभाव पड़ते हैं।
- उठाए गए कदम: टिम टिम तारे पहल
  - उद्देश्य: पूरे भारत में किशोर विद्यार्थियों को आवश्यक जीवन कौशल प्रदान करना।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के जीवन कौशल फ्रेमवर्क पर निर्मित, टिम टिम तारे पहल 16 प्रमुख जीवन कौशल (जैसे- सहानुभूति, क्रिटिकल थिंकिंग, शिष्टाचार, समय प्रबंधन, आदि) विकसित करने में मदद करती है।

### बेहतर शिक्षा के लिए बिल्डिंग ब्लॉक



| कार्यक्रम                                                                                                                 | उद्देश्य                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| निष्ठा/ NISHTHA                                                                                                           | एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम                                                                                           |
| जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIETs)                                                                                 | स्कूली शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण का मार्गदर्शन करने वाली जिला स्तरीय नोडल संस्थाएं                                         |
| कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय                                                                                            | वंचित समूहों की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय                                                                             |
| राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र 'परख' (PARAKH)                                                                                 | स्कूल शिक्षा बोर्डों का मार्गदर्शन, उपलब्धि सर्वेक्षण, छात्र मूल्यांकन के लिए मानक मानदंड, मूल्यांकन के लिए क्षमता निर्माण। |
| डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (DIKSHA)                                                                         | NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म।                                                                        |
| राज्यों के लिए शिक्षण-लर्निंग और परिणामों का सुदृढीकरण (Strengthening of teaching learning and results for states: STARS) | स्कूली शिक्षा के प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करना                                                                         |
| प्रधान मंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM SHRI)                                                                          | आदर्श विद्यालय स्थापित करना                                                                                                 |
| उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम                                                                                         | 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षरों के लिए आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान।                                              |
| PM पोषण                                                                                                                   | सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा 1-8 तक के विद्यार्थियों के लिए एक बार गर्म पका हुआ भोजन।                  |

<sup>46</sup> Social and Emotional Learning



|            |                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विद्यांजलि | स्वयंसेवकों (शैक्षणिक संस्थानों के पूर्व छात्र, सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षक, वैज्ञानिक) को सीधे उनकी पसंद के स्कूलों से जोड़ता है                                                         |
| नवचेतना    | यह पहल जन्म से तीन वर्ष तक के बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करती है तथा 36 महीने के प्रोत्साहन कैलेंडर के माध्यम से आयु के अनुरूप 140 विशिष्ट गतिविधियों की सूची प्रदान करती है। |
| आधारशिला   | यह तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 130 से अधिक ऐसी गतिविधियों के साथ खेल-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देता है, जो बाल-नेतृत्व और शिक्षक-नेतृत्व वाली शिक्षा का समर्थन करती हैं।          |

## डिजिटल प्रौद्योगिकी की मदद से कमियों को दूर करना

डिजिटल साक्षरता यह सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थी डिजिटल जानकारी का विश्लेषण, संश्लेषण और संचार जैसे कौशल में निपुणता प्राप्त करके प्रतिस्पर्धी बने रहें।

### उठाए गए कदम

- स्वयं/ SWAYAM (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एम्पायरिंग माइंड्स): एक ओपन शिक्षण विशाल ऑनलाइन कोर्सेस प्लेटफॉर्म है।
- प्रधान-मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA)।
- PM ई-विद्या: यह पहल 'दीक्षा' और 'साथी' प्लेटफॉर्म के माध्यम से विविध कंटेंट प्रस्तुत करके डिजिटल शिक्षा प्रयासों को एकीकृत करती है।
- कुशल और प्रभावी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।
  - शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए AI का लाभ उठाना और विद्यार्थियों के लिए AI-संचालित व्यक्तिगत ट्यूटर प्रदान करना।
  - शिक्षा में उद्योग के मांग के अनुरूप कौशल और प्रमाणन को एकीकृत करना।
  - व्यक्तिगत शिक्षण सॉफ्टवेयर लेयर्स का निर्माण और AI प्रयोगशालाओं का विकास करना।
- कक्षा में भौतिक तरीकों से लर्निंग की पारंपरिक पद्धति अभी भी उपयोगी है।
  - तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई इल्लम थेडी कलवी योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी और डिजिटल डिवाइड के कारण पैदा हुए शिक्षा संबंधी कमियों को दूर करना है।

### विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CwSN)<sup>47</sup>

- 16.8 लाख CwSN प्राथमिक (एलीमेंट्री) स्तर पर, 2.87 लाख माध्यमिक स्तर पर तथा 1.18 लाख उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नामांकित हैं।
- पहले: दिव्यांगता स्क्रीनिंग प्रशस्त (PRASHAST), PM ई-विद्या, समतामूलक और समावेशी शिक्षा पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश और कार्यान्वयन फ्रेमवर्क (NGIFEIE) (2021-2030)।

## उच्चतर शिक्षा

- 2014-15 से 2021-22 तक उच्चतर शिक्षा में नामांकन में 26.5% की वृद्धि हुई है।
- इसी अवधि के दौरान 18-23 आयु वर्ग के लिए GER 23.7% से बढ़कर 28.4% हो गया है।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) की संख्या 16 (2014) से बढ़कर 23 (2023) हो गई है, जबकि भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIMs) की संख्या 13 (2014) से बढ़कर 20 (2023) हो गई है।
- 2014-15 से 2022-23 तक उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEIs) की संख्या में 13.8% की वृद्धि हुई।

<sup>47</sup> Children with Special Needs

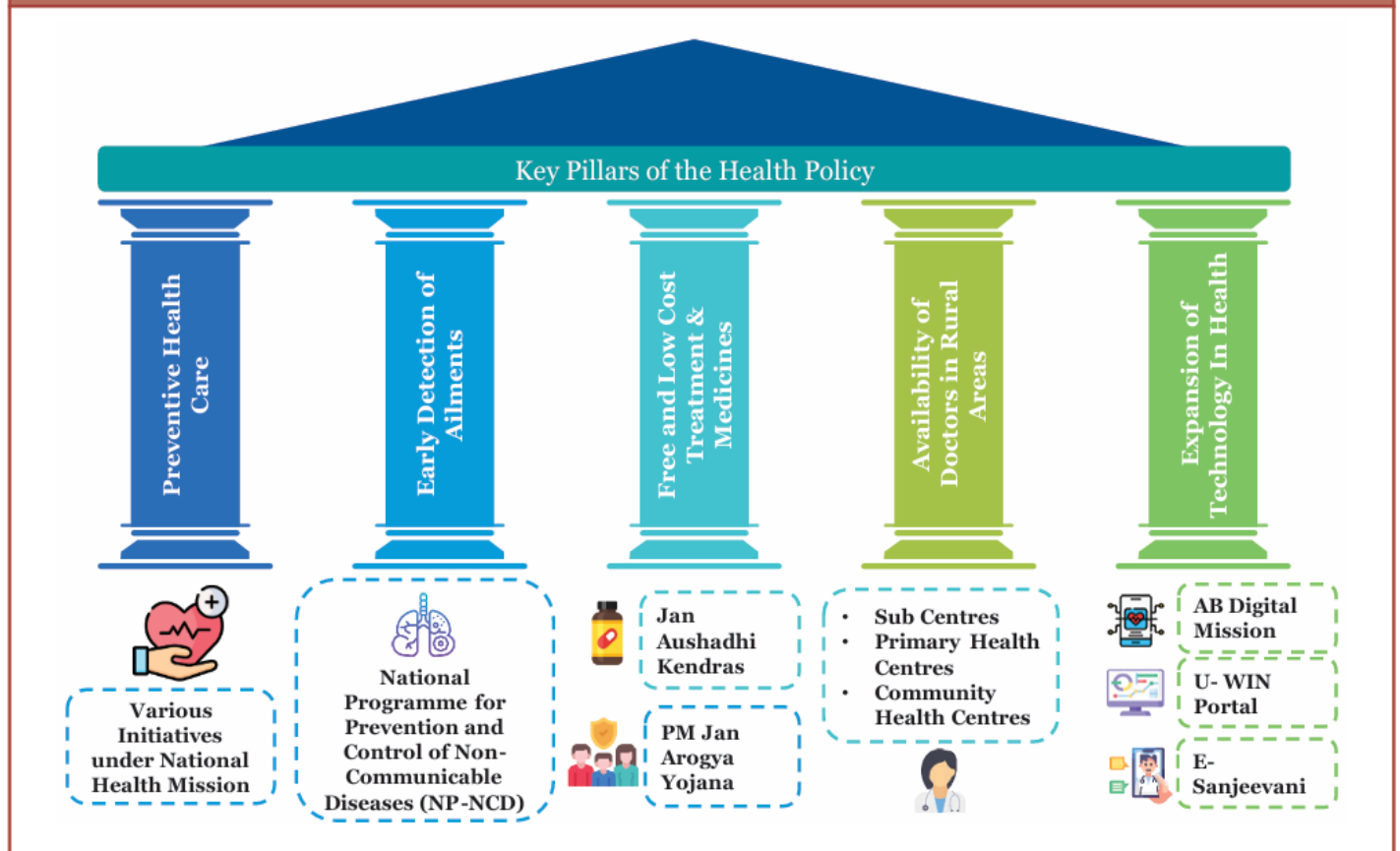
- भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक बनाने के लिए उठाए गए कदम:
  - NEP 2020, ऑनलाइन शिक्षा और ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ODL), निजी/ परोपकारी विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति, NEP द्वारा परिकल्पित 'लाइट बट टाइट' विनियामक मॉडल आदि।
- मेडिकल शिक्षा में चुनौतियां:
  - बहुनीयता (निजी क्षेत्र में फीस 60 लाख से एक करोड़ रुपये या उससे अधिक है, जिनमें MBBS की 48% सीटें हैं।)
  - भौगोलिक पहुंच (स्नातक स्तर की 51% सीटें और स्नातकोत्तर स्तर की 49% सीटें दक्षिणी राज्यों में हैं)
  - विशेषज्ञता कुछ ही शाखाओं की ओर अधिक है,
  - प्रवेश स्तर पर और डॉक्टरों के लिए पारिश्रमिक कम है, फैकल्टी की उपलब्धता कम है।

## एक स्वस्थ राष्ट्र की ओर

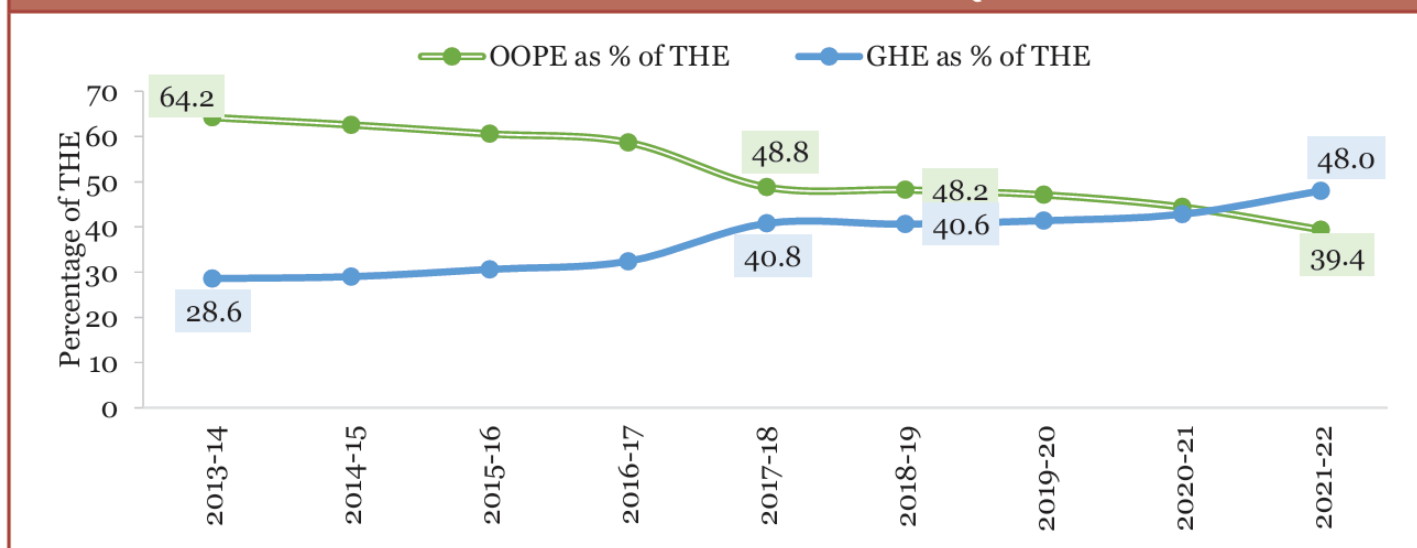
### स्वास्थ्य-देखभाल का अनुमान

- प्रति व्यक्ति कुल स्वास्थ्य व्यय (स्थिर मूल्यों पर) में वित्त वर्ष 2019 से वृद्धि का रुझान देखा गया है।
- सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29.0% से बढ़कर 48.0% हो गया है।
- कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) 62.6% से घटकर 39.4% हो गया है।

### चार्ट XI.5: स्वास्थ्य नीति के प्रमुख स्तंभ<sup>92</sup>



चार्ट XI.7: स्वास्थ्य संबंधी व्यय की प्रवृत्ति



- बीमा कवरेज के लिए उठाए गए कदम:-
  - कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)
  - केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS)
  - भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS)
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)
  - आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)

## भविष्य के लिए स्वास्थ्य-देखभाल सेवा में परिवर्तन

- उठाए गए कदम:
  - आयुष्मान भारत (AB):** 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना कुछ चुनिंदा स्वास्थ्य-देखभाल सेवाओं की जगह कई देखभाल-सेवाएं प्रदान करके बदलाव लाया है। यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) के संचालन के साथ प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य-देखभाल स्तरों पर बीमारी की रोकथाम, स्वस्थ-सेहत को बढ़ावा और उपचार से जुड़ी चिंताओं को दूर करती है।
  - PM-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM):** अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। यह मिशन वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 26 तक पांच वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य-देखभाल अवसंरचना को मजबूत करना है।
  - निःशुल्क औषधि सेवा पहल (FDSI):** यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  - सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP):** इसके तहत 11 टीके निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं, जो टीका से रोकथाम योग्य 12 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। वित्त वर्ष 24 में पूर्ण टीकाकरण कवरेज राष्ट्रीय स्तर पर 93.5% है।
  - किफायती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई जन औषधि योजना** ने महत्वपूर्ण गति प्राप्त कर ली है। इसने 2024 में रिकॉर्ड बिक्री हासिल की है और इसके देश भर में 14,000 से अधिक केंद्र हो गए हैं।

## निर्बाध और समतापूर्ण स्वास्थ्य-देखभाल सेवा प्रदान करने वाली रूपांतरणकारी प्रौद्योगिकियां

- **U-WIN:** यह यूजर-फ्रेंडली प्लेटफॉर्म टीकाकरण रिकॉर्ड तक बिना बाधा के पहुंच, लचीली शेड्यूलिंग और 'किसी भी समय पहुंच' और 'कहीं भी' टीकाकरण को सक्षम बनाता है।
- **ई-संजीवनी:** यह राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में दुनिया की सबसे बड़ी टेलीमेडिसिन कार्यान्वयन के रूप में उभरी है।
- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM):** इसे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन करता है।
- **एरियल एंजेल्स:** यह स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य को बदल रहा है, उदाहरण के लिए 'आई-ड्रोन' (ICMR का ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच फॉर नॉर्थ ईस्ट) पहल: यह टीके और चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग करती है।
- **AI के माध्यम से स्वास्थ्य-देखभाल सेवा को बेहतर बनाना:** रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स (IoMT) के साथ संयुक्त AI 'स्वास्थ्य-देखभाल सेवा के लिए नया नर्वस सिस्टम' बन सकता है। उदाहरण के लिए, राजस्थान सरकार द्वारा सिलिकोसिस प्रबंधन में टेली-रेडियोलॉजी और AI का उपयोग, आदि।
  - AI को अपनाने में चुनौतियों में विशेष प्रतिभा (तकनीकी और डोमेन-विशिष्ट दोनों) की कमी, डेटा जटिलताएं और विस्तार में कठिनाइयां शामिल हैं।

## मानसिक स्वास्थ्य पर जीवन-शैली और कार्य संस्कृति का प्रभाव

- मानसिक सेहत स्थायी नहीं होती है। कार्यस्थल की संस्कृति, कार्य के घंटे और जीवन-शैली सहित कई कारक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।
  - **मेंटल हेल्थ क्वेश्चनर (MHQ)** मूल्यांकन मानसिक कार्य-प्रणाली का आकलन करता है, जो तनावग्रस्त (distressed) से लेकर सुखद (thriving) स्थिति तक की स्थिति को दर्शाता है।
- एक अध्ययन में पाया गया है कि वैश्विक स्तर पर, अवसाद और चिंता के कारण प्रतिवर्ष लगभग 12 बिलियन दिन बर्बाद होते हैं, जिससे 1 ट्रिलियन डॉलर की वित्तीय हानि होती है।
- **बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं:** यह अक्सर इंटरनेट और विशेष रूप से सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से जुड़ी होती हैं।
  - "फोन-आधारित बचपन" बड़े होने के अनुभव को ही बदल रहा है।
- **उठाए गए कदम:** राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति, 2014; मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017, टेली-मानस मोबाइल एप्लिकेशन।

## स्वास्थ्य पर जीवन-शैली विकल्पों का प्रभाव

- **गैर-संचारी रोग (NCDs):**
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, गैर-संचारी रोग (NCDs) प्रत्येक वर्ष 41 मिलियन लोगों की मृत्यु का कारण बनते हैं। यह वैश्विक स्तर पर होने वाली कुल मौतों का 74% है।
  - भारत में NCDs के कारण होने वाली मौतों का अनुपात 1990 के 37.9% से बढ़कर 2016 में 61.8% हो गया।
    - **कारण:** अस्वास्थ्यकर आहार और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन, शारीरिक गतिविधियों की कमी, तंबाकू और शराब का सेवन।



- उठाए गए कदम:
  - NCDs की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NP-NCD)
  - NCDs का शीघ्र पता लगाने के लिए जनसंख्या-आधारित स्क्रीनिंग (PBS) पहल शुरू की गई है। इसका लक्ष्य 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति को शामिल करना है।
- आगे की राह: हेल्थ टैक्स लगाना, हानिकारक उत्पादों पर लेबलिंग लगाना और इनकी मार्केटिंग पर प्रतिबंध लगाना, जागरूकता का प्रसार करना, लाइफ (LIFE) पहल शुरू करना, विज्ञापन का विनियमन आदि।

## ग्रामीण अर्थव्यवस्था

सरकार का जोर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर है, ताकि अधिक न्यायसंगत और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस संबंध में ग्रामीण आवास, पेयजल और स्वच्छता, स्वच्छ ईंधन, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण कनेक्टिविटी जैसे कई उपाय किए गए हैं।

## ग्रामीण बुनियादी ढांचा

- ग्रामीण आवास: प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN), विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) की असंबद्ध बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत एक अलग वर्टिकल लॉन्च किया गया है।

## सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण: ग्रामीण प्रगति को बल देना

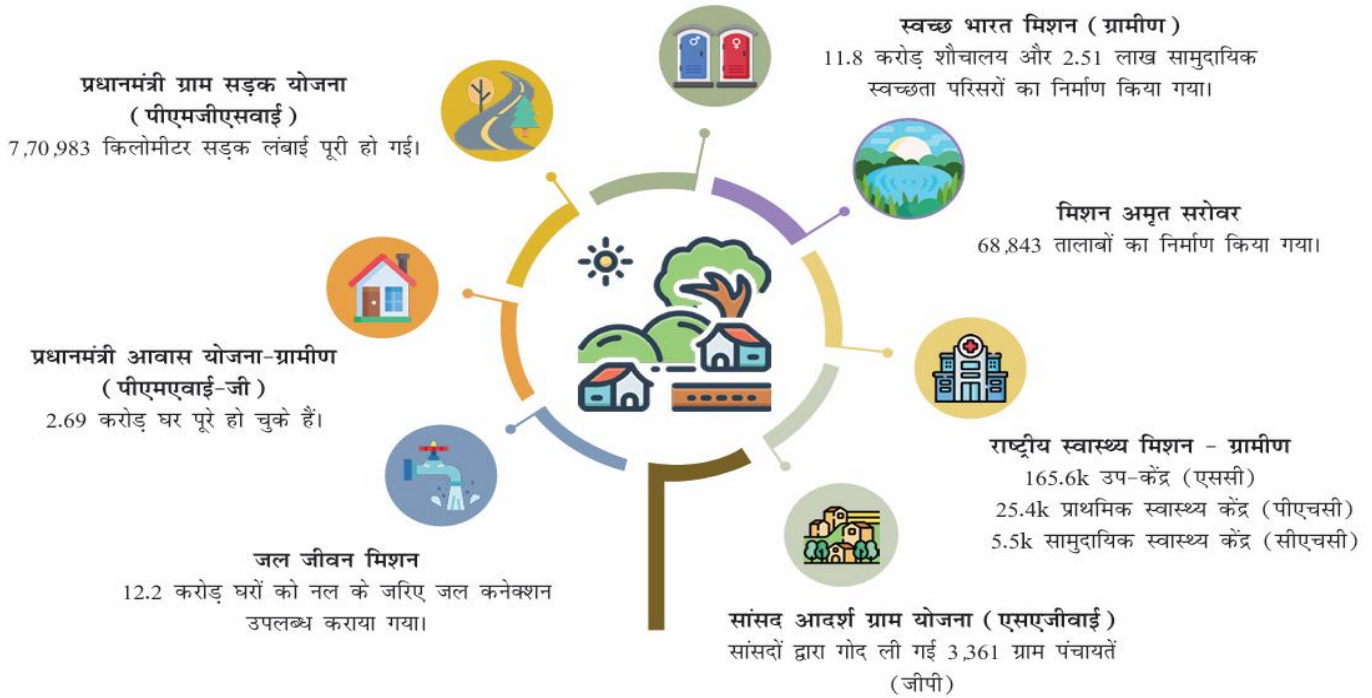
- **SDGs स्थानीयकरण** SDGs को अनुकूलित और कस्टमाइज करने तथा उन्हें ऐसी स्थानीय विकास योजनाओं और रणनीतियों में लागू करने की प्रक्रिया है, जो राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के साथ सामंजस्य में किसी विशेष क्षेत्र या इलाके की जरूरतों, प्रासंगिकता और प्राथमिकताओं के अनुकूल हो (संयुक्त राष्ट्र, 2024)।
  - यह सोच जमीनी स्तर पर समावेशी विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाती है।
- मिशन अंत्योदय और आकांक्षी जिला परिवर्तन कार्यक्रम (TADP)<sup>48</sup> के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से ग्राम पंचायत (GP) स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण का कार्य किया जा रहा है।
- ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय संकेतक फ्रेमवर्क (LIF)<sup>49</sup> की तैयारी पहले से ही चल रही है। इसके अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्यों को शामिल करते हुए नौ थीम तैयार की गई हैं।
- भारत में उदाहरण:
  - स्थानीय स्वशासन विभाग ने केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान (KILA)<sup>50</sup> के तकनीकी सहयोग से स्थानीय योजना में सतत विकास लक्ष्यों को शामिल करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं विकसित की हैं।
  - 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (जैसे-आंध्र प्रदेश, हरियाणा आदि) में SDG समन्वय केंद्र (SDGCCs) स्थापित किए गए हैं।
  - नीति आयोग के SDG समन्वय और एक्सीलरेशन केंद्र (SDGCACs) कार्य कर रहे हैं।

<sup>48</sup> Transformation of Aspirational Districts Programme

<sup>49</sup> Local Indicator Framework

<sup>50</sup> Kerala Institute for Local Administration

## ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना



## ग्रामीण कल्याण की दिशा में अन्य उपाय

- **खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और वाश/ WASH (FNHW):** स्वास्थ्य, पोषण, WASH और स्वच्छता संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए, DAY-NRLM FNHW उपायों को लागू करता है। यह न्यूट्री-गार्डन; मुर्गी पालन, जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और डेयरी से प्राप्त उत्पादों के उपभोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **सामाजिक समावेशन और जेंडर:** राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLMs) ने DAY-NRLM घटकों और सामुदायिक संस्थाओं को एकीकृत करने के लिए राज्य-विशिष्ट रणनीति तैयार की है। इससे बाल शिक्षा, कम उम्र में विवाह, महिलाओं के लिए परिसंपत्ति निर्माण और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे मुद्दों का समाधान हो सकेगा।
- **स्थानीय स्तर पर लैंगिक मुद्दों के समाधान के लिए जेंडर पॉइंट पर्सन्स (GPPs) द्वारा समर्थित जेंडर प्रोसेसिंग सेंटर्स (GRCs) स्थापित किए जा रहे हैं।**
  - 25 लाख से अधिक GPPs और 89,000 से अधिक जेंडर-CRPs 31,000 से अधिक क्लस्टर स्तरीय फेडरेशंस (CLFs) और 5,00,000 ग्राम संगठनों (VOs) के साथ कार्य करते हैं।
- **दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क कानूनी सहायता:** विधिक सेवा प्राधिकरण (LSA) अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) समाज के वंचित वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करता है।
- **अन्य:** ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)।

## ग्रामीण आय में वृद्धि

- **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY NRLM)**
  - DAY-NRLM प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। इसे 2011 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और मजदूरी आधारित कौशल वाले रोजगार के अवसरों तक पहुंच प्रदान करके गरीबी को कम करना है।

## • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना:

- मनरेगा 2005 का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इसके तहत ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, जिसके वयस्क सदस्य अनस्किल्ड शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तैयार होते हैं।
- 99.98% मजदूरी-भुगतान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से होते हैं।
- मनरेगा की शुरुआत मजदूरी आधारित रोजगार योजना के रूप में हुई थी, लेकिन अब यह स्थायी आजीविका के लिए विविध कार्य के रूप में स्थायी ग्रामीण परिसंपत्ति सृजन कार्यक्रम का रूप ले चुकी है।
  - इनमें मृदा गुणवत्ता और वृक्षारोपण बढ़ाने के माध्यम से ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार और एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन (IWM) परिसंपत्तियों के माध्यम से कृषि के लिए बेहतर ग्रामीण जल प्रबंधन शामिल हैं।
  - बेयर फुट टेक्नीशियन (बीएफटी) और उन्नति कौशल परियोजना जैसी पहलों के माध्यम से श्रमिकों की क्षमता विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- अन्य पहलों के साथ एकीकरण: NRLM के साथ न्यूट्री-गार्डन्स, पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) के साथ चारा फार्म, मत्स्य पालन विभाग के साथ तालाबों और कृषि तालाबों में जलीय कृषि को बढ़ावा देना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ ग्रामीण सड़कें आदि।

## आउटलुक

- सरकार द्वारा कल्याण-संवर्द्धन एग्रेस, जो सभी नागरिकों को सशक्त बनाने और कल्याणकारी उपायों के कुशल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने पर केंद्रित हो।
- शिक्षा, स्वास्थ्य-देखभाल, कौशल और इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बेहतर सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के साथ, सभी के लिए कल्याण प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य हैं।
- स्कूली कक्षा के मानकों और वास्तविक लर्निंग के स्तर के बीच अंतर विद्यमान है। इसे ऐसे नवीन शिक्षण पद्धतियों तथा रणनीतियों को लागू करके दूर किया जा सकता है जो पीयर-लर्निंग, सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता और जीवन कौशल को प्राथमिकता देती हों।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, वृद्धि देखभाल और गैर-संचारी रोगों की रोकथाम को बढ़ावा देती है। इसके अलावा, मानसिक स्वास्थ्य पहल और रणनीतियाँ स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने, गैर-संचारी रोगों से निपटने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- आने वाले वर्षों में जनसांख्यिकीय लाभांश को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए बाजारों को बढ़ावा देने के साथ-साथ पारदर्शिता और डिस्क्लोजर द्वारा समर्थित विश्वसनीय विनियमन की भी आवश्यकता है।

## बजट में क्या कहा गया है?

- सामाजिक कल्याण: 60,052 करोड़ रुपये आवंटित,
- ग्रामीण विकास: 2,66,817 करोड़ रुपये आवंटित,
- शिक्षा व्यय: 1,28,650 करोड़ रुपये आवंटित,
- स्वास्थ्य व्यय: 98,311 करोड़ रुपये आवंटित
- ग्रामीण अवसंरचना: PMGSY (चरण IV) के तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

## शब्दावली

| शब्द/ पद  | अर्थ                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जीवन कौशल | WHO के अनुसार, जीवन कौशल अनुकूली और सकारात्मक व्यवहार संबंधी क्षमताएं हैं जो लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आवश्यकताओं और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाती हैं। उदाहरण के लिए, सहानुभूति, क्रिटिकल थिंकिंग, शिष्टाचार, समय प्रबंधन। |



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा (SEL) | सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा (SEL) भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने, दूसरों की देखभाल करने और उनके बारे में चिंतित होने, सकारात्मक संपर्क स्थापित करने, जिम्मेदार निर्णय लेने और चुनौतीपूर्ण स्थितियों को प्रभावी तरीके से संभालने की क्षमता हासिल करने की एक प्रक्रिया है। (यूनेस्को) |
| आउट ऑफ पॉकेट व्यय                 | यह उस व्यय को दर्शाता है जो एक रोगी को अपने या अपने परिवार के उपचार में अपनी पॉकेट से करने होते हैं, और स्वास्थ्य-बीमा इलाज पर सभी खर्चों को कवर नहीं करती हैं।                                                                                                                          |
| घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण        | यह परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के बारे में जानकारी एकत्र करता है।                                                                                                                                                                                                         |
| SDG स्थानीयकरण                    | यह सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के स्थानीयकरण SDGs को अनुकूलित और कस्टमाइज करने तथा उन्हें इन स्थानीय विकास योजनाओं और रणनीतियों में एकीकृत करने की प्रक्रिया है।                                                                                                                           |

## अपने सीखने के कौशल का परीक्षण कीजिए

### MCQs

- निम्नलिखित में से कौन-सा 'आधारशिला' का उद्देश्य है?
  - प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा
  - वहनीय सामाजिक बीमा योजना
  - गंभीर बीमारियों के लिए सब्सिडी वाली दवाइयाँ
  - रोजगार सृजन कार्यक्रम
- निम्नलिखित में से कौन-से 'टिम टिम तारे पहल' के उद्देश्य हैं?
  - इसका उद्देश्य पूरे भारत में किशोर विद्यार्थियों को आवश्यक जीवन कौशल प्रदान करना है।
  - यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के जीवन कौशल फ्रेमवर्क पर आधारित है।
  - इसमें सॉफ्ट स्किल्स पर जोर दिया जाता है।
  - प्रत्येक विषय को गतिविधि-आधारित लर्निंग के साथ डिज़ाइन किया गया है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

  - केवल एक
  - सभी चारों
  - कोई नहीं
  - केवल दो
- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  - इसका उद्देश्य निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराना है।
  - इसमें 11 टीके दिए जाते हैं, जिनमें डिप्थीरिया, पर्तुसिस, टिटनेस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बाल क्षय रोग के गंभीर रूप, हेपेटाइटिस B, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B (Hib), न्यूमोकोकल और डायरिया रोगों के खिलाफ टीके शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  - केवल 1
  - केवल 2
  - 1 और 2 दोनों
  - कोई नहीं

## 4. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

1. **U-WIN:** यह यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म टीकाकरण रिकॉर्ड तक बिना बाधा के पहुंच, लचीला शेड्यूलिंग और 'किसी भी समय पहुंच' और 'कहीं भी' टीकाकरण को सक्षम बनाता है।
2. **ई-संजीवनी:** यह राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में दुनिया की सबसे बड़ी टेलीमेडिसिन कार्यान्वयन के रूप में उभरी है।
3. **'आई-ड्रोन/ i-DRONE' (ICMR का ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच फॉर नॉर्थ ईस्ट):** टीके और चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग करना।

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) कोई नहीं
- (d) सभी तीनों

## 5. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

- (a) PMGSY के अंतर्गत एक अलग वर्टिकल शुरू किया गया है।
- (b) जनसंख्या मानदंड में 1,00,000 तक की छूट दी गई है।
- (c) इस परियोजना के अंतर्गत कुल 80,000 किलोमीटर लम्बी सड़क का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है।
- (d) इसका उद्देश्य सभी जनजातीय बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

## मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न

1. शिक्षा देश के विकास की नींव है। चर्चा कीजिए कि क्या प्रौद्योगिकी ने भारतीय संदर्भ में पारंपरिक शिक्षण संरचना में व्यापक बदलाव लाया है। सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए क्या विभिन्न उपाय किए गए हैं? (250 शब्द)
2. "फोन-आधारित बचपन" बड़े होने के अनुभव को ही बदल रहा है। बच्चों पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर चर्चा कीजिये और इससे होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय सुझाइये। (150 शब्द)

# मासिक समसामयिकी रिवीजन कक्षाएं 2025

GS प्रीलिम्स और मेन्स

हिन्दी माध्यम



English Medium

31 JAN | 5 PM

25 JAN | 5 PM

**VISIONIAS**  
INSPIRING INNOVATION



► Live/Online Classes are available

## अध्याय 12: रोजगार और कौशल विकास: अस्तित्वगत प्राथमिकताएँ (Employment and Skill Development: Existential Priorities)

### परिचय

संवृद्धि और समृद्धि के बीच रोजगार एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत की युवा पीढ़ी की वाजिब आकांक्षाओं के अनुरूप उपयुक्त रोजगार अवसरों का सृजन, जनसांख्यिकीय लाभांश के दुर्लभ अवसर का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है।

### अध्याय का प्रीकैप

#### रोजगार की स्थिति

- वर्तमान रोजगार परिदृश्य: बेरोजगारी दर में गिरावट आई है।
- महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) में वृद्धि आर्थिक संवृद्धि के लिए महिला श्रम का उपयोग।
- मजदूरी और आय में सुधार हुआ है।
- भारत में औपचारिक क्षेत्र का विकास: EPFO सब्सक्राइबर्स की संख्या में निवल वृद्धि।

#### रोजगार सृजन: रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में कदम

- सुरक्षा बनाम लचीलापन: रोजगार सृजन में विनियमन की भूमिका
- डिजिटल अर्थव्यवस्था के माध्यम से रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना
- हरित कार्यबल का निर्माण: अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार सृजन

#### कौशल विकास: बदलती दुनिया के लिए नव कौशल (न्यू-स्किलिंग), कौशल में सुधार (रिस्किलिंग) और कौशल बढ़ाना (अप-स्किलिंग)

- कौशल परिदृश्य
- स्तरीय कौशल फ्रेमवर्क और इंटर्नशिप कार्यक्रमों का महत्व
- कुशल कार्यबल की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही

### भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश

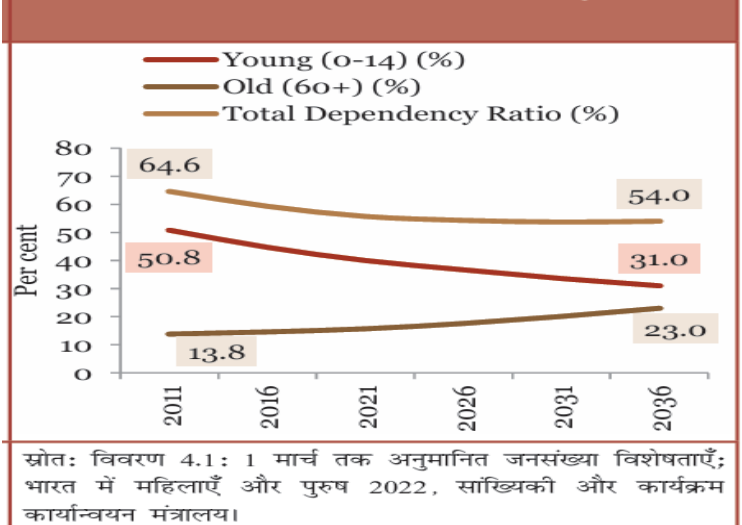
- लगभग 26% जनसंख्या 10-24 वर्ष आयु वर्ग में है, जिससे निर्भरता अनुपात में गिरावट आई है।
- प्रजनन दर में गिरावट के कारण निर्भरता अनुपात में कमी (जो बाल निर्भरता अनुपात में आई गिरावट से साफ परिलक्षित होता है) ने जनसांख्यिकीय लाभ में योगदान दिया है।
- कुल निर्भरता अनुपात 64.6% (2011) से घटकर 55.7% (2021) हो गया है और 2026 तक इसके और गिरकर 54.3% होने का अनुमान है।

### रोजगार की स्थिति

#### वर्तमान रोजगार परिदृश्य

- बेरोजगारी:
  - 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दर (UR) 2017-18 के 6.0% से लगातार घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है।
  - शहरी बेरोजगारी दर (UR) वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही में 6.6% से घटकर वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 6.4% हो गई है।
- श्रम बल भागीदारी:
  - इसी अवधि (वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही से वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही) के दौरान श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 49.3% से बढ़कर 50.4% हो गई और श्रमिक-जनसंख्या अनुपात (WPR) 46% से बढ़कर 47.2% हो गया।

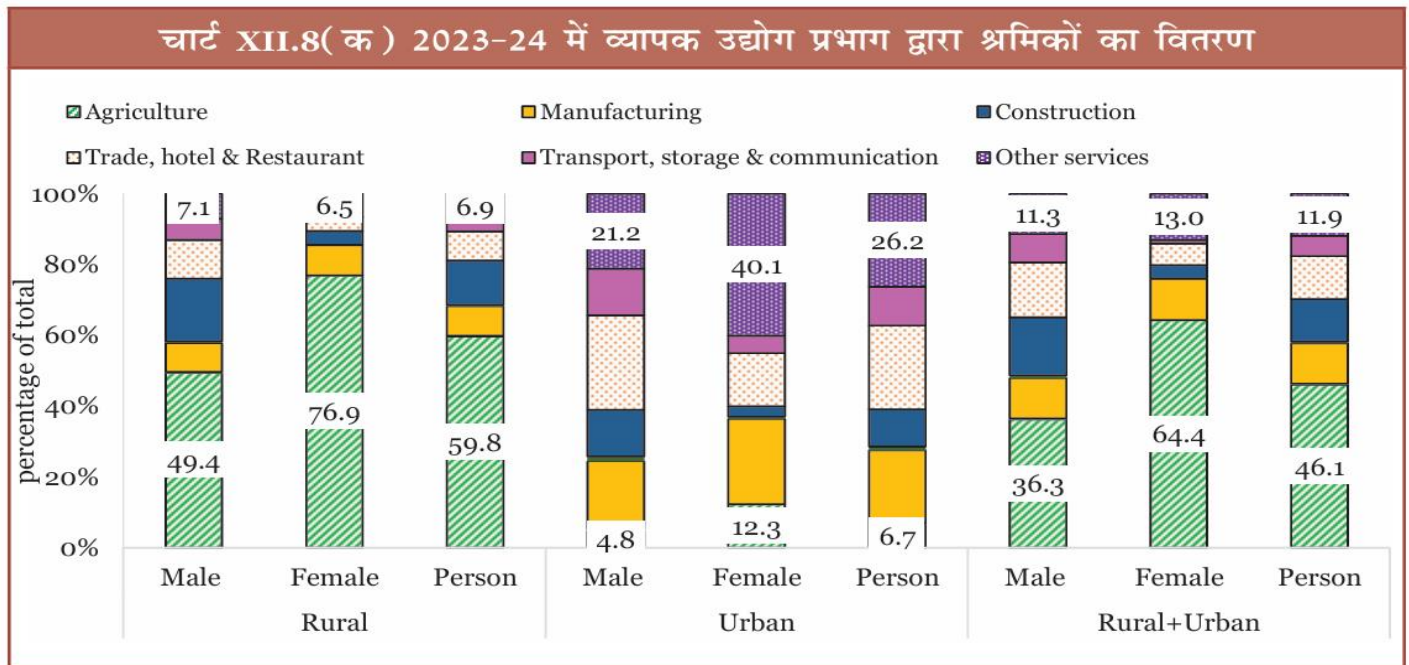
चार्ट XII.2 (ख): निर्भरता अनुपात



- 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 12 राज्यों में WPR (सभी आयु वर्गों के लिए) 43.7% के राष्ट्रीय औसत से कम है तथा 12 राज्यों में LFPR (सभी आयु वर्गों के लिए) 45.1% के राष्ट्रीय औसत से कम है।
- श्रमिकों की श्रेणियाँ:
  - स्व-नियोजित श्रमिक: यह 2017-18 के 52.2% से बढ़कर 2023-24 में 58.4% हो गया।
  - नियमित/ वेतनभोगी कामकाजी श्रमिक: इसी अवधि के दौरान यह 22.8% से घटकर 21.7% हो गया, यह प्रवृत्ति 2020-21 से स्थिर हो गई है।
  - कैजुअल वर्कर्स अनुपात में गिरावट: 24.9% से घटकर 19.8% हो गई है, जिससे स्वरोजगार के अधिक संगठित रूपों की ओर बदलाव का संकेत मिलता है।
  - महिलाएँ
    - नियमित वेतन/ वेतनभोगी रोजगार में महिलाओं का अनुपात कम हुआ है, लेकिन अब अधिक महिलाएं स्व-रोजगार में संलग्न हैं या घरेलू उद्यमों में योगदान दे रही हैं।

## कार्यबल का क्षेत्रीय वितरण

- रोजगार में कृषि का हिस्सा 2017-18 में 44.1% से बढ़कर 2023-24 में 46.1% हो गया है।
  - महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2017-18 की 57.0% से बढ़कर 2023-24 में 64.4% हो गई है, जबकि कृषि में पुरुषों की भागीदारी 40.2% से घटकर 36.3% हो गई है।
  - रोजगार में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 12.1% से घटकर 11.4% हो गई है।
- इसी अवधि के दौरान रोजगार में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी भी 31.1% से घटकर 29.7% हो गई है।



## महिला LFPR में वृद्धि: आर्थिक विकास के लिए महिला श्रम का उपयोग

- लैंगिक दृष्टिकोण से, महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) 23.3% (2017-18) से बढ़कर 41.7% (2023-24) हो गई है।
  - इसका मुख्य कारण ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है (ग्रामीण FLFPR 2017-18 की 24.6% से बढ़कर 2023-24 में 47.6% हो गई है)।
  - इसके अलावा, ग्रामीण FLFPR में वृद्धि का श्रेय दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत महिला समूहों को प्रदान किए गए विविध आजीविका के लिए कौशल पहल और ऋण वितरण में सुधार को दिया जा सकता है।

- अधिकतर राज्यों (21) में FLFPR 30-40% के बीच है।
- सात राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने 2023-24 में 40% से अधिक FLFPR दर्ज किया है (सिक्किम में अधिकतम 56.9% की वृद्धि दर दर्ज की गई)।
- महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ: बच्चों की देखभाल की ज़िम्मेदारियाँ, पारंपरिक से गैर-पारंपरिक जीवन में परिवर्तन, कौशल विकास, लैंगिक भेदभाव।

## भारत के आर्थिक भविष्य के लिए महिला उद्यमियों की शक्ति का उपयोग

- अलग-अलग क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी
  - खादी क्षेत्र में लगभग 80% से अधिक कारीगर महिलाएं हैं।
  - रेशम उत्पादन का कार्य करने वाले व्यक्तियों में 50% से अधिक महिलाएं शामिल हैं।

- चिंताएं
  - स्वामित्व एवं नेतृत्व: सभी MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) में से केवल 22% MSMEs का स्वामित्व महिला उद्यमियों के पास हैं। इसके अलावा, 2023 में केवल 18.3% कम्पनी बोर्ड सदस्य महिलाएं थीं।

- ग्रामीण महिलाओं को सीमित व्यावसायिक कौशल, बाजार तक पहुंच और प्रौद्योगिकी उपयोग क्षमता की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो मार्गदर्शन और नेटवर्किंग की कमी से और भी जटिल हो जाती हैं।
- कौशल की कमी, नियमों के पालन संबंधी बाधाओं और सीमित आवाजाही जैसी व्यवस्थागत चुनौतियां महिलाओं को डिजिटल प्लेटफार्मों के उपयोग को सीमित करती हैं।

| बॉक्स XII.2: महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने कई पहल शुरू की हैं, जिनमें से कुछ नीचे प्रस्तुत हैं।                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
| सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय <sup>0</sup>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
| <br><b>उद्यमों का औपचारिकीकरण<sup>1</sup></b><br>जनवरी 2023 से औपचारिक रूप से स्थापित 2.41 करोड़ उद्यमों में से 63 प्रतिशत महिला स्वामित्व वाले हैं।          | <br><b>विपणन सहायता<sup>2</sup></b><br>महिलाओं की व्यापार मेले में भागीदारी को पूरी तरह से सब्सिडी दी जाती है। | <br><b>प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम<sup>3</sup></b><br>वित्त वर्ष 24 में 41 प्रतिशत ऋण महिलाओं को स्वीकृत किए गए, जिनमें सब्सिडी अधिक (25-35 प्रतिशत) और योगदान कम (5 प्रतिशत) था।                                                    | <br><b>खरीद</b><br>सीपीएसई द्वारा खरीद का 3 प्रतिशत महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए आरक्षित है। |
| <br><b>कौशल विकास</b><br>5 वर्षों में 21,600 से अधिक महिलाओं ने कॉयर निर्माण में प्रशिक्षण प्राप्त किया; निःशुल्क उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। | <br><b>जेडईडी प्रमाणन<sup>4</sup></b><br>महिला एमएसएमई के लिए प्रमाणन पर 100 प्रतिशत सब्सिडी।                | <br><b>ऋण सहायता<sup>5</sup></b><br>क्रेडिट गारंटी योजना के तहत महिला उद्यमियों को 90 प्रतिशत गारंटी (अन्य के लिए 75 प्रतिशत की तुलना में) मिलता है और कम शुल्क मिलता है। स्वीकृत 97.68 लाख गारंटियों में से 22 प्रतिशत महिलाओं के लिए हैं। |                                                                                                                                                                                             |
| कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
| <br><b>संकल्प<sup>6</sup></b><br>2021 से 2024 के बीच 32,262 महिलाओं (67 प्रतिशत लाभार्थियों) को उद्यमिता में प्रशिक्षित किया गया।                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |

- उठाए गए कदम: ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप (GAME), "ग्रोथरेटर" कार्यक्रम MSME विकास के लिए मेंटरशिप और सहकर्मी नेटवर्क के माध्यम से लाभप्रदता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है।
- WE हब - तेलंगाना सरकार का महिला उद्यमी केंद्र।

## मजदूरी और आय में रुझान

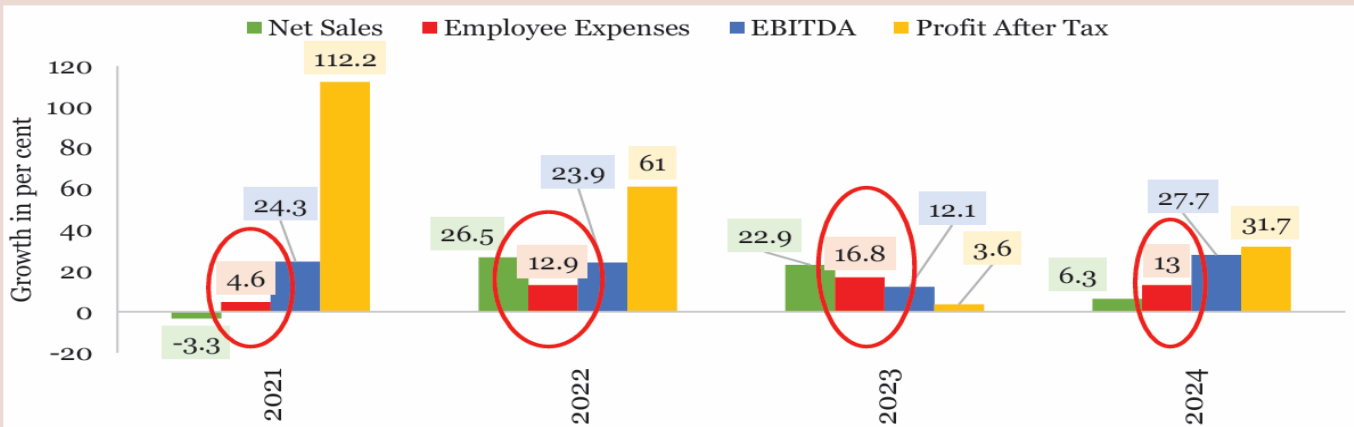
- नियमित वेतन/ वेतनभोगी श्रमिकों और स्व-नियोजित श्रमिकों की औसत मासिक आय 2018-19 से 2023-24 की अवधि के दौरान 5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ी है, जबकि कैजुअल वर्कर्स का दैनिक वेतन समान अवधि में 9% की CAGR से बढ़ा है।
- सभी श्रेणियों में नॉमिनल मजदूरी दर में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है, जो वास्तविक मजदूरी की वृद्धि से अधिक है।
- ग्रामीण मजदूरी: वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल से सितंबर 2024) में ग्रामीण मजदूरी हर महीने सालाना आधार पर 4% से अधिक बढ़ी है।
  - कृषि में नॉमिनल मजदूरी दर पुरुषों के मामले में 5.7% और महिलाओं के मामले में 7% बढ़ी है।
  - गैर-कृषि गतिविधियों में पुरुषों के लिए नॉमिनल मजदूरी वृद्धि 5.5% थी जबकि महिलाओं के लिए यह 7.9% थी।
- असंगठित क्षेत्र (unincorporated) के उद्यमों में मजदूरी:
  - असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE)<sup>51</sup> परिणाम:
    - 2022-23 की तुलना में 2023-24 में प्रति कर्मचारी औसत पारिश्रमिक 13% बढ़ा है।
  - कॉर्पोरेट लाभप्रदता
    - वित्त वर्ष 2024 में यह 15 वर्ष के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई, जिसमें लाभ 22.3% बढ़ा, हालांकि रोजगार सृजन में मात्र 1.5% की वृद्धि हुई।
    - समाधान: सरकार, व्यवसायों और श्रमिकों के बीच एक सामाजिक अनुबंध जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में किया गया था।

तालिका XII.2: आय के रुझान

| अंकित मान  | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| नियोजित    | 15885   | 16728   | 17572   | 18391   | 19491   | 20702   |
| स्व-रोजगार | 10323   | 10454   | 10563   | 11678   | 13131   | 13279   |
| अनियत      | 277     | 291     | 318     | 374     | 403     | 418     |

नोट: 1. नियमित और स्व-रोजगार श्रमिकों के लिए, औसत मासिक नकद आय की सूचना प्रदर्शित है।  
2. अनियत श्रमिकों के लिए, प्रति दिन औसत कमाई की सूचना प्रदर्शित है।  
स्रोत: वार्षिक पीएलएफएस 2023-24, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

चार्ट XII.12: 4000 सूचीबद्ध संस्थाओं के प्रमुख मापदंडों में वृद्धि



स्रोत: क्लाइन; एसबीआई रिसर्च; लगभग 4000 सूचीबद्ध संस्थाएँ

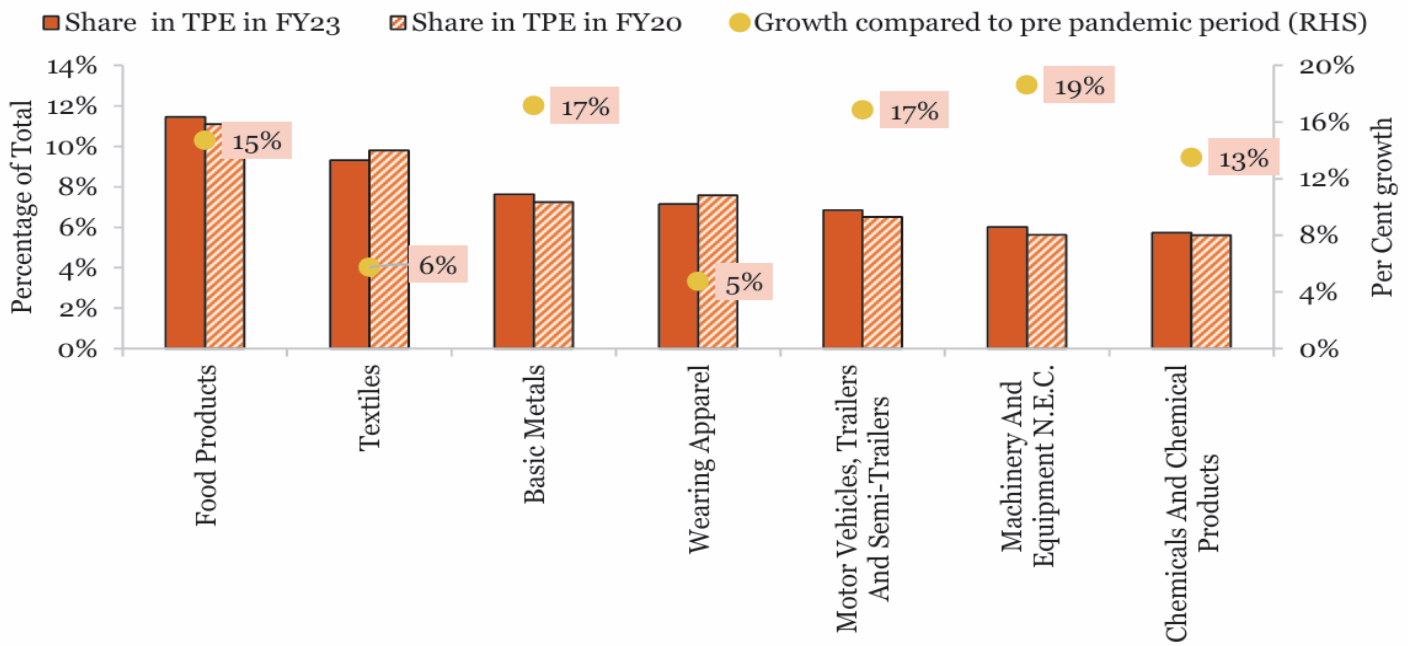
## कारखानों में रोजगार

- उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) वित्त वर्ष 2023 के परिणाम:
  - विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में 7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

<sup>51</sup> Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises

- बड़े कारखानों में कुल श्रमिकों का लगभग 80% नियोजित है।
- कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों तथा फर्नीचर के विनिर्माण में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है।

चार्ट XII.15: रोजगार में उच्च हिस्सेदारी दर्ज करने वाले उद्योग समूह



स्रोत: वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

### भारत में औपचारिक क्षेत्र का विकास

- EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) सब्सक्रिप्शन में निवल वृद्धि दोगुने से अधिक हो गई है, जो वित्त वर्ष 2019 के 61 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 131 लाख हो गई।
- औद्योगिक संरचना: EPFO पेरोल वृद्धि में सबसे बड़ा हिस्सा विशेषज्ञ सेवाओं (एक्सपर्ट सर्विसेज) का है (वित्त वर्ष 2025, अप्रैल-नवंबर में 50%), इसके बाद व्यापार-अन्य उद्योग (12%) और व्यापार-वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का (7%) स्थान है।
- आयु समूह: सभी आयु समूहों में, 18-25 वर्ष के आयु समूह ने निवल पेरोल वृद्धि में 47% का योगदान दिया।

### असंगठित श्रमिकों का कल्याण

- असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण और उनका समर्थन करने के लिए ई-श्रम पोर्टल शुरू किया गया।
- ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" लॉन्च किया गया, जिसमें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/ कल्याण योजनाओं को एक ही पोर्टल पर एकीकृत करना शामिल है।

### रोजगार सृजन: रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में कदम

#### सुरक्षा बनाम लचीलापन: रोजगार सृजन में विनियमन की भूमिका

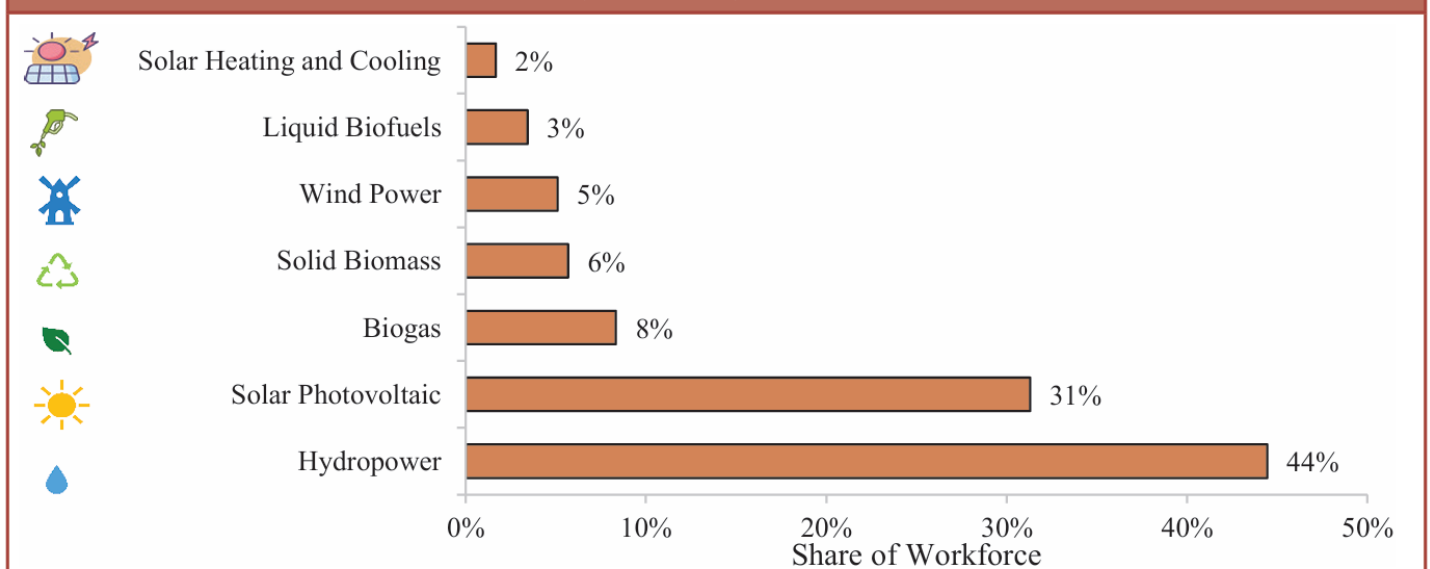
- विनियमन का उद्देश्य: व्यवसाय करने में सुगमता, श्रम बाजार में लचीलापन, श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा और फर्मों को जवाबदेह बनाना।
- उठाए गए कदम: चार श्रम संहिताओं का निर्माण
  - वेतन संहिता, 2019
  - सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020
- चुनौतियाँ:
  - व्यावसायिक सुरक्षा (रोजगार की प्रकृति की वजह से खतरा) और स्वास्थ्य
    - समाधान: प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान, MSMEs में जोखिम का पता लगाने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) को अपनाना, कफायती वर्चुअल रियलिटी प्रशिक्षण मॉड्यूल, क्लेम की ट्रैकिंग के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी।
    - अन्य: कार्यस्थल पर सुरक्षा पुरस्कार, कर छूट और मशीन सुरक्षा सब्सिडी कार्यक्रम।
  - लचीलापन की कमी: श्रम नियमों का अत्यधिक अनुपालन, जैसे कि कारखाना अधिनियम (1948) की धारा 51 के तहत अधिकतम कार्य घंटों को सीमित करना, कारखाना अधिनियम (1948) की धारा 65(3)(iv) के तहत कारखाना श्रमिकों के लिए ओवरटाइम पर प्रतिबंध।

### डिजिटल अर्थव्यवस्था के माध्यम से रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना

- OECD डिजिटल अर्थव्यवस्था को "डिजिटल प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे, डिजिटल सेवाओं और डेटा सहित डिजिटल इनपुट के उपयोग पर निर्भर या महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाई गई सभी आर्थिक गतिविधियों के रूप में परिभाषित करता है। यह सरकार सहित सभी उत्पादकों और उपभोक्ताओं को संदर्भित करता है, जो आर्थिक गतिविधियों में इन डिजिटल इनपुट का उपयोग करते हैं"।
- भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के 2025 तक एक ट्रिलियन अमरीकी डालर को पार करने का अनुमान है।
  - संरचना: वस्तु डिलीवरी कर्मी, कैब ड्राइवर, ब्यूटीशियन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट्स, परिवहन, खाद्य वितरण और घरेलू सेवा उद्योग जैसे हाइपरलोकल सेवा प्लेटफॉर्म।
  - आंकड़े:
    - अनुमान है कि 2029-30 तक गिग कार्यबल 23.5 करोड़ तक पहुंच जाएगा, जिसमें गैर-कृषि कार्यबल का 6.7% और कुल आजीविका का 4.1% शामिल होगा।
    - फिनटेक से महिला रोजगार और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।

चार्ट XII.19: अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में नौकरियों का हिस्सा



स्रोत: अक्षय ऊर्जा और नौकरियाँ: वार्षिक समीक्षा 2024. अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी

### हरित कार्यबल का निर्माण: अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार सृजन

- IRENA, 2024 के अनुसार भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में नौकरियों की कुल संख्या 2023 में अनुमानित 1.02 मिलियन तक पहुंच गई जिसमें हाइड्रो पावर क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है।

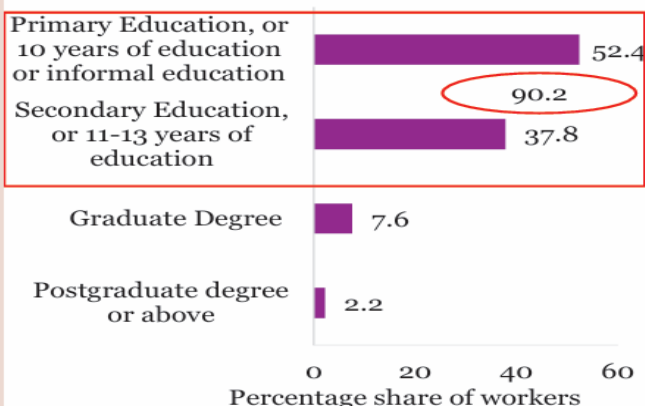
- ग्लोबल एनर्जी एलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट (GEAPP) उपाय: GEAPP इंडिया महिला उद्यमों की आजीविका में सुधार लाने के लिए, विश्वसनीय स्वच्छ ऊर्जा तक उनकी पहुंच प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों को डिजाइन और विकसित करने के लिए DAY-NRLM के साथ मिलकर काम करता है।
- महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर की चुनौतियाँ:
  - जलवायु परिवर्तन, आपदाएं, पुरुष और महिला के बीच भेदभाव करने वाली प्रौद्योगिकियां, सीमित वित्तपोषण, सामाजिक-सांस्कृतिक और भौगोलिक बाधाएं।
    - दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा की कमी, बाजार पहुंच में बाधाएं और ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति की कमी सहित कई अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- समाधान: विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा (DRE)<sup>52</sup> का उपयोग करने वाले जलवायु-स्मार्ट समाधानों का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ओडिशा के मिलेट मिशन के तहत बोइपारीगुडा-सबुजिमा FPO ने सौर-ऊर्जा से चलने वाली प्रसंस्करण सुविधाओं को अपनाया है।

## कौशल विकास: बदलती दुनिया के लिए नव कौशल (न्यू-स्किलिंग), कौशल में सुधार करना (रिस्किलिंग) और कौशल बढ़ाना (अप-स्किलिंग)

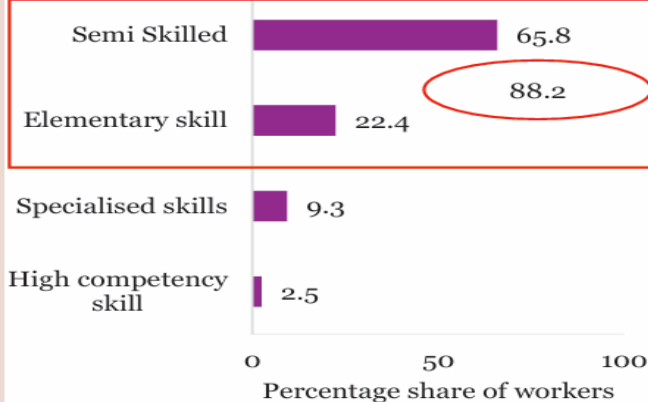
### कौशल परिदृश्य

- शिक्षा और कौशल स्तर:
  - आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)<sup>53</sup> आंकड़ों से पता चलता है कि 90.2% कार्यबल के पास माध्यमिक स्तर के बराबर या उससे कम शिक्षा है।
  - 88.2% कार्यबल कम-दक्षता वाले व्यवसायों में संलग्न हैं - प्राथमिक कुशल और अर्ध-कुशल व्यावसायिक कौशल।
  - उन्नत शिक्षा और विशेष कौशल से लैस 4.2% कार्यबल सालाना 4 लाख से 8 लाख रुपये के बीच कमाता है, लगभग 46% लोग 1 लाख रुपये से कम कमाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से कृषि मजदूर, लिपिक कर्मचारी, कारखाना श्रमिक और छोटे पैमाने पर सेवा प्रदाता जैसे निम्न से अर्ध-कुशल श्रमिक शामिल हैं।
- चुनौतियाँ:
  - 65.3% कार्यबल को किसी भी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं मिला है।
  - कौशल की मांग और उपलब्धता में अंतर: इसका कारण उद्योग जगत की मांग और उपलब्ध कुशल कार्यबल के बीच अंतर है। यह अंतर मुख्य रूप से श्रम बाजार की अक्षमताएं या मांग के अनुरूप विशिष्ट कौशल वाले कार्यबल की कमी है।

चार्ट XII.20: श्रमिकों का शैक्षिक स्तर



चार्ट XII.21: श्रमिकों का व्यावसायिक कौशल स्तर



स्रोत: पीएलएफएस यूनिट लेवल डेटा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

<sup>52</sup> Decentralized Renewable Energy

<sup>53</sup> Periodic Labour Force Survey

- **प्रगति:** सभी सामाजिक-आर्थिक वर्गीकरणों में 2018-19 से 2023-24 तक कुशल लोगों के अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

### सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- **पुनः कौशल प्रदान करना और कौशल बढ़ाना:** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत 1.24 करोड़ से अधिक लोगों ने नामांकन किया है।
- **महिलाओं की भागीदारी: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)** के तहत महिलाओं की भागीदारी 58% (वित्त वर्ष 2025) तक पहुँच गई है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTI) में, महिलाओं की भागीदारी 9.8% (वित्त वर्ष 2016) से बढ़कर 13.3% (वित्त वर्ष 2024) हो गई है।
- **उद्योग साझेदारी: नई ITI अपग्रेडेशन योजना (2024)** जिसमें पीएम इंटरनशिप योजना के साथ-साथ हब-एंड-स्पोक मॉडल का उपयोग करके 1,000 ITIs को अपग्रेड करना शामिल है।
- **कौशल विकास के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर:** उद्योग जगत की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रमों को शुरू करके सभी को कौशल प्रदान करने हेतु स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल लॉन्च किया गया है।
- **आगे की राह:**
  - स्कूल और उच्चतर शिक्षा, दोनों स्तरों पर शिक्षा को बढ़ावा देना।
  - उद्योग 4.0 तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) जैसी नई युग की प्रौद्योगिकियों को शामिल करते हुए कौशल विकास करना।
  - कौशल प्रशिक्षण के व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण और अपग्रेडेशन पर ध्यान केंद्रित करना।
  - कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए इंटरनशिप कार्यक्रम लागू करना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।

### रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए स्तरीकृत कौशल फ्रेमवर्क

- **एक बहुस्तरीय अप्रोच की आवश्यकता है।** इस नए अप्रोच में विशिष्ट कार्यों या नौकरी के लिए तैयार उपयुक्त कौशल, श्रमिकों के चयनित समूहों के लिए लक्षित कौशल तथा सबको और सभी क्षेत्रों में सार्वभौमिक रूप से प्रदान किए जाने वाले मूलभूत AI कौशल शामिल हो सकते हैं।





## कुशल श्रमिकों का अंतर्राष्ट्रीय आवागमन

- दुनिया भर में प्रवासी भारतीय आबादी 32 मिलियन है। 2020 में यह आबादी 18 मिलियन थी।
- 2025 तक दुनिया भर में स्वास्थ्य-देखभाल सेवा, निर्माण, IT, कृषि और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में रोजगार के 97 मिलियन अवसर सृजित होने का अनुमान है।
- उठाए गए कदम:
  - द्विपक्षीय साझेदारी: माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स (MMPA), श्रम गतिशीलता समझौते (LMA) और श्रम कल्याण समझौते।
  - ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क जैसे देशों के साथ G2G समझौता ज्ञापन।
  - नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) के तहत पाठ्यक्रम का विकास।
  - स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, प्रस्थान-पूर्व ओरिएंटेशन प्रशिक्षण, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, MEA (विदेश मंत्रालय) का ई-माइग्रेट प्लेटफॉर्म।
- आगे की राह: वैश्विक स्तर पर कौशल की मांग का पता लगाने और कौशल कार्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए नियमित रूप से विस्तृत मांग-आपूर्ति विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

## निष्कर्ष

- भारत में रोजगार में वृद्धि हुई है, जो उद्यमिता, औपचारीकरण, कौशल विकास और विनियामक फ्रेमवर्क के परिवर्तन के साथ जुड़ी है।
- नियमों के अनुपालन को सरल बनाने, बाजार की मांग के अनुरूप श्रम को बढ़ावा देने और श्रमिक कल्याण को बढ़ावा देने से श्रम सुधार की दिशा में बेहतर माहौल सृजित किया है जो व्यवसाय करने में सुगमता और श्रमिक अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करता है।
- स्थायी रोजगार वृद्धि और आर्थिक समावेशिता को समर्थन देते हुए 'रोजगार सृजन का एक पुण्य चक्र' (Virtuous cycle of job creation) विकसित किया गया है।

## बजट में क्या कहा गया है?

- रोजगार-सृजन आधारित विकास के लिए पर्यटन: देश के शीर्ष 50 पर्यटक स्थलों को चैलेंज मोड के माध्यम से राज्यों के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा।
- कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र: देश के युवाओं को "मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने हेतु वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

## शब्दावली

| शब्द/पद                      | अर्थ                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जनसांख्यिकीय लाभांश          | यह किसी देश की आयु संरचना में बदलाव से उत्पन्न होने वाली आर्थिक संवृद्धि क्षमता को संदर्भित करता है, जहां कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या (15 से 59 वर्ष) निर्भर आयु वर्ग की जनसंख्या से अधिक होती है। |
| निर्भरता अनुपात              | निर्भरता अनुपात कामकाजी आयु वर्ग की आबादी (15-59 वर्ष की आयु) में हर 100 लोगों में बच्चों (0-14 वर्ष की आयु) और वृद्ध व्यक्तियों (60 वर्ष और उससे अधिक आयु) की संख्या को मापता है।                   |
| श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)   | LFPR कामकाजी आयु वर्ग की आबादी के उस प्रतिशत को दर्शाता है जो या तो कार्यरत है या सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहा है और अवसर मिलने पर 'कार्य' करने के लिए उपलब्ध है।                             |
| कार्यकर्ता भागीदारी दर (WPR) | WPR को कुल आबादी में कार्यरत व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।                                                                                                                  |



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) | राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा संचालित ASUSE, तीन क्षेत्रों; विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवाओं से संबंधित असंगठित गैर-कृषि प्रतिष्ठानों का एक सर्वेक्षण है।                                                                                                                                                                                                           |
| डिजिटल अर्थव्यवस्था                                     | डिजिटल अर्थव्यवस्था में वे सभी आर्थिक गतिविधियां शामिल होती हैं जो डिजिटल इनपुट पर निर्भर करती हैं या डिजिटल इनपुट की वजह से उस गतिविधि का व्यापक रूप से विस्तार होता है। इसमें डिजिटल प्रौद्योगिकियां, बुनियादी ढाँचा, डिजिटल सेवाएँ और डेटा शामिल हैं। यह सरकार सहित उन सभी उत्पादकों और उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है, जो आर्थिक गतिविधियों में इन डिजिटल इनपुट का उपयोग करते हैं। |

## अपने सीखने के कौशल का परीक्षण कीजिए

### MCQs

#### 1. रोजगार परिदृश्य के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 15 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों के मामले में बेरोजगारी दर (UR) में गिरावट दर्ज की गई है।
- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) और श्रमिक-जनसंख्या अनुपात (WPR) में वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- कोई नहीं

#### 2. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

- ई-श्रम पोर्टल: इसे असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत करने और उनका समर्थन करने के लिए लॉन्च किया गया है।
- ग्रोथरेटर: MSME विकास, लाभप्रदता को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और दीर्घकालिक सफलता के लिए मेंटरशिप और सहकर्मी नेटवर्क प्रदान करता है।
- नंदिनी सहकार योजना: नवीन सहकारी परियोजनाओं के लिए 2% ब्याज अनुदान।
- स्वयं शक्ति सहकार योजना: महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को समर्थन देने के लिए कार्यशील पूंजी ऋण।

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है/ हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- कोई नहीं
- सभी चारों



3. भारत के अपने कार्यबल के लिए विदेशी रोजगार की सुविधा के प्रयासों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 2024 तक भारत की प्रवासी आबादी 18 मिलियन हो जाएगी।
  2. सरकार ने विदेशों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते (MMPA) और श्रम गतिशीलता समझौते (LMA) जैसी पहलें शुरू की हैं।
  3. नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) भारत के कौशल कार्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
- (a) केवल 1 और 2  
(b) केवल 2 और 3  
(c) केवल 1 और 3  
(d) 1, 2, और 3
4. कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए भारत सरकार की पहल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) ने 1.57 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है, जिसमें प्रमाणन दर 75% से अधिक है।
  2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTIs) में महिलाओं की भागीदारी वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2024 तक तीन गुना बढ़ गई है।
  3. स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल का उद्देश्य कौशल विकास के लिए भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हिस्से के रूप में उद्योग-अनुरूप पाठ्यक्रमों तक आसान पहुंच प्रदान करना है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
- (a) केवल 1 और 2  
(b) केवल 2 और 3  
(c) केवल 1 और 3  
(d) 1, 2, और 3
5. भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और गिग कार्यबल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।
  2. गिग कार्यबल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा विश्लेषक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं।
  3. भारत में फिनटेक के विकास से महिला रोजगार और लैंगिक समानता बढ़ने की उम्मीद है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
- (a) केवल 1 और 3  
(b) केवल 2 और 3  
(c) केवल 1 और 2  
(d) 1, 2 और 3

## मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न

1. विभिन्न सरकारी पहलों के बावजूद, भारत के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा कम-कुशल बना हुआ है और उपयुक्त कौशल का अभाव और व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करता है। इस समस्या में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों पर चर्चा कीजिए तथा उद्योग 4.0 और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के अनुरूप कौशल विकास को बढ़ाने वाले उपाय सुझाइए।
2. डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत में रोजगार सृजन के एक प्रमुख चालक के रूप में उभरी है, विशेष रूप से गिग कार्यबल और फिन्टेक-आधारित वित्तीय समावेशन के विस्तार के माध्यम से। रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कौशल आवश्यकताओं से जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने में डिजिटल अर्थव्यवस्था की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।

# Lakshya

**PRELIMS MENTORING PROGRAM 2025**

## 5 Month Expert Intervention

*A Strategic Revision, Practice, and Mentoring Program for UPSC Prelims Examination*

**15 MARCH 2025**

- Highly experienced and qualified team of Mentors for continuous support and guidance
- A structured plan of revision for GS Prelims, CSAT, and Current Affairs
- Effective Utilization of learning resources, including PYQs, Quick Revision Modules (QRMs), and PT-365

# Lakshya

**PRELIMS & MAINS INTEGRATED MENTORING PROGRAM**

## Lakshya Prelims & Mains Integrated Mentoring Program 2025 & 2026

*(A Strategic Revision, Practice, and Mentoring Program for UPSC Prelims and Mains Examination 2025 & 2026)*

VisionIAS introduces the Lakshya Prelims & Mains Integrated Mentoring Programme 2025 & 2026, offering unified guidance for UPSC aspirants across both stages, ensuring comprehensive support and strategic preparation for success

|             |                    |                 |
|-------------|--------------------|-----------------|
| <b>2025</b> | <b>5 MONTHS</b>    | <b>16 MARCH</b> |
| <b>2026</b> | <b>17.5 MONTHS</b> | <b>16 MARCH</b> |

**Highlights of the Program**

- Coverage of the entire UPSC Prelims and Mains Syllabus
- Development of Advanced answer writing skills
- Highly experienced and qualified team of senior mentors
- Special emphasis to Essay & Ethics

## अध्याय 13. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-AI) युग में श्रम व्यवस्था: संकट या उत्प्रेरक? (Labour in the AI Era: Crisis or Catalyst?)

### परिचय

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-AI) के क्षेत्र में हो रही तीव्र प्रगति दुनिया भर के श्रम बाजारों के लिए अभूतपूर्व अवसर के साथ साथ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी प्रस्तुत करती है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) श्रमिक कार्यसमूहों में व्यापक बदलाव ला सकती है, क्योंकि पिछले चार वर्षों में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय तेजी देखी गई है। इससे आर्थिक विस्थापन की आशंका बढ़ती है और यह चिंता गहरी होती जा रही है कि कहीं AI मौजूदा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को और न बढ़ा दे।

### AI परिदृश्य

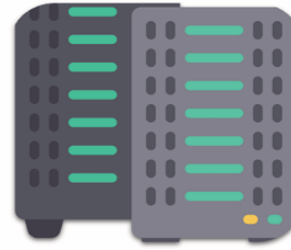
- 2021 और 2023 के बीच, सभी प्रकार के AI में वैश्विक कॉरपोरेट निवेश कुल 761 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का अनुमान है कि AI के कारण उत्पन्न ऑटोमेशन के परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर लगभग 75 मिलियन नौकरियां पूरी तरह से खतरे में हैं।
- NASSCOM का अनुमान है कि भारतीय AI बाजार में 2027 तक 25% से 35% CAGR की दर से वृद्धि होगी।

### मजबूत संस्थाओं की आवश्यकता

- पिछली तकनीकी क्रांतियों को जब सावधानीपूर्वक प्रबंधित नहीं किया गया, तो उन्होंने व्यापक आर्थिक कठिनाइयों, लंबे समय तक बेरोजगारी और बढ़ती आय असमानताएं जैसी दुखदायी परिस्थितियों को जन्म दिया।
- उच्च गुणवत्ता वाले संस्थान यह सुनिश्चित करते हुए मध्यवर्ती के रूप में कार्य करते हैं कि तकनीकी प्रगति सभी को लाभ प्रदान करती है, जबकि कमजोर संस्थाएं या इनकी अनुपस्थिति अक्सर असमानताओं को बढ़ाती हैं जिसके परिणामस्वरूप असमान आर्थिक और सामाजिक प्रतिफल प्राप्त होते हैं।
- कार्यबल परिवर्तन के लिए संस्थागत आवश्यकताएँ
  - सक्षम संस्थाएं: ये लोगों को परिवर्तन के अनुकूल ढालने और उनके विकास के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने पर केंद्रित होती हैं। वे कौशल प्रदान करती हैं और शिक्षा के कंटेंट को बेहतर बनाती हैं ताकि दी जा रही शिक्षा जॉब मार्केट की आवश्यकताओं के अनुरूप बनी रहे।
    - वे इन नई जॉब्स में सुचारू रूप से ढलने की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे कार्यबल की आय को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और रोजगार की हानि को रोका जा सके।
  - बीमा संस्थाएं: इनका उद्देश्य उन कार्यबल की राह आसान करना है जिनकी वित्तीय स्थिति और रहन-सहन परिवर्तन काल के दौरान प्रभावित हुई है।
    - ये संस्थाएं बदलाव के दौरान जीवन स्तर को सुरक्षित रखने, असमानताओं को कम करने और सामाजिक ताने-बाने को एकजुट बनाए रखने में मदद करती हैं। वे व्यक्तियों और समाजों पर मंदी के जोखिम को कम करने में भी सहायक सिद्ध होती हैं।
  - स्टीवर्डिंग संस्थाएं: इन्हें एक ऐसी अप्रोच तैयार करने का दायित्व उठाना होगा जो इनोवेशन को बाधित किए बिना जन कल्याण को संतुलित करें।
    - ये संस्थाएँ सतर्क होंगी, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करेंगी और नवीनतम विकास से परिचित रहेगी ताकि वे अवसरों और खतरों, दोनों को पहचानने में सक्षम हों।

## विजन से व्यावहारिकता की ओर: AI के लिए प्रत्यक्ष चुनौतियाँ

### एआई के स्केल निर्धारण संबंधी चुनौतियाँ



#### व्यावहार्यता

सफलताओं को व्यावहारिक, व्यापक रूप से अपनाए गए अनुप्रयोगों में परिवर्तित करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि एआई वर्तमान में प्रयोगात्मक और असमान उपयो. गिता को दर्शाता है

#### विश्वसनीयता

वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के लिए एआई की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वायत्त संवाहकों या स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख उद्योगों में विफलताएँ समस्या बढ़ाने वाली साबित हो सकती हैं

#### अवसंरचना

बड़े पैमाने पर एआई से संबंधित अवसंरचना में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है, जिसमें डाटा सेंटर, डाटा को क्लीन करने संबंधी पाइपला. इन और कम्प्यूटेशनल संसाधन शामिल हैं

#### संसाधन

बड़े मॉडल सघन संसाधन युक्त होते हैं, जिनमें उच्च ऊर्जा खपत, हार्डवेयर और वित्तपोषण के लिए दुर्लभ खनिजों पर निर्भरता की आवश्यकता होती है, जिससे संधारणीय नवाचार आवश्यक हो जाता है

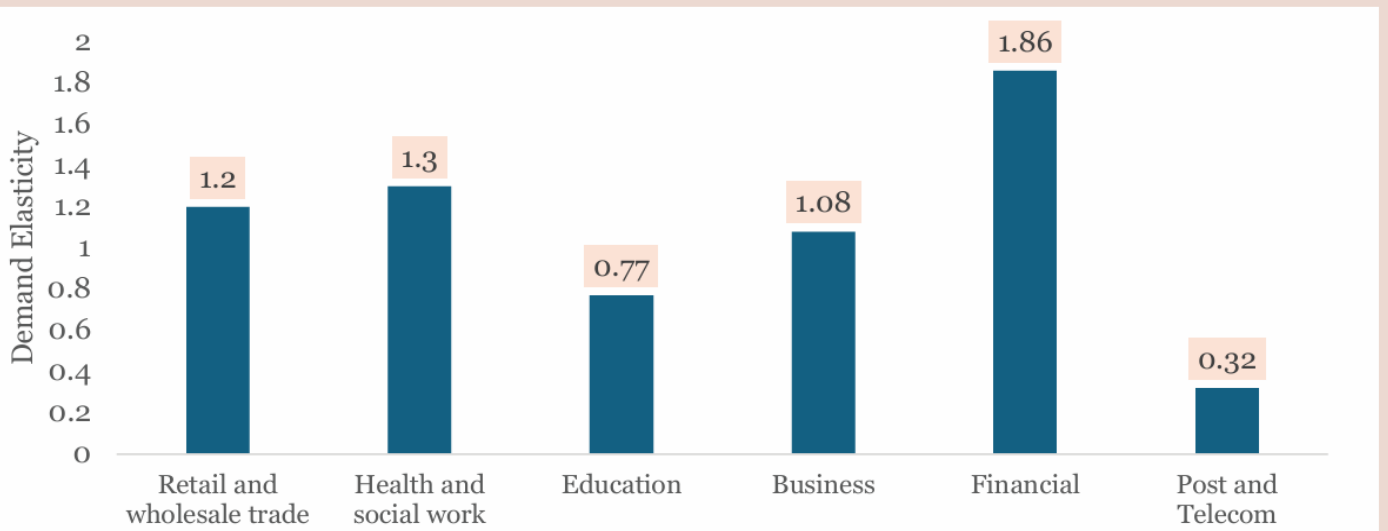
## AI और भारत: क्या अवसर है?

- देश की सेवा क्षेत्रक-आधारित अर्थव्यवस्था, साथ ही इसकी युवा और ऊर्जावान आबादी, नई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करती है।
- श्रम बाजार
  - प्रौद्योगिकीय परिवर्तन से प्रभावित उद्योग के रोजगार में हमेशा गिरावट दर्ज नहीं की जाती है; बल्कि, इससे उन दशकों के दौरान रोजगार में मजबूत वृद्धि हुई है जब नई प्रौद्योगिकियाँ अपनाई जा रही थीं।
    - उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्त्र, इस्पात और मोटर वाहन उद्योगों पर ऑटोमेटेड विनिर्माण से मजबूत रोजगार वृद्धि और उच्च आय दर्ज की गई।
  - उत्तरदायित्व, दुनिया के व्यक्तिपरक और व्यावहारिक वास्तविकताओं की समझ, निरंतर तार्किक रूप से सोचने, परिणामों के प्रति जागरूक रहने और आलोचनात्मक सोच जैसे कारक, ऐसे तत्व हैं, जो मानव संसाधन वाले किसी भी उद्यम में विद्यमान रहते हैं। इसलिए AI को समस्या की बजाय समस्याओं को सुलझाने में इंसानों की मदद करने वाले एक टूल के रूप में देखा जाना चाहिए।
- भारत के सेवा क्षेत्रक में सुधार
  - चूंकि ऑटोमेशन नियमित और सामान्य कार्यों को संभाल लेता है, इसलिए अधिक जटिल समस्याओं और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कौशल को अपग्रेड करने की आवश्यकता है।
  - भारत के लिए रोजगार की चुनौती केवल संख्या को लेकर नहीं है, बल्कि व्यावहारिक कौशल (सॉफ्ट स्किल्स) और मूल दक्षताओं जैसे अधिक मूलभूत कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्यबल की समग्र 'गुणवत्ता' को बढ़ाने के बारे में भी है।

## • भारत के सेवा क्षेत्रक पर प्रभाव का अनुमान

- मांग की लोच (कीमत में परिवर्तन से मांग की संख्या में परिवर्तन) वास्तव में ऑटोमेशन से उत्पादकता में वृद्धि के कारण किसी क्षेत्रक की रोजगार बढ़ाने की क्षमता का आकलन करने में मदद कर सकती है।
- अत्यधिक लोच यह दर्शाती है कि ऑटोमेशन से आर्थिक क्षेत्रकों में उत्पादकता और रोजगार बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- नए उत्पादों और सेवाओं की मांग नए सहायक कार्यों का सृजन करेगी।
- इससे उत्पादकता प्रभाव और पुनर्स्थापन प्रभाव उत्पन्न होगा। इसका मतलब है कि विविध कार्य उपलब्ध होने पर श्रमिकों को किसी अन्य कार्य में फिर से नियोजित किया जा सकेगा, और इस प्रकार उत्पादन के कार्य क्षेत्र को श्रम के पक्ष में बदला जा सकेगा।

चार्ट XIII.1: भारत के लिए सेवा क्षेत्रों में मांग लोच



स्रोत: लेखक का अनुमान

## निष्कर्ष

- नीति-निर्माताओं को इनोवेशन और सामाजिक लागतों के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए, क्योंकि श्रम बाजार में AI संचालित बदलावों का सतत दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है।
- उन कार्यों में जहां AI की वजह से 'श्रम को हटाने' की बजाय 'श्रम को कुशल' बनाने की आवश्यकता हो, भविष्य के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होगी।
- कार्य का भविष्य 'ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस' को होगा, जहां कार्यबल मानव और मशीन, दोनों क्षमताओं का एकीकरण करेगा।
- भारत के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए क्षमता निर्माण और संस्थान निर्माण करना समय की आवश्यकता है, साथ ही इसके लिए शिक्षा और सुरक्षा तंत्र (Safety Nets) की व्यवस्था करना भी अनिवार्य है।

## बजट में क्या कहा गया है?

- शिक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र: शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए कुल परिव्यय ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- डीप टेक फंड ऑफ फंड्स: नेक्स्ट जनरेशन के स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की संभावनाओं को तलाशा जाएगा।



## शब्दावली

| शब्द/पद                                    | अर्थ                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>'ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस', वह स्थिति है जहां कार्यबल मानव और मशीन दोनों क्षमताओं को एकीकृत करता है।</li> </ul>                    |
| पुनर्स्थापना प्रभाव (Reinstatement Effect) | <ul style="list-style-type: none"> <li>पुनर्स्थापना प्रभाव उस प्रक्रिया को कहा जाता है जहां ऑटोमेशन नए कार्य सृजित करता है, और जिससे रोजगार सृजन होता है।</li> </ul> |

## अपने सीखने के कौशल का परीक्षण कीजिए

### MCQs:

- वैश्विक श्रम बाजार पर AI के प्रभाव के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  - अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का अनुमान है कि AI के कारण उत्पन्न ऑटोमेशन से वैश्विक स्तर पर लगभग 75 मिलियन नौकरियां पूरी तरह से खतरे में हैं।
  - NASSCOM का अनुमान है कि भारतीय AI बाजार में 2027 तक 50% CAGR की दर से वृद्धि दर्ज की जाएगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    - केवल 1
    - केवल 2
    - 1 और 2 दोनों
    - न तो 1, न ही 2
- AI और भारत के श्रम बाजार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  - पुनर्स्थापना प्रभाव यह उस प्रक्रिया को कहते हैं जहां ऑटोमेशन नए कार्य सृजित करता है, तथा जिससे रोजगार सृजन होता है।
  - किसी क्षेत्र में उच्च मांग लोच का अत्यधिक तीव्र होना यह दर्शाता कि ऑटोमेशन से मुख्य रूप से रोजगार में वृद्धि होगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    - केवल 1
    - केवल 2
    - 1 और 2 दोनों
    - न तो 1, न ही 2
- निम्नलिखित में से कौन AI युग में "ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस" की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है?
  - AI पूरी तरह से कार्यबल में मानव श्रमिकों की जगह ले रहा है।
  - मनुष्य और AI एक साथ कार्य कर रहे हैं, और AI मानव की क्षमताओं को भी बढ़ा रहा है।
  - AI केवल कम-कुशल नौकरियों को स्वचालित करता है, उच्च-कुशल नौकरियां अप्रभावित रहती हैं।
  - AI का उपयोग बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के केवल डेटा विश्लेषण के लिए किया जा रहा है।

4. AI-संचालित समाधानों को बड़े पैमाने पर लागू करने में, निम्नलिखित में से किन्हें प्रमुख चुनौतियां माना जाता है?
1. उच्च ऊर्जा खपत और दुर्लभ खनिजों पर निर्भरता
  2. AI आधारित निर्णयन में जवाबदेही का अभाव
  3. सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत के बीच त्रिपक्षीय समझौते का अभाव
  4. नए कौशल और दक्षताओं की मांग में गिरावट
- नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
- (a) केवल 1 और 2
  - (b) केवल 1, 2, और 3
  - (c) केवल 2 और 4
  - (d) 1, 2, 3, और 4
5. भारत में किस क्षेत्र को प्रतिस्थापन की बजाय AI-संचालित संवर्धन से सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है?
- (a) विनिर्माण
  - (b) कृषि
  - (c) सेवाएं
  - (d) खनन

### मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न

1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से वैश्विक श्रम बाजारों में बदलाव करने, नौकरी छूटने और आर्थिक असमानताओं के बढ़ने की अपेक्षा की जाती है। भारत 'श्रम-प्रतिस्थापन' परिणामों की बजाय 'श्रम-संवर्द्धन' परिणाम प्राप्त करने के लिए AI का लाभ कैसे उठा सकता है? समावेशी और सतत AI अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाइए।
2. AI युग में कार्य के भविष्य को दिशा देने में संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। AI की वजह से रोजगार में व्यापक रूपांतरण को कम करने में 'स्टीवर्डिंग संस्थानों' (Stewarding Institutions), 'सक्षम संस्थान,' और 'बीमा संस्थान' के महत्व को समझाइए।





## MCQs के उत्तर

### अध्याय 1:

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1) C | 2) C | 3) C | 4) C | 5) C |
|------|------|------|------|------|

### अध्याय 2:

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1) A | 2) C | 3) B | 4) A | 5) A |
|------|------|------|------|------|

### अध्याय 3:

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1) C | 2) A | 3) A | 4) D | 5) B |
|------|------|------|------|------|

### अध्याय 4:

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1) B | 2) A | 3) C | 4) C | 5) C |
|------|------|------|------|------|

### अध्याय 5:

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1) B | 2) B | 3) A | 4) B | 5) B |
|------|------|------|------|------|

### अध्याय 6:

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1) C | 2) C | 3) B | 4) A | 5) C |
|------|------|------|------|------|

### अध्याय 7:

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1) A | 2) C | 3) B | 4) A | 5) A |
|------|------|------|------|------|

### अध्याय 8:

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1) B | 2) B | 3) B | 4) D | 5) C |
|------|------|------|------|------|

### अध्याय 9:

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1) D | 2) B | 3) B | 4) B | 5) D |
|------|------|------|------|------|

### अध्याय 10:

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1) B | 2) C | 3) B | 4) A | 5) D |
|------|------|------|------|------|

### अध्याय 11:

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1) A | 2) B | 3) C | 4) D | 5) A |
|------|------|------|------|------|

### अध्याय 12:

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1) C | 2) D | 3) B | 4) C | 5) A |
|------|------|------|------|------|

### अध्याय 13:

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1) A | 2) C | 3) B | 4) B | 5) C |
|------|------|------|------|------|

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

# Heartiest Congratulations

to all Successful Candidates



1  
AIR

**Aditya Srivastava**

**79**

in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**

from various programs of **Vision IAS**



**Animesh  
Pradhan**



**Ruhani**



**Srishti  
Dabas**



**Anmol  
Rathore**



**Nausheen**



**Aishwaryam  
Prajapati**

**हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में**

**= हिंदी माध्यम टॉपर =**



**मोहन लाल**



**अर्पित  
कुमार**



**विपिन  
दुबे**



**मनीषा  
धर्वे**



**मयंक  
दुबे**



**देवेश  
पाराशर**

**UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें**



**मोहन लाल**



**UPSC  
CSE 2026  
सामान्य अध्ययन**



**UPSC  
Prelims 2025  
10 years PYQ**



**Master  
Classes Series  
करेंट अफेयर्स**



**DELHI**

## HEAD OFFICE

Apsara Arcade, 1/8-B 1<sup>st</sup> Floor,  
Near Gate-6 Karol Bagh  
Metro Station

## MUKHERJEE NAGAR CENTER

Plot No. 857, Ground Floor,  
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab  
& Sindh Bank, Mukherjee Nagar

## GTB NAGAR CENTER

Classroom & Enquiry Office,  
above Gate No. 2, GTB Nagar  
Metro Building, Delhi - 110009

## FOR DETAILED ENQUIRY

Please Call:  
+91 8468022022,  
+91 9019066066

[enquiry@visionias.in](mailto:enquiry@visionias.in) [@visioniashindi](https://www.youtube.com/@visioniashindi) [/visionias.upsc](https://www.facebook.com/visionias.upsc) [/vision\\_ias\\_hindi/](https://www.instagram.com/vision_ias_hindi/) [/hindi.visionias](https://www.facebook.com/hindi.visionias)

